



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2015/आश्विन 7, 1937

No. 333]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2015/ASVINA 7, 1937

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2015

सं. 1सीए(5)/66/2014.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

66वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् “परिषद्” कहा गया है) को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 66वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति की वर्तमान प्रास्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि और विकास में उसकी वर्तमान भूमिका, जिसे वह वर्षों से निभा रही है, के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2014-2015 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के उस वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2015 की अवधि तक, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है।

1. परिषद्

बाइसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2013 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। वर्ष 2015-2016 के लिए परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियाँ

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधानुसार 12 फरवरी, 2014 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों/बोर्डों का गठन किया था। 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 231 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

मैसर्स एसए एसोसिएट्स एलएलपी और मैसर्स बी एम छत्रथ एंड कं. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनके द्वारा उसे प्रदान की गई सेवाओं की अनुशंसा करती है।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय, जिनमें परिषद् को सिफारिश किए गए विनिश्चय भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

- आईसीएआई और पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के बीच एक एमओयू के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- दार ए-सलाम में आईसीएआई के चैप्टर की स्थापना।
- मध्यवर्ती (आईपीसी) पाठ्यक्रम के छात्रों के संबंध में प्रत्येक वर्ष आवश्यकता आधारित और समाज के कमजोर वर्गों के प्रवर्ग में छात्रवृत्तियों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 करना तथा फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु इन छात्रवृत्तियों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 करना। अनुमोदित छात्रवृत्तियों की संख्या के अलावा ऐसे मामलों में, जहां आईसीएआई के मृतक सदस्यों पति/पत्नी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि (सीएबीएफ) से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, वहां मृतक सदस्यों के ऐसे बालक, जो सीए पाठ्यक्रम कर रहे हैं, भी उक्त निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और ऐसी पात्रता आवश्यकता आधारित और समाज के कमजोर वर्गों के प्रवर्ग के अधीन छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु यह कि वे अध्ययन बोर्ड द्वारा विहित आवेदन प्ररूप में आवेदन करते हैं।
- प्रश्नपत्र नियत करने के लिए, अर्थात् 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 10 सब्जेक्टिव प्रश्नों को तय करने के लिए मानदेय को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करना तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की निधिरण परीक्षा के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए संदाय को 150 रुपए करना।
- विदेश में आर्टिकलशिप प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण।
- माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन द्वारा विशेष निबंधनों पर आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों को माइक्रोसाफ्ट आफिस 365 उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।
- आईसीएआई को झूठे/बनाए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम करने से छात्रों/अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से वजित करना और साथ ही पाठ्यक्रम की किसी भी पाठ्यचर्या में उन्हें रजिस्ट्रीकृत न किया जाना और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई पाठ्यक्रम फीस को जब्त कर लिया जाना।
- छात्रों के कतिपय प्रवर्गों को, जिन्हें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त थी और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम में सीधा प्रवेश लेने के लिए पात्र थे, एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्रतिशत के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने संबंधी सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना।

संबंधित समितियों से प्राप्त सिफारिशें, जिन्हें उसके पश्चात् कार्यपालक समिति की सिफारिशों के साथ परिषद् के समक्ष रखा गया था :

- सूचना प्रणाली सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- सीपीटी रूट के अधीन आईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रीकृत ऐसे छात्रों के संबंध में, जिन्हें सीधे प्रवेश स्कीम में स्थानांतरित कर दिया गया था, आईपीसी परीक्षा में बैठने के लिए 9 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने की अपेक्षा को शिथिल करना।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति – जो परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है – चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई थी। उक्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के नियंत्रण एवं निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं को 26 मई, 2014 से 9 जून, 2014 के दौरान विदेशों और देश भर में क्रमशः 414 और 302 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह		समूह I		समूह II	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसीई)	66625	6326	125187	20537	121855	16878
फाइनल	42533	3100	65792	8884	65706	7004

इसके अतिरिक्त, बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का सफल आयोजन मई, 2014 में किया गया था, जिनमें कुल 65 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 46 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया था।

इसके अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) परीक्षाओं को 22 जून, 2014 और 14/21 दिसम्बर, 2014 को, विदेशों और देश भर में क्रमशः 163 और 167 नगरों में स्थित क्रमशः 414 और 383 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
22 जून, 2014 को आयोजित सीपीटी	130291	37303
14 और 21 दिसम्बर, 2014 को आयोजित सीपीटी	100957	14880

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का आयोजन 7 से 23 नवंबर, 2014 के दौरान विदेशों और देश भर में क्रमशः 421 और 308 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाएं और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह		समूह I		समूह II	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसीई)	47795	2963	123488	17603	104435	15982
फाइनल	36254	2983	64972	15208	66552	6830

इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (एमएसी)(भाग-I), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी)(भाग-I), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी)(भाग-I), बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) की परीक्षाओं का सफल आयोजन भी नवम्बर, 2014 में किया गया था।

वर्ष के दौरान, अर्हतापत्र पाठ्यक्रम सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 28 जून, 2014 को देश भर में 61 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था और एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 27 दिसंबर, 2014 को देश भर में 65 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। उक्त परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
28 जून, 2014 को आयोजित आईएसए-एटी	3288	219
27 दिसंबर, 2014 को आयोजित आईएसए-एटी	2684 (पुराना) 256 (नया)	668 (पुराना) 125 (नया)

आईसीएआई अपनी परीक्षा प्रणालियों को प्रश्रपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रणालियों में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे कि परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले छह दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

आईसीएआई की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करती हैं जिससे छात्र अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति के पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें।

प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईसीएआई की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हक छात्र एक सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

अंतरराष्ट्रीय पहले : आईसीएआई ब्रांड द्वारा मदद के लिए हाथ बढ़ाना

विशेष परीक्षा : निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए परस्पर मान्यता करारों/समझ ज्ञापनों से उदभूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें उक्त निकायों की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हमारे सदस्य बैठना चाहते थे, सफलतापूर्वक आयोजन (i) 21 से 24 जनवरी, 2014, (ii) 10 से 13 जून, 2014 और (iii) 6, 7 और 9 जनवरी, 2015 में नई दिल्ली में किया गया था :

1. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)
2. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
3. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
4. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
5. कैनेडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीआईसीए)

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने न्यूजीलैंड इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एनजेडआईसीए) के साथ हुए परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

उपरोक्त विशेष परीक्षा, उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन के सदस्यों के लिए भी खुली है।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन संस्थानों को सहयोग : परीक्षा समिति ने श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को उनकी आईएसए निर्धारण परीक्षा के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड को भी भारत में उनकी परीक्षा के संचालन के लिए अवसरचना संबंधी, प्रशासनिक और जनशक्ति संबंधी सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा गया है।

वृत्ति के लिए पहले : घटक निर्माण संबंधी कार्यकरण

जांचकर्ताओं की नियुक्ति : मई, 2012 में आयोजित की गई परीक्षाओं से, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए रखे गए पैनल में से आईसीएआई के किसी एक सदस्य द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस जांच में, अन्य बातों के साथ, यह जांच सम्मिलित है कि क्या सभी प्रश्नों/उपप्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है, दिए गए अंकों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया गया है, कोई योग संबंधी त्रुटि तो नहीं है, आदि। उपरोक्त पुनरीक्षित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, परीक्षकों की प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्द्धक हैं। उक्त प्रक्रिया को मई, 2014 और नवम्बर, 2014 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी अपनाया गया था।

आईटी संबंधी पहले : परिवर्तित होते समय के साथ आगे कदम बढ़ाना

स्वचालन : कोडिंग, उपस्थिति के आंकड़ों का संग्रहण, अंकों का सुमेलन और संग्रहण (परीक्षकों द्वारा उनके मूल्यांकन के पश्चात्), उनके सारणीकरण आदि को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया के स्वचालन को मई, 2014 तथा नवम्बर, 2014 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था।

प्रश्नोत्तर बैंक : सामान्य प्रवीणता परीक्षा और सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर बैंकों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

संपरीक्षक वेबपोर्टल का विकास : मई, 2014 की परीक्षाओं से परीक्षा केंद्रों में नियुक्त संपरीक्षकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों को सुकर बनाने के लिए, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, आबंटित समनुदेशन के ब्यौरे का रखा जाना, स्वीकृति पत्रों/दैनिक रिपोर्टों/मानदेय के लिए दावों आदि का प्रस्तुत किया जाना है, <http://observers.icaexam.icaai.org> नामक एक वेबपोर्टल को विकसित किया गया था और स्थापित किया गया था। इस सुविधा को नवंबर, 2014 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया था।

परीक्षा केंद्र वेबपोर्टल का विकास : मई, 2014 की सीए परीक्षाओं के लिए, परीक्षा के दिवस को अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से संबंधित डाटा को दैनिक आधार पर आनलाइन रखने के लिए <http://centres.icaexam.icaai.org> नामक एक वेबपोर्टल को विकसित किया गया था और स्थापित किया गया था। इस सुविधा को नवंबर, 2014 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया था।

एनईएफटी के माध्यम से संदाय : वर्ष के दौरान परीक्षकों, परीक्षा केंद्रों, संपरीक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों आदि को एनईएफटी के माध्यम से संदाय की स्कीम को प्रारंभ किया गया था और सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था।

छात्रों के लिए पहले : आधारभूत कारकों को सुदृढ़ बनाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्र इस वृत्ति का भविष्य हैं ; उनके कल्याण और सुविधा के लिए निम्नलिखित पहले की गई थी :

पठन समय : छात्रों की परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप अभ्यर्थियों को मई, 2011 की परीक्षाओं से, परीक्षाएं आरंभ होने के नियत समय से पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षाओं में 15 मिनट का पठन समय अनुज्ञात किया गया था, जिसे मई, 2014 और नवम्बर, 2014 की परीक्षाओं में भी जारी रखा गया है।

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्ररूप : ऑनलाइन रूप से परीक्षा आवेदन प्ररूपों को प्रस्तुत करने और ऑनलाइन माध्यम से <http://icaexam.icaai.org> नामक पेमेंट गेटवे के द्वारा परीक्षा फीस के संदाय की स्कीम को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था और इसे वर्ष 2014 के दौरान भी जारी रखा गया था। ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षा प्ररूप ऑनलाइन माध्यम से भरने का विकल्प लिया था, आवेदन प्ररूपों की लागत का संदाय करने से छूट प्रदान की गई थी। सभी परीक्षा प्ररूपों के लगभग 97 प्रतिशत प्ररूप ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।

परीक्षा हेतु प्ररूप प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रविष्टियों में ऑनलाइन शुद्धियां : परीक्षा प्ररूपों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भी छात्रों के पास उनकी विशिष्टियों में ऑनलाइन शुद्धियां करने का एक अन्य अवसर उपलब्ध है, अर्थात् <http://icaexam.icaai.org> पर, जहां परीक्षा केंद्रों, समूह और माध्यम आदि में परिवर्तन करने जैसी शुद्धियां की जा सकती है। इस लिंक को शुद्धि विंडो कहा जाता है और इसने छात्रों को परीक्षा प्ररूपों में शुद्धियां करने के लिए संपर्क करने में समर्थ बनाया था।

प्रवेश पत्र : नवम्बर, 2012 की सीए परीक्षाओं और दिसम्बर, 2012 की सीपीटी परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के स्कैन किए गए फोटो और नमूना हस्ताक्षर के साथ प्रवेशपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा को आरंभ किया गया है, जिसे मई/जून, 2014 तथा नवंबर/दिसंबर, 2014 की परीक्षाओं के दौरान भी जारी रखा गया था।

सत्यापन हेतु आवेदन : नवम्बर, 2011 में हुई परीक्षाओं से, परिणामों की घोषणा के फलस्वरूप अपने अंकों के सत्यापन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को उनका अनुरोध <http://icaiaexam.icaai.org> पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा को मई, 2014 और नवम्बर, 2014 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है। उनके अनुरोधों के परिणामों को भी उसी वेबसाइट पर रखा जाता है।

उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति : नवम्बर, 2011 में हुई परीक्षाओं से छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए और/या उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी आवेदनों को <http://icaiaexam.icaai.org> पर ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा को मई, 2014 और नवम्बर, 2014 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीए विनियम, 1988 के विनियम 39(4) के अधीन, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध किया था, अंकों के स्वतः सत्यापन की स्कीम को नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं से प्रारंभ किया गया था, जिसे मई, 2014 और नवम्बर, 2014 की परीक्षाओं के लिए जारी रखा गया था।

नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं और आगे की परीक्षाओं से, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए, जो मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रतियों का अनुरोध करते हैं, उनकी मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन प्रतियों को उस वेबसाइट पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिस तक संबंधित परीक्षार्थी द्वारा एक सुरक्षित उपयोक्ता आईडी और पासवर्ड के साथ पहुंच बनाई जा सकती है।

नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों द्वारा उनके आवास से निकटतम स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से निम्नानुसार नए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी:

सीए मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केन्द्र :

- क) मई, 2014 और आगे की परीक्षाओं के लिए : गांधीनगर, फतेहाबाद, कुरनूल, नीमच, करीमनगर, झुन्झुनु, चितौडगढ़ और झांसी
- ख) नवम्बर, 2014 और आगे की परीक्षाओं के लिए : तिरुनेलवेली, ओंगोले, धुले और अनंतपुर
- ग) मई, 2014 और आगे की परीक्षाओं के लिए : भिवंडी और इच्छलकरंजी

सीपीटी परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केन्द्र :

- क) जून, 2014 की परीक्षा से गांधीनगर, फतेहाबाद, कुरनूल, नीमच, करीमनगर, झुन्झुनु, चितौडगढ़, झांसी और नवसरी
- ख) दिसंबर, 2014 की सीपीटी परीक्षा से : तिरुनेलवेली, ओंगोले, धुले और अनंतपुर

परीक्षा परिणाम : परीक्षा परिणाम, उनकी घोषणा के तुरंत पश्चात्, अभिहित साइट पर देखे जा सकेंगे। उनके लिए एसएमएस सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सीपीटी परीक्षा परिणाम पत्र (फोटो और हस्ताक्षर सहित) को डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

भिन्न रूप से समर्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायता : आईसीआईए अब प्रारंभिक रूप से मई, 2014 की परीक्षाओं से अपने भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को लेखक/लिपिक उपलब्ध कराएगा, जिन्हें प्रति परीक्षा-पत्र 500 रुपए की दर से संस्थान द्वारा मानदेय का संदाय किया जाएगा। पात्र लेखकों/लिपिकों का एक नगरवार पैल हमारी वेबसाइट www.icaai.org पर उपलब्ध है। भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को उनके उत्तर लिखने हेतु कंप्यूटर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

“छूट” प्रास्थिति की जांच करने के लिए वेबसाइट प्रारंभ करना :

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षाओं में समूह में असफल रहते हैं किंतु एक या अधिक प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों से कतिपय मानदंडों के अधीन रहते हुए “छूट” प्रदान की जाती है। ऐसी छूट की प्रास्थिति को, उन्हें जारी अंकों के विवरण में उपदर्शित किया जाता है। इस संबंध में और अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराने और अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों/संदेहों को दूर करने के लिए एक वेबसाइट <http://exemption.icaiaexam.icaai.org> का विकास किया गया है और स्थापित किया गया है जिस पर ऐसे अभ्यर्थियों की प्रास्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है जो आगामी परीक्षाओं में छूट के लिए पात्र हैं।

प्रतिक्रिया प्ररूप :

अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्रों के संबंध में प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के विचार से, एक प्रारूप तैयार किया गया है और उसे www.icaai.org पर रखा गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी सीए परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के संबंध में उनकी गुणवत्ता/उन्हें हल करने में आई कठिनाईयों के संबंध

में, अंतिम परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर परीक्षा विभाग को अपनी राय दे सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित ई-मेल आईडी examfeedback@icai.org को भी तैयार किया गया है।

4.4 अनुशासन समिति

वर्ष 2006 में किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधनों के परिणामस्वरूप, अनुशासन तंत्र की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और वर्तमान में आईसीएआई के पास दो अर्ध-न्यायिक तंत्र हैं, जिनके माध्यम से वह अपने मुख्य अनुशासनात्मक कृत्यों का निर्वहन करता है, जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन उपबंधित किया गया है, अर्थात् (i) अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) और (ii) अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)। इसके अतिरिक्त, जहां तक धारा 21घ के अधीन पुराने अनुशासन संबंधी मामलों का संबंध है, धारा 21घ के अधीन संपरिवर्ती उपबंध लागू होंगे और अनुशासन समिति धारा 21घ के अधीन, अधिनियम और तदधीन विरचित विनियमों में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगी। अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन)/अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) और अनुशासन समिति (धारा 21घ के अधीन) के ब्यौरेवार क्रियाकलापों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथम दृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर सात (7) बैठकों की थी। वर्ष के दौरान हुई उक्त बैठकों में, बोर्ड ने 9 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। अनुशासन बोर्ड के कार्यकरण से संबंधित आंकड़ों के ब्योरे नीचे एक पृथक् सारणी में दिए गए हैं।

ऐसे मामले, जिनपर नए अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन)

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	अनुशासन बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान की गई बैठकों की संख्या	7
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया और जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	58*/20
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन बोर्ड ने आगे और जांच के लिए अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया था	11/1
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	8/2
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	12/0

* इनके अंतर्गत ऐसे मामले भी थे, जिन पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामले में अन्वेषण की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 के नियम 6/12 के अधीन कार्रवाई की गई थी।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम,

2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान समिति ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर 21 बैठकों की थी, जो कुल मिलाकर 22 दिन चली थीं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 53 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। अनुशासन समिति के कार्यकरण से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे नीचे एक पृथक् सारणी में दिए गए हैं :

अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	अनुशासन समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान की गई बैठकों की संख्या	21
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया और जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	18/8
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन समिति ने आगे और जांच के लिए अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया था	18/8
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	37/16
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	16/5

धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले उसे परिषद् द्वारा प्रथमदृष्टया राय के आधार पर पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के अधीन निर्दिष्ट किए गए हैं, विरुद्ध अनुशासन संबंधी जांच करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस समिति ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था और वह उसके समक्ष लंबित तीन शेष मामलों में सुनवाईयों को पूरा करने और प्रक्रियाओं में तेजी लाने का कार्य कर रही है।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई थी (धारा 21(घ))

1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	अनुशासन समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या (समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित कुल मामलों में से)	-
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई की गई थी)	04
3.	उपरोक्त में से,-- (क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दोषी पाया गया था किंतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया था (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है। (ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है	-- 02 -- -- 02

4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	01
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	07

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन आईसीएआई द्वारा वर्ष 1977 में, एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने और भारत में विद्यमान विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में संगतता लाने के विचार से किया गया था। एएसबी, इसके गठन के प्रारंभ से ही नए लेखांकन मानकों को तैयार करके और साथ ही समयसमय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करके इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) /अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है। एएसबी वर्तमान कारबार परिस्थितियों, जो शनैः शनैः जटिल होती जा रही हैं, में लेखांकन मानकों के एक समान उपयोग से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समयसमय पर विभिन्न मार्गदर्शन सामग्रियां भी जारी करता है।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) अंतःस्थापित करके अक्तूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 211(3ग) के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) के परामर्श से विहित किया जा सकेगा। इस धारा के परंतुक के अनुसार, सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना जारी किए जाने तक, कंपनियों द्वारा संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों को अपनाया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2006 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को भारत के राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित किया था। ये मानक, इन लेखांकन मानकों की प्रकाशन की तारीख (अर्थात् 7 दिसम्बर, 2006) को प्रभावी होंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (अकाउंट्स) नियम, 2014 में, जिन्हें तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है, यह विनिर्दिष्ट किया कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के बारे में यह माना जाएगा कि वे तब तक लेखांकन मानक बने रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 133 के अधीन लेखांकन मानक विनिर्दिष्ट न कर दिए जाएं।

चूंकि वैश्वीकरण और उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा के आरपार उधार लेना, उधार देना, विक्रय, क्रय आदि के माध्यम से कारबार व्यवहारों की संख्या में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संवहनीय विकास को बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शक वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की आवश्यकता है। बहुविध अधिकारिताओं में प्रचालन करने के परिणामस्वरूप, विभिन्न कारबार इकाइयों के बीच आर्थिक संसाधनों के आबंटन और अनुकूलतम उपयोग के दृष्टिकोण से कारबार संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है। जहां तक वित्तपोषण के स्रोतों का संबंध है, कोई संगठन किसी विशिष्ट अधिकारिता तक ही निर्बंधित नहीं है, इसलिए किसी अस्तित्व द्वारा उसके वित्तीय विवरणों के माध्यम से उसके विभिन्न पणधारियों को संप्रेषित वित्तीय जानकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अस्तित्व के कारबार की सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करने के साथ-साथ वैश्विक रूप से समतुलनीय भी हो। वैश्विक रूप से समतुलनीय वित्तीय जानकारी अस्तित्व के प्रबंध द्वारा आर्थिक स्रोतों के उचित आबंटन और अनुकूलतम उपयोग के लिए निर्धारण और मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। ऐसी जानकारी वर्तमान और भावी निवेशकों, देनदारों और अन्य उपयोक्ताओं को अस्तित्व में उनके निवेशों और हितों के संबंध में तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार भारत सरकार ने भारत में विदेशी निधियों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि खुदरा, रक्षा आदि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमाओं में वृद्धि करके एफडीआई संबंधी नीति को उदार बनाया है, सीमा पार के निवेशकों को भारतीय निगमों के वित्तीय कार्यपालन का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। सीमा पार के निवेशकों को, ऐसे उद्यमों के संबंध में, जिनमें वे निवेश करने जा रहे हैं, वैश्विक रूप से तुलनात्मक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः, वित्तीय रिपोर्टिंग में समतुल्यता को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए वैश्विक रूप से स्वीकृत और उच्च गुणवत्ता प्राप्त लेखांकन मानकों का एकल सेट ही समय की आवश्यकता है। आईएएसबी द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अधिकाधिक रूप से वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है। अधिकांश देशों ने विभिन्न अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या तो आईएफआरएस को अपना लिया है या उन्हें अपनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक मुख्यतः आईएएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं,

फिर भी कतिपय मामलों में देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अलावा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, लेखांकन मानकों में आईएस/आईएफआरएस से विचलन किया गया है।

हाल ही के वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व में जोर पकड़ा है। यूएसए के वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएएसबी) और आईएसबी ने यूएस जीएपी और आईएफआरएस के अभिसरण के लिए कार्य किया है। यूएसए के प्रतिभूति और विनियम आयोग (एसईसीए) ने यह विनिश्चय किया है कि यूएस जीएपी और आईएफआरएस के बीच किसी समाधानप्रद विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना आईएफआरएस से संगत वित्तीय विवरण फाइल करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस परिदृश्य में, भारत जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वर्ष 2007 में कंपनियों के कतिपय वर्ग के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से आईएफआरएस से अभिसरण का विनिश्चय किया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह अभिसरण, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्व को विदेशों से निम्न लागत की पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भी, विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ प्रदान करेगा।

आईसीएआई ने आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने फरवरी, 2011 के दौरान पैंतीस भारतीय लेखांकन मानकों को अपनी वेबसाइट पर रखा था। तथापि, कर संबंधी विवक्षाओं और अन्य अपरिहार्य कारणों से इन भारतीय लेखांकन मानकों को अभी सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।

वर्ष 2013 में, भारत सरकार ने भारतीय निगमों हेतु विनियमों के अद्यतन और आधुनिक सैट से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लंबे समय से चर्चित और चिर प्रतिष्ठित कंपनी अधिनियम, 2013 को अंतिम रूप देकर जारी किया था, जिसने अपने पूर्ववर्ती कानून कंपनी अधिनियम, 1956 को अधिकांशतः किया था जो पिछले पांच दशकों से लागू था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 यह विहित करती है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से और उसके द्वारा समीक्षा के पश्चात् की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा सिफारिश किए गए लेखांकन मानकों को विहित कर सकेगी। उक्त धारा स्वयं में संस्थान द्वारा भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन मानकों को तैयार करने में किए गए कार्यों के प्रति भारत सरकार के भरोसे और विश्वास को दर्शित करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से आईएफआरएस अभिसरित इंड एस कारबार परिस्थितियों के लिए रास्ता साफ हुआ था क्योंकि इसमें ऐसे अनेक उपबंधों को सम्मिलित किया गया था, जो आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं से संगत हैं।

भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने, जुलाई, 2014 के अपने बजट भाषण में यह कथन किया था कि –

“वर्तमान भारतीय लेखांकन मानकों का अंतराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण करना अत्यंत आवश्यक है। मैं, भारतीय कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्तीय वर्ष 2016-17 से आज्ञापक आधार पर नए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को अपनाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। अंतराष्ट्रीय सहमति के आधार पर, विनियामक पृथक् रूप से बैंकों, बीमा कंपनियों आदि के लिए इंड एस के कार्यान्वयन की तारीख अधिसूचित करेगा। कर की संगणना के लिए मानकों को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा।”

उपरोक्त उद्घोषणा के अनुसरण में आईसीएआई द्वारा आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभिसरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, आईसीएआई आईएफआरएस के साथ अभिसरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आईएफआरएस के साथ अभिसरित बने रहने के लिए, एमसीए की वेबसाइट पर वर्ष 2011 में इंड एस को रखे जाने के पश्चात् आईएसबी द्वारा जारी नए आईएफआरएस के आधार पर, इंड एस को संशोधनों के आधार पर विरचित/पुनरीक्षित किया गया था। ये नए/पुनरीक्षित इंड एस, जिन्हें आईसीएआई द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय लेखांकन मानक संबंधी सलाहकार समिति (एनएसीएस) को प्रस्तुत किए गए थे, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन किए जाने तक पुनः गठित किया गया है। एनएसीएस द्वारा विचार किए जाने और सिफारिश किए जाने के पश्चात् इंड एस को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के रूप में तारीख 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया था, विद्यमान लेखांकन मानकों (एस) को इंड एस के समीप लाने के लिए अद्यतन करने का विनिश्चय किया गया है। ये एस ऐसे अस्तित्वों को लागू होंगे, जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) लागू नहीं होते हैं, अर्थात् प्रमुख रूप से ऐसे असूचीबद्ध अस्तित्वों को, जिनकी कुल आवर्त 250 करोड़ रुपए से कम है। लेखांकन मानकों के द्वितीय सेट के लिए एक चरणबद्ध रीति में विद्यमान लेखांकन मानकों के उन्नयन संबंधी दृष्टिकोण को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। विद्यमान लेखांकन मानकों को भी पुनरीक्षित किया जा रहा है।

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी), भारतीय उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय रूप से दर्ज कराने और एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड और अन्य निकायों जैसे कि एशिया ऑशिनियन स्टैंडर्ड्स सैटर्स ग्रुप (एओएसएसजी), इंटरनेशनल फोरम ऑफ एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सैटर्स (आईएफएएसएस) और एमर्जिंग इकोनोमिज ग्रुप (ईईजी) द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों में भी भाग ले रहा है और सहयोग कर रहा है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड के विभिन्न क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को तैयार करना/का पुनरीक्षण करना

वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड ने आईएएस/आईएफआरएस में किए गए संशोधनों के तत्समान भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) में निम्नलिखित संशोधनों को अंतिम रूप प्रदान किया है और नए आईएफआरएस के तत्समान निम्नलिखित नए इंड एएस को तैयार किया है :

- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 101), पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों का अपनाया जाना
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 109), वित्तीय लिखतें
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 115), ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व
- भारतीय लेखांकन मानकों इंड एएस में आगे और संशोधन : कारव आउट्स/इन्स पर विचार
- भारतीय लेखांकन मानकों इंड एएस में संशोधन : कारव आउट्स/इन्स पर विचार
- कृषि: बियरर पादप (इंड एएस 16 का संशोधन) (बियरर पादप : आईएएस 16 का संशोधन के तत्समान)
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 41 कृषि (आईएएस 41 के तत्समान)
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 114, (विनियामक आस्थगन लेखा आईएफआरएस 14 के तत्समान)
- इंड एएस 16 और एएस 38 का संशोधन (अवमूल्यन और अपाकरण की स्वीकार्य पद्धतियों का स्पष्टीकरण) (आईएएस 16 और आईएएस 38 के संशोधनों के तत्समान)
- सतही खान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत (इंड एएस 16 का संशोधन) (आईएफआरएससी 20 के तत्समान)
- संयुक्त प्रचालनों में हित के अर्जनों के लिए लेखांकन (भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 111, संयुक्त ठहराव) (आईएफआरएस 11 के संशोधनों के तत्समान)
- भारतीय लेखांकन मानकों का संशोधन (आईएफआरएससी 2011-13 चक्र में वार्षिक सुधारों के तत्समान)
- भारतीय लेखांकन मानकों का संशोधन (आईएफआरएससी 2010-12 चक्र में वार्षिक सुधारों के तत्समान)
- परिभाषित फायदे योजना : कर्मचारी का अभिदाय (इंड एएस 19 का संशोधन)
- व्युत्पन्नों का नवीनीकरण और हेज लेखांकन का जारी रखा जाना (इंड एएस 39 का संशोधन)
- भारतीय लेखांकन मानकों का संशोधन
- परिशिष्ट बी -1, उद्ग्रहण, इंड एएस 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां
- गैर वित्तीय आस्तियों के लिए वसूलनीय रकमों का प्रकटन (इंड एएस 36 का)
- निवेश अस्तित्व (इंड एएस 110, इंड एएस 112 और इंड एएस 27 का संशोधन)
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 107, वित्तीय लिखतें : प्रकटन का संशोधन
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 32, वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतीकरण का संशोधन

विद्यमान लेखांकन मानकों (एएस) का पुनरीक्षण

वर्ष के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड ने पुनरीक्षित एएस 10, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया है।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में भागीदारी

बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी के साथ परस्पर क्रियाएं करता है जैसे कि :

- विश्व मानक निर्धारकों (डब्ल्यूएसएस) और आईएसबी तथा प्रादेशिक मानक निर्धारकों और आईएसबी की बैठकों में सक्रिय भागीदारी। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने लंदन में 29-30 सितंबर, 2014 के दौरान आयोजित विश्व मानक निर्धारकों की बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में विभिन्न आईएसबी परियोजनाओं को अद्यतन करने के अलावा, विभिन्न तकनीकी मुद्दों जैसे कि अवधारणात्मक ढांचे, प्रकटन संबंधी पहल, राजस्व, दर विनियमित क्रियाकलापों आदि पर विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि ने आईएफआरएस 15, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व, दर विनियमित क्रियाकलापों पर परामर्श पत्र आदि जैसे विभिन्न तकनीकी मुद्दों के संबंध में विभिन्न प्रश्न उठाए थे।
- बोर्ड आईएसबी द्वारा जारी विभिन्न उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों को परिचालित करता है और अपनी वेबसाइट पर भी रखता है और उनके संबंध में विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित करता है।
- बोर्ड नियमित रूप से आईएसबी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करता है, जैसे कि :
 - (i) पट्टे
 - (ii) बीमा संविदाएं
 - (iii) दर विनियमित क्रियाकलाप
 - (iv) अवधारणात्मक ढांचे
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने आईएसबी के उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समरूप (ईईजी) की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया था :

(क) 28-29 मई, 2014 के दौरान मास्को, रूस में आयोजित ईईजी की सातवीं बैठक। इस बैठक में, विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे कि लेखांकन की साम्यापूर्ण पद्धति, अवधारणात्मक ढांचागत आदि जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था। आईसीएआई ने, आईएस 32 के अधीन दिए गए लेखांकन उपचार के संबंध में भारत की चिंताओं को प्रमुख रूप से उपदर्शित करते हुए विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्रों (एफसीसीबी) के संबंध में एक लघु पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था।

(ख) 11-12 दिसंबर, 2014 के दौरान जर्काता, इंडोनेशिया में ईईजी की आठवीं बैठक। इस बैठक में, आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा "विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्रों (एफसीसीबी) के लिए लेखांकन" विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया था। इस बैठक में विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे कि निष्कर्षणीय क्रियाकलापों के लिए लेखांकन, गैर-वित्तीय आस्तियां आदि के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) 25-26 मई, 2015 के दौरान मैक्सिको सिटी में ईईजी 9 बैठक। इस बैठक में, अन्य मुद्दों के साथ-साथ 'आईएफआरएस में वर्तमान मूल्य मापमान' विषय पर विचार-विमर्श किया गया था।
- 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2014 को लंदन, यूके में लेखांकन मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएसएस) की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा 'आईएफआरआईसी 12 के अधीन संनिर्माण चरण के दौरान आय की मान्यता' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया था। इस बैठक में विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे कि लेखांकन की साम्या पद्धति, कर्मचारियों के फायदे, नकल प्रवाह विवरण आदि पर विचार-विमर्श किया गया था।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने, 27 मई, 2014 को मास्को, रूस में 'भारत में लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली' विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय आईएफआरएस संगोष्ठी में भी प्रस्तुतीकरण किया था।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 23-24 जून, 2014 के दौरान लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित आईएफआरएस के सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में, विभिन्न विषयों जैसे कि अवधारणात्मक ढांचा, पट्टे, साम्या पद्धति, वित्तीय लिखतें आदि पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श किया गया था।
- 26-27 नवंबर, 2014 के दौरान हांगकांग में एशियन ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) की छठी बैठक का आयोजन किया गया था। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा 'भारत में आईएफआरएस के साथ अभिसरण – अद्यतन जानकारी' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया था। इस बैठक में विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे कि उत्सर्जन अधिकार, अवधारणात्मक ढांचा, दर विनियमित क्रियाकलाप आदि पर चर्चा की गई थी।
- 28 सितंबर, 2014 को लंदन में एओएसएसजी के सदस्यों की एक अंतरिम बैठक का आयोजन किया गया था। भारत से, आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे वित्तीय लिखतें, आईएफआरएस 15, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व आदि पर चर्चा की गई थी।

- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 28 अप्रैल, 2014 और 23 जुलाई, 2014 को आयोजित एओएसएसजी के सीएसी की टेलीकांफ्रेंसिंग में भाग लिया था। इस टेलीकांफ्रेंसिंग में, एओएसएसजी की नीतिगत योजना के प्रारूप के साथ विभिन्न आगामी बैठकों और आयोजनों के कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा की गई थी।

आईएसबी को निम्नलिखित आईएसबी उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों पर टीका-टिप्पणियां भेजी गई थी :

- (क) आईएसआरएस 15 के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आईएफआरएस की प्रभावी तारीख संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (ख) आनुषंगिक संयुक्त उद्यमों और सहबद्धों में उचित मूल्य पर उत्कथित निवेश के मापमान संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (ग) प्रकटन पहल : आईएसएस 7 में प्रस्तावित संशोधन संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (घ) शेयर आधारित संदाय संव्यवहारों के वर्गीकरण और मापमान संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (ङ) दायित्वों के वर्गीकरण, आईएसएस 1 में प्रस्तावित संशोधन उद्भासन प्रारूप
- (च) परिचर्चा पत्र : दर विनियमन के वित्तीय प्रभावों की रिपोर्टिंग
- (छ) अवसूलीकृत हानियों के लिए आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता (आईएसएस 12 में प्रस्तावित संशोधन) संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (ज) निवेश अस्तित्वों : समेकित अपवाद को लागू करने (आईएफआरएस 10 और आईएसएस 28 में प्रस्तावित संशोधनों) संबंधी उद्भासन प्रारूप
- (झ) प्रकटन पहल का प्रारूप (आईएसएस 1 में प्रस्तावित संशोधन)

विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है।

आईसीएआई ने एमसीए के अनुरोध पर, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को लागू करने के संबंध में एक पुनरीक्षित कार्य योजना की भी सरकार को सिफारिश की थी। एएसबी ने विभिन्न विनियामकों जैसे कि आरबीआई, सेबी, सी एंड एजी के पदधारियों से भी इंड एस को लागू करने हेतु पुनरीक्षित कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें की थीं।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न लेखांकन मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

- एएसबी द्वारा 15 जनवरी, 2014 को मुंबई में इंड एस के कार्यान्वयन के संबंध में एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ऐसे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों, जो कार्यान्वयन के दौरान सामने आ सकते हैं, की पहचान करने के लिए विभिन्न हितबद्ध पणधारियों को आमंत्रित किया गया था, जिससे कि बोर्ड इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और/या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करा सके। लगभग 20 कंपनियों से 40 से अधिक सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था।
- 7 फरवरी, 2015 को मुंबई में आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के संबंध में एक एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगे आने वाले इंड एस के बारे में जागरूकता का सृजन करने के विचार से और साथ ही देश में इंड एस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए किन्हीं कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की पहचान करने हेतु विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। लगभग 40 कंपनियों से 63 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए इंड एस की विशिष्टताओं को सम्मिलित किया गया था।

अन्य परियोजनाएं

विचाराधीन अन्य दस्तावेज

- ग्राहियों द्वारा सेवा अनुदान ठहरावों हेतु लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण
- विद्यमान लेखांकन मानकों को इंड एस के यथासंभव समीप लाने के लिए उनका उन्नयन
- भारतीय लेखांकन मानकों को अद्यतन बनाना
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 को लागू करने से उदभूत होने वाले मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण
- गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 का अनुपालन करने वाले इंड एस तैयार करना
- इंड एस के अनुकूल निदर्शी वित्तीय विवरणों को तैयार करना

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति

आईसीएआई, जो देश में एक प्रमुख लेखांकन निकाय है, सरकार द्वारा जारी किए गए लेखांकन सुधारों का एक अभिन्न अंग है, विशेषकर स्थानीय निकायों के स्तर पर। इस प्रयोजन के लिए, आईसीएआई ने वर्ष 2005 में प्रमुख रूप से स्थानीय निकायों हेतु लेखांकन मानक (एएसएलबी) तैयार करने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक समिति (सीएसएलबी) का गठन किया था। इसके प्रारंभ से ही, समिति ने 'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी प्रकथन' और साथ ही 11 एएसएलबी जारी किए हैं, जिनमें से 4 एएसएलबी को चालू परिषद् वर्ष के दौरान जारी किया गया है। ये एएसएलबी सिफारिशात्मक प्रकृति के हैं और वे संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीखों से भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए आज्ञापक बनेंगे। अनेक अन्य एएसएलबी को भी अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

समिति के अन्य प्रकाशनों में "भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन संबंधी सुधार और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका" विषय पर प्रास्थिति पत्र और "स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्ग्वन आधार पर लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी" नामक पुस्तिका के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ सम्मिलित हैं।

एएसएलबी तैयार करने के अलावा सीएसएलबी स्थानीय निकायों और विभिन्न पणधारियों जैसे अंत उपयोक्ता और नागरिकों आदि के बीच सरकार और स्थानीय निकायों में लेखांकन संबंधी सुधार की प्रक्रिया के फायदों के बारे में जागरूकता का सृजन करने में भी संलिप्त रही है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

अध्यक्ष, आईसीएआई, शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) के, उसके प्रारंभ से ही, सदस्य रहे हैं। तकनीकी निदेशक, आईसीएआई, जीएसएबी में अध्यक्ष, आईसीएआई के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अध्यक्ष, आईसीएआई, तकनीकी निदेशक, आईसीएआई के साथ जीएसएबी की बैठकों में भाग लेते हैं और इस प्रकार बोर्ड के तकनीकी क्रियाकलापों के प्रति सहयोग करते हैं।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक समिति के इस अवधि (1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015) के दौरान महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

जारी किए गए प्रकाशन :

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) का सार संग्रह

जारी किए गए एएसएलबी

- एएसएलबी 3, 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और वृद्धियां'
- एएसएलबी 17, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'
- एएसएलबी 19, 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'
- एएसएलबी 31, 'अमूर्त आस्तियां'।

5.3 संपरीक्षा समिति

आईसीएआई की संपरीक्षा समिति का गठन परिषद् द्वारा शासित है। परिषद् ने वर्ष 2001 में, एक अस्थाई समिति के रूप में संपरीक्षा समिति का गठन किया था। संपरीक्षा समिति की आईसीएआई रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटन का पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित है। आईसीएआई के वार्षिक लेखाओं को परिषद् द्वारा संपरीक्षा समिति की सिफारिश पर अंगीकृत किया जाता है। आईसीएआई की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् में भी एक-एक प्रादेशिक संपरीक्षा समिति है और इस प्रकार कुल 5 प्रादेशिक संपरीक्षा समितियां भी हैं। संपरीक्षा समिति, आईसीएआई के विभिन्न क्षेत्रों में, संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है। समिति सभी क्षेत्रों/विभिन्न इकाईयों की आंतरिक और कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है और संपरीक्षकों और साथ ही ऐसे विभागों जिनकी संपरीक्षा की गई है, के साथ नियमित परस्पर क्रियाएं करती हैं ताकि आईसीएआई के भीतर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

5.4 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

संपरीक्षा जवाबदेही को सुदृढ़ करके तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास और निष्ठा पुनःस्थापित करके लोकहित की सेवा और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपरीक्षा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की किस्म, संख्या और मूल्य में वृद्धि करने में सहायता करती है। तथापि, हाल ही के वर्षों में, कारबार परिस्थितियों और कारबार मॉडलों में बढ़ती जटिलता तथा उनके भौगोलिक प्रसार के कारण संपरीक्षा वृत्ति से जनता की आशाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आईसीएआई सक्रिय रूप से इन आशाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की अत्यावश्यकता को मान्यता प्रदान करता है। आईसीएआई अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले संपरीक्षा संबंधी मानकों को तैयार करता है, उनका पुनर्विलोकन करता है, अन्य आश्वासनों, उनकी गुणवत्ता के नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं के संबंध में उपबंध करता है। ये मानक न केवल संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हैं, अपितु वे ऐसे मानदंडों का भी उपबंध करते हैं, जिनके आधार पर संपरीक्षकों के कार्यपालन का मापमान किया जा सकेगा। बोर्ड, उद्योग विनिर्दिष्ट संपरीक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में संपरीक्षकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रमुख उद्देश्य से संपरीक्षा संबंधी सामान्य और साथ ही उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करता है। बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली एक कड़ी सम्यक प्रक्रिया के पश्चात्, इन दस्तावेजों को आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के प्राधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, प्रैक्टिस मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों को भी तैयार करता है। संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड मानकों के संबंध में एक कार्यान्वयन गाइड भी निकाल रहा है। आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक व्यापक पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक

- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, “ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन” ।
- संपरीक्षा संबंधी 37 मानक
- पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी 2 मानक ।
- आश्वासन नियोजनों संबंधी 2 मानक ।
- संबंधित सेवाओं संबंधी 2 मानक ।

संपरीक्षा संबंधी विवरण

- संपरीक्षा संबंधी 2 मानक

संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण

- संपरीक्षा संबंधी 30 मार्गदर्शक टिप्पण

प्रकाशन

उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक टिप्पण

- बैंकों की संपरीक्षा
- स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
- साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा

कार्यान्वयन गाइड

- रिपोर्टिंग मानकों (एसए 700, एसए 705 और एसए 706) संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- वित्तीय विवरणों की जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाइड (पुनरीक्षित 2012 संस्करण)
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 530, संपरीक्षा के नमूने लेना, संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- किसी संपरीक्षा की योजना तैयार करने और उसे संपन्न करने में सामग्रियों संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- एसए 230, संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण से संबंधित कार्यान्वयन गाइड
- एसए 501, संपरीक्षा साक्ष्य चयनित मदों के लिए विनिर्दिष्ट विचार से संबंधित कार्यान्वयन गाइड

- एसए 570, गोइंग कंसर्न से संबंधित कार्यान्वयन गाइड
- कार्यान्वयन गाइडों का सारसंग्रह (1 जुलाई, 2013 को यथा विद्यमान)

तकनीकी गाइड/गाइडें

- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- ऑटोमोबाइल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- टेलीकाम उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड - राजस्व, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतें
- ईकॉमर्स संबंधी तकनीकी गाइड - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए विचारार्थ विषय
- अंशभाजित सेवा केन्द्र संरचना में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- उद्योग विनिर्दिष्ट संपरीक्षा गाइडों का सार संग्रह (1 सितंबर, 2013 को यथाविद्यमान)
- लघु आस्तित्वों की संपरीक्षा संबंधी प्रैक्टिशनर गाइड
- जटिल वित्तीय लिखतों की संपरीक्षा संबंधी गाइड
- [सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसरण में] प्रारूप वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी गाइड

अध्ययन

- धनशोधन निवारण संबंधी एक अध्ययन : एक लेखाकार का परिप्रेक्ष्य
- बेजल 2 और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण संबंधी एक अध्ययन

अन्य प्रकाशन

- संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2014 संस्करण
- संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- संपरीक्षा क्या है - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा को समझना
- आईएएसबी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अभिसरण : प्रास्थिति पत्र और कार्य योजना

वर्ष 2014-15

- वर्ष के दौरान बोर्ड की छह बैठकें हुई थीं।
- बोर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले थे, उदाहरणार्थ, संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2014 संस्करण, संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री, 2014 संस्करण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (यह मार्गदर्शक टिप्पण वर्तमान में पुनरीक्षणाधीन है), बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण 2015 संस्करण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन कपट संबंधी रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शक टिप्पण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(च) और (छ) के अधीन रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शक टिप्पण
- बोर्ड ने देश भर में संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा पहलुओं के संबंध में अनेक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया था। अलवर, सिलीगुड़ी, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- बोर्ड ने पुनर्विलोकन नियोजनों से संबंधित पुनरीक्षण मानक (एसआरई) 2400, 'ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियोजन' जारी किया।
- बोर्ड ने संबद्ध सेवाओं से संबंधित पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक (एसआरएस) 4410, 'संग्रहण संबंधी नियोजन' जारी किया।
- बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निदर्शी प्रारूप जारी किए थे

- बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संपरीक्षा नियोजन पत्रों के निदर्शी प्रारूप जारी किए थे
- बोर्ड ने सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित उद्घोषणाएं जारी की :
 - सीएआरओ 2003 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अतिरिक्त रिपोर्टिंग।
 - 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ करते हुए लेखांकन वर्षों के लिए किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध संपरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण।
 - कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सीएआरओ 2015) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी मार्गदर्शन और किसी कंपनी के संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारूप में पारिणामिक संशोधन।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) और संबंधित नियमों के उपबंधों का लागू होना।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) और संबंधित नियमों के उपबंधों का 31 मार्च, 2014 या उससे पूर्व लागू होना।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) का 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होना।
 - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षिती के संबंध में आस्थगित कर दायित्व संबंधी आरबीआई के परिपत्र के संबंध में संपरीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग की रीति।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 का वित्तीय वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संपरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में लागू होना।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने मई, 2014 और मई, 2015 के दौरान न्यूयार्क में हुई वार्षिक आईएएसबी – एनएसएस बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था।
- बोर्ड ने शहरी, सहकारी बैंकों की संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारूप प्ररूप को आरबीआई को प्रस्तुत किया था।
- बोर्ड ने एएएसबी से तकनीकी अंतःनिवेशों के रूप में प्रस्तावित वार्षिक सूचना ज्ञापन (एआईएम) में सम्मिलित किए जाने के लिए वित्तीय जानकारी से संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारूप प्ररूप को सेबी को प्रस्तुत किया था।
- बोर्ड ने अप्रत्यक्ष कर समिति को सेवाकर विधि के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट का प्रारूप पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे वह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगी।
- बोर्ड ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने वाले मुद्दों की सूची।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन कपटों की रिपोर्टिंग के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने वाले मुद्दों की सूची और सुझाव दी गई सारवान अवसीमाएं।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमों में विहित प्ररूपों से संबंधित मुद्दे।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में जारी किए जाने वाले आदेश के संबंध में आईसीएआई के विचार।
 - समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्बलित विभिन्न मुद्दे।

ऐसी परियोजनाएं, जिन पर कार्य चल रहा है

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने, वर्ष के दौरान अनेक अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की थीं।

अन्य पहलु और विकास

विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया

बोर्ड, नियमित रूप से संपरीक्षा मानकों, संपरीक्षा रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संपरीक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर

विचार करने के लिए विनियामकों और सरकारी संस्थाओं/मंत्रालयों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) आदि से परस्पर क्रियाएं करता है।

आईएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना

आईसीएआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है। संस्थान के अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स संघ (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य होने के कारण बोर्ड, अपने अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की राष्ट्रीय मानक निर्धारक समिति के संपर्क में रहा था और उसने समय-समय पर उसे महत्वपूर्ण अंतःनिवेश उपलब्ध कराए थे। अध्यक्ष, एएसबी ने मई, 2014 और मई, 2015 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित आईएएसबीएनएसएस की वार्षिक बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। मई, 2014 में हुई बैठक में, अध्यक्ष, एएसबी ने, उक्त बैठक की कार्यसूची के भागरूप में कार्यसूची मद "वित्तीय संस्थाओं की संपरीक्षा" के संदर्भ में "बैंकों की संपरीक्षा" विषय पर एक प्रस्तुतिकरण किया था। आईसीएआई के प्रतिनिधि ने कार्यसूची की अन्य मदों के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न उद्भासन प्रारूपों के संबंध में भी अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

जागरूकता सृजित करना और सक्षमता का निर्माण

वर्ष 2014-15 के दौरान सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता का सृजन करना बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था। इस प्रक्रिया में, सदस्यों के सामने आने वाले संपरीक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर क्रिया को आसान बनाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, आदि का आयोजन किया था।

भावी रणनीति और कार्यक्रम

बोर्ड अब अपना ध्यान सदस्यों के बीच लेखांकन मानकों के संबंध में जागरूकता सृजित करने पर केन्द्रित करेगा। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड दोहरी रणनीति अपनाएगा। वह संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और सदस्यों द्वारा उन्हें बेहतर रूप से समझने और मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए कार्यान्वयन गाइडें जारी करेगा। बोर्ड, उद्योग सेक्टरों से विनिर्दिष्ट समकालीन मुद्दों पर सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए संपरीक्षा से संबंधित संपरीक्षा संबंधी साहित्य जैसे कि मार्गदर्शक टिप्पण, तकनीकी गाइडें, अध्ययन, अन्य गाइडें, आदि भी तैयार करेगा।

5.5 बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति

- बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने श्री हेमंत जी. कन्ट्रेक्टर, अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और पीएफआरडीए के अन्य सदस्यों/वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की थी तथा अन्य बातों के साथ, विभिन्न पेंशन स्कीमों के प्रबंध में अंतर्वर्तित विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए एक सुचारू मानीटरी और अनुपालन प्रबंध प्रणाली को स्थापित करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया था, यह प्रणाली, अन्य बातों के साथ, मध्यवर्तियों के क्रियाकलापों की संपरीक्षा और समय-समय पर पीएफआरडीए/एनपीएस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग करेगी।
- समिति के अध्यक्ष ने श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) से, बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचार करने के लिए बैठक की थी।
- पीएफआरडीए के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर विचार करते हुए, समिति के अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्य को पीएफआरडीए द्वारा गठित क्रमशः पेंशन सलाहकार समिति और उप समूह के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- समिति के अध्यक्ष ने सी.ए. एस. जयसिंहन, संयुक्त निदेशक (निवेश), आईआरडीआई के साथ परस्पर हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की थी।
- डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या सामग्री को पुनरीक्षित करने के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने हेतु बीमा क्षेत्र के चुने गए विशेषज्ञों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- समिति ने सदस्यों के लिए 30-31 दिसंबर, 2014 के दौरान बिरला आडोटोरियम, जयपुर में आईसीएआई की लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से "चुनौतियों का सामना करना – हमारी भूमिका को पुनः परिभाषित करना" विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की जयपुर शाखा ने किया था। इस सम्मेलन में देश भर से 3700 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।

- समिति ने 26 जून, 2015 को कोलकाता में “बीमा और पेंशन क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाना” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी की मेजबानी आईसीएआई की पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम को अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा डा. बी.एस. भंडारी, सदस्य, पीएफआरडीए, श्री ए. रमन्ना राव, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण), आईआरडीएआई, श्री एम. वसंत कृष्णा, निदेशक और महाप्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्री सोहन लाल कदेल, अध्यक्ष, इश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संबोधित किया गया था।
- यह समिति होटल ताज रेजिडेंट, मुंबई में 8 मई, 2014 को आयोजित किए गए भारतीय मर्चेंट्स चेम्बर के “इंडियन बैंकिंग एट द क्रासरोड्स – चैलेंज आफ रिस्क मैनेजमेंट फ्राम ग्लोबलाइजेशन टू फाइनेंशियल इंकलूजन” विषय पर सम्मेलन में सम्मेलन भागीदार थी।
- 2 मई, 2015 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन बैंक ऋणों और अग्रिमों तथा विनियामक निर्बंधनों विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित गोष्ठी संबंधी एक वेबकास्ट।
- गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संपरीक्षा के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और सदस्यों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने के लिए 29 जून, 2015 को “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और नेशनल पेंशन प्रणाली की संपरीक्षा – नए युग की ओर प्रस्थान” विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन।
- साधारण जनता में बीमा के प्रति जागरूकता का प्रसार करने में आईआरडीएआई की पहलों का समर्थन करने के लिए समिति आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से बीमा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवधि के दौरान आयोजित किए गए बीमा जागरूकता कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्रम सं.	प्रादेशिक परिषद्/शाखा का नाम	तारीख और स्थान
1.	आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की धुले शाखा	16 अप्रैल, 2014 को धुले में
2.	आईसीएआई की एसआईआरसी की सलेम शाखा	19 अप्रैल, 2014 को सलेम में
3.	आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलिगुडी शाखा	10 मई, 2014 को सिलिगुडी में
4.	आईसीएआई की सीआईआरसी की बीकानेर शाखा	25 जून, 2014 को बीकानेर में
5.	आईसीएआई की एसआईआरसी	16 अक्टूबर, 2014 को चेन्नई में
6.	आईसीएआई की ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा	20 जून, 2015 को गुवाहाटी में

- समिति ने “इश्योरेंस सेक्टर – एंकरिंग इकनोमिक ग्रोथ” नामक एक लेख आईआरडीए को प्रस्तुत किया है ताकि उसे “बीमा जागरूकता दिवस” के अवसर पर निकाले जाने वाली “विजन 2020-25 फार इश्योरेंस सेक्टर” नामक पुस्तिका में सम्मिलित किया जा सके। यह लेख उद्योग के वरिष्ठ पदधारियों/विशेषज्ञों के विचारों को संकलित करता है।
- समिति सभी संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर समिति के मुख पृष्ठ पर बैंककारी, बीमा और पेंशन से संबंधित नई अद्यतन जानकारी को दैनिक रूप से अपलोड करती है।
- समिति ने, बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्र के अपने विभिन्न पणधारियों के बीच समिति के कार्यकरण के संबंध में जानकारी के प्रसार हेतु अपनी पीआर किट भी निकाली है। इस पीआर किट को भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन निधि प्रबंधकों, परस्पर निधियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और वित्तीय क्षेत्र के अन्य पणधारियों को भेजा गया था।
- बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम**
 - समिति ने डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सदस्यों के अनुकूलन कार्यक्रम के पांच बैचों का आयोजन किया था, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	तारीख	स्थान
1.	28 अप्रैल, – 3 मई, 2014	नोएडा
2.	12 – 17 मई, 2014	मुंबई
3.	17 – 22 नवंबर, 2014	कोलकाता
4.	11 – 16 मई, 2015	मुंबई

5.	25 – 29 मई, 2015	कोलकाता
----	------------------	---------

- डीआईआरएम पाठ्यक्रम करने वाले सदस्यों के फायदे के लिए डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा, जिनका आयोजन नवंबर, 2014 में किया गया था, के लिए सुझाए गए उत्तरों को तैयार किया गया था और आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।
- बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरणों की कुल संख्या 10 जुलाई, 2015 को 4690 तक पहुंच गई है।

5.6 व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

पर्यावलोकन

सीए फर्मों और व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति को, जो आईसीएआई की एक अस्थाई समिति है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन गठित किया गया है। इस समिति को सीए फर्मों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों की अवधारणा को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा साथ ही सीए फर्मों के समेकन हेतु व्यापक मार्गदर्शन तैयार करने के लिए सीए फर्मों में सक्षमता निर्माण तथा समेकन को सुकर बनाने हेतु स्थापित किया गया था। इसी प्रकार समिति का उद्देश्य लघु और मध्यम व्यवसायियों को सशक्त बनाना भी है जिससे कि उनके व्यवसाय को दक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक रीति में आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। समिति अपना ध्यान उद्योग में लगे सदस्यों के बीच सॉफ्ट कौशलों के विकास को सुकर बनाकर उन्हें समर्थ बनाने पर भी केंद्रित करती है।

पहले

क) वित्तपोषण

आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष ऋण स्कीम और आईसीएआई के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण स्कीम की व्यवस्था

समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष ऋण स्कीम और आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड के साथ मिलकर छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक ऋण स्कीम का प्रबंध करने संबंधी महत्वपूर्ण पहल की है। महिला सदस्य और छात्र पूर्वोक्त स्कीम में भारतीय महिला बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित विद्यमान ब्याज दर में से 1 प्रतिशत की छूट का फायदा प्राप्त करेंगे।

विशेष ऋण स्कीम 'कार्प सीए' स्कीम

समिति ने कारपोरेशन बैंक के माध्यम से एक विशेष रूप से तैयार की गई ऋण स्कीम के रूप में व्यवसायरत/फर्मों में नियोजित अपने सभी सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंध करने हेतु एक प्रमुख पहल की है। इस स्कीम के माध्यम से पात्र चार्टर्ड एकाउंटेंट अपने कार्यालयों को स्थापित करने के लिए वित्तपोषण का लाभ उठा सकते हैं जिसके अंतर्गत फर्नीचर/फिक्सचर/ कार्यालय उपस्कर – कंप्यूटर और अन्य सहायिकियों की लागत भी है।

ख) व्यवसायियों की क्षमता का संवर्धन

अनुपालन

विशेष कीमत पर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर

समिति ने अपने सदस्यों के लिए बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को विशेष कीमत पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। आईसीएआई के सदस्यों के लिए इसकी प्रस्तावित कीमत 4500 रुपए+ लागू कर होगी। क्रेता कंपनी ने सभी उन्नयनों पर 50 प्रतिशत छूट का भी प्रस्ताव किया है।

विशेष कीमत पर आईटी आडिटर सॉफ्टवेयर

समिति ने व्यवसायरत सदस्यों और सीए फर्मों के लिए एक विशेष कीमत पर आईटी आडिटर सॉफ्टवेयर, अर्थात् कर संपरीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग के साथ आयकर अनुपालन सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की है। प्रथम निर्धारण वर्ष के लिए आईसीएआई के सदस्यों के लिए इसकी प्रस्तावित कीमत 2100 रुपए+ लागू कर होगी। अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रभार 2100 रुपए धन लागू कर होंगे।

विशेष कीमत पर क्लाउड आधारित सेवाकर, टीडीएस और पीडीएफ साइनर सॉफ्टवेयर

समिति ने व्यवसायरत सदस्यों और सीए फर्मों के लिए प्रथम निर्धारण वर्ष के लिए एक विशेष कीमत पर क्लाउड आधारित सेवाकर, टीडीएस और पीडीएफ साइनर सॉफ्टवेयर, अर्थात् आनलाइन टीडीएस और सेवाकर सॉफ्टवेयर, दस्तावेजों पर अंकीय रूप से हस्ताक्षर करने हेतु पीडीएफ साइनर के साथ, सॉफ्टवेयर की व्यवस्था 2100 रुपए की दर पर की है। अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रभार 2100 रुपए धन लागू कर होंगे।

विशेष कीमत पर भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रबंधक (आईएफआरएम)

समिति ने, वित्तीय रिपोर्टिंग में नवीनतम घटनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु अपने सदस्यों को समर्थ बनाने के प्रयास रूप में आईएफआरएम की व्यवस्था की है, जो कि एक वेब आधारित अनुसंधान और समाधान किट है। यह किट सदस्यों को 3500 रुपए धन कर प्रति उपयोक्ता प्रतिवर्ष की विशेष कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रबंधक की सूचीबद्ध कीमत 9995 रुपए धन कर प्रति उपयोक्ता प्रतिवर्ष है।

आईसीएआई – कर सुइट : एक कर अनुपालन साफ्टवेयर

समिति ने व्यवसायगत सदस्यों और सीए फर्मों को एक टैक्स अनुपालन साफ्टवेयर अर्थात् 'आईसीएआई टैक्स सुइट' उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, यह साफ्टवेयर आयकर, टीडीएस, संपरीक्षा रिपोर्टों, परियोजना रिपोर्ट/सीएमए/प्रारूप प्रबंधक, एआईआर (वार्षिक सूचना विवरणी), सेवाकर और दस्तावेज प्रबंध की सुविधा को सुमिश्रित करता है।

एक्सबीआरएल साफ्टवेयर

समिति ने एक्सबीआरएल संबंधी साफ्टवेयर की व्यवस्था की है, जिसका नाम आईसीएआई – एक्सबीआरएल साफ्टवेयर है और जो सीए फर्मों को एमसीए आज्ञापक एक्सबीआरएल फाइलिंग को उपलब्ध कराएगा। यह एक्सबीआरएल साफ्टवेयर, एमसीए की आज्ञा के अनुसार कंपनी की वित्तीय सूचना को एक्सबीआरएल प्रारूप में परिवर्तित करने का समाधान उपलब्ध कराता है।

मुकदमेबाजी

प्रत्यक्ष करों के लिए विशेष कीमत पर सीटीआर पुस्तकालय

प्रत्यक्ष कर के मामले में होने वाली नवीनतम घटनाओं से सदस्यों को अवगत कराने में समर्थ बनाने के वर्तमान प्रयास के भागरूप में समिति ने यह व्यवस्था की है कि कर मामलों के सीटीआर पुस्तकालय को एकल डीवीडी में उपलब्ध कराया जाए। यह डीवीडी सभी लागू करों सहित 1500 रुपए (एक वर्ष के लिए विधिमान्य) की विशेष कीमत पर उपलब्ध होगी, जिसके साथ प्रत्यक्ष कर ट्रेकर भी प्राप्त होगा और यह सदस्यों को प्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों का व्यापक भंडार उपलब्ध कराएगी। सीटीआर पुस्तकालय के कर मामलों की एकल डीवीडी का सूचीबद्ध मूल्य 3600 रुपए है।

ग) कार्यालय प्रबंधन

आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष कीमत पर “एंड्रायड समर्थ मोबाइल फोन के लिए क्विक हील टोटल स्क्योरिटी” साफ्टवेयर की व्यवस्था

समिति ने मैसर्स क्विक हील टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लि., पुणे से आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष कीमत पर “एंड्रायड समर्थ मोबाइल फोन के लिए क्विक हील टोटल स्क्योरिटी” साफ्टवेयर की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त साफ्टवेयर की कीमत 250 रुपए धन लागू कर प्रति दो वर्ष है।

घ) सामाजिक सुरक्षा

कार्यालय संरक्षण शील्ड बीमा

समिति के पास सदस्यों के लिए कार्यालय संरक्षण शील्ड बीमा है। यह स्कीम व्यवसाय/फर्मों में लगे सदस्यों के लिए 18 सितंबर, 2013 से प्रभावी है। उपरोक्त स्कीम का फायदा उठाने की बांछा करने वाले सदस्य/सीए फर्म <http://icai.newindia.co.in> पर जाकर उसके लिए ऑनलाइन समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम

समिति ने सदस्यों और छात्रों के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई स्वास्थ्य बीमा स्कीम की व्यवस्था करके एक प्रमुख पहल की है। इस स्वास्थ्य बीमा स्कीम में कुछ विशेष विशिष्टियां सम्मिलित हैं, जैसे कि किसी स्वास्थ्य जांच का न होना, कोई आयु सीमा और प्रवेश करने की सीमा न होना, संचयी बोनस के बदले प्रीमियम में छूट, ऐसे मामलों में जहां सदस्यों ने समाप्त होने वाली पालिसी के प्रति कोई दावा नहीं किया है और वे पालिसी को नवीकृत करा रहे हैं तो बीमा कंपनी को संदाय किए जाने वाले प्रीमियम में 5 प्रतिशत की छूट का प्रदान किया जाना, पूर्व में विद्यमान रोगों के लिए व्यापक बीमा कवरेज आदि। यह स्कीम सदस्यों के लिए 12 मार्च, 2013 से प्रभावी है। इसके व्यौरों हेतु और बीमा पालिसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और पूर्वोक्त बीमा स्कीम के बारे में अन्य औपचारिकताओं तथा व्यौरों का पता लगाने के लिए <http://icai.newindia.co.in> पर संपर्क किया जा सकता है।

सदस्यों और सीए फर्मों के लिए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा

समिति ने व्यवसाय/फर्मों में लगे सदस्यों के लिए बीमा सुरक्षा की व्यवस्था की है। यह सुरक्षा व्यवस्था एक युक्तियुक्त प्रीमियम पर, अर्थात् बाजार दर से 85 प्रतिशत की छूट पर विशेष रूप से तैयार वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा के रूप में है। इसके व्यौरों हेतु और बीमा

पालिसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और पूर्वोक्त बीमा स्कीम के बारे में अन्य औपचारिकताओं तथा ब्यौरों का पता लगाने के लिए <http://icai.newindia.co.in> पर संपर्क किया जा सकता है।

सदस्यों के लिए विशेष प्रीमियम पर मोटर बीमा

प्राइवेट चार पहिया और दुपहिया वाहनों के संबंध में पूर्ववर्ती दावों पर ध्यान न देते हुए स्वयं की क्षति संबंधी प्रीमियम पर 55 प्रतिशत की छूट के साथ एक छूट प्राप्त दर पर सदस्यों को उनके वाहनों हेतु एक विशेष मोटर बीमा स्कीम उपलब्ध कराई गई है। इस मोटर पालिसी के ऑनलाइन क्रय हेतु आईसीएआई के सदस्यों को सुविधा प्रदान की गई है और आईसीएआई के सदस्य निम्नलिखित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन रूप से इन पालिसियों को प्राप्त कर सकते हैं :

<http://www.orientalinsurance.org.in/BuyNewWeb/faces/AvailablePolicies.jsp>

सदस्यों के लिए निजी दुर्घटना बीमा

समिति ने आरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली से सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार निजी दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करके एक प्रमुख पहल की है।

सदस्यों के लिए गृह बीमा

समिति ने आरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली से सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार गृह बीमा की व्यवस्था करके एक प्रमुख पहल की है।

ऊ) ज्ञान का आदान-प्रदान और उसमें वृद्धि

आईसीएआई कनेक्ट – आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक सेल्फ सर्विस पोर्टल

समिति ने सदस्यों के लिए एक सेल्फ सर्विस पोर्टल – आईसीएआई कनेक्ट का शुभारंभ किया है। पूर्वोक्त एकल विंडो सेल्फ सर्विस पोर्टल की प्रमुख विशिष्टियों में अपने निजी प्रोफाइल को देखना, अपनी फर्म के संविधान को देखना, आईसीएआई की उद्घोषणाओं, फीस के संदायों के ब्यौरों और आईसीएआई के विनियामक प्रभारों के ब्यौरे, माई आर्टिकल्स के ब्यौरों, विनियामक प्ररूपों की ट्रेकिंग और आवेदन की प्राप्ति, ई-सेवाएं, माई फर्म, माई साफ्टवेयर, पत्र और प्रमाणपत्र, सीपीई घंटों का प्रत्यय, नेटवर्किंग संबंधी दिशा-निर्देश, विलयन और निर्विलयन आदि सम्मिलित हैं।

आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उठाए गए वृत्ति संबंधी प्रश्नों का समाधान करने के लिए ई-समाधान पोर्टल

समिति ने सदस्यों के वृत्ति संबंधी प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक ई-समाधान पोर्टल आरंभ किया है। पैनलबद्ध वृत्तिक सदस्यों द्वारा वृत्ति के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। सदस्यों को अपने प्रश्नों को रजिस्टर करने के लिए एसएसपी पर लॉगिन करके 'ई-समाधान' को क्लिक करना होगा।

समिति की अन्त्य वेबसाइट - www.icai.org.in

समिति ने एक वेबसाइट विकसित की है, अर्थात् www.icai.org.in, जहां व्यवसायगत सदस्य और फर्म, आईसीएआई की परिषद् द्वारा अधिकथित सनियमों के अनुसार अपने स्वयं के पोर्टल का सृजन कर सकती हैं। यह वेबसाइट सीए फर्मों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जिस पर वह अपनी फर्म के ब्यौरे अपलोड कर सकते हैं, जिससे उन्हें व्यवसाय में लगे विश्वभर के सदस्यों और फर्मों तक पहुंच प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 3 फरवरी, 2015 तक, 6852 से अधिक सीए फर्मों ने पूर्वोक्त वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का सृजन किया था।

यह वेबसाइट, नेटवर्किंग, विलयन और व्यवसाय के निगम प्ररूप आदि जैसे समेकन उपायों को उपलब्ध कराकर सदस्यों और सीए फर्मों के समेकन हेतु एक मंच के रूप में भी कार्य करती है। सदस्य अन्य सदस्यों और फर्मों के पोर्टल को देख सकते हैं और एक जैसी प्रकृति वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर अपना विकास कर सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं।

वरिष्ठ सदस्यों के लिए पोर्टल - www.seniormembers.icai.org

समिति ने एक वेबसाइट विकसित की है, अर्थात् www.seniormembers.icai.org। यह वेबसाइट वरिष्ठ सदस्यों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है जिस पर वे अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नमनीय कार्य घंटों का कार्य और साथ ही पूर्णकालिक कार्य भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, यह वेबसाइट उद्योग की अनुभव प्राप्त योग्यता तक पूर्व पहुंच बनाने में भी सहायता करेगी, जो कि अन्यथा सामान्य क्रम में उपलब्ध नहीं होता है। उक्त पोर्टल सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए उपयोगी और सुगम सिद्ध होगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए "ट्रेकिंग्वर" – एक त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर

समिति ने सीए भातृसंघ के लिए एक त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर निकालने की भी पहल की है। इस ई-न्यूज लैटर में वृत्ति संबंधी नवीनतम घटनाओं के ब्यौरे सम्मिलित होंगे। यह ई-न्यूज लैटर एक आदर्श उपकरण है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह वृत्ति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी संकलित करता है और सदस्यों के लिए यह काफी फायदेमंद सिद्ध होगा।

‘मेक इन इंडिया में सीए वृत्तिक और एसएमई : व्यवसायियों के लिए एक हैंडबुक’

समिति ने मेक इन इंडिया में सीए वृत्तिक और एसएमई : व्यवसायियों के लिए एक हैंडबुक विषय पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। समिति ने यह पुस्तक इस उद्देश्य से निकाली है कि सदस्यों को “मेक इन इंडिया” मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप मेक इन इंडिया में सीए वृत्तिकों की भूमिका के संबंध में अंतःदृष्टि प्राप्त हो सके, जिससे भारत में निवेश हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके और जिसका उद्देश्य नौकरियों का सृजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करना है – जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था को संवहनीय विकास के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु अति महत्वपूर्ण है।

“लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के क्षेत्र के रूप में परियोजना वित्तपोषण संबंधी हैंडबुक”

सीए साधारण रूप से उच्च गुणवत्ता वाला उद्योग संबंधी अध्ययन और विश्लेषण करते हैं क्योंकि उनकी वाणिज्य और अर्थशास्त्र में नींव मजबूत होती है। यह सीए को मूल्यांकित की जाने वाली किसी परियोजना को वित्तपोषित करने वाले व्यवहार से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने में सुसंगत रूप से सहायता करती है। समिति ने इस उद्देश्य के लिए “लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के क्षेत्र के रूप में परियोजना वित्तपोषण संबंधी हैंडबुक” निकाली है।

शीघ्र अंतःदृष्टि संबंधी ई-पुस्तक

समिति ने “शीघ्र अंतःदृष्टि 2014” संबंधी एक ई-पुस्तक को तैयार करने और उसका प्रकाशन करने की पहल की है। इस शीघ्र अंतःदृष्टि ई-पुस्तक में कर, लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मानकों सीमित दायित्व भागीदारी, प्रबंधन परामर्शी सेवाओं, विवरणों और मानकों तथा संपरीक्षा संबंधी मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही सीए छात्रों से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण प्ररूप अंतर्विष्ट होते हैं।

च) नेटवर्किंग और विलयन

नेटवर्क के लिए पुनरीक्षित दिशा-निर्देश

समिति ने नेटवर्किंग के माध्यम से सीए फर्मों के समेकन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों पर विचार किया है। समिति ने उपयुक्त रूप से नेटवर्किंग संबंधी पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया है, जो सदस्यों और फर्मों द्वारा उनको सुगम रूप से अपनाए जाने को सुकर बनाएंगे। नेटवर्किंग के पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के ब्यौरे http://www.icaai.org/post.html?post_id=7710 पर उपलब्ध है। विलयन से संबंधित नियमों के ब्यौरों को <http://www.icaai.org> पर अपलोड किया गया है।

छ) वर्ग ‘क’ और वर्ग ‘ख’ नगरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए जाने वाले वृत्तिक समनुदेशनों के लिए फीस के पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए स्केल से संबंधी विवरणिका

समिति ने वर्ग ‘क’ और वर्ग ‘ख’ नगरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए जाने वाले वृत्तिक समनुदेशनों के लिए फीस के पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए स्केल से संबंधी विवरणिका तैयार की है। पूर्वोक्त विवरणिका को पहले ही भारत में सीए फर्मों को उनके प्रतिनिर्देश हेतु परिचालित किया गया है।

ज) धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने 8 फरवरी, 2015 को मुंबई में धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को धन प्रबंध के सिद्धांतों से सुसज्जित करना है और साथ ही प्रभावी निवेश रणनीति और व्यावहारिक प्रक्रियात्मक पहलुओं से सुसज्जित करना भी है और इसके अतिरिक्त सदस्यों में ऐसे सक्षमता स्तर का निर्माण करना है, जो एक बहु आयामी वित्तीय परामर्शकों के रूप में उनकी स्थिति को सुदृढ़ कर सके।

1 जनवरी, 2015 से समिति द्वारा आयोजित वृत्तिक विकास संबंधी कार्यक्रम

- 15 जनवरी, 2015 को केरल में मेक इन इंडिया में सीए की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सीए वृत्तिकों के लिए सक्षमता निर्माण के उपायों संबंधी तीन सीपीई घंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 7 फरवरी, 2015 को आईसीएआई भवन, धनबाद, झारखंड में मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन में सीए वृत्तिकों संबंधी 6 सीपीई घंटों की राष्ट्रीय संगोष्ठी

- 7 फरवरी, 2015 को आर. सिंघी हाल, ईआईआरसी परिसर, कोलकाता में मेक इन इंडिया पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसायगत वृत्तिकों के सक्षमता निर्माण उपायों संबंधी शिखर वार्ता

5.7 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

आईसीएआई ने अपने सदस्यों को इस सतत परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण में विश्वभर में हो रहे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से, निरंतर कौशल तीव्र करने की प्रक्रिया, कक्षा अध्यापन, ई-पठन पद्धति, घरेलू कार्यकारी विकास कार्यक्रमों, टेलीकांफ्रेंसों, जागरूकता कार्यक्रमों और सेमिनारों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आजीवन पठन के रूप में जागरूक बनाने तथा इन घटनाओं से अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

वैश्विक अपेक्षाओं से कदम मिलाकर चलने के लिए अब सीपी अपेक्षाओं को आईसीएआई के सभी सदस्यों, चाहे वे व्यवसाय में हों अथवा सेवारत हों, के लिए आज्ञापक बना दिया गया है और इस प्रणाली की मानीटरी और प्रबंध वैज्ञानिक रूप से किया जाता है।

सीपीई समिति द्वारा की गई प्रमुख पहले

- सीपीई समिति के तत्वाधान में सीपीई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और गैर-राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केवल व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाओं को उपलब्ध वित्तीय सहायता में वृद्धि।
- समिति ने निम्नलिखित विषयों पर पृष्ठभूमि सामग्रियां निकालने के लिए उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया है, जिससे कि पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीपीई कार्यक्रमों/शृंखला संगोष्ठियों के लिए तकनीकी सामग्री के एकसमान प्रदाय को सुनिश्चित किया जा सके।

क्रम सं.	विषय के व्यौरे
1.	जीएसटी
2.	आईसीडीएस
3.	कंपनी अधिनियम 2013 – रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं और सीएआरओ
4.	लेखापरीक्षा के मानक - कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आज्ञापक
5.	लेखांकन मानक – इंड एएस
6.	अंतरण मूल्य निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय कराधान ('ख' शहरों के लिए बुनियादी स्तर और 'क' शहरों के लिए एडवांस स्तर)
7.	जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
8.	कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अवमूल्यन
9.	नए कंपनी अधिनियम के अधीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनुपालन संबंधी अपेक्षाएं
10.	प्रमुख अनुपालनों की जांच सूची - (i) कंपनियों द्वारा (ii) संपरीक्षकों, निगमों की संपरीक्षा करते समय, उनसे संबंधित शास्तिक उपबंधों के साथ
11.	संबद्ध पक्षकार संव्यवहार, प्रकटन और विवक्षाएं
12.	कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निगमों द्वारा निक्षेपों और ऋणों को स्वीकार करने से संबंधित उपबंध
13.	निदेशकों, अनुषंगियों, सहबद्धों, संबंधित पक्षकारों और अन्यो को ऋण
14.	फेमा – विदेशी राष्ट्रिकों और अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) पर अनुपालन अपेक्षाएं और निर्बंधन
15.	अनिवासी भारतीयों का कराधान
16.	सेवाकर – सेनबेट प्रत्यय संबंधी मुद्दे
17.	सेवाकर - ऋणात्मक सूची संबंधी मुद्दे
18.	धन शोधन निवारण
19.	विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)
20.	न्यायलयीय लेखांकन और लेखापरीक्षा
21.	आयकर - टीडीएस (मुद्दे और विवाद)

22.	आयकर - सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती
23.	कराधान और भू-संपदा संव्यवहार
24.	हाल ही के निर्णय - अप्रत्यक्ष कर विधि
25.	पूँजी अभिलाभ संबंधी मुद्दे
26.	कारबार आय का निर्धारण
27.	कंपनियों के आवास और अनिवासी कंपनियों के कराधान के अवधारण में प्रभावी प्रबंधन का स्थान।

- सीपीई समिति ने सभी अध्ययन सर्कलों को परिषद् द्वारा लिए गए निम्नलिखित विनिश्चयों की संसूचना देते हुए सूचना भेजी है -

“यह कि संस्थान की परिषद् ने यह विनिश्चय किया है कि आयोजित किए गए सीपीई कार्यक्रमों के संबंध में आईसीएआई के सेवाकर दायित्व का अवधारण करते समय, अध्ययन सर्कलों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में सेवाकर दायित्व को गणना में नहीं लिया जाएगा और यह कि अध्ययन सर्कलों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में सेवाकर दायित्व का वहन स्वयं अध्ययन सर्कलों द्वारा किया जाएगा और ऐसा करते समय अध्ययन सर्कल आईसीएआई के सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं. और पेन सं. का उपयोग नहीं करेंगे, इसकी बजाए वे सभी संबद्ध अनुपालनों के लिए अपने स्वयं का सेवाकर रजिस्ट्रीकरण और पेन सं. प्राप्त करेंगे। प्रत्येक अध्ययन सर्कल स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने सभी कर संबंधी अनुपालनों को पूरा किया है, उदाहरण के लिए यदि कुल आवर्त दस लाख रुपए की सीमा से अधिक होती है तो पृथक् कर रजिस्ट्रीकरण।”

- समिति ने यह विनिश्चय किया कि ऐसे किसी सदस्य को, जो किसी सीपीई कार्यक्रम में संकाय के रूप में कार्य करता है, अधिकतम 4 घंटों प्रति सीपीई कार्यक्रम के अधीन रहते हुए तकनीकी सत्रों की अवधि के अनुसार दुगने सीपीई घंटों का प्रत्यय प्रदान किया जाएगा।
- सीपीई समिति ने केंद्रीय समितियों द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए मानकीकृत नीति/दिशा-निर्देशों/पैरामीटरों का क्रियान्वयन किया है। उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर और साथ ही सीपीई पोर्टल पर रखा गया है। परिषद् के सभी सदस्यों और आईसीएआई की सभी अस्थायी समितियों के सचिवों को इस संबंध में एक संसूचना भेजी गई है।
- समिति ने यह विनिश्चय किया है कि महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों को, उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर, गर्भावस्था के कारण एक कलेंडर वर्ष के लिए अस्थायी आधार पर छूट प्रदान की जाए।
- समिति ने यह विनिश्चय किया कि भिन्न रूप से सशक्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को, उनसे लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर, जिसे संबद्ध प्रादेशिक परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अग्रेषित किया गया हो, संरचित पठन से मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाए। समिति ने यह और विनिश्चय किया कि स्थायी निःशक्तता से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो 40 प्रतिशत से अन्यून स्थायी निःशक्तता धारण कर रहे हैं। आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्षम चिकित्सीय प्राधिकारी, अर्थात् सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कोई अस्पताल या संस्थान जैसा कि आयकर अधिनियम के अधीन परिभाषित है, द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
- सीपीई समिति के अध्यक्ष ने सभी अध्ययन सर्कलों को यह संसूचना भेजी है कि वे अध्ययन सर्कलों के संयोजकों और उप संयोजकों के निबंधनों के संबंध में सभी सनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सीपीई कलेण्डर

समिति ने वर्ष 2015-16 के लिए सीपीई कलेण्डर को अंतिम रूप प्रदान किया है, जिसमें वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में 600 से अधिक विषय अंतर्विष्ट हैं। उसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया है।

ई-न्यूजलेटर

अप्रैल, 2014 के पश्चात् से त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर (सीपीई बुलेटिन) के पांच अंक निकाले गए हैं और उन्हें परिषद् के निर्णय के अनुसार आईसीएआई की वेबसाइट पर रख दिया गया है।

सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों की मानीटरी

अध्यक्ष, सीपीईसी ने सभी पांच क्षेत्रों में वर्ष 2015-16 के लिए सीपीई प्रादेशिक मानीटरी समितियों का पुनर्गठन किया है।

सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों में पारदर्शिता

समिति ने सीपीई कार्यक्रमों में पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया है। समिति ने जनता में आईसीएआई द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों और आयोजित किए जाने वाले प्रमुख आयोजनों के बारे में जागरुकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आईटी

उपकरणों का उपयोग करते हुए सीपीई पोर्टल पर प्रबंध सूचना प्रणाली को आरंभ किया है। यह सदस्यों को, आगामी सीपीई कार्यक्रमों की नगरवार सूची देखने में समर्थ बनाता है और साथ ही उनमें रजिस्ट्रीकरण हेतु पीओयूके संपर्क ब्यौरे भी उपलब्ध कराता है।

सर्वेक्षण का संचालन

संगठन के दीर्घकालिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए सदस्यों की राय जानने हेतु सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए सीपीई समिति ने एक मानकीकृत फीड बैक प्ररूप तैयार किया है और उसने सभी पीओयू से यह अनुरोध किया था कि वे उनके द्वारा आयोजित प्रत्येक सीपीई कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों से उक्त फीड बैक प्राप्त करें। उक्त फीड बैक प्ररूप को आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

सीपीई कार्यक्रमों के संचालन में वृत्तिकरण के लिए पहले

समिति ने सीपीई कार्यक्रमों के संचालन में व्यवसायिकता लाने के विचार से सभी पीओयू को निम्नलिखित संसूचना भेजी है –

- निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए :
 - ⇒ किसी सीपीई कार्यक्रम को सदैव उसके उद्घोषित समय पर आरंभ किया जाएगा। समय निष्ठा का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
 - ⇒ प्रस्तावना के प्रयोजनों के लिए कोई समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा। सीपीई कार्यक्रम सीधे संकाय द्वारा तकनीकी सत्र से प्रारंभ होगा।
 - ⇒ स्मृति चिह्न अधिमानतः उपयोगी पुस्तकों के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
 - ⇒ कार्यक्रम के ब्यौरे, कार्यक्रम के समय से काफी समय पूर्व सीपीई पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाने चाहिए (अर्थात् कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पूर्व)।
 - ⇒ पिछली तारीखों के आयोजनों को सीपीई घंटों के अनुमोदन हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा (अर्थात् आयोजन कराने के पश्चात् यदि कार्यक्रम के ब्यौरे अपलोड किए जाते हैं तो)।
- निम्नलिखित ब्यौरों को प्रस्तुत किया जाए :
 - ⇒ पिछले तीन वर्षों के दौरान संयोजक और उप संयोजक के ब्यौरे और साथ ही चालू वर्ष के ब्यौरे।
 - ⇒ उस तारीख को अध्ययन सर्कल के साथ जुड़े सदस्यों की सूची।
 - ⇒ वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 के लिए संपरीक्षित लेख।
- आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना को कम से कम कार्यक्रमों के आयोजनों से दो मास पूर्व तैयार करना और आगामी कार्यक्रमों के ब्यौरे भी समयानुसार अपलोड करना ताकि सदस्यों के लिए, इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालना सुगम हो सके।
- निम्नलिखित संनियमों का कड़ाई से पालन करना :

“सीपीई अध्ययन सर्कलों के कार्यों/क्रियाकलापों की देखभाल करने और साथ ही सीपीई अध्ययन सर्कलों के उचित लेख बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एक संयोजक और एक उप संयोजक का निर्वाचन किया जाएगा और कोई व्यक्ति किसी सीपीई अध्ययन सर्कल के संयोजक/ उप संयोजक के रूप में एक वर्ष के अधिकतम तीन कार्यकालों तक कार्य कर सकेगा।”
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा प्रादेशिक सम्मेलन और उप प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश :
 - ⇒ प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किसी प्रादेशिक परिषद् द्वारा उसके अपने क्षेत्र में वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता है। ऐसे सम्मेलन की अवधि न्यूनतम एक दिन होनी चाहिए।
 - ⇒ उप प्रादेशिक सम्मेलन/राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्रादेशिक परिषदों द्वारा किया जा सकता है, जिनकी मेजबानी उनकी शाखाओं द्वारा की जाएगी। इन सम्मेलनों की अवधि न्यूनतम एक दिन होनी चाहिए।
 - ⇒ एक उप प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक राज्य में एक वर्ष के दौरान एक बार किया जा सकता है।

सभी प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं को, उन्हें प्रादेशिक और उप प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिशा-निर्देशों की सूचना देते हुए एक संसूचना भेजी गई थी।
- समिति ने, सीपीई पोर्टल पर एक वचनबंध का प्ररूप रखा है, जिसे सीपीई पोर्टल पर उपस्थिति अपलोड करने से पूर्व सीपीई पीओयू में स्थित संबद्ध व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। यह वचनबंध निम्नानुसार है :

“एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि अपलोड किए जाने वाला डाटा सत्य और सही है तथा वह ऐसे सदस्यों द्वारा जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, उपस्थिति पत्र पर किए गए हस्ताक्षर के आधार पर अपलोड किया जा रहा है।”

- सीपीई पोर्टल पर पीओयू द्वारा अपलोड किए जाने वाले बीजीएम की साफ्ट प्रति के संबंध में एक उपबंध किया गया है, जिसे उनके संबद्ध सीपीई कार्यक्रम में परिचालित किया गया है।
- समिति ने सीपीई कार्यक्रमों के स्तर में वृद्धि करने के लिए एक केंद्रीय गुणवत्ता निरीक्षण दल का गठन किया।
- समिति ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का विनिश्चय किया, जो लघु और मध्यम व्यवसायियों को नए वृत्तिक अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही ऐसे क्षेत्रों में और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भी कार्यक्रमों को आयोजित करने का विनिश्चय किया।
- सीपीई पोर्टल पर मास के प्रत्येक शुक्रवार को सभी पीओयू को स्व:जनित मेल भेजने के लिए एक प्रणाली आरंभ की गई है। इन मेलों के माध्यम से उनकी ओर से उपस्थिति को अपलोड किए जाने के लिए लंबित कार्यक्रमों के संबंध में स्मरण कराया जाएगा और उनसे शीघ्र अपलोड करने का अनुरोध किया जाएगा।

सीपीई वृहत्त कार्यक्रम

सीपीई समिति द्वारा अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान कुल 34 वृहत्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

सीपीई टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रम

सीपीई समिति द्वारा अप्रैल, 2014 से जून, 2014 की अवधि के दौरान इग्नू, नई दिल्ली में कुल 5 सीपीई टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

सीपीई राष्ट्रीय लाइव वेबकास्ट

इग्नू में ज्ञान दर्शन चैनल - 2 को बंद कर दिए जाने के कारण समिति ने यह विनिश्चय किया है कि सीपीई टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों के समरूप अधिकाधिक सीपीई राष्ट्रीय लाइव वेबकास्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तदनुसार, मार्च, 2015 से, समिति प्रत्येक मास दो सीपीई राष्ट्रीय लाइव वेबकास्ट कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। समिति ने मार्च, 2015 से जुलाई, 2015 के दौरान इस वर्ष 12 ऐसे वेबकास्टों का आयोजन किया है, जिनमें वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया था।

घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम

सीपीई समिति विभिन्न निगमों में कार्य कर रहे अपने सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न विषयों पर घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का भी संवर्धन कर रही है। सीपीई समिति ने अप्रैल, 2014 से फरवरी, 2015 की अवधि के दौरान कुल 3 घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

आयोजित किए गए सीपीई अनुकूलन कार्यक्रम

समिति ने सभी पांच क्षेत्रों में सभी अध्ययन सर्कलों/चैप्टरों के सभी संयोजकों और उप संयोजकों की बैठक आयोजित करने का विनिश्चय किया। सीपीईसी द्वारा आयोजित दो अनुकूलन कार्यक्रमों के व्यौरे निम्नानुसार हैं :-

- पश्चिमी क्षेत्र के सभी संयोजकों/उप संयोजकों के साथ बैठक का आयोजन 12 जून, 2014 को मुंबई में किया गया था।
- सीपीई पीओयू के शीर्षस्थ अधिकारियों की बैठक का आयोजन 15-16 जुलाई, 2015 के दौरान आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा द्वारा किया गया था। समिति ने एसआईआरसी, शाखाओं के अध्यक्षों और सचिवों तथा तमिलनाडु, केरल राज्यों और कर्नाटक राज्य की समीपस्थ शाखाओं (उडुपी, मंगलौर और मैसूर) के सीपीई अध्ययन सर्कलों/चैप्टरों/समूहों के संयोजकों/उप संयोजकों को रमाडा रिजार्ट, कोचीन में आमंत्रित किया था, जिससे कि सीपीई कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी तथा सदस्य मित्र बनाया जा सके और साथ ही सीपीई कार्यक्रमों में सर्वोत्तम व्यवहारों का पालन किया जा सके।

5.8 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह वृत्ति के सशक्तिकरण और साथ ही सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक समुचित निगम व्यवस्था की ओर शीघ्रतापूर्वक अग्रसर होने और इसे सुकर बनाने के लिए एक उपकरण बन सके। यह समिति जारी की गई निगम विधियों/नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं/स्कीमों की सर्वोत्तम व्यवहारों की तुलना में समीक्षा करती है और सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को उपयुक्त अभ्यावेदन/सुझाव प्रस्तुत करती है और इस प्रकार विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती है।

समिति देश में विभिन्न केन्द्रों पर मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रही है, इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अब टियर I, टियर II और टियर III नगरों तक पहुंचा दिया गया है और इन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु भारी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। समिति ने भारत से बाहर दुबई और बहराइन में भी इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया है।

समिति देश के विभिन्न स्थानों पर निगम विधि और निगम शासन विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 संबंधी समकालीन विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का आयोजन करती है ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। समिति निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन करती है। समिति सदस्यों के फायदे के लिए कंपनी अधिनियम के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण/आवेदन गाइडें/बुलेटिन और अन्य प्रकाशन भी निकालती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- मंत्रालय को उचित प्रतिवेदन करके कंपनी अधिनियम, 2013 के कारण सदस्यों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करना।
- कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संबंध में मंत्रालय को सुझाव, अंतःनिवेश/ डांचागत सुझाव आदि उपलब्ध कराना। साथ ही मंत्रालय को वृत्ति हेतु अवसर के क्षेत्रों के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराना।

2. स्वतंत्र निदेशक निक्षेपागार पोर्टल को विकसित करना और उसे बनाए रखना

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक निक्षेपागार पोर्टल को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सक्रिय प्रोत्साहन से विकसित किया गया है। समिति नियमित रूप से इस पोर्टल का रखरखाव कर रही है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के संबंध में वर्ष 2014 में किए गए वेबकास्ट

- समिति कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियमों के व्यष्टिक विषयों के संबंध में वेबकास्टों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है।
- पहले वेबकास्ट का आयोजन 16 अप्रैल, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियम” विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे अध्यक्ष, सीएल एंड सीजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने भी सदस्यों और निगमों को संबोधित किया था।
- दूसरे वेबकास्ट का आयोजन 23 अप्रैल, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 का प्राइवेट कंपनियों पर प्रभाव” विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएल एंड सीजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- तीसरे वेबकास्ट का आयोजन 30 अप्रैल, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 में लेखाओं और संपरीक्षा संबंधी उपबंध” विषय पर आयोजित किया गया था।
- चौथे वेबकास्ट का आयोजन 7 मई, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 में निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और केएमपी की भूमिका और उत्तरदायित्व” विषय पर आयोजित किया गया था।
- पांचवे वेबकास्ट का आयोजन 4 जून, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन वृत्तिकों के लिए अवसर” विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे अध्यक्ष, सीएल एंड सीजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- छठे वेबकास्ट का आयोजन 11 जून, 2014 को “कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध” विषय पर आयोजित किया गया था।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित ई-पुस्तक

- सदस्यों के फायदे और सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित एक ई-पुस्तक का शुभारंभ किया गया था।

5. प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यक्रम

- वर्ष 2014-2015 के लिए : चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियमों को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिकांश चेष्टरों के लिए अधिसूचित कर दिया गया है और यह आवश्यक है कि सदस्य नए अधिनियम के उपबंधों के बारे में सचेत हों, अतः समिति ने यह विनिश्चय किया था कि प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से समिति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समिति ने देश भर में निम्नलिखित स्थानों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में 86 कार्यक्रमों का आयोजन किया है :

कोलकाता (2 कार्यक्रम), वदोदरा, हुबली, अकोला, गाजियाबाद, जालंधर, अहमदाबाद, नांदेड, अलवर, भिलाई, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, हिमाचल प्रदेश, सूरत, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जलगांव, संगरूर, सिलीगुडी (2 कार्यक्रम), रांची आगरा, मैसूर, गुवाहाटी, कटक, मंगलूरु, बरेली, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोयंबटूर, मथुरा, नवी मुंबई, हैदराबाद, गुंटूर, संबलपुर,

देहरादून, पानीपत, एनाकुलम, पुणे, डिब्रूगढ़, गांधीधाम, नासिक, जमशेदपुर, पटना (3 कार्यक्रम), लुधियाना, अमरावती, काकीनाडा (2 कार्यक्रम), सांगली, अंबाला, लखनऊ, तिरुनेलवेली, भरूच, फरीदाबाद, जबलपुर, राजामहेन्द्रवरम् (2 कार्यक्रम), उज्जैन (2 कार्यक्रम), पांडिचेरी, भावनगर, हिसार, कोझीकोड, जामनगर, वसई, इरोड, गोवा (2 कार्यक्रमों), ठाणे (2 कार्यक्रम), तिनसुकिया, सलेम, ओंगोले, नागपुर, चेन्नई, कूर्ग, दिसपुर, मदुरै, पालघाट, बेल्लारी, लातूर, कलूर और सलेम।

- **वर्ष 2015-2016 के लिए :** समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का विनिश्चय किया था ताकि कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुचारू किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में निम्नलिखित 35 स्थानों पर किया गया है :

चंडीगढ़, दिल्ली, पटियाला, करनाल, जालंधर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, पालघाट, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, त्रिचूर, उडुपी, इरोड, राउरकेला, गुवाहाटी, रानीगंज, दुर्गापुर, भुवनेश्वर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, जामनगर, अहमदाबाद, अकोला, वापी, जमशेदपुर, बिलासपुर, पटना, जोधपुर, गाजियाबाद, रांची, वेल्लोर, संबलपुर, तिनसुकिया, आगरा और मथुरा।

- कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में अक्टूबर, 2014 में आईसीएआई की दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की बंगलौर शाखा के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 संबंधी बुलेटिन

- समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में बुलेटिनों की एक श्रृंखला निकाल रही है। बुलेटिनों की 14 श्रृंखलाओं को पहले ही जारी कर दिया है और उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट और आईसीएआई के नॉलेज गेटवे पर भी अपलोड किया गया है।

श्रृंखला 1 -	अगस्त, 2014 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण
श्रृंखला 2 -	अगस्त, 2014 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन पत्रों का संक्षिप्त विवरण
श्रृंखला 3 -	अगस्त, 2014 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नियमों का संक्षिप्त विवरण और उस अध्याय से संबंधित नियमों का व्याख्यात्मक पाठ
श्रृंखला 4 -	कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और सेवा द्वारा संशोधन सम्मिलित करते हुए सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खंड 49 में तत्समान उपबंधों के बीच तुलना। साथ ही, सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खंड 49 और तारीख 15.09.2014 के परिचालन पत्र द्वारा सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खंड 49 में संशोधनों के बीच में अंतर। इसके अतिरिक्त, सेवा द्वारा तारीख 15.09.2014 के परिचालन पत्र द्वारा संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खंड 49 का व्याख्यात्मक पाठ।
श्रृंखला 5 -	अगस्त, 2014 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2014 का संक्षिप्त विवरण
श्रृंखला 6 -	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों और वृत्तियों पर शास्तियां
श्रृंखला 7 -	कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के महत्वपूर्ण उपबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण
श्रृंखला 8 -	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 से नवंबर, 2014 के दौरान जारी नियमों का संक्षिप्त विवरण और उस अध्याय से संबंधित नियमों का व्याख्यात्मक पाठ
श्रृंखला 9 -	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान जारी अधिसूचनाओं और परिचालन पत्रों का संक्षिप्त विवरण
श्रृंखला 10 -	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में सम्मिलित किए गए उपबंध और संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् धारा का अंतिम पाठ
श्रृंखला 11 -	ऐसी धाराओं की सूची जहां विशेष संकल्प अपेक्षित है और ऐसी धाराओं की सूची जहां केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है
श्रृंखला 12 -	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2015 में सम्मिलित किए गए उपबंध और संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात् धारा का अंतिम पाठ
श्रृंखला 13 -	नवंबर, 2014 से अप्रैल, 2015 के बीच जारी परिचालन पत्रों, अधिसूचनाओं, कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2015 का संक्षिप्त विवरण
श्रृंखला 14 -	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2014 से अप्रैल, 2015 के दौरान जारी नियमों में संशोधनों का संक्षिप्त विवरण और संबंधित धाराओं के अध्यायों के व्याख्यात्मक नियम

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण

समिति कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पण का उस सीमा तक पुनरीक्षण कर रही है, जहां तक उसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में परिवर्तन किए गए हैं।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के उपबंधों के संबंध में एप्लीकेशन गाइड

समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के उपबंधों के संबंध में एक एप्लीकेशन गाइड जारी की है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के उपबंधों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के उपबंधों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया है और उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के संबंध में एप्लीकेशन गाइड

समिति शीघ्र ही कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के संबंध में निम्नलिखित एप्लीकेशन गाइड निकाल रही है :

- प्रबंधकीय पारिश्रमिक एप्लीकेशन गाइड
- निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित उपबंधों से संबंधित एप्लीकेशन गाइड
- प्राइवेट कंपनी के उपबंधों से संबंधित एप्लीकेशन गाइड
- संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के उपबंधों से संबंधित एप्लीकेशन गाइड

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्राइवेट कंपनियों को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन प्राइवेट कंपनियों को छूट प्रदान करने के लिए चिरप्रतिष्ठित अधिसूचना को एमसीए द्वारा तारीख 5 जून, 2015 को जारी किया गया है। इस संबंध में बहुत बड़ी संख्या में एसएमएस, ई-मेल आदि भेजे गए सदस्यों को इसकी सूचना दी गई थी और साथ ही इसकी उदघोषणा को आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।
- ऐसे उपबंधों का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया था, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था और उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।

12. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015

- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 को अधिसूचित किया गया है और उसे 29 मई, 2015 से लागू किया गया है। इस संबंध में एक अवसीमा विहित की गई है जिससे अधिक के कपटों की रिपोर्टिंग केंद्रीय सरकार को की जानी है।
- कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार उपबंधों का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया था और उसे कंपनी अधिनियम, 2013 के बुलेटिन की श्रृंखला 12 के रूप में निकाला गया था। तथा उसे आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।

13. आईसीएआई-एनएफसीजी कार्य योजना

निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वर्ष 2014-15 के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की।

14. एमसीए को अभ्यावेदन

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षा समनुदेशनों की संख्या को सीमित करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नए प्ररूपों को एमसीए – 21 के साथ फाइल करने में, जहां सदस्यों का सीओपी संख्यांक पृच्छा जा रहा था, उदभूत होने वाले मुद्दों का समाधान करने के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- जुलाई, 2014 में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारूप नियमों के संबंध में आईसीएआई की मुख्य चिंताओं और प्रमुख मुद्दों पर अपर सचिव, एमसीए को अभ्यावेदन किया गया था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों में अंतर्बलित ऐसे मुद्दों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो वृत्ति को प्रभावित करते हैं जैसे कि कंपनी अधिनियम के अधीन संपरीक्षाओं की संख्या पर सीमा, कपट की रिपोर्टिंग, शास्तियां, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में रिपोर्टिंग, सापेक्ष परिभाषा डीपीटी – 4 को फाइल करने में समय विस्तारण, कंपनी विधि समझौता स्कीम का विस्तारण आदि। समिति ने आज की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न मुद्दों पर 29 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न मुद्दों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए – संशोधनों/उपांतरणों/स्पष्टीकरणों के लिए सुझाव।
- कंपनी विधि बोर्ड, मुंबई में रिक्ति को भरने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अधीन सीएसआर कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर टीका-टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत किए गए।

- माननीय वित्त मंत्री को – भारत में कारबार करने की सुगमता – कंपनी अधिनियम में अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को – भारत में कारबार करने की सुगमता – कंपनी अधिनियम में अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया और साथ ही एनएफआरए के गठन में अंतर्बलित मुद्दों तथा कड़ी शास्तियों के संबंध में भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

15. मूल्यांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- समिति ने अभी तक मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 54 बैचों का संचालन किया है।
- आज की तारीख तक 2600 सदस्य इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत हुए हैं।
- समिति ने इस पाठ्यक्रम को जुलाई, 2015 से मेरठ और कानपुर में आरंभ किया है।
- वर्ष 2015-16 के लिए समिति ने इस पाठ्यक्रम के 12 बैचों का संचालन करने की योजना बनाई है।

16. तुलन पत्रों/वार्षिक रिपोर्टों का बहुत अधिक संख्या में फाइल किया जाना

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2014 में आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह चालू वर्ष के लिए कंपनी के तुलन पत्र और वार्षिक विवरणी को समय से पूर्व फाइल करने हेतु सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करे और अधिमानी रूप से उन्हें अंतिम तारीख को लगने वाली भीड़ से बचने के लिए अंतिम तारीख से काफी समय पहले फाइल कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में एक उदघोषणा भी संस्थान की वेबसाइट पर रखी गई थी।

17. मंत्रालयों/विनियामकों/सरकारी कार्यालयों के साथ वृत्ति संबंधी विषयों पर परस्पर क्रियाएं

कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया की जा रही है।

18. वर्ष 2014-15 में वृत्ति संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठकें

- अप्रैल, और जून, 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यान्वयन मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक।
- जून, 2014 में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने, स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बेस को बनाए रखने और निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों के प्रावधानों से संबंधित अन्य मुद्दों और लेखांकन के संबंध में अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक।
- जून, 2014 में, स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक।
- जुलाई, 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 से जुड़े मुद्दों के संबंध में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक।
- अप्रैल, 2015 में एओसी – 4 और एमजीटी – 7 के संबंध में सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक।
- अप्रैल, 2015 में माननीय वित्त मंत्री और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ भारत में कारबार करने की सुगमता – कंपनी अधिनियम में अपेक्षित परिवर्तनों के विषय पर बैठक।

19. वर्ष 2014-15 में सरकारी विभागों/सरकारी पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति नियमित रूप से लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, इन कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

1. 24 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में 5वां आईसीएआई – डीपीई कार्यक्रम
2. 9 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में 6वां आईसीएआई – डीपीई कार्यक्रम

20. तमिलनाडु सरकार के सीएफओ के लिए वर्ष 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में कार्यशालाएं

समिति तमिलनाडु सरकार के सीएफओ के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। ऐसी एक कार्यशाला का आयोजन अक्टूबर, 2014 में चेन्नई में किया गया था।

21. वर्ष 2014-15 में कंपनी अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशालाएं

- समिति ने नवंबर 2014 और जनवरी, 2015 में क्रमशः मुंबई और दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन विषय पर दो राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है।
- समिति ने नवंबर 2014 में दिल्ली और चेन्नई में कंपनी अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन विषय पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

22. वर्ष 2015 में निदेशकों के लिए दो दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम की श्रृंखला

- समिति ने मार्च, 2015 में बंगलूरु में निदेशकों के लिए दो दिवसीय प्रमाणन कार्यक्रम की श्रृंखला में से पहले कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस श्रृंखला के दूसरे कार्यक्रम का आयोजन मई, 2015 में कोयम्बटूर में किया गया था।
- श्रृंखला के तीसरे कार्यक्रम का आयोजन जून, 2015 में मुंबई में किया गया था।
- श्रृंखला के चौथे कार्यक्रम को अगस्त, 2015 में चेन्नई में आयोजित करने की योजना की जा रही है।

23. कंपनी विधि में विधिक और व्यावहारिक मुद्दों पर परस्पर क्रियाशील बैठक और वर्ष 2015 की भावी कार्य योजना

अनेक प्रश्नों, संदेहों और कंपनी अधिनियम, 2013 से उद्भूत होने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर विचार करते हुए समिति कंपनी विधि में विधिक और व्यावहारिक मुद्दों पर परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन कर रही है और भावी कार्य योजना भी तैयार कर रही है। आज की तारीख तक मई, जून और जुलाई, 2015 में मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में 5 बैठकों का आयोजन किया गया है। समिति 6ठीं परस्पर क्रियाशील बैठक को जुलाई, 2015 में दिल्ली में कराए जाने की योजना बना रही है।

चालू पहले/परियोजनाएं

- निगम शासन की रेटिंग/संपरीक्षा समिति के संघ का निर्माण/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनों के नए मंच/निदेशकों के लिए विचार-विमर्श हेतु मंच का सृजन।
- निगम शासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण करना (लिस्टिंग करार के पुनरीक्षित खंड 49 के आधार पर)।
- समिति कंपनियों की पुनः संरचना और कंपनियों के परिसमापन संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने की योजना बना रही है।

5.9 प्रत्यक्ष कर समिति**किए गए क्रियाकलाप****क. सीबीडीटी को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं**

1. कर संपरीक्षा रिपोर्टों के नए प्रारूप
2. निदेशक से पत्र, आईटीआरए (आरए-1)
3. 29 सितंबर, 2014 को टीडीएस के संबंध में स्थायी समिति की 5वीं बैठक का आयोजन
4. चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी)
5. आयकर नियम, 1962 के अधीन आईटीआर प्ररूपों और अधिसूचित की जाने वाली अन्य रिपोर्टों के संबंध में सुझाव
6. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान संबंधी परिषद् के साथ बैठक
7. जावा यूटिलिटी को संशोधन करने का अनुरोध, जिससे कि 8 अंकों वाले एफआरएन को अनुज्ञात किया जा सके – 3 सीए/3 सीबी
8. संयोजित फीस की दर में कमी, धारा 276ख के संबंध में
9. सीबीडीटी द्वारा जारी आयकर संगणना और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के प्रारूप के संबंध में अंतःनिवेश
10. 9 फरवरी, 2015 को मुकदमेबाजी कम करने संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन
11. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पासवर्ड में परिवर्तन

12. ई-टीडीएस/टीसीएस आरपीयू को अद्यतन करना (वर्जन 4.2)
13. निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कर संपरीक्षा प्रारूप उपयोगिता में कतिपय ब्यौरों को समिलित करने के लिए तथा आईटी प्रणाली में उपयुक्त नियंत्रण तंत्रों को समाविष्ट करने के लिए सुझाव, ताकि कर संपरीक्षाओं की अधिकतम सीमा का अनुपालन किया जा सके।
14. इंड एस के कार्यान्वयन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115अख (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के उपबंधों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अंतःनिवेश प्रस्तुत करना।
15. बकाया मांग सत्यापन पोर्टल के संबंध में फीड बैक।
16. धारा 200क के अधीन जारी मांग सूचनाओं में 31 मई, 2015 तक धारा 234ड के अधीन फीस को बाहर रखना।
17. नियम 37खख और संबंधित प्ररूपों में पारिणामिक संशोधन
18. प्ररूप 26थख में ऑनलाइन सुधार को समर्थ बनाना (संपत्ति के क्रय पर टीडीएस)
19. निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कर संपरीक्षा डाटा
20. 'कालाधन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015' के संबंध में सुझाव।
21. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में स्टाम्प शुल्क के पुनरीक्षण के कारण निर्धारितियों के सामने आने वाली कठिनाइयां।

ख. संघीय बजट से संबंधित क्रियाकलाप

1. बजट अवलोकन कार्यशाला
2. संघीय बजट में कर प्रस्तावों संबंधी लाइव वेबकास्ट
3. सीए जर्नल के विशेष बजट के लिए संघीय बजट के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में लेख
4. संघीय बजट 2014-15 में किए गए ऐसे प्रस्ताव, जिनके संबंध में आईसीएआई के सुझावों को स्वीकार किया गया था
5. बजट-पूर्व ज्ञापन – 2015 के संबंध में सुझाव
6. बजट-पश्च ज्ञापन – प्रत्यक्ष कर का प्रस्तुत किया जाना

ग. अन्य पहल

1. डीटीसी आर्थिक सर्वेक्षण – 2013-14 के संबंध में अंतःनिवेश
2. सीपीसी (टीडीएस) के साथ परस्पर संपर्क
3. सी एंड एजी कार्यालय द्वारा सत्यापन हेतु भेजे गए मामले
4. "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण" शीर्षक वाले प्रकाशन का पुनरीक्षण
5. ई-फाइलिंग वेबसाइट तक पहुंच बनाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने संबंधी गाइड
6. क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त टिप्पण
7. सीए जर्नल के लिए कर संपरीक्षा संबंधी लेख
8. आईसीएआई जर्नल की मानार्थ प्रतियां जारी करने के लिए सूची को अद्यतन करना
9. रिट याचिका (सिविल) सं. 621/2007, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अंतःनिवेश, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
10. त्वरित अंतःदृष्टि से संबंधित संप्रेक्षण
11. "ई-फाइलिंग को सुकर बनाना – मुद्दे और समाधान" विषय पर वेबकास्ट

12. “निर्धारण कार्यवाहियों में तृतीय पक्षकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) रिपोर्टिंग के मूल्यांकन संबंधी कार्यपालन संपरीक्षा” विषय पर भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2014 की सं. 32) के संबंध में प्रारूप संप्रेक्षण
13. प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अनुरोध

घ. संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरूकता कार्यक्रम

देश भर में अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कर जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

5.10 आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति आईसीएआई की एक अस्थायी तकनीकी समिति है, जिसे अन्य बातों के साथ, आर्थिक और वाणिज्यिक तथा कारबार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों का विश्लेषण करने, उनसे संबंधित जानकारी का प्रसार करने, नीति तैयार करने के लिए अंतर्निवेश प्रदान करने और उनके संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का बहु कार्यकरण संबंधी कार्य सौंपा गया है। समिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यू.टी.ओ में एक अर्हता पश्च पाठ्यक्रम और दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों अर्थात् एडीआर (माध्यस्थता, मध्यकता और सुलह) में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा धन शोधन निवारण विधियों (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी प्रशासन करती है।

कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन

वर्ष 2014-15 के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है :

- 25 जुलाई, 2014 को माध्यस्थता (एडीआर तंत्र में उभरते वृत्तिक अवसर) विषय पर वेबकास्ट ।
- 23 अगस्त, 2014 को प्रतिस्पर्धा विधि और उभरते वृत्तिक अवसरों पर वेबकास्ट ।
- 23 सितंबर, 2014 को सीए के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के अधीन उनके लिए वृत्तिक अवसरों पर वेबकास्ट ।
- समिति द्वारा 18 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) और प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा की गई थी।
- आस्ट्रेलिया में वृत्तिक अवसरों के संबंध में समिति द्वारा 4 दिसंबर, 2014 को इंदौर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा द्वारा की गई थी।
- आईसीएआई की उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति और आर्थिक, वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यू.टी.ओ संबंधी समिति ने संयुक्त रूप से 13 और 14 दिसंबर, 2014 को मुंबई में एडीआर तंत्र, आईपीआर, डब्ल्यू.टी.ओ, फेमा, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसरों के संबंध में एक व्यापक सम्मेलन का आयोजन किया था।
- 25 जनवरी, 2015 को सदस्यों के लिए चेन्नई में समिति द्वारा एडीआर तंत्र के क्षेत्र में पर्यावलोकन और नवीनतम घटनाओं तथा सीए के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में एक वेबकास्ट।
- 23 मई, 2015 को अमृतसर में आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ के विषय पर तथा सीए के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- सदस्यों के लिए 13 जून, 2015 को नई दिल्ली में आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों में उभरते हुए वैश्विक वृत्तिक अवसरों के संबंध में एक सभा का आयोजन किया गया था।
- सदस्यों के लिए 20 जून, 2015 को जम्मू में एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला की मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू और कश्मीर शाखा द्वारा की गई थी।
- नई काला धन विधि (आयकर अधिनियम के अधीन), विपरित प्रभार और संकर्म संविदा पर कर (सेवाकर) और कंपनी विधि तथा सीएआरओ में नवीनतम संशोधनों के विषय पर 26 जून, 2015 को लुधियाना में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी की मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी की लुधियाना शाखा द्वारा किया गया था।

सेवा सभा – 2014

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सीआईआई, एसईपीसी, एफआईआईओ और आईआईएफटी के साथ मिलकर, “भारत से सेवा निर्यात का संवर्धन – अवसर” विषय पर 12 और 13 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में सेवा महासभा, 2014 का आयोजन किया था, जिसमें अध्यक्ष, सीईसीएल एंड डब्ल्यू.टी.ओ ने आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।

23-25 अप्रैल, 2015 के दौरान नई दिल्ली में आईसीएआई – सीए सेवाओं की वैश्विक प्रदर्शनी

समिति ने भारत से सीए सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने और भारतीय सीए ब्रांड को विश्व भर में अग्रणी के रूप में स्थापित करने हेतु एक पहल की है। इस दिशा में आईसीएआई द्वारा 23-25 अप्रैल, 2015 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सेवा भागीदार के रूप में आईसीएआई – सीए सेवाओं की वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। सेवाओं की वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) 2015 भारत सरकार की एक पहल थी जिसमें 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था।

माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने, प्रादेशिक परिषद की संबद्ध शाखाओं के सहयोग से माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैचों का आयोजन नागपुर, आगरा और मेरठ में किया था। वर्तमान में आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल में 648 सदस्य पैनलबद्ध हैं।

समिति के विद्यमान प्रकाशनों का पुनरीक्षण

समिति के 'धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 संबंधी एक अध्ययन' शीर्षक वाले तथा 'विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 संबंधी एक अध्ययन' शीर्षक वाले प्रकाशनों को इन विधियों में हुई नवीनतम घटनाओं और संशोधनों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित और अद्यतन किया गया है।

धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ)

सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में काले धन के जनन को रोकने के प्रयासों और उसकी पहलों को ध्यान में रखते हुए और सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में निकट रूप से कार्य करते हुए तथा धन शोधन निवारण के सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सहायता करने के लिए समिति ने सदस्यों के लिए धन शोधन निवारण विधियों संबंधी एक नया प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) आरंभ किया है।

एडीआर में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ में अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम की पुनःसंरचना

- हाल ही में हुई नवीनतम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और मामले के महत्व का मूल्यांकन करते हुए तथा सदस्यों को इस विशिष्ट क्षेत्र में सुसज्जित करने हेतु समिति ने अपने माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित और पुनःसंरचित किया है। इस प्रक्रिया में इस पाठ्यक्रम के नाम को परिवर्तित करके एडीआर (माध्यस्थम, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कर दिया है। यह पाठ्यक्रम आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए अभिप्रेत है, जो माध्यस्थम, मध्यक्ता और सुलह तथा संबंधित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और कौशलों को सुदृढ़ करने की वांछा करते हैं और स्वयं को वैश्विक सेवा बाजार में एक बहु आयामी परामर्शी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम, मध्यक्ता और सुलह के व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं। व्यापक सैद्धांतिक पहलुओं के अलावा, यह पाठ्यक्रम बहुविध मामला अध्ययनों और बनावटी एडीआर कार्यवाहियों के माध्यम से व्यावहारिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता को और अधिक धारदार बनाएगा। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को पाठ्यक्रम के अंत में पूरा किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु परीक्षा देनी होगी।
- समाप्त किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु और पाठ्यचर्या को वर्ष 2005 में तैयार किया गया था जब इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। चालू वर्ष के दौरान, समिति ने वर्तमान बाजार परिदृश्य, नवीनतम घटनाओं, सदस्यों की आशाओं, वृत्तिक अवसरों आदि को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को पुनः संरचित किया था।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

आईसीएआई को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति को विनियमित करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा कानूनी प्राधिकार प्रदान किया गया था। यह घटना अपने आप में इकलौती नहीं थी अपितु यह घटनाओं की ऐसी श्रृंखला में से एक थी, जिसका प्रारंभ बहुत समय पूर्व वर्ष 1866 में हुआ था जब लेखाओं को बनाए रखने और संपरीक्षा से संबंधित विधि को लाया गया था और संपरीक्षक के लिए औपचारिक अर्हता की अपेक्षा की गई थी। उसके पश्चात् भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 का अधिनियमन किया गया था, जिसमें लेखा बहियों को रखे जाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई थी। उक्त कंपनी अधिनियम की धारा 144(2) के अधीन नियमों के दो सेट, अर्थात् संपरीक्षक प्रमाणपत्र नियम, 1932 और निर्बंधित प्रमाणपत्र नियम, 1932 को विरचित किया गया था।

वृत्ति की इस विरासत के साथ एक युवा और लोकतांत्रिक भारत में आईसीएआई का गठन किया गया था, जिसे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विनियमित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जो स्वयं भारत के विकास की कहानी में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। "विनियमन", जैसा कि नाम से दर्शित होता है, से चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उचित व्यवहार अभिप्रेत है और किसी वृत्तिक कदाचार के लिए उन पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, अधिनियम के साथ संलग्न दो अनुसूचियों के साथ अधिनियमित किया गया था, जिसमें वृत्ति के सदस्यों के लिए अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए संनियम अधिकथित किए गए थे। अधिनियम की धारा 22 'वृत्तिक कदाचार' को परिभाषित करती है और

उसके संघटकों के बारे में भी बताती है। दो अनुसूचियाँ ब्यौरेवार रूप से ऐसे विभिन्न करणों और लोपों को वर्णित करती हैं जो वृत्तिक/अन्य कदाचार का गठन करते हैं, जिनके संबंध में अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसार दंड दिया जाता है। संस्थान के अनुशासन तंत्र के संबंध में अधिनियम में ही उपबंधित किया गया है, जिसका प्रभावी रूप से और बिना किसी कठिनाई के अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से ही अनुपालन किया गया है।

इस प्रणाली के सुस्थापित होने के बावजूद भी, एक आचार-संहिता लाने के संबंध में विचार किया गया था और ऐसा आधुनिक समय में वृत्ति के आयामों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अतः, आईसीएआई ने नवंबर, 1963 में अपने सदस्यों के लिए नैतिक-संहिता के पहले संस्करण को निकाला था, जिसे उस समय 'आचार-संहिता' कहा गया था। नैतिक-संहिता ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों को विनियमित करने हेतु वृत्तिक नैतिक मानकों को स्थापित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम को अनुपूरित किया था। अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट फेडरेशन (आईएफएसी) की वर्ष 2009 की नैतिक संहिता से उपबंधों को सम्मिलित करके भारतीय नैतिक संहिता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1975 में वृत्ति के सदस्यों के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ, संस्थान के नैतिक मानक बोर्ड का गठन किया गया था। प्रारंभ से ही, यह बोर्ड विभिन्न वृत्तिक साधनों और पद्धतियों के माध्यम से सदस्यों की प्रतिस्पर्धात्मक बढत को सुदृढ़ करने के लिए सदस्यों को सुसज्जित बनाने हेतु विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। संस्थान के नैतिक मानक बोर्ड को सदस्यों के लिए नैतिक संहिता को अद्यतन करने का कार्य सौंपा गया है। बोर्ड के मिशन का कथन निम्नानुसार है :

'श्रेष्ठता, स्वाधीनता, सत्यनिष्ठा के आदर्शों को दीर्घकाल से हृदय में संजोए रखते हुए, सदस्यों के लिए नैतिकता और नैतिक व्यवहार की समसामयिक और प्रगतिशील संहिता को उत्सर्जित करने का कार्य करना और सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा करना भी है।'

नैतिक मानक बोर्ड, उसे निर्दिष्ट नैतिकता संबंधी मुद्दों की समीक्षा भी करता है और उन पर अपनी राय भी प्रदान करता है। नैतिक संहिता के अलावा बोर्ड अपने प्रकाशनों 'नैतिकता संबंधी मुद्दों पर एफ.ए.क्यू.', 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शक टिप्पण' का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण भी करता है। बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठता, सुयोग्यता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह किसी अस्तित्व के संपरीक्षक के रूप में अन्यायपूर्ण ढंग से हटाए जाने के विरुद्ध सदस्यों की शिकायतों की परीक्षा और निपटारा भी विकसित प्रक्रिया के अनुसार करता है और सदस्यों के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

विशेषज्ञ राय

आज के आर्थिक विकास के युग में, कारबार संव्यवहार और अधिक जटिल तथा पेचीदा हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, अकाउंटेंटों और संपरीक्षकों को अपने कृत्यों का निर्वहन विभिन्न लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के ढांचे के अधीन रहते हुए करना होता है, जो पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्वीकार्य होते जा रहे हैं। ऐसी जटिल परिस्थितियों में, लेखांकन वृत्तिकों के समक्ष कतिपय ऐसी पेचीदा परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ एक अनुप्रमाणित मत की अपेक्षा होती है। ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई की परिषद् ने, आईसीएआई के सदस्यों के लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और अन्य संबद्ध विषयों की बाबत व्यापक मुद्दों पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था तथापि, समिति ऐसे किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों का केवल विधिक निर्वचन अंतर्बलित होता है। यह ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती है, जो ऐसे किसी मामले को प्रभावित करते हैं, जो आईसीएआई की अनुशासन समिति या किसी विधि के न्यायालय या आयकर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य उपयुक्त विभाग के समक्ष लंबित हैं। समिति सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देती है, जो कि आईसीएआई की वेबसाइट पर उसके हाइपर लिंक http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142 पर उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा दी गई राय ऐसी राय हैं या समिति के सदस्यों के किन्हीं विशिष्ट प्रश्नों के तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए मत ऐसे मत हैं, जो मत देने की तारीख को आईसीएआई के लागू लेखांकन/संपरीक्षा मानकों, मार्गदर्शक टिप्पणों और किन्हीं अन्य उद्घोषणाओं और साथ ही प्रश्न की परिस्थितियों के अंतर्गत लागू सुसंगत विधियों और विनियामक परिस्थितियों पर आधारित हैं। अतः, प्रत्येक राय को समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की तारीख के पश्चात् हुए किन्हीं संशोधनों और/या अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

यद्यपि, समिति द्वारा दी गई राय या व्यक्त किया गया मत समिति के सदस्यों की राय या मत का प्रतिनिधित्व करता है और वह आईसीएआई की परिषद् की शासकीय राय नहीं होता है। यह एक प्राधिकार युक्त मार्गदर्शन के रूप में होता है, जिसे विभिन्न शासकीय/विनियामक निकाय जैसे कि भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि मान्यता प्रदान करते हैं और न्यायालय आदि द्वारा भी उनका अवलंब लिया जाता है।

01.04.2014 से 7.07.2015 की अवधि के दौरान, समिति ने आईसीएआई के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों पर 61 रायों को और विनियामकों/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 6 रायों को अंतिम रूप दिया था। ऐसे मुद्दों में, जिन पर समिति द्वारा इस अवधि के दौरान राय दी गई थी, अर्जित भूमियों के लिए प्रतिपूर्ति पर संदत्त ब्याज का उपचार, धारण कंपनी द्वारा किसी अनुषंगी कंपनी को भेजे जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में एएस 15 के अनुसार अपेक्षाओं का प्रकटन, उधार संबंधी लागतों का लेखाकरण संबंधी उपचार, जब किसी संनिर्माण कार्य की परियोजना में बाधा आती है तो उस अवधि के दौरान उपगत प्रशासनिक और अन्य साधारण शीर्षोपरि व्यय, एक दीर्घकालिक दायित्व के माध्यम से क्रेता के खाते/प्रदायकर्ता के खाते में पुनः संदत्त रकम के बारे में एएस 11 के पैरा 46 के लागू होने के संबंध में, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और पुनरीक्षित डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार संवहनीय क्रियाकलापों के मद्दे ऐसे व्यय के लिए लेखांकन, जिसे खर्च नहीं किया गया था, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास में लगी किसी कंपनी द्वारा भूमि के पट्टे के लिए प्राप्त पट्टा निक्षेपों का लेखाकरण संबंधी उपचार, साधारण वनीला काल विकल्प द्वारा उसके अंतर्गत आने वाले विदेशी मुद्रा धनीय दायित्वों (हेज्ड) का पुनर्कथन, एफसीसीबी को जारी करने पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज की लागत से संबंधित उपचार, चाहे विदेशी मुद्रा (अमरीकी डालर) में संदत्त प्रीमीयम के परिशोधन द्वारा इसे उधार संबंधी लागतों के रूप में उपचारित करने हेतु सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं, ऐसी कारबार हानियों, जिन्हें गणना में नहीं लिया गया है और गणना में न लिए गए अवमूल्यों पर आस्थगित कर आस्ति को मान्यता, मुद्रा परिवर्तन में केवल मूल राशि के लिए लेखांकन, प्रत्यक्ष रूप से और विदेशी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से अर्जित तेल और गैस आस्तियों के लिए उधार संबंधी लागत का लेखांकन उपचार आदि हैं।

समिति द्वारा जारी सभी रायों को राय सारसंग्रह की जिल्द के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक सारसंग्रह के 34 जिल्दों को विक्रय के लिए जारी किया जा चुका है। सभी रायों के सारसंग्रह की सभी 34 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1350 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जिसमें सुगम संदर्भ के लिए प्रयोक्ता अनुकूल लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, जो वांछित विषय और/या किसी विशिष्ट अवधि के दौरान जारी राय का पता लगा सकते हैं, भी जारी किया गया है जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 34 के साथ उपलब्ध है।

समिति द्वारा जारी की गई कुछ राय आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित होती हैं। समिति की कतिपय अभिनव रायों को आईसीएआई की वेबसाइट पर समिति के नॉलेज शेयरिंग पृष्ठ पर भी रखा जाता है।

5.13 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति

वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति आईसीएआई की एक अस्थायी समिति है। इस समिति को विभिन्न क्रियाकलाप करने का कार्य सौंपा गया है, जो निम्नानुसार है :

1. समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।
2. समिति विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है।
3. वर्तमान में समिति दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अर्थात् विदेशी मुद्रा और राजकोषीय प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और व्युत्पन्न संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है।
4. समिति ने दो और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं, अर्थात् वित्तीय बाजारों और प्रतिभूमि विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और मूलभूत विश्लेषण तथा साम्या अनुसंधान सहित तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
5. समिति, समिति से संबंधित विषयों पर अध्ययन करती है और प्रकाशन निकालती है।
6. समिति लाइव वेबकास्टों और गुगल हेंगआउट का भी आयोजन करती है।
7. समिति अपनी वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय बाजारों के संबंध में पणधारियों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है।

1. निवेशक जागरुकता कार्यक्रम

समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन करती है। निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति पूरे भारत वर्ष में निवेशकों को शिक्षित करने के लिए निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

समिति अपने निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में उसके विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने वाली इकाईयों पीओयू (प्रादेशिक परिषद, शाखाएं, अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और अध्ययन समूह) और आरपी (संसाधन व्यक्तियों) के माध्यम से करती है।

1 अप्रैल, 2004 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान कुल 849 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें से 91 कार्यक्रमों का आयोजन पीओयू द्वारा तथा शेष 751 कार्यक्रमों का आयोजन संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया गया था।

समिति ने तीन वृहत्त निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

समिति, 'राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज – निवेशक संरक्षण निधि न्यास (एनएसईआईपीएफटी)' के तत्वधान में उसके विभिन्न कार्यक्रम आयोजक इकाईयों पीओयू के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ऐसे कुल चार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, समिति एक हजार से अधिक निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रही है।

2. संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति कंपनी अधिनियम, 2013, बजट 2015 के अनुसार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में संशोधनों, वित्तीय योजनाओं, बैंक संपरीक्षा आदि के संबंध में अपने सदस्यों को वृत्तिक रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाती है।

1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान 38 संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

समिति ने 27 मई से 30 मई, 2014 के दौरान मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के लिए सफलतापूर्वक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की ओर से अत्यधिक सराहना और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

3. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क) विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

पूंजी, धनीय बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजारों में हो रही हाल ही की घटनाओं ने विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव किया है और जिसके कारण तकदी संबंधी दबावों में वृद्धि हुई है, इसलिए निगमों और बैंकों ने राजकोष संबंधी और विदेशी मुद्रा प्रबंध संबंधी कृत्यों पर और अधिक ध्यान देना आरंभ किया है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और धन के संचालन ने तथा अन्य देशों से और उनमें निधियों के उपयोजन के कारण भी राजकोष और विदेशी मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी में वृद्धि हुई है। अतः, इसे ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया गया था। समिति ने आज की तारीख तक विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 27 बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान समिति ने 7 बैचों (अर्थात् 20वें बैच से 27वें बैच) को सफलतापूर्वक पूरा किया है और 28वां, 29वां, 30वां और 31वां बैच क्रमशः कोलकाता, कानपुर, मुंबई और दिल्ली में सफलतापूर्वक चल रहा है।

ख) व्युत्पन्न संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

पिछले तीन दशकों में व्युत्पन्न बाजार ने अत्यधिक विकास दर्ज किया है। विश्वभर में अनेक एक्सचेंजों पर व्युत्पन्न संविदाओं की बड़ी संख्या में किस्मों को आरंभ किया गया है। अभी तक, इस क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के विचार से व्युत्पन्न संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया गया था। समिति ने आज की तारीख तक इसके दो बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने इस आवासीय पाठ्यक्रम के पहले बैच का सफलतापूर्वक संचालन हैदराबाद स्थित उसके उत्कृष्टता केंद्र में पूरा किया है। समिति ने, व्युत्पन्न संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (आवासीय) के दूसरे बैच को अगस्त, 2015 के दौरान हैदराबाद स्थित उसके उत्कृष्टता केंद्र में पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

4. हाल ही में प्रारंभ किए गए दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क) वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने हाल ही में "वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम को आरंभ करने का उद्देश्य दोहरा है – एक ओर तो यह ऐसे सदस्यों की सहायता करता है जो वित्तीय बाजारों में मध्यवर्तियों के रूप में कैरियर बनाने के लिए इच्छुक हैं और दूसरी तरफ यह वित्तीय बाजारों के साथ जुड़े इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की दक्षता में वृद्धि करता है और बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में उन्हें समर्थ बनाता है।

ख) मूलभूत विश्लेषण और साम्या अनुसंधान सहित तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाणपत्र

समिति ने "मूलभूत विश्लेषण और साम्या अनुसंधान सहित तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाणपत्र" आरंभ किया है। यह पाठ्यक्रम शेयर बाजार, स्टॉक बाजार के उद्योग में लगे युवा विश्लेषकों के लिए आरंभ किया गया है और इसमें तकनीकी और आधारीक मूलभूत विश्लेषण सम्मिलित हैं।

5. प्रकाशन और अनुसंधान

समिति ने हाल ही में सीए दिवस समारोह के अवसर पर अर्थात् 1 जुलाई, 2015 को “निवेश अवसर और निवेशक जागरुकता” नामक एक प्रकाशन जारी किया है। इस प्रकाशन को जारी करने का उद्देश्य साधारण जनता को इस संबंध में जागरुक बनाना है कि वे किस प्रकार विभिन्न प्रतिभूतियों में अपने धन का निवेश करें जिससे कि न्यूनतम जोखिम के साथ उन्हें अधिक प्राप्तियां हो सकें। इस प्रकाशन की अंतर्वस्तु में धन संबंधी जादुई मंत्र, व्यष्टि – निवेशक और धन, वित्तीय और कर योजना, निवेश की कला, निवेश संबंधी जानकारी, आईसीएफ और निवेशक जागरुकता, प्रधानमंत्री की जन-धन योजना, कर संबंधी प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

6. वेबकास्ट और गुगल हँगआउट

समिति ने अपने सदस्यों के ज्ञान और कौशलों के सेट में वृद्धि करने के लिए अभी तक 18 वेबकास्टों और 1 गुगल हँगआउट का आयोजन किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने 6 वेबकास्टों और 1 गुगल हँगआउट का आयोजन किया है। इनके ब्यौरे नीचे उल्लिखित किए गए हैं :

- क. 9 मई, 2014 को “निगम ऋण पुनः संरचना (सीडीआर) और संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ)” विषय पर तेरहवें वेबकास्ट का आयोजन।
- ख. 30 मई, 2014 को “वित्तीय योजना और धन प्रबंध” विषय पर चौदहवें वेबकास्ट का आयोजन।
- ग. 12 दिसंबर, 2014 को “तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से स्टॉक बाजार में निवेश और स्टॉक बाजारों में निवेश की कमियां” विषय पर पन्द्रहवें वेबकास्ट का आयोजन।
- घ. 2 मार्च, 2015 को “संघीय बजट 2015 के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में संशोधन” विषय पर सोलहवें वेबकास्ट का आयोजन।
- ङ. 11 मई, 2015 को “जवाबदेही और सुशासन में सी एंड एजी की भूमिका – संपरीक्षा के बदलते पैटर्न, सीए भ्रातृसंघ के लिए उसकी संगतता” विषय पर सतरहवें वेबकास्ट का आयोजन, इसका आयोजन वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से किया गया था और इसे श्री शैलेन्द्र पांडे, भारत के पूर्व उप महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा संबोधित किया गया था।
- च. 1 जून, 2015 को आईसीएआई, नई दिल्ली में “कंपनी अधिनियम, 2013 के करंतीन मुद्दों पर लाइव वेबकास्ट” विषय पर अठारहवें वेबकास्ट का आयोजन।
- छ. 25 मई, 2015 को आईसीएआई, नई दिल्ली में “भारत में माल और सेवाकर (जीएसटी) का पर्यावलोकन” विषय पर पहले गुगल हँगआउट का आयोजन।

7. समिति की वेबसाइट :

समिति अपनी वित्तीय बाजारों संबंधी वेबसाइट अर्थात् www.financialmarket.icai.org को नियमित रूप से अद्यतन करती है। यह वेबसाइट उपयोगिता मित्र प्ररूप में है और सदस्य सुगमता से समिति में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत बने रह सकते हैं।

5.14 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

आईसीएआई, अपने वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफ.आर.आर.बी.) के माध्यम से देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यौहारों का सुधार करने का प्रयत्न करता है। एफ.आर.आर.बी., जो कि 13 वर्षों से कार्य कर रहा है, विनियामकों और आईसीएआई के सदस्यों के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहा है।

एफ.आर.आर.बी. विभिन्न उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट का, स्वप्रेरणा से या किसी विनियामक निकाय द्वारा उसको प्रतिनिर्देश पर पुनरीक्षण करता है, या जहां मीडिया रिपोर्ट द्वारा गंभीर लेखा अनियमितताओं को उजागर किया गया है, वहां, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का अवधारण करने की दृष्टि से पुनरीक्षण करता है :

- (क) वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन ;
- (ख) उद्यमों से सुसंगत विनियामक निकायों, विधियों और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन ; और
- (ग) उद्यमों और साथ ही संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन।

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकन और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं।

साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन

स्वप्रेरणा से

बोर्ड ने, इस अवधि के दौरान 52 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है, जिनमें से 4 मामलों को आईसीएआई के निदेशक, अनुशासन को निर्दिष्ट किया गया है तथा 42 मामलों में, ऐसे उद्यमों के, जिनके वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान संप्रेक्षण किए गए हैं, संपरीक्षकों को अननुपालन संबंधी उपयुक्त सूचना जारी करने का विनिश्चय किया गया था।

विशेष मामले

• सेबी द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय विवरण

बोर्ड ने अपने निर्देश निबंधनों के अनुसार सेबी द्वारा उसे निर्दिष्ट तीन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया था।

• कतिपय मीडिया रिपोर्टों/अन्य तथ्यों के आधार पर, जिनमें लेखांकन या वित्तीय अनियमितताओं को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, चुने गए मामले

मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, 6 वित्तीय विवरणों को चुना गया था और बोर्ड ने अभी तक तीन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन पूरा कर लिया है।

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजनीतिक दलों के संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन

भारत निर्वाचन आयोग ने आईसीएआई को 35 राजनीतिक दलों के संपरीक्षित लेखा यह देखने के लिए निर्दिष्ट किए थे कि क्या वे लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं। बोर्ड ने उसे निर्दिष्ट लेखापरीक्षित लेखाओं के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है और इस संबंध में अपनी एक रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

सेबी के क्यूएआरसी द्वारा निर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन

सूचीबद्ध अस्तित्वों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के अपने प्रयास के भागरूप में, सेबी ने अर्हित संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन समिति (क्यूएआरसी) का गठन किया है। इसकी भूमिका, सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उसे निर्दिष्ट अर्हित वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन करना सम्मिलित होगा। सेबी ने आईसीएआई-एफआरआरबी से महत्वपूर्ण संपरीक्षा अर्हता का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया है। एफआरआरबी इस संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करेगा कि क्या यह अर्हता न्यायोचित है अथवा नहीं। सेबी-क्यूएआरसी, क्यूएआरसी बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर और एफआरआरबी की राय पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि सूचीबद्ध उद्यम प्रोफार्मा वित्तीय परिणामों के माध्यम से अपने वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण करें।

एफआरआरबी दिसंबर, 2013 से ऐसे पुनर्विलोकनों के लिए क्यूएआरसी से जुड़ा है। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने उसे निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट संपरीक्षा अर्हता से संबंधित 103 मामलों और साथ ही ऐसी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो, यथास्थिति, किसी कंपनी और/या संपरीक्षक से प्राप्त हुई हो, पर विचार किया है और 100 मामलों में अपने विचारों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन

बोर्ड ने 21 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया था, जो संबंधित वर्षों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर तकनीकी पुनर्विलोकनों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे। इस अवधि के दौरान, 79 उद्यमों की पुनर्विलोकन रिपोर्टों को इन समूहों को आबंटित किया गया था, जिनमें से इन समूहों ने 70 उद्यमों की पुनर्विलोकन रिपोर्टों को प्रस्तुत कर दिया है।

आगामी प्रकाशन

संस्थान के जर्नल "द चार्टर्ड अकाउंटेंट में लेख"

आईसीएआई के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान जानकारी में आए अननुपालनों के संबंध में अवगत कराने के विचार से, कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा पाए गए 'रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अननुपालन' संबंधी एक टिप्पण को आईसीएआई के जर्नल के मई, 2015 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों और संपरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने और उन्हें लेखांकन मानकों में किए गए परिवर्तनों से अवगत कराने और साथ ही संस्थान और/या अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा इस अवधि के दौरान जारी संपरीक्षा मानकों से उन्हें अवगत कराने के विचार से बोर्ड ने ठाणे, झांसी, भयन्दर, वसंत नगर, कोलकाता, चेन्नई, जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई, राजकोट, जलगांव में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों संबंधी 11 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें 1881 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।

‘राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी व्यवहार’ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन

राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों के संपरीक्षकों के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कौशलों में वृद्धि करने और उन्हें राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान एफआरआरबी द्वारा पाए गए प्रमुख अननुपालनों से अवगत कराने के लिए 23 जून, 2015 को नई दिल्ली में “राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी व्यवहार” विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डा. नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा श्री पी.के. दास, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग के साथ किया गया था। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में 27 राजनीतिक दलों के संपरीक्षकों ने भाग लिया था।

5.15 अप्रत्यक्ष कर समिति

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के संबंध में पहले

(i) **टीएआरसी को कर प्रशासन संबंधी मुद्दों पर सुझाव :** सरकार ने कर नीतियों को लागू करने और सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के संदर्भ में भारत में कर विधियों का पुनर्विलोकन करने के विचार से डा. पार्थसारथी सोम की अध्यक्षता में एक कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) का गठन किया है। इस संबंध में, समिति ने अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अध्यक्ष, कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) को 17 अप्रैल, 2014 को प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

(ii) **सीबीईसी को सेवाकर के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रारूप :** 8 मई, 2014 को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को सेवाकर संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रारूप एक अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसमें सेवाकर संपरीक्षा आरंभ करने का सुझाव दिया गया था।

(iii) **आयुक्त, दिल्ली को संपरीक्षा रिपोर्ट सूक्ष्म रूप में – एआर 1 :** समिति ने तारीख 29 मई, 2014 को आयुक्त, दिल्ली वेट को दिल्ली वेट संपरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप (एआर 1) का सूक्ष्म प्रारूप उसके कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप को आयुक्त, डी वेट के साथ हुई अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति की चर्चा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था।

(iv) बजटपूर्व और बजट-पश्च ज्ञापन :

क) बजटपूर्व ज्ञापन 2014 और 2015 – अप्रत्यक्ष कर का प्रस्तुत किया जाना

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजटपूर्व ज्ञापन, 2014 और 2015 को, क्रमशः 2 जून, 2014 और 15 दिसंबर, 2014 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इस ज्ञापन में कर संग्रहण में सुधार करने, मुकदमों की संख्या में कमी/उन्हें न्यूनतम करने, कराधान विधियों के उपबंधों के सुव्यवस्थिकरण, प्रशासनिक और प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सुझाव अंतर्विष्ट थे।

ख) वित्त मंत्रालय के साथ बजटपूर्व बैठक

अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति और अप्रत्यक्ष कर समिति के सदस्यों ने 2 जून, 2014 और 15 दिसंबर, 2014 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बजटपूर्व बैठकों में भाग लिया था और क्रमशः संस्थान के बजटपूर्व ज्ञापन, 2014 और 2015 में की गई सिफारिशों को संक्षिप्त रूप से बताया था।

ग) बजट-पश्च ज्ञापन 2014 और 2015 – अप्रत्यक्ष कर का प्रस्तुत किया जाना

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट-पश्च ज्ञापन, 2014 और 2015 को, क्रमशः 22 जुलाई, 2014 और 27 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किया गया था। इस ज्ञापन में ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव अंतर्विष्ट थे, जो बजट प्रस्तावों को कार्यान्वित करते समय सामने आ सकते थे।

(v) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार को वेट संपरीक्षा प्रारंभ करने के लिए अभ्यावेदन :

8 जुलाई, 2014 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने राज्य में वेट संपरीक्षा आरंभ करें। इस अभ्यावेदन में, उस समय प्राप्त होने वाले फायदों का उल्लेख किया गया था, जो उस समय उद्भूत होंगे यदि ऐसी संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा कराई जाएगी।

(vi) सीबीईसी को कर प्रशासन संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रस्तुतीकरण

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड से प्राप्त हुए एक पत्र के प्रत्युत्तर में, समिति ने 19 सितंबर, 2014 को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कर प्रशासन संबंधी मुद्दों पर सुझाव प्रस्तुत किए थे।

(vii) सितंबर, 2014 को समाप्त हुई छमाही के लिए सेवाकर विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए सीबीईसी को अभ्यावेदन

समिति ने 7 अक्टूबर, 2014 को सीबीईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि सितंबर, 2014 को समाप्त हुई छमाही के लिए सेवाकर विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित किया जाए। तदनुसार, सीबीईसी ने अपने तारीख 24 अक्टूबर, 2014 के आदेश सं. 02/2014-एसटी के द्वारा अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2014 की अवधि के लिए सेवाकर विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को 25 अक्टूबर, 2014 से बढ़ाकर 14 नवंबर, 2014 कर दिया गया था।

(viii) प्रस्तावित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन

समिति ने 27 नवंबर, 2014 को सरकार को प्रस्तावित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। सेवा पद को परिभाषित करने, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने, प्रवेश कर को जीएसटी में समाविष्ट आदि करने, जैसे विभिन्न सुझावों को सरकार द्वारा संसद में पुरःस्थापित विधेयक में सम्मिलित किया गया था।

(ix) शिक्षा उपकर और एसएचईसी की उपयोगिता के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सीबीईसी को अभ्यावेदन

समिति ने 28 अप्रैल, 2015 को टीआरयू, सीबीईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनसे निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है :

- क) निर्धारिती के अप्रयुक्त ईसी और एचएसईसी के पुराने प्रत्यय के संबंध में उपचार ;
- ख) 1 मार्च, 2015 को अंतरण में उत्पाद-शुल्क मालों के संबंध में उपचार, जिसमें बिल तैयार करने में उपकर का तत्व अंतर्बलित है ; और
- ग) सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन उपकर को वापस लेने के लिए प्रभावी तारीख के बीच में विसंगति, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माता के हाथ में प्रत्यय का एकत्रण होगा क्योंकि उस समय उत्पाद-शुल्क में कोई उपकर नहीं होगा जब कि सेवाकर पर उपकर लागू होगा।

इस संबंध में, आधारीक उत्पाद-शुल्क के संदायों के लिए ईसी और एसएचईसी के प्रत्यय का उपयोग करने के संबंध में निम्नलिखित कुछ मुद्दों का समाधान तारीख 30 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 12/2015 – केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के माध्यम से कर दिया गया था :

- क) 1 मार्च, 2015 को या उसके पश्चात् अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के कारखाने में प्राप्त अंतःनिवेशों या पूंजी मालों पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ;
- ख) वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के कारखाने में प्राप्त पूंजी मालों पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर का बकाया 50 प्रतिशत ; और
- ग) 1 मार्च, 2015 को या उसके पश्चात् अंतिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा प्राप्त अंतःनिवेशों पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

तदनुसार, 25 जून, 2015 को सीबीईसी को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बकाया मुद्दों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था :

- क) निर्धारिती के पास 28 फरवरी, 2015 को एकत्रित उत्पाद-शुल्क के ईसी और एसएचईसी के अप्रयुक्त/एकत्रित पुराने प्रत्यय के संबंध में उपचार।
- ख) निर्धारिती के पास 31 मई, 2015 को एकत्रित सेवाकर के ईसी और एसएचईसी के अप्रयुक्त/एकत्रित पुराने प्रत्यय के संबंध में उपचार।
- ग) 1 जून, 2015 को या उसके पश्चात् सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं के संबंध में शिक्षा उपकर और एसएचईसी का उपचार।

(x) प्रमाणित सुविधा केंद्र के लिए सीबीईसी के साथ एमओयू का विस्तारण

प्रमाणित सुविधा केंद्र (सीएफसी) के संबंध में सीबीईसी के साथ एमओयू को दो वर्ष की और अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, कोई व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं सीएफसी के रूप में रजिस्टर कर सकता है और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर निर्धारितियों के लिए विवरणियों और अन्य दस्तावेजों को अपलोड कर सकता है।

(xi) प्रवर समिति को 122वां संविधान संशोधन (जीएसटी) विधेयक, 2014 के बारे में सुझाव

समिति ने 7 जुलाई, 2015 को जब राज्य सभा द्वारा उसे यह विधेयक निर्दिष्ट किया गया था, प्रवर समिति को 122वां संविधान संशोधन (जीएसटी) विधेयक, 2014 के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

(xii) उत्पाद-शुल्क और सेवाकर कमीशनरी के पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरकार को उसकी सक्षमता निर्माण में सहायता करने और राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में सहायता करने के विचार से समिति नियमित रूप से उत्पाद-शुल्क और सेवाकर कमीशनरियों के पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवधि के दौरान, समिति ने विभिन्न कमीशनरियों और एनएसीईएन के लिए 37 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

इसके अतिरिक्त, समिति ने होटल मालिकों, यात्रा अभिकर्ताओं और टूरर प्रचालकों के साथ एक परस्पर क्रियाशील सत्र में, जिसका आयोजन भुवनेश्वर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कमीशनरी द्वारा 1 मई, 2014 को किंग्स कोर्ट, होटल क्राउन, भुवनेश्वर में किया गया था, एक ज्ञान भागीदार के रूप में सहायता प्रदान की थी।

ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआई के सरकार के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

(i) लाइव वेबकास्ट

इस अवधि के दौरान, समिति ने सदस्यों के लिए राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से 18 वेबिनारों का आयोजन किया था। इस लाइव वेबकास्ट को एक लाख से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था और उन्होंने इनकी सराहना की थी। इन वेबकास्टों की रिकार्डिंग को <http://www.icaai.org/post.html?postid=9656> पर देखा जा सकता है।

(ii) सीमाशुल्क, सेवाकर, उत्पाद-शुल्क और केंद्रीय विक्रय कर के संबंध में ई-पठन

माउस के एक क्लिक के साथ कहीं भी और किसी भी समय सदस्यों द्वारा पठन को सुकर बनाने के विचार से समिति ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और केंद्रीय विक्रय कर के संबंध में ई-पठन प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, सेवाकर और सीमाशुल्क से संबंधित ई-पठन को वित्त अधिनियम, 2014 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है।

(iii) समिति का वेबसाइट पोर्टल www.idtc.icaai.org

समिति ने अपने सदस्यों को अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की ई-परीक्षा सुविधा को उपलब्ध कराने, सदस्यों को प्रकाशनों का लेखन करने और उनका पुनर्विलोकन करने हेतु आमंत्रित करने, सरकार को प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों से सुझाव मांगने आदि जैसी सेवाएं सदस्यों को उनके द्वार तक प्रस्तावित करने हेतु अप्रत्यक्ष कर समिति पोर्टल www.idtc.icaai.org को विकसित किया है।

आयोजित किए गए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और पाठ्यक्रम

(i) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम – यू.के. और आयरलैंड का अध्ययन दौरा

अप्रत्यक्ष कर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ संयुक्त रूप से 26 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2014 के दौरान एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया था। इस अध्ययन दौरे में वेट, यू.के. और आयरलैंड में स्थित संस्थागत पणधारियों के साथ परस्पर क्रिया जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे।

(ii) अप्रत्यक्ष कर संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें अन्य वृत्तियों के मुकाबले सदैव अग्रणी बने रहने में सहायता करने हेतु समिति ने भुवनेश्वर, सूरत, गुडगांव, एर्नाकुलम, बंगलूरु, वदोदरा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था। इन राष्ट्रीय सम्मेलनों में 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(iii) अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति सदस्यों को एक प्रणालीगत रीति में अप्रत्यक्ष कर संबंधी विशेषीकृत और अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराके उन्हें इस क्षेत्र में उभरने वाले विभिन्न वृत्तिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु समर्थ बनाने के विचार से अप्रत्यक्ष करों संबंधी एक 12 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। इस अवधि के दौरान, समिति ने देश भर में इस पाठ्यक्रम के 21 बैचों का संचालन किया है, जिनमें 820 सदस्यों ने भाग लिया है।

(iv) संकाय विकास कार्यक्रम – नए संकाय विकसित करने के लिए प्रयास

समिति ने अपने संकाय आधार में वृद्धि करने और नए अर्हित व्यक्तियों को एक अप्रत्यक्ष कर संकाय के रूप में एक सुस्थापित मंच उपलब्ध कराने के विचार से नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, मुंबई

में एक राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उससे पूर्व आयोजित सभी संकाय विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था।

(v) आवासीय कार्यक्रम

समिति ने सेवाकर के अधीन सेवाओं के संबंध में कर धारिता का निर्धारण करने और प्रक्रियाओं को समझने के लिए गोवा, धर्मशाला, झांसी और जिम कार्वट पार्क में तीन आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों ने भाग लिया था।

(vi) अन्य संगोष्ठियां और सम्मेलन

सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें अन्य वृत्तियों के मुकाबले सदैव अग्रणी बने रहने में सहायता करने हेतु समिति नियमित रूप से अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में और प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था के संबंध में विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती रही है। इस अवधि के दौरान 96 ऐसी संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया है।

प्रकाशनों का निकाला जाना

(i) सेवाकर संबंधी तकनीकी गाइड/पृष्ठभूमि सामग्री

सेवाकर के क्षेत्र में कार्य कर रहे सदस्यों की सहायता करने के विचार से समिति द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं :

- क) सेवाकर – संकर्म संविदा संबंधी तकनीकी गाइड
- ख) सेनवेट प्रत्यय संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित)
- ग) सेवाकर – बीमा क्षेत्र संबंधी तकनीकी गाइड
- घ) सेवाकर – मनोरंजन क्षेत्र संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री

(ii) राज्य वेट संबंधी तकनीकी गाइड

वेट के क्षेत्र में कार्य कर रहे सदस्यों की सहायता करने के विचार से समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए वेट विधि संबंधी तकनीकी गाइड विकसित करने का विनिश्चय किया है, इस दिशा में समिति द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं :

- क) राजस्थान वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- ख) गुजरात वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- ग) झारखंड वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- घ) मिज़ोरम वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- ङ) असम वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- च) उत्तराखंड वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- छ) दिल्ली वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- ज) कर्नाटक वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- झ) गोवा वेट संबंधी तकनीकी गाइड
- ञ) ओडिशा वेट संबंधी तकनीकी गाइड

(iii) जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री

देश में जीएसटी के संबंध में हुई हाल ही की घटनाओं के संबंध में सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से समिति ने माल और सेवाकर संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री को विकसित तथा जारी किया है। इसके अतिरिक्त, उस पृष्ठभूमि सामग्री को पुनरीक्षित किया गया है, जिसमें 122वां संविधान संशोधन विधेयक, मानकीकृत पीपीटी और जीएसटी के लिए आईटी रणनीति, वेट/जीएसटी कार्यान्वित करने वाले देशों की सूची जैसे अनुलग्नकों को भी जोड़ा गया है।

(iv) जीएसटी किट

समिति ने जीएसटी के विषय पर सुगम समझ को सुकर बनाने के लिए 29 जनवरी, 2015 को बंगलौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक जीएसटी किट को आरंभ किया था। इस किट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं :

- क) जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- ख) जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी

ग) लाइव वेबकास्ट की रिकार्डिंग – जीएसटी पर एक वार्ता

(v) एक नया प्रकाशन : जीएसटी – भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

1 जुलाई, 2015 को संस्थान के वार्षिक समारोह के दौरान एक नया प्रकाशन : जीएसटी – भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान, को जारी किया गया था। इसे विशिष्ट रूप से संसद सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के लिए तैयार किया गया है और इसमें संक्षिप्त रूप से जीएसटी की अवधारणा को और दृष्टांतों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु इसके फायदों को उपदर्शित किया गया है। राजस्व तटस्थ दर, जीएसटी के आईटी रणनीति, वर्तमान और प्रस्तावित कर व्यवस्था के बीच तुलना, अन्य देशों में जीएसटी आदि जैसी अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

(vi) संघीय बजट 2014-15 द्वारा किए गए संशोधनों संबंधी ई-फ्लैश

संघीय बजट 2014-15 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से समिति ने, प्रत्यक्ष कर समिति, अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति और लोक वित्त तथा शासकीय लेखांकन समिति के साथ मिलकर संघीय बजट 2014-15 द्वारा किए गए संशोधनों के संबंध में ई-फ्लैश जारी किया था।

(vii) बैंककारी क्षेत्र में सेवाकर का अनुपालन – पुनरीक्षण

समिति ने अपने प्रकाशन 'बैंककारी क्षेत्र में सेवाकर का अनुपालन' का पुनरीक्षण किया है। इसमें, अन्य बातों के साथ, बैंक की सेवाकर संपरीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर अंतर्विष्ट हैं, जो कि ऐसे सदस्यों के लिए सहायक सिद्ध होंगे, जो बैंककारी क्षेत्र में सेवाकर के अनुपालनों की जांच करते हैं।

(viii) सीबीईसी पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री

समिति ने अप्रैल, 2015 तक किए गए संशोधनों को अंतर्विष्ट करते हुए सीबीईसी पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री का गहन पुनरीक्षण किया है।

(ix) सीबीईसी किट

समिति ने उत्पाद-शुल्क और सेवाकर कमीशनरियों के लिए, सरकार के राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में की गई एक पहल के भागरूप में उनके पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्य और फायदे की समझ को सुकर बनाने हेतु सीबीईसी किट को विकसित किया है। इस किट में प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके उद्देश्य और पृष्ठभूमि सामग्री अंतर्विष्ट है।

5.16 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

वृत्ति के समक्ष आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और प्रैक्टिस गाइडों, प्रशिक्षण सहायिकियों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों के अलावा सदस्यों के फायदे के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्यावहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ईआरपी/ सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आयोजन करके, उन्हें सदस्यों हेतु फायदाप्रद वृत्तिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए परिषद् ने वर्ष 2000 में एक अस्थायी समिति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था।

1. आयोजित किए गए कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेलन/आरआरसी

समिति अनेक आईटी संबंधित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती है, जिनकी अवधि नमनीय होती है और वे सदस्यों को आईटी संबंधी क्षेत्रों में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने में सहायता करते हैं। विभिन्न संगोष्ठियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	तारीख	कार्यक्रम का नाम	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	23-02-2014	सीए के कार्यालय में आईटी सुरक्षा	मुंबई	22
2	08-03-2014	समुन्नत एक्सेल पर कार्यशाला 2010	वाशी, महाराष्ट्र	28
3	05-04-2014	एमएस एक्सेल पर कार्यशाला	सिलीगुड़ी	45
4	17-05-2014	सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यावहारिक कार्यशाला	बदोदरा	35

5	17-05-2014	सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला	जामनगर	8
6	17-05-2014	समुन्नत एक्सेल पर कार्यशाला	धुले	11
7	30-05-2014	डिजिटल खतरों और सुरक्षा पर संगोष्ठी	पणजी	33
8	31-05-2014	समुन्नत एक्सेल पर कार्यशाला	लातूर	26
9	14-06-2014	टेली.ईआरपी 9के अनुकूलतम उपयोग पर अग्रिम पाठ्यक्रम	सिलीगुडी	50
10	11-07-2014	सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	हुबली	286
11	26-07-2014	एक आईटी वातावरण में न्यायालयीय और डिजिटल अन्वेषण पर संगोष्ठी	दिल्ली	121
12	04-10-2014	सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	पुणे	164
13	18-10-2014	सूचना प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी	कोलकाता	127
14	21-11-2014	साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला	भुवनेश्वर	27
15	07-12-2014	साइबर अपराध अन्वेषण और डिजिटल न्यायलयीय लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त उपकरण	मुंबई, बीकेसी	26
16	20-12-2014	मैक्रोज़ पर कार्यशाला के साथ एक्सेल और वीबीए प्रशिक्षण	मुंबई, बीकेसी	10
17	28-03-2015	सीए के कार्यालय में आईटी सुरक्षा	मुंबई, बीकेसी	27
18	04-04-2015	एक लेखापरीक्षा उपकरण के रूप में एक्सेल पर कार्यशाला	मुंबई, बीकेसी	35
19	25-04-2015	सीए के कार्यालय में आईटी सुरक्षा पर कार्यशाला	सूरत	34
20	12-05-2015	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा कपट का पता लगाना और निवारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मुंबई, बीकेसी	29
21	29-05-2015	द्वितीय संकाय विकास कार्यक्रम – न्यायलयीय लेखापरीक्षा और कपट निवारण	मुंबई, बीकेसी	24
22	06-06-2015	न्यायलयीय लेखांकन और कपट निवारण पर संगोष्ठी	हैदराबाद	30
23	11-06-2015	न्यायलयीय लेखांकन और कपट निवारण पर संगोष्ठी	गोवा	42
24	18-06-2015	सूचना प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी	कोलकाता	40
25	03-07-2015	आईएसए पाठ्यक्रम के लिए द्वितीय संकाय विकास कार्यक्रम	मुंबई	24

2. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क) सूचना प्रणाली संपरीक्षा 2.0 संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम

सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम एक ऐसी पहली और अग्रणी तथा महत्वपूर्ण पहल है, जिसे समिति द्वारा सदस्यों को आईएस संपरीक्षा के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाएं प्रस्थापित करने में समर्थ बनाने हेतु आरंभ किया गया है।

समिति ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा 2.0 संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया है, जिसका संचालन ई-पठन (आनलाइन और सुविधा प्राप्त), कक्षा प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण के एक सुमिश्रण के माध्यम से और साथ ही जानकारी के व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित

करने के लिए व्यावहारिक मामला अध्ययनों और परियोजना कार्यों के माध्यम से किया जाएगा।

अद्यतन आईएसए 2.0 पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीए की बढ़ती बाजार आवश्यकताओं को ठोस आईटी कौशलों के साथ पूरा करना है, जो गुणवत्ता से भरपूर परामर्शी/आश्वासन संबंधी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। अध्ययन सामग्री के साथ एक डीवीडी भी है, जिसमें साफ्ट प्रति के रूप में सभी पठन सामग्रियां, ई-पठन, अनुपूरक निर्देश सामग्री और जांच सूचियां अंतर्निहित हैं।

ख) न्यायालयीय लेखांकन और कपट निवारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति न्यायालयीय लेखांकन और कपट निवारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करती है। अब इस पाठ्यक्रम को पूरे देश में प्रारंभ किया गया है। यह पाठ्यक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण, मामला अध्ययनों, संकाय द्वारा प्रस्तुतिकरणों, परियोजनाओं की प्रस्तुति (जिसके लिए 20 अंक प्राप्त होते हैं), पीपीटी प्रस्तुतीकरण (जिसके लिए 20 अंक प्राप्त होते हैं) और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दो न्यायालयीय रिपोर्टें भी तैयार की जाती हैं, जो 60 अंकों की होती हैं। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, एक 100 अंक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा आयोजित की जाती है। यह पाठ्यक्रम सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय है और समिति पूरे देश में इन पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन कर रही है।

क्रम सं.	तारीख	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	08-05-2014 से 18-05-2014	इंदौर	47
2	30-05-2014 से 05-06-2014	कोलकाता	41
3	12-06-2014 से 22-06-2014	मुंबई	52
4	16-07-2014 से 22-07-2014	लुधियाना	44
5	01-08-2014 से 07-08-2014	बेंगलुरु	48
6	10-10-2014 से 19-10-2014	मुंबई	51
7	27-10-2014 से 02-11-2014	हैदराबाद	48
8	06-11-2014 से 12-11-2014	चंडीगढ़	39
9	09-01-2015 से 15-01-2015	मुंबई	47
10	22-01-2015 से 30-01-2015	भोपाल	36
11	31-01-2015 से 06-02-2015	चेन्नई	34
12	25-04-2015 से 10-05-2015	राजकोट	39
13	01-5-2015 से 17-05-2015	लखनऊ	47
14	09-05-2015 से 17-05-2015	ठाणे, महाराष्ट्र	44

15	21-05-2015 से 07-06-2015	इंदौर	40
16	30-05-2015 से 21-06-2015	भुवनेश्वर	46
17	08-06-2015 से 18-06-2015	नागपुर	26
18	12-06-2015 से 28-06-2015	औरंगाबाद	21
19	13-06-2015 से 05-07-2015	जयपुर	29
20	27-06-2015 से 26-07-2015	नई दिल्ली	40
21	03-07-2015 से 26-07-2015	भिलाई	30

3. आईटी जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन

समिति अनेक आईटी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती है जो नमनीय अवधि के होते हैं और जो सदस्यों को आईटी संबंधी क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने में सहायता करते हैं।

4. डीआईएसए संकाय बैठक

समिति ने डीआईएसए पाठ्यक्रम और डीआईएसए पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री का सुधार और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए चार डीआईएसए संकाय बैठकों का आयोजन किया है। समिति ने संकाय से यह अनुरोध किया था कि वे ईटी और एटी परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम मामला अध्ययनों और आदर्श प्रश्न पत्रों का संकलन तैयार करें।

डीआईएसए संकाय बैठक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- 31 मई 2014 को मणिपाल, उडुपी में डीआईएसए संकाय बैठक, जिसमें 25 संकायों ने भाग लिया
- 5 जून 2015 को वीकेसी, मुंबई में डीआईएसए संकाय बैठक, जिसमें 28 संकायों ने भाग लिया
- 30 जून 2015 को सीओई, हैदराबाद में डीआईएसए संकाय बैठक, जिसमें 20 संकायों ने भाग लिया
- 1 जुलाई 2015 आईसीएआई भवन, इंदरप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली में डीआईएसए संकाय बैठक, जिसमें 21 संकायों ने भाग लिया
- 15 जुलाई 2015 को कोलकाता (ईआईआरसी परिसर) में डीआईएसए संकाय बैठक, जिसमें 19 संकायों ने भाग लिया।

5. सरकारी संगठनों के लिए न्यायालयीय लेखांकन पाठ्यक्रम

समिति ने सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के लिए कपट के अन्वेषण और न्यायालयीय लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विनिश्चय किया है। इस पाठ्यक्रम का और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिकारियों और उसके वरिष्ठ सदस्यों को कपट जगत, वित्तीय दुष्कर्मों और उनका पता लगाने के लिए संभावित मार्गों के बारे में अंदरूनी जानकारी प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम कपटों के संबंध में पूर्वतर चेतावनी प्रदान करने, उनकी समीक्षा करने और जब कभी आवश्यक समझा जाए उनके संबंध में अन्वेषण करने के लिए है। अन्वेषण अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से तैयार करने तथा हर प्रकार से सुसज्जित करने हेतु नई और असामान्य पद्धतियों को स्पष्ट करता है तथा इसके दौरान उन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

- भारतीय स्टेट बैंक के पदधारियों के लिए न्यायालयीय लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 11 मार्च, 2015 से 14 मार्च, 2015 के दौरान आईआईसीए मानेसर में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अधिकारियों के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. "सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए)" संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम

सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम (पीक्यूसी) एक ऐसा महान समेकक बल है, जो सदस्यों को अद्वितीय जानकारी के आदान-प्रदान, वृत्तिक विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहलों के लिए एक साथ लाता है। देशभर में आईएसए पीटी बैचों, आईएसए पात्रता परीक्षा और आईएसए निर्धारण परीक्षा का आयोजन किया गया था।

- 10 मई, 2014 को श्रीलंका और नेपाल सहित 42 केंद्रों पर
- 15 नवंबर, 2014 को श्रीलंका सहित 38 केंद्रों पर
- 9 मई, 2015 को श्रीलंका सहित 42 केंद्रों पर

2. संकाय विकास कार्यक्रम

समिति ने 29 मई से 31 मई, 2015 तथा 3 जुलाई से 5 जुलाई, 2015 के दौरान क्रमशः एफएएफपी और आईएसए के लिए आईसीएआई टावर, बीकेसी, मुंबई में दो संकाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया था और इसके लिए क्रमशः एफएएफपी – एफडीपी तथा आईएसए – एफडीपी से 20 और 22 आईएसए संकायों को आमंत्रित किया था। संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापन पद्धति को मानकीकृत करना था। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इसकी सराहना की थी और हमें एफएएफपी तथा आईएसए संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सुधार करने के बारे में काफी अच्छी फीडबैक और सुझाव प्राप्त हुए थे।

3. पुनरीक्षित आईएसए पाठ्यक्रम का शुभारंभ

समिति ने नया आईएसए पाठ्यक्रम 2.0 प्रारंभ किया है और नए पाठ्यक्रम के लिए आईएसए – पीटी बैच को 5 जुलाई, 2014 को आईसीएआई भवन, सेक्टर 62, नोएडा में आरंभ किया गया था। इस डीआईएसए पाठ्यक्रम 2.0 का मुख्य उद्देश्य, शासन, जोखिम प्रबंध, प्रतिभूति, नियंत्रण और अनुपालन के क्षेत्र में सूचना प्रणालियों के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आश्वासन या परामर्शी समनुदेशनों की योजना बनाने और उन्हें सुसंगत मानकों, ढांचागत प्रणालियों, दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुसार पूरा करने के लिए सुसंगत व्यावहारिक ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराना है। डीआईएसए पाठ्यक्रम का संचालन ई-पठन (आनलाइन और सुविधा प्राप्त), कक्षा प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक मामला अध्ययनों और परियोजना कार्य के साथ एक सुमेलित रीति में किया जाता है जिससे कि ज्ञान के व्यावहारिक उपयोजन को सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने 12 फरवरी, 2015 तक पुनरीक्षित पाठ्यचर्या के 36 बैचों का संचालन किया है।

4. विद्यमान ई-पठन कार्यक्रमों को बनाए रखना

समिति निम्नलिखित ई-पठन पाठ्यक्रमों को चलाती है :

- सेवाकर
- अंतरण कीमत निर्धारण
- संपरीक्षा के मानक
- संपरीक्षा के मानक – चरण 2
- संपरीक्षा के मानक – चरण 3
- संपरीक्षा के मानक – चरण 4

5. वेबकास्ट

वृहत् डाटा शासन और अनुपालन, विभिन्न न्यायालयीय संपरीक्षा उपकरणों का बैंकरो और एफआई द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी उपयोग और डाटा प्राइवेसी और संरक्षण : किसी संपरीक्षक का परिप्रेक्ष्य, विषय पर तीन वेबकास्टों का आयोजन किया गया था।

5.17 प्रौद्योगिकी विकास समिति

प्रौद्योगिकी विकास समिति का गठन 1 अप्रैल, 2014 को निम्नलिखित निर्देश निबंधनों के अनुसार किया गया था :

1. कारबार प्रक्रिया कमियों का पता लगाना, कारबार प्रबंधन रणनीति की योजना बनाना, पणधारियों को प्रदान की जाने वाली आईसीएआई की सेवाओं में सुधार करने के लिए आईसीएआई की सहायता करने के उद्देश्य से आईसीएआई के भीतर कारबार प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी पर ध्यान केंद्रित करना और प्रचालनात्मक लागतों में कमी करना।
2. आईसीएआई के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पहचान करना और उसका विकास और मानीटरी

करना

3. आईसीएआई के लिए आईटी मंचों, जिसके अंतर्गत मोबाइल प्लेटफार्म भी है, की पहचान करना और उसका कार्यान्वयन तथा विकास करना और किसी भी समय और कहीं भी पहुंच वाले नए संपर्क प्लेटफार्म को स्थापित करना
4. बाजार में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों की पहचान करना और समिति को यह सुझाव देना कि वह उनके क्रियान्वयन के बारे में तथा उनके फायदों के संबंध में आईसीएआई को सलाह दें
5. विभिन्न आईटी पहलों का पुनर्विलोकन, मानीटरी और कार्यान्वयन
6. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं का पता लगाना और आईसीएआई के फायदे के लिए इनका उपयोग करना।

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप और उपलब्धियां

समिति ने 12 मार्च, 2015 को हुई अपनी दूसरी बैठक तथा 22 अप्रैल, 2015 को हुई तीसरी बैठक में यह विनिश्चय किया कि आईसीएआई में विभिन्न समितियों की बैठकों, आयोजनों आदि के लिए गुगल हैंगआउट आन एयर का संवर्धन किया जाना चाहिए। तदनुसार, समिति ने विभिन्न समितियों और विभागों के लिए एकीकृत यू ट्यूब चैनल, गुगल प्लस पृष्ठ का सृजन किया है। इसके साथ ही समितियों की बैठकों, विभिन्न आयोजनों के लिए गुगल हैंगआउट आन एयर के माध्यम से अनेक आयोजन सफलतापूर्वक किए गए हैं। समिति ने प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी तीसरी समिति बैठक का संचालन आनलाइन गुगल हैंगआउट के माध्यम से किया था।

समिति ने सभी मोबाइल मंचों (एंड्रायड, आईओएस, विंडोज और ब्लैकबेरी 10) के लिए एक आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन “आईसीएआई नाओ” को भी जारी किया है। आईसीएआई नाओ प्रमुख नवीनतम घटनाओं जैसे कि उद्घोषणाएं, आयोजन, फोटो, वीडियो गैलरी, आईसीएआई के समाचार, संस्थान के कार्यक्रम, अध्यक्ष का संदेश, निविदा आदि को बताता है। आईसीएआई की इस मोबाइल एप्लीकेशन के नवीनतम वर्जन को आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org/mobile या संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन सभी मंचों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

समिति ने आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन के नवीनतम वर्जन को अद्यतन किया है जो कि अब एंड्रायड पर 1.12 (10 जून, 2015 को जारी), आईओएस पर 1.6 (10 जून, 2015 को जारी), विंडोज पर 1.3 (10 जून, 2015 को जारी) के रूप में उपलब्ध है। ब्लैकबेरी 10 समर्थित वर्जन को भी 20 फरवरी, 2015 को जारी किया गया था।

आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन सभी मंचों पर सर्वोत्तम निःशुल्क प्रवर्ग के अधीन सूचीबद्ध है और वर्तमान में इसे पांच में से 4.2 रेटिंग प्राप्त है। आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन को 1 जुलाई, 2015 तक 2,30,000 से अधिक छात्रों और सदस्यों द्वारा सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया है।

समिति ने सोशल मीडिया पर भी “फेसबुक, टि्वटर, लिंकेडइन, गुगल प्लस और यू ट्यूब” पर आईसीएआई को समर्थ बनाया है। समिति नियमित रूप से आईसीएआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मानीटरी करती है।

आईसीएआई के सदस्य और छात्र आईसीएआई सोशल नेटवर्क से आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org/followus के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई, 2015 तक आईसीएआई की सोशल मीडिया साइट को 1,65,000 से अधिक छात्रों और सदस्यों द्वारा देखा जा रहा है। (यू ट्यूब चैनल 3500+, गुगल प्लस पृष्ठ 9800+, फेसबुक 42000+, टि्वटर 3500, और लिंकेडइन 1,06,000+)

5.18 आंतरिक संपरीक्षा मानक संबंधी बोर्ड

प्रभावी निगम शासन और जोखिम प्रबंध ढांचे के लिए आंतरिक संपरीक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य करती है। यह इस बात का आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सुशासन के भागरूप में रिपोर्टिंग में पारदर्शिता है। आंतरिक संपरीक्षा का परिधि क्षेत्र विस्तारित हो रहा है क्योंकि बोर्ड और प्रबंधन नए विनियामक वातावरण में उससे जो आशाएं रखते हैं वो पहले से काफी बढ़ गई हैं। आईसीएआई ने वर्ष 2004 में आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड का गठन किया था ताकि यह आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति के भीतर सर्वोत्तम व्यवहारों के संबंध में मूल्यवान अंतर्वस्तु और समकालीन मुद्दों का समाधान उपलब्ध करा सके। बोर्ड आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने वाले सदस्यों की संपरीक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसे सतत और वृत्तिक रूप से निष्पादित किया जाए।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के रूप में आंतरिक संपरीक्षा के संयवहारों को संहिताबद्ध करने के अलावा बोर्ड सदस्यों को तकनीकी साहित्य की सदैव विस्तारणीय टूल किट से लैस करने में भी सहायता करने का प्रयास करता रहा है। इस दिशा में, बोर्ड अथक रूप से साधारण और उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें जारी करने के लिए कार्य कर रहा है, जिनमें किसी आंतरिक संपरीक्षक द्वारा उद्योग विनिर्दिष्ट और अन्य समकालीन क्षेत्रों के संबंध में की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा में प्रयुक्त होने वाली ब्यौरेवार प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। सदस्यों के बीच जानकारी के प्रसार हेतु, बोर्ड संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, वेबिनारों का आयोजन और साथ ही बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन करता है।

आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी अठारह मानक

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह (1 जुलाई, 2013 को यथाविद्यमान)

उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 23 उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें

उद्योग विनिर्दिष्ट आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह (1 जनवरी, 2015 को यथाविद्यमान)

साधारण मार्गदर्शन

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 17 साधारण गाइडें

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी साधारण मानकों का सार-संग्रह (1 जनवरी, 2015 को यथाविद्यमान)

ज्ञान पुस्तिकाएं

आंतरिक संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित दो ज्ञान पुस्तिकाएं।

इस रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के प्रमुख प्रयासों का नीचे उल्लेख किया गया है :

- बोर्ड ने अपनी कार्ययोजना/भावी योजना 2014-15 में, वर्ष के दौरान किए जाने वाले अपने क्रियाकलापों को बोर्ड के कार्यकरण के अनुसार यथासंभव लागू रूप में आईसीएआई की कार्य योजना में दर्शित नीतिगत केंद्र बिन्दुओं के क्षेत्र से सुमेलित करने का प्रयास किया है।
- इस अवधि के दौरान बोर्ड की 5 बैठकों का आयोजन किया गया था।
- बोर्ड ने उद्योग विनिर्दिष्ट आंतरिक संपरीक्षा गाइडों का एक सार संग्रह निकाला है, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी सभी 22 तकनीकी गाइडों का पाठ अंतर्विष्ट है।
- बोर्ड ने साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइडों का एक सार संग्रह निकाला है, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी सभी 10 तकनीकी गाइडों का पाठ अंतर्विष्ट है।
- बोर्ड ने जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक गाइड निकाली है जो इस विषय पर व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है।
- सदस्यों के बीच आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के बारे में ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है इसलिए बोर्ड ने अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया है।
- बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा और संबद्ध विषयों से संबंधित 8 वेबिनारों का आयोजन किया है।
- इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने अपने ई न्यूज लेटर “इंटरनल आडिट एंड ब्रियोंड” के छोटे संस्करण को भी जारी किया है।

क) तकनीकी साहित्य**आईटी साफ्टवेयर उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड**

पिछले दशक के दौरान भारत ने आईटी साफ्टवेयर उद्योग में एक सतत विकास को देखा है, जो कि निरंतर होने वाले उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी परिवर्तनों का साक्ष्य है, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबीलिटी, एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। यह अद्वितीय क्षेत्र प्रक्रियाओं की जटिलता का सामना करता है, जिनके कारण नीतिगत, आर्थिक, प्रचालनात्मक, अनुपालन संबंधी, आपदा, राजनीतिक, मानव पूंजी और मान सम्मान संबंधी जोखिम सामने आते हैं। आंतरिक संपरीक्षक शासन, जोखिम और अनुपालन संबंधी पहलूओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जो कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि आईटी साफ्टवेयर उद्योग विकास के मार्ग पर चलता रहे। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने “आईटी साफ्टवेयर उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड” नामक प्रकाशन, जिसका उद्देश्य आंतरिक संपरीक्षकों को इस अद्वितीय और जटिल उद्योग के बारे में उनकी समझ को सुदृढ़ बनाना है।

जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा योजना संबंधी गाइड

जोखिम प्रबंध, किसी भी संगठन के शासन, प्रबंधन और प्रचालनों में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है क्योंकि यह संगठन को ऐसे जोखिमों को, जो उनके सामने आने वाले हैं, समझने में सहायता करता है, इन जोखिमों का सामना करने हेतु नियंत्रणों को सुस्थापित करने और साथ ही अपने उद्देश्यों की प्रभावी रूप से पूर्ति में भी सहायता करता है। जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा मुख्य रूप से ऐसे जोखिम प्रबंध के संबंध में रिपोर्ट करती है, जिसके अंतर्गत जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, नियंत्रण और उसकी मानीटरी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षकों की उनके जोखिम आधारित दृष्टिकोण को

धारदार बनाने और इस प्रकार उन्हें पणधारियों की आशाओं पर खरा उतरने में समर्थ बनाने के लिए “जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा योजना संबंधी गाइड” नामक प्रकाशन निकाला है।

• **आंतरिक संपरीक्षा संबंधी साधारण दिशा-निर्देश (पुनरीक्षित 2015 संस्करण)**

कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित करने और साम्या सूचीकरण करार के पुनरीक्षित खंड 49 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी साधारण दिशा-निर्देशों का गहन पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित निगम शासन संनियमों ने निश्चित रूप से भारत में निगम शासन संबंधी परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। यद्यपि, ये नई अपेक्षाएं शासन संबंधी मानकों का उन्नयन करने की ईप्सा करती हैं और इस प्रकार आंतरिक संपरीक्षक की, इस नए विनियामक वातावरण में निभाई जाने वाली भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बोर्ड ने इस प्रकाशन को सदस्यों के फायदे के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने हेतु जारी किया है। ये पुनरीक्षित साधारण दिशा-निर्देश, आंतरिक संपरीक्षकों को एक ऐसा ठोस आधार उपलब्ध कराते हैं, जिसके द्वारा वे परिवर्तित परिदृश्य में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं और पणधारियों की आशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

ख) ज्ञान पुस्तिकाएं

ज्ञान पुस्तिका 2 : आंतरिक संपरीक्षा में एक नया युग - कंपनी अधिनियम, 2013

यह ज्ञान पुस्तिका विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सुदृढ़ समर्थन प्रभावी जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और अनुपालन सुनिश्चित करने आदि में आंतरिक संपरीक्षक की बढ़ी हुई भूमिका को उपदर्शित करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पास ऐसे कौशल और ज्ञान होते हैं जो उनकी आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सक्षमता और वृत्तिकता को दर्शित करते हैं।

ग) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड निम्नलिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है :

1. बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए “बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा” संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करता है। आज की तारीख तक, बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर इस पाठ्यक्रम के 176 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसमें देश भर से लगभग 9100 सदस्यों ने भाग लिया था। बोर्ड ने बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच के लिए ओएमआर प्रणाली आरंभ की है। बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए विशेषज्ञ संकाय सदस्यों का एक पैनल भी तैयार किया गया है।

2. उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड “उद्यम जोखिम प्रबंध” संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करता है, ताकि आंतरिक संपरीक्षकों में, संपरीक्षा समिति और कार्यकारी प्रबंध मंडल को जोखिम प्रबंध के संबंध में सलाह और आश्वासन देने के उनके सार्वभौमिकों में वृद्धि करके उनकी पूर्ण संभावनाओं का उपयोग किया जा सके। बोर्ड ने क्रमशः दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में इस पाठ्यक्रम के चार बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। बोर्ड इस पाठ्यक्रम को पुनः संरचित कर रहा है।

3. आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों के लिए प्रस्थापित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऐसे शैक्षिक अनुभव, उपयोग्य ज्ञान और कारबार उपकरणों का सृजन करना है, जो किसी भी संगठन या कारबार परिस्थितियों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। बोर्ड ने हैदराबाद में इस पाठ्यक्रम के एक बैच का सफलतापूर्वक संचालन किया है। बोर्ड इस पाठ्यक्रम को पुनः संरचित कर रहा है।

घ) त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर “इंटरनल ऑडिट एंड बियाँड”

बोर्ड ने अपने त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर “इंटरनल ऑडिट एंड बियाँड” के छठे संस्करण को जारी किया है। इस ई-न्यूजलेटर का उद्देश्य आंतरिक संपरीक्षा जगत की मुख्य धारा में अवसरों का लाभ उठाने के लिए वृत्तिकों और अन्य सुसंगत सदस्यों के बीच अद्यतन जानकारी और तकनीकी उदघोषणाओं के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना है।

ङ) आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में जागरूकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन

बोर्ड देश के विभिन्न भागों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है, जिनकी मेजबानी संस्थान की संबद्ध प्रादेशिक परिषदों/ शाखाओं द्वारा की जाती है। इस अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था :

1. 9 अप्रैल, 2014 को अमृतसर में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी।

2. 10 अप्रैल, 2014 को पटियाला में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी।
3. 26 और 27 मई, 2014 को तिरुपति में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
4. 8 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में “संपरीक्षा, जोखिम और शासन” विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
5. 14 मई, 2015 को नई दिल्ली में आईसीएआई आंतरिक संपरीक्षकों की परस्पर क्रियाशील बैठक

च) आंतरिक संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित लाइव वेबिनार

बोर्ड ने निम्नलिखित लाइव वेबिनारों का आयोजन किया है :

- 23 मई, 2014 को “आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्टिंग” विषय पर 13वां वेबिनार।
- 25 जून, 2014 को “संपरीक्षा समिति को आंतरिक संपरीक्षा के महत्व का प्रदर्शन” विषय पर 14वां वेबिनार।
- 9 अक्टूबर, 2014 को “आंतरिक संपरीक्षा का परिवर्तनशील प्रतिमान” विषय पर 15वां वेबिनार।
- 7 नवंबर, 2014 को “एसएमई की आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण” विषय पर 16वां वेबिनार।
- 27 दिसंबर, 2014 को “भावी सफलता के लिए स्थिति मजबूत करना - आंतरिक संपरीक्षा में संपरिवर्तन” विषय पर 17वां वेबिनार।
- 28 जनवरी, 2015 को “उद्यम जोखिम प्रबंध ढांचा और आंतरिक नियंत्रण ढांचा” विषय पर 18वां वेबिनार।
- 9 फरवरी, 2015 को “गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) की आंतरिक संपरीक्षा” विषय पर 19वां वेबिनार।
- 8 मई, 2015 को “आंतरिक संपरीक्षक से संपरीक्षा समिति की आशाएं” विषय पर 20वां वेबिनार।

छ) संकाय विकास कार्यक्रम

बोर्ड ने अगस्त, 2013 में हैदराबाद में बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। बोर्ड ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया था ताकि वह विनियामकों और बैंकों की आशाओं पर खरा उतर सके। इसके अतिरिक्त, बोर्ड वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसे और कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहा है।

ज) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सर्वेक्षण

बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक सर्वेक्षण कराने का विनिश्चय किया है और इस प्रयोजन के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिलक्षित उद्देश्य देश में आंतरिक संपरीक्षा की वृत्ति में वर्तमान प्रवृत्तियों और उसके समक्ष चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है।

झ) जोखिम प्रबंध के संबंध में ई-पठन

बोर्ड ने, “जोखिम प्रबंध के संबंध में ई-पठन” नामक परियोजना को प्रारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सदस्यों के बीच जोखिम प्रबंध से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बेहतर समझ बनाना है और साथ ही इस क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना भी है।

ञ) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय सभा

बोर्ड, सुसंगत कारबार व्यवहारों के संबंध में विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करने, करंतीन मुद्दों पर चर्चा करने और निगम भारत में आंतरिक संपरीक्षकों की भूमिका को प्रभावित करने वाले अन्य बाजार संबंधी आयामों का समाधान करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “आंतरिक संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय सभा” का आयोजन करने की योजना भी बना रहा है।

5.19 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

किए गए क्रियाकलाप

क. सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

- प्ररूप सं. 3गडख के संबंध में अभ्यावेदन
- अभ्यावेदन – वित्त अधिनियम, 2014 – प्रमुख अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी संशोधन और उनका कार्यान्वयन

- 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की संनिकट कीमत (एएलपी) की संगणना हेतु प्रस्तावित नियमों की प्रारूप स्कीम के संबंध में अभ्यावेदन
- एफआईआई संबंधी मेट के मुद्दे पर श्री अशोक लाहिरी की अध्यक्षता के अधीन बनाई गई कर विधि संबंधी उच्च स्तरीय समिति के साथ 15 जून, 2015 को हुई बैठक में उसे अंतःनिवेशों का प्रस्तुत किया जाना
- नियम 37खख में संशोधन करने और धारा 119 के अधीन परिवर्ती अनुतोष के संबंध में अभ्यावेदन
- प्रत्यक्ष कर समिति को श्री ए.पी. शाह की अध्यक्षता में सृजित समिति के साथ 1 जुलाई, 2015 को हुई बैठक में एफआईआई पर मेट के संबंध में अंतःनिवेशों का प्रस्तुत किया जाना

ख. बजट – 2015 से संबंधित क्रियाकलाप

बजट-पूर्व ज्ञापन – 2015 के संबंध में सुझाव

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को बजट-पूर्व ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इस बजट-पूर्व ज्ञापन – 2015 में सम्मिलित किए जाने हेतु सुझाव पूरे भारत में फैले सदस्यों से आईसीएआई की वेबसाइट पर रखी गई एक उदघोषणा के माध्यम से मांगे गए थे। इस प्रकार प्राप्त सुझावों को संकलित किया गया था और प्रत्यक्ष कर समिति को प्रस्तुत किया गया था ताकि वह उन्हें बजट पूर्व ज्ञापन में सम्मिलित कर सके। तदनुसार, बजट पूर्व ज्ञापन को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, उसके पदधारियों के साथ हुई बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था, जिनमें अन्यो के साथ अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

बजट अवलोकन कार्यशाला

संघीय बजट 2015-16 को 28 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किया गया था और एक नियमित व्यवहार के रूप में इस समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति तथा अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ मिलकर बजट जारी होने की तारीख को एक बजट अवलोकन सत्र का आयोजन किया था, जिसमें सभी परिषद् सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों को आमंत्रित किया गया था। उनमें बजट संबंधी प्रस्तावों के बारे में व्यौरेवार विचार-विमर्श किया गया था। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों को तैयार किया गया था और उसी दिन वेबसाइट पर रख दिया गया था। संघीय बजट 2015-16 के संबंध में प्रैस विज्ञप्ति को तैयार किया गया था और उसे जन संपर्क समिति को भेजा गया था।

संघीय बजट 2015-16 के कर संबंधी प्रस्तावों का लाइव वेबकास्ट

समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति और अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ मिलकर 28 फरवरी, 2015 को संघीय बजट 2015-16 के कर संबंधी प्रस्तावों का लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था। सभी सदस्यों को उक्त वेबकास्ट के बारे में सूचित करते हुए बड़ी संख्या में मेल और एसएमएस काफी समय पूर्व भेज दिए गए थे। इस वेबकास्ट की सदस्यों द्वारा सराहना की गई थी और इसे लगभग 16,000 सदस्यों द्वारा देखा गया था।

(ग) अन्य पहले

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से अंतर्राष्ट्रीय कर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अनुमोदन

चूंकि आईसीएआई ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से अंतर्राष्ट्रीय कर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, इसलिए समिति अब दिसंबर, 2015 तक इस पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए कार्य कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने 1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का नई दिल्ली (2), मुंबई, हैदराबाद, जामनगर, राजकोट, कोलकाता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, काठमांडु (नेपाल), वदोदरा, सूरत, ठाणे और पुणे में बैचों का आयोजन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी ई-पठन

समिति ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में जानकारी के प्रसार के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले किन्हीं सदस्यों के लिए इस विषय के संबंध में पठन को सुकर बनाने हेतु ई-पठन मॉड्यूल विकसित किए हैं। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान की प्रस्तावना और अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में ई-पठन माड्यूल विकसित कर लिए गए हैं और वे सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं।

ई-न्यूज लैटर

समिति ने अगस्त, 2014 में समिति के ई-न्यूज लैटर के द्वितीय अंक को जारी किया है।

सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था

(क) एसीई टीपी ऑनलाइन के साथ करार – समिति ने अपने माननीय सदस्यों के लिए अकार्ड फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक

ठहराव किया है, जिसके अंतर्गत सदस्यों को एक छूट प्राप्त अभिदाय दर पर एसीई – टीपी के आनलाइन पाठ के माध्यम से उनके अंतरण कीमत निर्धारण डाटा बेस तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। एसीई टीपी सभी सदस्यों के लिए 14,000 रुपए (करोड़ों से रहित) प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध है।

(ख) आईसीएआई के सदस्यों के लिए बीएनए ब्लूमबर्ग की वैश्विक कर गाइड (निःशुल्क) : बीएनए ब्लूमबर्ग के साथ आईसीएआई के ठहराव के अनुसार, वैश्विक कर गाइड अब प्रभावी रूप से हमारे सभी 2,30,000 सदस्यों को उपलब्ध है। वैश्विक कर गाइड एक आनलाइन सेवा है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ज्ञान को व्यावहारिक कर सूचना, जिसके अंतर्गत कर दरें, फाइल करने की अंतिम तारीखें और अन्य प्रमुख घटनाएं भी सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराके अद्यतन बनाएंगे और यह सेवा 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। यह सेवा सही कर दर को ढूंढने में और कर व्यवस्थाओं की परस्पर तुलना करने में लगने वाले समय की बचत करेगी।

68वीं कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ फैलोशिप बैठक

वैश्विक अर्थव्यवस्था के बढ़ते वैश्विककरण के साथ, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अधिक महत्वपूर्ण तथा जटिल होता जा रहा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विशिष्ट रूप से हमारे सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला बढ़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होती जा रही है। इस अतिआवश्यकता के प्रति सचेत रहते हुए आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में हमारे सदस्यों की सक्षमताओं का निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आईसीएआई ने अंतर्राष्ट्रीय धनीय संघ (आईएफए), जो कि एक नीदरलैंड में स्थित एक अतिविश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो 110 देशों का प्रतिनिधित्व करता है और जो अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक धनीय विधियों और कराधान के वित्तीय और आर्थिक पहलुओं को विकसित करने की दिशा में कार्य करता है, के साथ सहयोग किया है। हमारे सदस्यों और आईएफए के प्रतिनिधियों के बीच एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन उस समय किया गया था जब वे मुंबई में 68वीं आईएफए कांग्रेस, 2014 के लिए इकट्ठे हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में अनुसंधान

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में एक पहल की है और उसने सदस्यों को निम्नलिखित में से किसी भी विषय पर अनुसंधान कार्य करने के लिए आमंत्रित किया है :

1. बेस इरोजन प्राफिट शिफ्टिंग
2. परमानेंट एस्टेबलिशमेंट एट्रीब्यून
3. इलैक्ट्रानिक कामर्स
4. ट्रांसफर प्राइसिंग
5. डिजिटल इकनोमी

इसके प्रत्युत्तर में, समिति को 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से सदस्य अनुसंधान कार्य करने के इच्छुक हैं। प्राप्त हुए सारांश के आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों से अनुसंधान पत्र मंगाए गए थे। उनके पुनर्विलोकन की कार्यवाही जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर वेबकास्ट

समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान अंतरण कीमत निर्धारण और फेमा के विभिन्न विषयों पर लाइव वेबकास्ट आयोजित करने की पहल की है। इन वेबकास्टों का उद्देश्य सभी सदस्यों के बीच नियमित आधार पर विषय के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है। वेबकास्ट के वीडियो को www.icai.tv.com पर अपलोड किया गया है। 1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी विभिन्न विषयों पर कुल 13 वेबकास्टों का आयोजन किया था।

घ. संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरूकता कार्यक्रम

देश भर में अनेक संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

5.20 उद्योग में सेवारत सदस्यों संबंधी समिति

उद्योग में सेवारत सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई और उद्योग में विभिन्न हैसियतों में कार्यरत चार्टर्ड एकाउंटेंटों के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने के कार्य में लगी है और साथ ही उन्हें ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल के निबंधनों में एक संदर्भ आधार और उनके व्यक्ति कैरियर में विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। इसके लिए समिति सरकार के विभिन्न संगठनों और अभिकरणों के साथ व्यापक और गहन संबंधों का विकास करती है ताकि अधिकतम नियोजन संबंधी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की

पूर्ति के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शासन जगत के साथ अधिकतम संभव उदभासन का उपबंध किया जा सके।

I. आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए कैरियर सहायता कार्यक्रमों का आयोजन

समिति वर्ष में दो बार नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

वर्ष 2014-15 के लिए

1. अनुकूलन कार्यक्रम

समिति ने वर्ष 2014-15 के दौरान अनुकूलन कार्यक्रमों के दो चक्रों का आयोजन किया है :

- (1) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जो कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - फरवरी-मार्च, 2014 में उपस्थित हुए थे, 16 केन्द्रों में, अर्थात् भुवनेश्वर, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, नागपुर, इंदौर, कोयंबटूर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली।
- (2) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जो कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - अगस्त-सितंबर, 2014 में उपस्थित हुए थे, 20 केन्द्रों में, कैम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रम में, अर्थात् एर्नाकुलम, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कानपुर, कोयंबटूर, नागपुर, इंदौर, जयपुर, पुणे, बड़ौदा, ठाणे, वसई, नवी मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली।

इन अनुकूलन कार्यक्रमों में सुविख्यात संकाय को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कि निगमों की चार्टर्ड एकाउंटेंटों से आशाएं, नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अपेक्षित सॉफ्ट कौशल, व्यक्तिगत साक्षात्कार में कैसे सफल हों, विभिन्न उद्योगों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर, आदि विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों को संबोधित किया था।

2. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

समिति ने नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 39वें और 40वें संस्करण का आयोजन किया था।

- (1) ऐसे नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए, जिन्होंने सीए फाइनल परीक्षा नवंबर, 2013 में उत्तीर्ण की थी, कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 39वां संस्करण। इसका आयोजन दो चरणों में देश भर में 15 केंद्रों पर किया गया था और इनके लिए लगभग 2600 अभ्यर्थियों ने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था। प्रमुख संगठनों, जिनके अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, आदि के, में इस कार्यक्रम में भाग लिया था और नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आकर्षक वेतनों का प्रस्ताव किया था। कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों में से 700 अभ्यर्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही, इस कार्यक्रम में उद्योग के 80 शीर्ष अस्तित्वों ने भाग लिया था जिसके लिए सभी केंद्रों पर कुल 136 साक्षात्कार दलों को नियुक्त किया गया था। चुने गए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अंतरराष्ट्रीय और साथ ही देशी नौकरियों के लिए आकर्षक वेतन की पेशकश की गई है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति के लिए अधिकतम वेतन का शराफ शिपिंग एजेंसी, एलएलसी ने चेन्नई केंद्र में तीन अभ्यर्थियों को प्रस्ताव दिया था, अर्थात् 20.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष और देशी नियुक्ति के लिए अधिकतम वेतन का प्रस्ताव भारती एयरटेल द्वारा नई दिल्ली केंद्र में दो अभ्यर्थियों को किया गया था, अर्थात् 21 लाख रुपए प्रतिवर्ष।
- (2) ऐसे नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए, जिन्होंने सीए फाइनल परीक्षा मई, 2014 में उत्तीर्ण की थी, कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 40वां संस्करण। इसका 6 बड़े केन्द्रों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तथा 13 छोटे केंद्रों अहमदाबाद, वदोदरा, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, एर्नाकुलम, इंदौर, जयपुर, नागपुर, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे और वसई में किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 4800 उम्मीदवारों ने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था, जिसमें प्रमुख संगठनों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत उम्मीदवारों में से 1018 उम्मीदवारों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही उद्योग से लगभग 86 शीर्ष अस्तित्वों ने कार्यक्रम में भाग लिया था जिसके लिए सभी केंद्रों हेतु कुल 154 साक्षात्कार दलों का गठन किया गया था। चुने गए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अंतरराष्ट्रीय और साथ ही देशी नियुक्तियों के लिए आकर्षक वेतनों का प्रस्ताव किया गया है। देशी नियुक्ति के लिए अधिकतम 17 लाख रुपए प्रतिवर्ष का और अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति के लिए अधिकतम 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया है।

3. आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक

समिति ने, मुंबई में 29 अप्रैल, 2014 को आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था। इस आईसीएआई उद्योग एचआर की बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में विभिन्न केन्द्रों पर कैम्पस नियोजन कार्यक्रम से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।

वर्ष 2015-16 के लिए (7 जुलाई, 2015 तक)

1. अनुकूलन कार्यक्रम

देश भर में 20 केंद्रों पर अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, अर्थात् अहमदाबाद, वदोदरा, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, एनकुलम, इंदौर, जयपुर, नागपुर, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे और वसई, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली। इन अनुकूलन कार्यक्रमों में प्रमुख संकायों को विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों से निगमों की अपेक्षाएं, नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अपेक्षित साफ्ट कौशल, व्यक्तिगत साक्षात्कारों में कैसे सफल बनें, विभिन्न उद्योगों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर आदि।

2. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए देश भर के 19 केंद्रों पर दो चरणों में कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के लिए लगभग 5591 अभ्यर्थियों ने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था और इस कार्यक्रम में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, बैंकों आदि सहित प्रमुख संगठनों ने भाग लिया था, जिन्होंने नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों आकर्षक वेतनों की पेशकश की थी।

कुल मिलाकर, इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरियों की पेशकश की गई थी। साथ ही, उद्योग के 90 शीर्ष अस्तित्वों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था जिसके लिए सभी केंद्रों हेतु कुल 183 साक्षात्कार दलों का गठन किया गया था। चुने गए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अंतरराष्ट्रीय और साथ ही घरेलू नौकरियों के लिए आकर्षक वेतनों का प्रस्ताव किया गया था। इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव तोलाराम समूह द्वारा बंगलूरु और कोलकाता के केंद्रों में 8 अभ्यर्थियों को किया गया था और देशी नियुक्ति के लिए अधिकतम 21.50 लाख प्रतिवर्ष के वेतन पेशकश भारतीय एयरटेल द्वारा नई दिल्ली केंद्र पर दो अभ्यर्थियों को की गई थी।

3. एचआर बैठक

समिति ने आईसीएआई और निगमों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए तथा अगस्त-सितंबर, 2015 के आगामी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के लिए नियोजन के संनियमों और प्रक्रिया के संबंध में फीड बैक/सुझाव प्राप्त करने के लिए 26 जून, 2015 को (1 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक) होटल ललित, नई दिल्ली में आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था। विभिन्न निगमों से 43 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था और कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव और फीड बैक प्रदान की थी।

II. संस्थान के उद्योग में सेवारत सदस्यों के बीच सक्षमताओं का विकास

वर्ष 2014-15 के लिए

1. अकांक्षा और इच्छा रखने वाले युवा सीए के मार्गदर्शन के लिए परामर्शदाता कार्यक्रम - परामर्शदाता कार्यक्रम का शुभारंभ

सीएमआईआई ने परामर्शदाता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें आईसीएआई के अनुभवी सदस्यों से परामर्शदाता की भूमिका अपनाने का और इस आदर्श वृत्ति की संवहनीयता और विकास के प्रति अपना योगदान देने और वृत्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बढत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ और अनुभवी सीए वृत्तिकों को अनुरोध पत्र भेजे गए थे कि वे हाल ही में अर्हता प्राप्त करने वाले और अकांक्षा तथा इच्छा रखने वाले अन्य सीए को, उनकी योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर परामर्श देने हेतु स्वैच्छापूर्वक सहमति दें, ऐसा इस विश्वास के साथ किया गया था कि उनकी विनम्र उपस्थिति और सहारा देने की भावना अकांक्षा तथा इच्छा रखने वाले सीए को उच्च गुणवत्ता वाला परामर्श उपलब्ध कराएगी और वे प्रभावी परामर्श और परस्पर क्रियाशील पठन प्रक्रिया के माध्यम से अपने कौशलों, ज्ञान और मनोवृत्ति को विकसित करके भविष्य में स्वयं के लिए सही मार्ग चुनने में समर्थ होंगे। वरिष्ठ सदस्यों और नए अर्हित तथा अकांक्षा रखने वाले नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों, दोनों से प्राप्त अति सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए समिति ने इस परामर्शदाता कार्यक्रम का कार्यान्वयन हितबद्ध परामर्शियों और परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तक पहुंच बनाकर कर दिया है। इस परामर्शदाता कार्यक्रम के लिए कुल 54 परामर्शियों और परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं को नामांकित किया है।

2. सीएमआईआई ई न्यूज लैटर के 12वें अंक का विमोचन

समिति ने, सीएमआईआई ई न्यूज लैटर के 12वें अंक का विमोचन किया है, जो <http://220.227.161.86/33552cmii-eneewsletter23183main.pdf> पर उपलब्ध है। यह ई-न्यूज लैटर, समिति की वर्ष 2014-15 की उपलब्धियों को दर्शित करता है और साथ ही सदस्यों को उद्योग में कार्यरत सदस्यों के फायदे के लिए की गई नई पहलों के बारे में भी अवगत कराता है।

3. आईसीएआई रिकनेक्ट का शुभारंभ

समिति ने, आईसीएआई की सदस्यता के साथ जुड़े विशेषाधिकारों और अन्य फायदों को संसूचित करने के उद्देश्य से आईसीएआई रिकनेक्ट का शुभारंभ किया है ताकि ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट जो अपनी सदस्यता प्राप्ति को सक्रिय नहीं रखे हुए हैं, उसके महत्व को समझ सकें और सतत आधार पर उसका नवीकरण करें।

4. उद्योग में कार्यरत सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल

आईसीएआई ने सीपीई अध्ययन सर्कलों के लिए संनियम अधिसूचित किए हैं जो कि अनन्य रूप से उद्योग में कार्यरत सदस्यों के लिए अभिप्रेत हैं। इन सीपीई अध्ययन सर्कलों को ऐसे सदस्यों की सहायता करने के लिए अनुध्यात किया जा रहा है, जो उद्योग में कार्य कर रहे हैं ताकि वे अपनी मूल सक्षमताओं को बनाए रखने के उद्देश्यों और सदस्यों के बीच अपनी वृत्तिक जानकारी का आदान-प्रदान करने और साथ ही भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने में समर्थ हो सकें। उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल के संपूर्ण संनियमों को देखने के लिए <http://www.cmii.icaai.org/cpe.asp> देखें।

समिति को उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों का अनुमोदन करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और उनका अधीक्षण करने हेतु सशक्त किया गया है, जो उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये संनियम इन सीपीई अध्ययन सर्कलों के लिए सदस्यों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या और आवेदन प्रक्रिया, कार्यकरण, प्रशासन और लेखों के लिए नियमों हेतु उपबंध करते हैं। अभी तक समिति द्वारा उद्योग में लगे सदस्यों के लिए 111 सीपीई अध्ययन सर्कल बनाए गए हैं।

5. आउटरीच कार्यक्रम

समिति ऐसे निगम के परिसरों में, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजित किया है, सदस्यों के लिए अर्ध-दिवसीय या पूर्ण दिवसीय आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना इस विचार से की गई थी कि उद्योग में लगे सदस्यों को आईसीएआई के समीप लाया जा सके ताकि वे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए एक समान मंच पर उपस्थित हो सकें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आईसीएआई ऐसे संगठनों के द्वार तक पहुंचता है और उद्योग में लगे सदस्यों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करता है।

समिति ने निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया है :

- (1) 16 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में गेल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के परिसरों में आउटरीच कार्यक्रम।
- (2) 6 मई 2014 को मुंबई में सिटेल लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (3) 10 मई 2014 को मुंबई में एस्सार लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (4) 6 जून, 2014 को मुंबई में आईडीबीआई बैंक के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (5) 2 जुलाई, 2014 को मुंबई में ओएनजीसी लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (6) 21 जुलाई, 2014 को मुंबई में गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के परिसरों में आउटरीच कार्यक्रम।
- (7) 6 सितंबर, 2014 को पुणे में जॉन डीरे प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (8) 9 सितंबर, 2014 को मुंबई में इंडियन ऑयल कापोरेशन लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (9) 19 सितंबर, 2014 को मुंबई में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (10) 12 अक्टूबर 2014 को मुंबई में पर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (11) 7 नवम्बर, 2014 को मुंबई में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (12) 23 नवंबर, 2014 को मुंबई में, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।
- (13) 25 नवंबर, 2014 को मुंबई में कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के परिसर में आउटरीच कार्यक्रम।

6. राज्य कार्यबल

समिति ने समिति की और सकल रूप में आईसीएआई की पहलों को और दृश्यता प्रदान करने के लिए राज्य कार्य बलों का गठन किया है। राज्य कार्य बलों के क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : -

- नियोजन संगोष्ठियों का आयोजन।
- पारंपरिक क्षेत्रों से परे सीए को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें प्रक्षेपित करना।
- समिति द्वारा बनाए रखे गए नियोजन पोर्टल को लोकप्रिय बनाना।
- परामर्शदाता स्कीम को लोकप्रिय बनाना और उसका कार्यक्रम।
- उद्योगों में लगे सदस्यों की विभिन्न उद्योगों के साथ परस्पर संपर्क हेतु बैठकें आयोजित करना।

- समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न शाखाओं के साथ समन्वय करना ।
- विभिन्न राज्यों के उद्योग में लगे सदस्यों की विशेष समस्याओं के संबंध में समिति को वापस रिपोर्ट करना ।
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- उद्योग विनिर्दिष्ट अध्ययन समूहों का गठन करना और उन्हें चलाना ।
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना ।
- ऐसे सदस्यों के लिए, जो उद्योग से व्यवसाय में आते हैं और विलोमत के लिए परामर्शी सत्रों का आयोजन ।
- संस्थान द्वारा जारी विभिन्न उद्भासन प्रारूपों पर चर्चा करना ।
- विभिन्न वाणिज्य चैम्बरों, व्यापार संघों के साथ वार्तालाप करना और नियोजन मेले आदि आयोजन करने के संबंध में चर्चा करना।
- उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति के क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाना ।

राज्य कार्य बलों के अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :--

1. किसी राज्य कार्यबल में सदस्यों की अधिकतम संख्या केवल बीस होगी।
2. प्रत्येक राज्य कार्यबल अधिकतम दो उद्योग विनिर्दिष्ट अध्ययन समूहों का गठन कर सकता है, जिनकी सदस्य संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. उद्योग विनिर्दिष्ट अध्ययन समूह निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं:
 1. कारबार संबंधी ज्ञान – जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, उत्पादन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन विकास, साधारण प्रबंधन हैं,
 2. लेखांकन और लेखापरीक्षा संबंधी मुद्दे,
 3. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आदि,
4. आईसीएआई की शाखाओं के अध्यक्ष, बैठकों के संचालन और समिति को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों के संबंध में समन्वय करेंगे ।

समिति महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों में राज्य कार्यबलों का सृजन किया था।

7. उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए समकालीन विषयों पर कार्यक्रम

समिति ने समकालीन विषयों पर निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

1. 27 अप्रैल, 2014 को मुंबई में "इंडस्ट्री गियर अप – रोड मैप फार इम्पलीमेंटेशन ऑफ न्यू कंपनी लॉ" विषय पर संगोष्ठी ।
2. 3 मई 2014 को ठाणे में "इंडस्ट्री गियर अप – रोड मैप फार इम्पलीमेंटेशन ऑफ न्यू कंपनी लॉ" विषय पर संगोष्ठी।
3. 26 और 27 मई 2014 को एर्नाकुलम में कंपनी अधिनियम के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ।
4. 21 जून, 2014 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में, सहकारिता एवं एनपीओ क्षेत्र संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से 'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व' विषय पर संगोष्ठी ।
5. 19 जुलाई, 2014 को बेंगलुरु में "निगम क्षेत्र को प्रभावित करने वाला हाल ही का घटनाक्रम" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ।
6. 13 दिसंबर, 2014 को मुंबई में विलयन और अर्जनों संबंधी संगोष्ठी
7. 13 और 14 दिसंबर, 2014 के दौरान डायरेक्ट्रीप्लेक्स, मुंबई में "डब्ल्यूटीओ, फेमा, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अन्य आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसरों" के विषय पर एक व्यापक सम्मेलन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी।
8. 17 दिसंबर, 2014 को मुंबई में संपत्तियों के पुनर्विकास के विषय पर व्याख्यान बैठक ।
9. 21 दिसंबर, 2014 को ठाणे में आयकर और एमवेट के अधीन आईएफआरएस, अपीलीय कार्यवाहियों के विषय पर संगोष्ठी ।

8. आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने 12-17 अगस्त, 2014 के दौरान ताशकंद में 7वें अंतर्राष्ट्रीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया था।

9. आवासीय परस्पर क्रियाशील बैठक

समिति ने लोक सेवाओं में नियोजित अपने सदस्यों के लिए 2, 3 और 4 जनवरी, 2015 को पुणे में आवासीय परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया था।

10. उद्योग में लगे सदस्यों की बैठक /सीएफओ /सीईओ बैठक

संस्थान और उद्योग में लगे कार्यरत सदस्यों के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए और परस्पर दिलचस्पी के महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति ऐसे सदस्यों के साथ सभी प्रमुख नगरों में बैठकों का आयोजन कर रही है, जो निगमों में उच्च पद धारण कर रहे हैं।

उद्योग में लगे सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन – 16 मई, 2014 को नई दिल्ली में, 1 जून, 2014 को राजकोट में, 27 जून, 2014 को मुंबई में, 4 जुलाई, 2014 को वदोदरा में, 6 जुलाई, 2014 को जलगांव में, 17 जुलाई, 2014 को कोलकाता में और 12 सितंबर, 2014 को नवी मुंबई में।

11. प्रकाशन/संकलन

समिति ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- सीएमआईआई क्रियाकलाप – उद्योग में लगे सदस्यों के लिए एक मंच
- नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु हैंडबुक का पुनरीक्षित संस्करण
- परामर्शदाता कार्यक्रम
- आईसीएआई रि-क्नेक्ट

12. उद्योग में सेवारत ऐसे सदस्यों के लिए मान्यता और सराहना, जिन्होंने वृत्तिक योगदान के अपने दो दशकों को पूरा कर लिया है

समिति ने 1 जुलाई, 2015 की पूर्व संध्या पर उद्योग में सेवारत ऐसे सदस्यों को मान्यता देने और उनकी सराहना हेतु, जिन्होंने वृत्तिक योगदान के अपने दो दशकों को पूरा कर लिया है, उन्हें विशेष पत्र भेजे हैं।

13. आईसीएआई पुरस्कार, 2014 के लिए ज्यूरी की बैठक

समिति ने, 19 दिसम्बर, 2014 को होटल सहारा स्टार, मुंबई में, आईसीएआई पुरस्कार, 2014 के लिए आवेदकों में से सर्वोत्तम चार्टर्ड एकाउंटेंट के चयन के लिए आईसीएआई पुरस्कार, 2014 के लिए ज्यूरी की बैठक का आयोजन किया था।

आईसीएआई पुरस्कार, 2014 के लिए ज्यूरी की बैठक हेतु ज्यूरी के सदस्यों की सूची :

- श्री पवन कांत मुंजाल, उपाध्यक्ष, सीईओ और एमडी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (ज्यूरी के अध्यक्ष)
- श्री तपन सिंघल, सीईओ और एमडी, बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ;
- श्रीमती वी.आर. अय्यर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ;
- श्री आशीष चौहान, एमडी और सीईओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ;
- श्री जी श्रीनिवासन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ;
- श्री डी के सराफ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ;
- डॉ अशोक कुमार बालियान, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ;
- श्री डी आर डोगरा के एमडी और सीईओ, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड,
- सुश्री शौना चौहान, सीईओ, पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड,

- श्री रमेश नायर, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,
- श्री राशेप शाह, चेयरमैन, एडलवाइस,
- श्री आनंद अग्रवाल, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक, स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
- श्रीमती पारु एम जयकृष्णा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, असाही सॉन्गवन कलर्स लिमिटेड और अक्षरकैम (इंडिया) लिमिटेड,
- श्री यदुवेन्द्र माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक आदि

14. 8वां आईसीएआई – सीएमआईआई कारपोरेट मंच और पुरस्कार 2014

(www.corporateforum.icai.org)

समिति ने लगातार 8वीं बार मुंबई में 31 जनवरी, 2015 और 1 फरवरी, 2015 के दौरान वार्षिक निगम मंच की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें निम्नलिखित उच्च स्तरीय आयोजन सम्मिलित थे :

(1) निगम सभा (31 जनवरी 2015 और 1 फरवरी 2015) : आईसीएआई-सीएमआईआई निगम सभा - उत्कृष्टता की खोज में - उत्कृष्टता की ओर परिवर्तनशीलता विषय दो दिवसीय राष्ट्रीय सभा - इस सभा में आईसीएआई के सदस्यों के लिए सुसंगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आज के क्रियाशील वातावरण में उन्हें अद्यतन बनाए जाने के लिए विचार-विमर्श किया गया था। निगम सभा के दौरान बीएसई, एसएमई मंच के माध्यम से निधियां जुटाना ; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए भारत में उभरते बाजार, फायदे, मुद्दे, चुनौतियां और अवसर ; स्वचालित कपट प्रकटन और निवारण : वास्तविक समय में कपट निवारण और पता लगाने संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए क्रियाशील रूप से पता लगाने और निवारण के लिए प्रणाली और पद्धतियां तथा कपट का पता लगाने की प्रौद्योगिकियों पर कारबार की निर्भरता ; एनबीएफसी - निधियां जुटाने संबंधी अवसर - कड़े विनियमन - आगे की रणनीति ; मीडिया उद्योग : पर्यावलोकन, कारबार मॉडल, निधि जुटाने के विकल्प, चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए पुनः संरचना और वृत्तिक अवसर ; आईआईटीएस - भू-संपदा बाजारों को आगे बढ़ाना, परिसीमाओं और कर संबंधी मुद्दे ; भू-संपदा उद्योग में विधिक, कर और लेखांकन संबंधी मुद्दों से संबंधित हाल ही का घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत पुनः विकास से संबंधी प्रमुख मुद्दे और कराधान भी है ; सीए की पारंपरिक भूमिका से आधुनिक भूमिका की ओर उन्नयन : नए युग की अपेक्षाओं से लैस होना, जैसे कि कारबार प्रक्रिया प्रमुख सक्षमता और आईटी में ; कारबार संबंधी भागीदारी ; सीए वृत्तिकों के लिए एक नई दिशा, भागीदारी ठहरावों में अंतर्बलित कारबार संबंधी मुद्दों को समझना और भागीदारियों की सफलता ; ज्ञान प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग - बढ़ते हुए आयाम - उद्योग, वृत्ति के लिए भावी कार्य योजना ; अमरीकी डालर - भारतीय रूपया : एक परिप्रेक्ष्य ; कंपनी अधिनियम, 2013 : नई अवधारणाएं, चुनौतियां, अवसर ; निजी साम्या वित्तपोषण की भूमिका का विस्तार : उद्योग के लिए अवसर, सीए की भूमिका ; किस प्रकार भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इस सत्र को प्रमुख संकायों द्वारा संबोधित किया गया था। 250 से अधिक व्यक्तियों ने इस अभिसमय में भाग लिया था।

श्री राणा कपूर, अध्यक्ष, एजोकेम और संस्थापक, एमडी और सीईओ, यश बैंक लिमिटेड, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

(2) वित्तीय सेवा प्रदर्शनी (31 जनवरी, 2015 और 1 फरवरी, 2015) - यह एक ऐसा मंच है जहां पूरे भारत वर्ष से चार्टर्ड अकाउंटेंट और निगम एकत्रित होते हैं। यह मंच विभिन्न संगठनों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों, निवेशकों, वित्त भ्रातृसंघ और निगम निर्णय निर्माताओं से परस्पर क्रिया करने में समर्थ बनाता है।

इसमें निम्नलिखित संगठनों ने भाग लिया था :

- (1) यस बैंक
- (2) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
- (3) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
- (4) एचडीएफसी लिमिटेड
- (5) ऑयल इंडिया लिमिटेड
- (6) बीएसई लिमिटेड
- (7) एनएचपीसी लिमिटेड
- (8) एचपीसीएल
- (9) ओएनजीसी लिमिटेड

- (10) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
- (11) गृह फायनांस लिमिटेड
- (12) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
- (13) फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (14) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (15) नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड
- (16) एलएंडटी आईडीपीएल, चेन्नई
- (17) आरईसी लिमिटेड
- (18) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)
- (19) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
- (20) आईडीबीआई बैंक
- (21) इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
- (22) ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड
- (23) एचपीसीएल
- (24) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
- (25) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
- (26) स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर
- (27) काटन कारपोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड

(3) आईसीएआई पुरस्कार 2014 (1 फरवरी, 2015) – आईसीएआई पुरस्कार 2014 द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, निगम गृहों और भारत में एमएनसी के साथ जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सहयोग को सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि डा. सुभाष चन्द्र, अध्यक्ष, जी एंटरटेन्मेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किया गया था। गणमान्य अतिथितियों में अनेक उद्योगपति और लोक जीवन में उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्मिलित थे।

पुरस्कार के लिए तीन प्रमुख प्रवर्ग थे, अर्थात् सीए बिजनेस लीडर, सीए सीएफओ और सीए प्रोफेशनल एचीवर।

बिजनेस एचीवर पुरस्कार सीएफओ, निदेशकों या समतुल्य पदस्थ ऐसे व्यक्तियों के वर्ग से वृत्तिकों की अनुशंसा करता है, जो वित्तीय सेवाओं, निगम, पब्लिक सेक्टर, एसएमई, सीए ग्लोबल एचीवर और महिलाओं और अन्य कंपनियों के उप प्रवर्ग से जुड़े हैं।

सीएफओ (मुख्य वित्त अधिकारी) के उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए सीएफओ पुरस्कार प्रवर्ग ऐसे वृत्तिकों के लिए आरंभ किया गया था, जो विनिर्माण, वित्तीय सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, टेलीफोन, एफएमसीजी सेक्टर, अवसंरचना और संनिर्माण, बैंककारी क्षेत्र, सरकारी विभाग, बीमा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तेल और गैस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, एनजीओ और सहकारी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, महिला, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरी और पूंजी मालों, पब्लिक और अन्य जैसे क्षेत्रों के उप प्रवर्गों से जुड़े हैं।

प्रोफेशनल एचीवर अवार्ड ऐसे प्रबंधकों की अनुशंसा के लिए प्रदान किया गया था, जो अपने कैरियर के शुरूआती या मध्यवर्ती दौर में हैं। इस उप प्रवर्ग में विनिर्माण, वित्तीय सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, टेलीफोन, एफएमसीजी सेक्टर, अवसंरचना और संनिर्माण, बैंककारी क्षेत्र, सरकारी विभाग, बीमा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तेल और गैस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, एनजीओ और सहकारी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, महिला, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरी और पूंजी मालों, पब्लिक और अन्य जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए (7 जुलाई, 2015 तक)

1. उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल तैयार करना

समिति ने उद्योग में लगे सदस्यों के लिए दो और सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन किया है, अर्थात् इंफोसिस्टम्स सीपीई अध्ययन सर्कल और टेक्नोस्मार्ट – सेक्टर 1 सीपीई अध्ययन सर्कल। इस प्रकार उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों की संख्या अब बढ़कर 113 हो गई है।

2. आउटरीच कार्यक्रम

समिति ने निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

(क) गेल, बर्कलेज शेयर्ड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में आउटरीच कार्यक्रम

(ख) एचसीएल टेक्नोलाजी लिमिटेड के परिसरों में आउटरीच कार्यक्रम

(ग) एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड के परिसरों में आउटरीच कार्यक्रम

3. आयोजित कार्यक्रम

समिति ने 19 अप्रैल, 2015 को चित्तौड़गढ़ में “निगम और कर विधियों में संशोधन और अनुपालन” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था।

4. उद्योग में लगे सदस्यों की बैठक/सीएफओ/सीईओ बैठक

समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

- (क) 22 अप्रैल, 2015 को आईसीएआई, नई दिल्ली में आईसीएआई सीएमआईआई – उद्योग संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक
- (ख) 12 मई, 2015 को आईसीएआई, नई दिल्ली में आईसीएआई सीएमआईआई – उद्योग संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक
- (ग) 9 जून, 2015 को होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली में, अध्ययन बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई सीएमआईआई – उद्योग संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक

5. वेबिनार

समिति ने निम्नलिखित वेबिनारों का आयोजन किया था :

- (क) 12 फरवरी, 2015 को ‘प्रिंसीपल बेस्ड लीडरशिप एंड इंटर्स बेनिफीट्स’ विषय पर वेबिनार
- (ख) 13 फरवरी, 2015 को ‘एनएचडी सन्सिडी स्कीम फार कोल्ड स्टोरेज एंड रोल आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स’ विषय पर वेबिनार

6. प्रकाशन/संकलन

समिति ने कारबार योजना के तीसरे संस्करण को जारी किया है।

5.21 पियर रिव्यू बोर्ड

आईसीएआई के पियर रिव्यू बोर्ड की स्थापना उसकी परिषद् द्वारा वर्ष, 2002 में की गई थी और यह सफल प्रयास रहा है। इसका उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना है। यह अपने ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ रहा है, जिनके लिए इसे बनाया गया था।

पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्वासन सेवा संबंधी समन्वयनों को पूरा करते समय आईसीएआई के सदस्य (क) उन्हें लागू तकनीकी वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिनके अंतर्गत अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके पास दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां हैं, जिनके माध्यम से वे आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकें।

बोर्ड के योजनाबद्ध प्रयासों ने पियर पुनर्विलोकनों के दक्ष कार्यपालन के साथ न केवल प्रैक्टिस इकाईयों को सतत रूप से सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है अपितु उन्होंने अपने कार्य से समाज का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है और इसलिए उन्हें विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है। बोर्ड के इस प्रयास को मान्यता देते हुए दो विनियामकों जैसे कि सेबी और सी एंड एजी ने अपनी अपेक्षाओं में निम्नानुसार कथन किया है :-

- भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 अप्रैल, 2010 से सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे संबद्ध स्टाक एक्सचेंजों को सीमित पुनर्विलोकन/ऐसी कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे, जो उन्हें ऐसे संपरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यक्षीन किया है और जिनके पास आईसीएआई ‘पियर रिव्यू बोर्ड’ द्वारा जारी एक विश्वमान्य प्रमाणपत्र है।
- भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने पियर रिव्यू बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है ; क्योंकि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से, उन्हें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की संपरीक्षा आबंटित करते समय आवेदन प्रारूप में उनके पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सी एंड एजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से ऐसी फर्मों के व्यौरे मांगता है, जिन्हें पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

मुख्य आंकड़े

- वर्ष के दौरान 1799 प्रैक्टिस इकाईयों, जो वृत्तिक विकास समिति के अनुसार प्रवर्ग 1 और प्रवर्ग 2 की 100 प्रतिशत इकाईयां थी, का पियर पुनर्विलोकन आरंभ किया था। (पूरे भारत वर्ष में पियर पुनर्विलोकन के अधीन चुनी गई कुल प्रैक्टिस इकाईयां : 11475)।

- वर्ष के दौरान 340 प्रैक्टिस इकाईयों/ पियर पुनर्विलोककों की फर्मों का, जिन्होंने कम से कम तीन पियर पुनर्विलोकन किए हैं, का ऐसा पुनर्विलोकन आरंभ किया गया।
- वर्ष के दौरान 1875 फर्मों का पियर पुनर्विलोकन आरंभ किया गया।
- वर्ष के दौरान 924 पुनर्विलोकनों को पूरा किया गया और प्रैक्टिस इकाईयों को पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- 22 मामलों में आगे और पुनर्विलोकनों की सिफारिश की गई।
- 890 नए पियर पुनर्विलोकनों को प्रशिक्षित किया गया।

बोर्ड ने वर्ष 2014-15 की शुरुआत “हाउस कीपींग” के साथ की थी और उसके पश्चात् 127 पुनर्विलोककों (कुल 4770 पुनर्विलोककों में से), जिन्होंने पूर्णकालिक व्यवसाय करना बंद कर दिया था, को पैनल से हटा दिया गया था और पियर रिव्यू बोर्ड के पैनल में से 422 प्रैक्टिस इकाईयों के बारे में यह पाया गया था कि वे एम एंड एसएस अनुभाग के अनुसार विभिन्न कारणों जैसे कि विलयन/परिसमापन आदि के कारण विद्यमान नहीं हैं।

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया और रिपोर्टिंग में सुधार

पियर पुनर्विलोकनों द्वारा पुनर्विलोकन की क्वालिटी और रिपोर्टिंग में सुधार करने के विचार से बोर्ड के सदस्यों के संयोजनाधीन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में छह अध्ययन समूहों का गठन किया गया था। ये अध्ययन समूह विदेशी अधिकारिताओं में अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों का अध्ययन करेंगे और उन्हें देश में सकल सुधार लाने के लिए पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा सम्मिलित किया जाएगा। इन अध्ययन समूहों की बैठकों का आयोजन नई दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, पटना और नोएडा में किया गया था। बोर्ड द्वारा विचार में ली गई फीड बैक के आधार पर निम्नलिखित सुधार सम्मिलित किए गए हैं :

- पैनल के आबंटन से पूर्व पियर पुनर्विलोकन के लिए घोषणा प्रैक्टिस इकाई द्वारा फाइल की जाएगी, जिसमें उसके वर्तमान प्रोफाइल और स्तर की सूचना दी जाएगी
- प्रैक्टिस इकाई के लिए प्रश्नोत्तरों को उनमें कंपनी अधिनियम, 2013 और अद्यतन एसए को सम्मिलित करके व्यापक बनाया गया है
- पियर पुनर्विलोकनों द्वारा स्तर 1 प्रैक्टिस इकाईयों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट को और अधिक व्यापक बनाया गया है
- प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका की अंतर्वस्तु को पुनरीक्षित किया गया है, जिसमें तकनीकी मानकों, संपरीक्षा दस्तावेजीकरण के अनुपालन पर और अधिक ध्यान केंद्रित करके तथा पुनर्विलोकन प्रक्रिया और रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है
- प्रथम आबंटन के पश्चात् फर्मों को पियर पुनर्विलोकनों के पैनल में परिवर्तन के लिए विहित मानदंड

ई-पहले : पियर पुनर्विलोकन की गुणवत्ता में सुधार

पियर पुनर्विलोकन मैनुअल की ई-पुस्तक – अध्यक्ष, आईसीएआई की कार्य योजना के अनुरूप सीए दिवस को यह ई-पुस्तक जारी की गई थी ताकि पियर पुनर्विलोकनों और प्रैक्टिस इकाईयों को वास्तविक समय आधार पर, अर्थात् जब पियर पुनर्विलोकन प्रैक्टिस इकाई के स्थान पर है तो पियर पुनर्विलोकन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वह इस ई-मैनुअल का संदर्भ ले सकता है, जिस तक जब कभी आवश्यक हो, स्मार्ट फोनों, टेबलेटों की मदद से पहुंच बनाई जा सकती है।

वेब समर्थित प्रारूप – पुनर्विलोकनों द्वारा उनके प्रोफाइल को अद्यतन बनाने के लिए वेब समर्थित प्रारूप : पियर पुनर्विलोकन विवरण के पैरा 10.1(च) में यह अपेक्षा है कि स्तर 1 अस्तित्व के पियर पुनर्विलोकन को व्यवसायगत सदस्य होना चाहिए, जिसने स्तर 1 के अस्तित्वों के लिए कम से कम 7 वर्षों तक संपरीक्षा की हो, यह डाटा हाउस कीपींग के दौरान पाया गया था, जो पियर पुनर्विलोकनों के लिए पृथक् रूप से उपलब्ध होगा। इस प्रकार, पियर पुनर्विलोकनों के व्यौरों को आनलाइन रूप से अद्यतन करने को सुकर बनाना, जिससे कि स्तर की आवश्यकता के अनुसार और प्रैक्टिस इकाईयों के प्रोफाइल के अनुसार पुनर्विलोकनों की नियुक्ति की जा सके। इससे पियर पुनर्विलोकन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पुनर्विलोकन, अपने कार्य के स्तर/वास्तविक समय आधार पर की गई संपरीक्षा के संबंध में अपने प्रोफाइल को अद्यतन कर सकते हैं।

पियर पुनर्विलोकनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- पुनर्विलोकनों द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन कार्य में संगतता और एकसमानता का प्रदुर्भाव करने के लिए बोर्ड, उन्हें नर्विलोकन हेतु प्रैक्टिस इकाईयां समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस वर्ष पियर रिव्यू बोर्ड ने गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, इंदौर, नोएडा, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, मुंबई, जालंधर, ग्वालियर, कानपुर, वदोदरा, चेन्नई, जयपुर, बीकानेर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, धनबाद में 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किया गया है और इनमें लगभग 890 (लगभग) पुनर्विलोककों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, इसके साथ ही पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा अभी तक आयोजित कुल 151 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुनर्विलोककों की संख्या 5363 हो गई है।

- पियर रिव्यू बोर्ड ने 6 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में एक सभा का भी आयोजन किया था जिसमें श्री प्रसेनजीत मुखर्जी, उप नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सीएजी) और अध्यक्ष, संपरीक्षा बोर्ड और श्री पी. शेष कुमार, महानिदेशक (वाणिज्यिक संपरीक्षा) क्रमशः मुख्य अतिथि तथा गणमान्य अतिथि थे।
- विनियामक परिस्थितियों में और तकनीकी मानकों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण पुनर्विलोककों के लिए भी इन घटनाओं से अवगत रहना आवश्यक हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण की कार्यविधि पांच वर्ष तक होगी।

5.22 वृत्तिक विकास समिति

प्रस्तावना

वृत्तिक विकास समिति को आईसीएआई द्वारा वर्ष 1962 में एक गैरस्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था। वृत्तिक विकास समिति आईसीएआई की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदैव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह वृत्तिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को अवधारित करती है और वृत्ति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है, आईसीएआई के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है। इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों। वृत्तिक विकास में अभी तक जांचे परखे नहीं गए क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा वृत्तिक विकास समिति समाज के विभिन्न तबकों में बहुप्रकार के उपयोक्ताओं के साथ संपर्क प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के विचार से, यह हित के समकालीन क्षेत्रों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

- केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ पदधारियों और उसके मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदधारियों को अभ्यावेदन भेजे गए हैं, जिनमें आईसीएआई और उसके सदस्यों की विधिक प्रास्थिति और संख्या के ब्यौरे कथित किए गए हैं और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सीए की वृत्तिक विशेषज्ञता को उपयोग करने संबंधी संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण भी किया गया है।
- वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों और विनियामक निकायों के विभिन्न पदधारियों से की गई बैठकें आदि। बैठकों के अलावा समिति ने सदस्यों के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए और इस प्रकार सदस्यों और विनियामकों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था।
- वृत्तिक विकास समिति का जानकारी पोर्टल, जो www.pdicai.org पर उपलब्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में नए वृत्तिक अवसरों के संबंध में सदस्यों को समय पर और अनिवार्य जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपनी सेवाएं सदस्यों को उपलब्ध कराता रहा है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति के प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- वृत्तिक विकास समिति पिछले कई वर्षों से पब्लिक सेक्टर बैंकों के संपरीक्षकों की, स्वयं बैंक के बोर्ड द्वारा नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही है। निगम शासन के उच्च मानकों को स्थापित करने और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की अपनी बाध्यता को पूरा करने के लिए आईसीएआई उच्च पदस्थ सक्षम प्राधिकारियों को अभ्यावेदन करता रहा है।
- भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के कार्यालय (ओ/ऋ सी एंड एजी) ने एकमात्र प्रोप्राइटर फर्मों के संबंध में न्यूनतम प्रतिपूर्ति मानदंड के लागू बने रहने को समाप्त करने संबंधी सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
 - हमारे सुझाव के अनुसार, ओ/ऋ सी एंड एजी ने प्रथम बार फर्मों की स्थिति (ब्यौरेवार बिन्दु अंक) को उपदर्शित करने के लिए वर्ष 2015-16 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों/एलएलपी के अनंतिक पैन्ल को वेबसाइट पर रखा है। ऐसी फर्म के अनंतिम पैन्लबद्धता संबंधी प्रास्थिति/बिन्दु अंक, ऑनलाइन आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ आनलाइन डाटा और आईसीएआई के डाटा के सत्यापन के अध्यधीन थे। यह अनंतिम पैन्ल 27 अप्रैल, से 6 मई, 2015 के बीच उपलब्ध था। इस संबंध में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों/प्रश्नों को ओ/ऋ सी एंड एजी को, जब कभी भी वे

प्राप्त हुए, अग्रेषित किया गया था।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), नई दिल्ली ने, उनके साथ हुई हमारी बैठक के अनुसरण में, उनके भावी आरएफपी में अग्रिम निक्षेप धन को 10,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
- तत्कालीन सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया है कि वे पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं की संपरीक्षा के लिए अवसीमा (अग्रिम) को पुनः छह करोड़ रुपए पर स्थापित करके कानूनी संपरीक्षा के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं की संपरीक्षा के विस्तार में वृद्धि करने पर विचार करें। एक अनुवर्ती पत्र भी भेजा गया है।
- संघ के माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया है कि वे पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं की संपरीक्षा के लिए अवसीमा (अग्रिम) को पुनः छह करोड़ रुपए पर स्थापित करके कानूनी संपरीक्षा के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं की संपरीक्षा के विस्तार में वृद्धि करने पर विचार करें।
- उप सी एंड एजी (वाणिज्य), भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया था कि वे उन फर्मों को, जिन्हें ओ/ओ सी एंड एजी द्वारा बनाए रखे गए पैनल में से यह विनिश्चय करते समय कि क्या किसी भागीदार को आवेदक फर्म के पूर्णकालिक भागीदार के रूप में विचारार्थ लिया जाए अथवा नहीं, न्यूनतम प्रतिपूर्ति मानदंड लागू करते हुए निरहित कर दिया गया है, पुनः पैनलबद्ध कर दिया जाए।
- तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया है कि वे सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करें कि कानूनी संपरीक्षा संबंधी कार्य समवर्ती संपरीक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता और समवर्ती संपरीक्षा संबंधी कार्य कानूनी संपरीक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता।
- गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया है कि वे पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं की संपरीक्षा के लिए अवसीमा (अग्रिम) को छह करोड़ रुपए के रूप में पुनः स्थापित करके कानूनी संपरीक्षा के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करें।
- तत्कालीन सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परस्पर वृत्तिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया है कि वे पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की शाखा कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए वही युक्ति अपनाएं, जो कि पीएसबी के केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों (सीएसए) की नियुक्ति के लिए अपनाई जाती है।
- सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया है कि वे पीएसबी के सीएसए की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शक और साम्यापूर्ण प्रक्रिया अपनाएं।
- मुंबई में केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों (सीएसए) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आरबीआई के पदधारियों ने भाग लिया था, जिनमें सुश्री मीना हेमचन्द्रा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंककारी अधीक्षण विभाग, आरबीआई और श्री एस.सी. मिश्रा, मुख्य प्रभारी महाप्रबंधक, बैंककारी अधीक्षण विभाग, आरबीआई भी सम्मिलित थे और उनके अलावा अनेक अति उत्साहित सीएसए ने भी इसमें भाग लिया था।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा शासित पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पूरा किए जाने वाले निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के भागरूप में, सभी पीएसयू अपनी सीएआर निधियों को ऐसे विद्यालयों में, जो उनके कार्यालयों/कार्यशालाओं/कारखानों आदि की अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जहां पर्याप्त शौचालय सुविधाएं नहीं हैं, शौचालय सुविधा के संनिर्माण के लिए भेजेंगे। विद्युत मंत्रालय ने यह वांछा की है कि ऐसे क्रियाकलापों में खर्च की गई रकम को उचित रूप से सत्यापित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए लोक हित आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
 - इस संबंध में, चार्टर्ड अकाउंटेंटों से इन संपरीक्षाओं को करने संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर, ऐसा करने के इच्छुक सदस्यों से हित की अभिव्यक्ति हेतु वेबसाइट पर सामग्री रखी गई थी। आज की तारीख तक हमें 625 से अधिक सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ, परस्पर वृत्तिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात् डा. हसमुख अधिया, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि वे प्रबंध संबंधी स्वायत्ता से संबंधित मुद्दों पर और साथ ही कानूनी संपरीक्षा के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं के संपरीक्षा संबंधी विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने के मुद्दे पर विचार करें।

- तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, बैंककारी अधीक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को, 8 अप्रैल, 2015 को मुंबई में आरबीआई के साथ हुई बैठक के प्रारूप कार्यवृत्तों के, जो आरबीआई की 17 अप्रैल, 2015 की ई-मेल द्वारा प्राप्त हुए थे, संदर्भ में एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उक्त ई-मेल के अनुलग्नक 1 के बिन्दु सं. 2 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि “सीआईएसए/आईएसए अर्हित भागीदार और सीए कर्मचारियों, दोनों को पूर्णकालिक होना चाहिए, जिससे सीआईएसए/आईएसए अर्हित भागीदार और वेतन प्राप्त करने वाले सीए, दोनों ही बैंक संपरीक्षा के दौरान उपलब्ध हों, जिससे संपरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।” इस संबंध में, हमारी ई-मेल और पत्र के द्वारा यह दोहराया गया कि ऐसा कोई परिवर्तन केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए होने वाली नियुक्तियों हेतु लागू होना चाहिए क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए संपरीक्षा के आबंटन हेतु प्रस्तुत वर्तमान डाटा 1.1.2015 तक का है और इस समय इस संबंध में किया गया कोई परिवर्तन उपबंध भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करेगा।
- एसीएस और विभागाध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य टेक ई-पंचायत सोसाइटी (एमपीएसटीईपीएस), आयुक्त कार्यालय, पंचायती राज निदेशालय, भोपाल को, संगठन द्वारा पीआरआई की समवर्ती संपरीक्षा करने के लिए निकाली गई निविदा के संबंध में एक पत्र भेजा गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि उक्त कार्य समनुदेशन के अनुसार किया जाना चाहिए और समनुदेशन के मूल्य का प्राक्कलन आंतरिक रूप से किया जाना चाहिए और उक्त समनुदेशन के लिए प्राप्त सभी (तुच्छ) बोलियों, जो उक्त आंतरिक रूप से प्राक्कलित लागत से कम हैं, को नामंजूर कर दिया जाए।
 - इसके पश्चात्, आयुक्त, जीओएमपी, पंचायत राज निदेशालय और सीईओ, मध्य प्रदेश राज्य टेक ई-पंचायत सोसाइटी (एमपीएसटीईपीएस) से तारीख 22 अप्रैल, 2015 का एक पत्र सं. 617/पीआरडी/ एमपीएसटीईपीएस/ संपरीक्षा/51-बी/15, भोपाल प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने यह सिफारिश की है कि आईसीएआई को जवाबदेही, पारदर्शिता का सृजन करने के लिए संपरीक्षा और लेखाओं के संबंध में लोक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि लोक आस्तियों के विकास के लिए खर्च किए गए जनता के सभी धनो के संबंध में पारदर्शिता आ सके।
 - इस पत्र का उत्तर तारीख 14 मई, 2015 के पत्र द्वारा भेजा गया था, जिसमें यह कथन किया गया था कि आईसीएआई को मूलभूत स्तर पर सक्षमता निर्माण के उपाय करने के लिए उक्त संगठन हेतु विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव करने में अति प्रसन्नता होगी। आईसीएआई को संपूर्ण प्रक्रिया में और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अपने विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में भी अति प्रसन्नता होगी।
- स्वतंत्र सीए निदेशकों : एक सहयोगी पठन, विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होटल क्लेरिजिस, औरंगजेब मार्ग, नई दिल्ली में किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय (सी एंड एजी) ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी। इस बैठक में बड़ी संख्या में निदेशकों ने भाग लिया था।
- भोपाल में आधुनिक युग में उभरते वृत्तिक अवसरों के संबंध में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी। राजस्व और पुनर्वास मंत्री और एक संसद् सदस्य, मध्य प्रदेश, ऐसे गणमान्य व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। 727 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।

और अधिक वृत्तिक अवसरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित को अभ्यावेदन भेजे गए थे :

- एमजीनरेगा के तहत अनिवार्य रूप में लेखा, वाउचर तैयारी, अनिवार्य रजिस्ट्रों का रखरखाव के बुनियादी सिद्धांतों पर ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों/सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के बारे में आवर्ती लेखांकन प्रविष्टियों आदि के संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वित्त विभाग के प्रधान/मुख्य सचिवों।
- विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के साथ संलग्न शासकीय परिसमापकों को, चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पैनल की सेवाओं का उपयोग करने के लिए, एक सीडी अंतर्विष्ट करते हुए।
- चार्टर्ड एकाउंटेंटों/फर्मों की विभिन्न आंतरिक समनुदेशनों संबंधी सेवाओं में उपयोग के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/फर्मों के पैनल (आरबीआई को प्रस्तुत) को अंतर्विष्ट करने वाली सीडी के साथ सभी पीएसबी के सीएमडी/एमडी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक को, यह अनुरोध करते हुए कि वह पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीमा (अग्रिम) को छह करोड़ रुपए को पुनः स्थापित करके कानूनी संपरीक्षा के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की शाखाओं की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने पर विचार करें।
- प्रभारी, मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुरोध करते हुए कि वह पब्लिक सेक्टर बैंकों में संपरीक्षा के अंतर्गत आने वाले अग्रिमों की प्रतिशत और संपरीक्षाओं की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए।
- सहायक महाप्रबंधक (लेखा परीक्षा), भारतीय स्टेट बैंक, चंडीगढ़ को यह अनुरोध करते हुए कि वह समवर्ती संपरीक्षा की

आउटसोर्सिंग के लिए पैनल अधिसूचना पर पुनर्विचार करे, जिसमें बैंक शाखा संपरीक्षकों के पैनल के प्रवर्ग 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों/फर्मों को ही आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया है और साथ यह भी अनुरोध किया गया था कि प्रवर्ग 1 और 4 के चार्टर्ड एकाउंटेंटों को पैनल हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

- कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक को, इलाहाबाद बैंक द्वारा विभिन्न चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को प्रस्ताव की जा रही उधार खातों की स्टॉक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखा परीक्षा फीस में उपयुक्त रूप से पुनरीक्षण किया जाए।
- उप महाप्रबंधक एवं सीसीओ, भारतीय स्टेट बैंक, एलएचओ, नई दिल्ली को, अपने सम्माननीय बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- उप महाप्रबंधक (आईए), देना बैंक को यह सूचित करने के लिए कि कानूनी लेखा परीक्षकों पर लगाए गए प्रतिबंध/निरर्हताओं को स्वमेव तथ्यों के आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता।
- महाप्रबंधक निरीक्षण, पंजाब एंड सिंध बैंक को, इस बारे में उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि समवर्ती लेखापरीक्षक, कानूनी लेखापरीक्षा या सुसंगत अवधि के लिए बैंक के किसी भी अन्य संबंधित समनुदेशन के संबंध में कार्य नहीं कर सकते हैं।
- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल को यह अनुरोध करते हुए कि समवर्ती लेखा परीक्षकों के पैनल - मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शास्तिक खंड को विवर्जित करने के लिए।
- माननीय वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार को राज्य में बैट लेखापरीक्षा के संचालन के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को, राज्य में बैट लेखापरीक्षा के संचालन के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य में बैट लेखापरीक्षा के संचालन के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार, राजस्थान को, राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करने के लिए।
- मुख्य महाप्रबंधक (एफ एंड ए), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को, वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध के लिए प्रतिभूति निक्षेप को समाप्त करने और संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण करने के लिए।
- मुख्य लेखा अधिकारी (आईए), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को, अपने सम्माननीय संगठन में राजस्व लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा), भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड को, उनके सम्मानित संगठन में आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए।
- महानिदेशक (सी), ओ/ओ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों का कार्यालय को यह अनुरोध करते हुए कि पीएसयू की संपरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध करने हेतु आनलाइन प्ररूप में हुई किसी त्रुटि (किसी पश्चात्कर्ती प्रक्रम पर) को ठीक करने में सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु कोई प्रणाली विकसित की जाए।
- महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक द्वारा विभिन्न चार्टर्ड एकाउंटेंटों को प्रस्तावित उधार खातों की स्टॉक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखा परीक्षा फीस का उपयुक्त रूप से पुनरीक्षण करने के लिए।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को, प्रबंधन स्कूलों के लिए अपने संकाय मानदंडों में एआईसीटीई द्वारा विहित पात्रता मानदंड में आईसीएआई के फेलो सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए।
- उप सी एंड एजी, ओ/ओ सी एंड एजी को यह अनुरोध करते हुए कि पीएसबी के सीएसएस की नियुक्ति के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वह पारदर्शी, साम्यापूर्ण और प्रभावी होनी चाहिए और साथ ही यह सुझाव भी दिया गया था कि कम से कम चालू वित्तीय वर्ष के लिए चयन समिति की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए और सभी मुद्दों पर समुचित विचार करने के पश्चात् नई प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए।
- महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग, आंध्र बैंक को, यह अनुरोध करते हुए कि वे उधारकर्ताओं की स्टॉक और प्राप्य

लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अधिकृत करने पर विचार करें।

- वरिष्ठ वित्त प्रबंधक, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश को, यह अनुरोध करते हुए कि वे ऐसे आमंत्रण को वापस लें जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि सभी अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट 25,000 रुपए का अग्रिम धन निक्षेप (ईएमडी) प्रस्तुत करें।
- प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंककारी अधीक्षण विभाग, आरबीआई को यह अनुरोध करते हुए कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) को यह निदेश दिया जाए कि वे ऐसे आवेदकों को अधिमानतः/पूर्विकता प्रदान करें, जिन्होंने अधिकतम कूलिंग अवधि पूरी की है।
- आयुक्त-सह-सचिव, ओडिशा सरकार, पंचायती राज विभाग, ओडिशा सरकार को यह अनुरोध करते हुए कि वे ऐसे मानदंड को अधिकथित करें, जिसे ऐसी रीति में अपनाया जाना चाहिए जिससे कि फर्मों के बीच कार्य का साम्यापूर्ण वितरण हो, ताकि आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता को लाया जा सके और प्रत्येक फर्म को समनुदेशन प्राप्त करने में समान अवसर प्राप्त हो।
- प्रबंध निदेशक, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, मध्य प्रदेश, महिला वित्त एवं विकास निगम को उन्हें यह सुझाव देते हुए कि 12500 महिला स्व:सहायता समूहों (एसएचजी) की लेखापरीक्षा को किसी एकल फर्म की बजाए पात्र फर्मों के सेट के बीच वितरित किया जाए।
- रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, राजस्थान को यह अनुरोध करते हुए कि वे निविदा दस्तावेज की लागत को कम करके सुसंगत बनाएं अर्थात् वे केवल आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने की लागत ही वसूल करें।
- मुख्य नगरपालिक लेखापरीक्षक, कोलकाता नगर निगम को यह अनुरोध करते हुए कि यद्यपि निगम द्वारा अपनाए जाने वाला चयन संबंधी मानदंड लागू बना रह सकता है, तथापि फीस के मान को केएमसी द्वारा कार्य के विस्तार क्षेत्र और उनके लिए अपेक्षित वृत्तिकों की किस्म के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सहायक महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई को यह अनुरोध करते हुए कि वे समवर्ती लेखा परीक्षा समनुदेशन के लिए प्रस्ताव पत्र से शास्तिक खंड को विवर्जित करें।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को यह अनुरोध करते हुए कि वे आईसीएआई की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला का प्रस्ताव करने की पहल को स्वीकार करें ताकि उनके लेखा/ वित्त कार्मिकों को सुसंगत लेखांकन मानकों और विहित प्ररूपों से और अधिक निकट से अवगत कराया जा सके और इसे मूलभूत स्तर पर सक्षमता निर्माण उपाय करने के लिए वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रकटन के लिए सभी जगह उच्च पूर्विकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है ताकि शैक्षणिक संस्थाओं के लेखा/ वित्त कार्मिकों के बीच जागरूकता का सृजन किया जा सके।
- प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, आरबीआई को यह अनुरोध करते हुए कि वे बैंक में विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए संपरीक्षकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराएं ताकि वे 20 अप्रैल, 2015 तक अपनी लेखापरीक्षा को पूरा कर सकें।
- महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचित करते हुए कि समवर्ती लेखापरीक्षकों से एनपीए प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा करने संबंधी मामले की समीक्षा की गई थी और हमारा मत यह है कि कोई समवर्ती लेखापरीक्षक किसी ऐसी शाखा के लिए एनपीए आंकड़े प्रदान करेगा, जिसके लिए वह समवर्ती लेखापरीक्षक है तथापि वह समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाणपत्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया था कि इस अतिरिक्त कार्य के लिए समवर्ती लेखापरीक्षक को अतिरिक्त फीस का संदाय किया जाए।
- प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए कि बैंक शाखाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है और ऐसी शाखाओं की कानूनी लेखापरीक्षाओं के लिए नियुक्तियों की जा रही है जिसके अग्रिमों की राशि 31 मार्च 2015 को 20 करोड़ रुपए या अधिक हो गई थी।
- प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए कि बड़ी फर्मों (उदाहरण के लिए प्रवर्ग 1 फर्मों) को बड़ी शाखाएं आबंटित की जानी चाहिए ताकि ऐसी फर्मों की विशेषज्ञता और अवसंरचना का समुचित उपयोग हो सके और साथ ही प्राप्यों में गुणवत्ता की भी वृद्धि हो।
- मुख्य महाप्रबंधक (लेखा), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली को यह अनुरोध करते हुए कि वे मौजूदा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का निर्धारण करने और प्रणाली में सुधार करने का सुझाव देने के लिए परामर्शियों के नियोजन के लिए ऑनलाइन बोलियों को

आमंत्रित करने वाली उनकी सूचना से अग्रिम धन और प्रतिभूति राशि को समाप्त कर दें।

- समूह महाप्रबंधक (वित्त), मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रो रसायन लिमिटेड, मंगलौर को यह अनुरोध करते हुए कि वे वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लेखापरीक्षकों की भर्ती के लिए निविदा में उपयुक्त संशोधन करें।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को, उन्हें 20 अप्रैल, 2015 तक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तारण का अनुरोध करने के लिए।
- अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को, 20 अप्रैल, 2015 तक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तारण का अनुरोध करने के लिए और साथ ही इस बात की सूचना कानूनी लेखापरीक्षकों को देने के लिए।
- महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग, आंध्रा बैंक को यह अनुरोध करते हुए कि वे अपने सम्मानित बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सीए फर्मों के पैनल के लिए निविदा दस्तावेज को पुनः जारी करें।
- श्री मनीष श्रीवास्तव, आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की कानूनी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए अनुरोध किया गया था।
- आंध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को यह अनुरोध करते हुए कि वे आंध्रा बैंक की कर लेखापरीक्षा, अपने बैंक के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा करवाएं। इसके पश्चात्, इस पत्र की एक प्रति बैंक के सभी केंद्रीय कानूनी लेखापरीक्षकों को यह अनुरोध करते हुए भेजी गई थी कि वे इस बात के लिए बैंक को मनाने हेतु अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करें।
- सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी शाखा लेखापरीक्षकों को यह सूचित करते हुए एक पत्र भेजा गया था कि वे युक्तियुक्त समय के भीतर वर्ष 2014-15 के लिए बैंक शाखा लेखापरीक्षा को पूरा करें और बैंक द्वारा निर्धारित की गई सीमित समय-सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिए दबाव महसूस नहीं करें।
- कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुरोध करते हुए कि वे अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करते हुए बैंकों को यह अनुदेश जारी करें कि वे अपने समवर्ती लेखा परीक्षकों को दिए गए, मार्च, 2015 को समाप्त हुए तीन मासों की अवधि के लिए उनकी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का त्रैमासिक पुनर्विलोकन करने के अपने प्रस्ताव को वापस लें और साथ ही भविष्य में भी जब कभी ऐसे प्रस्ताव किए जाएं तो सारवान तथ्यों को विचार में लें।
- महानिदेशक (सी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को, "लेखापरीक्षा स्वीकार करने/उस कार्य को छोड़ने से इंकार करने" के संबंध में आईसीएआई को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट मुद्दे पर विचार प्रस्तुत किए गए थे।
- महानिदेशक (सी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को, उन्हें आईसीएआई के इस संबंध में मतों का अभ्यावेदन करते हुए कि आरबीआई ने पीएसबी के एससीए के विद्यमान संनियमों में परिवर्तनों का सुझाव दिया है, अर्थात् "फर्म के कम से कम दो भागीदारों या उसके वेतन प्राप्त करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पास सीआईएसए/आईएसए अर्हता होनी चाहिए"।
- मुख्य महाप्रबंधक, संस्थागत विकास विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन करते हुए :
 - प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की कानूनी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि
 - कर लेखापरीक्षा के लिए अलग से कोई फीस न होना
 - प्रत्येक लेखापरीक्षक को आबंटित शाखाओं की संख्या को सीमित करना
 - लेखा परीक्षकों के चयन के लिए मानदंड
 - एकमात्र प्रोप्राइटर फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन
 - संयुक्त संगोष्ठियां
 - आईसीएआई की वेबसाइटों के लिए नाबाई के परिपत्रों को जोड़ना।
- महाप्रबंधक (लेखापरीक्षा), स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, निरीक्षण विभाग को यह अनुरोध करते हुए कि वे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में वर्ष 2015-16 के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों के चयन के लिए मानदंड पर पुनर्विचार करें ताकि आबंटन

प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता को लाया जा सके।

- महाप्रबंधक (लेखापरीक्षा), देना बैंक, निरीक्षण विभाग को यह अनुरोध करते हुए कि वे देना बैंक में वर्ष 2015-16 के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों के चयन के लिए मानदंड पर पुनर्विचार करें ताकि आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता को लाया जा सके।
- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा प्रबंधक, वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब नेशनल बैंक में समवर्ती संपरीक्षा के लिए व्यक्तियों को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाली सूचना पर पुनः विचार करेगा।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और इंडियन बैंक को समवर्ती लेखा-परीक्षकों को संदत्त किए जाने वाले पारिश्रमिक का पुनरीक्षण करने के लिए।
 - आईडीबीआई बैंक से एक उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें यह कथन किया गया है कि आईडीबीआई बैंक समवर्ती लेखापरीक्षकों की फीस संरचना को समय-समय पर पुनरीक्षित करता है और तदनुसार समवर्ती लेखा परीक्षकों को संदेय फीस निर्धारित करता है। ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण फरवरी, 2015 में किया गया था।
- उप महाप्रबंधक, वित्त, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, उनका ध्यान, उनके संगठन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उनकी वेबसाइट पर निविदाएं आमंत्रित करते हुए रखी गई सूचना (एनआईटी) की ओर आकृष्ट करने हेतु, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अलावा लागत लेखाकारों को भी उक्त संपरीक्षा करने के लिए पात्र बनाया गया है।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आंध्रा बैंक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, समवर्ती लेखापरीक्षकों को संदत्त की जाने वाली लेखापरीक्षा फीस का पुनरीक्षण करने का अनुरोध करते हुए।
- उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, पुणे क्षेत्र को, उन्हें यह सुझाव देते हुए कि वे लेखापरीक्षा, कराधान और संबद्ध क्षेत्रों में सीए की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निविदा प्रणाली को प्रतिषिद्ध करके उसके स्थान पर कार्य और कार्य के मूल्य के अनुसार दर तय करें जिसे आंतरिक रूप से प्राक्कलित किया जा सकेगा।
- सीईओ, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ को यह अनुरोध करते हुए कि वे उनके विभाग के अधीन विभिन्न स्कीमों की संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का चयन करने के लिए हित की अभिव्यक्ति की सूचना में उचित संशोधन करें और आवेदकों को युक्तियुक्त समय प्रदान करते हुए उसे पुनः जारी करें। इसके पश्चात् श्री एस.सी. द्विवेदी, अपर आयुक्त, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), भूमि विकास एवं जल संसाधन, लखनऊ विभाग के साथ एक बैठक की गई थी।
- परियोजना निदेशक (अपर डीएम और कलेक्टर), डीआरडीए, धलाई, अम्बासा, त्रिपुरा को यह अनुरोध करते हुए कि वे उस सूचना को वापस लें, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को डीआरडीए, धलाई के माध्यम से प्रचालित होने वाली वित्तीय वर्ष 2014-15 की सभी केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसके अंतर्गत उनका संकलन भी है और यह अनुरोध भी किया गया था कि उसमें समुचित संशोधन करने के बाद पुनः जारी किया जाए।
- प्रबंध निदेशक, एम.पी. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को यह अनुरोध करते हुए कि वे एम.पी. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्त और लेखा प्रकोष्ठ के समर्थन के लिए अभिकरण की नियुक्ति के लिए आरएफपी में उपयुक्त संशोधन करें।
- उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली को पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैंक शाखा लेखापरीक्षकों को पैनल में सम्मिलित करने और नियुक्ति से संबंधित मुद्दों के बारे में, जो बैंक के बोर्ड को दी गई स्वायत्तता के कारण उद्भूत हो रहे हैं और साथ ही उन्हें उदाहरण भी दिए गए थे। हमारे अनुरोध के समर्थन में कंपनी अधिनियम, 2013 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का संदर्भ भी दिया गया था।
- प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा वन विकास एवं वृक्षारोपण निगम लिमिटेड, त्रिपुरा को यह अनुरोध करते हुए कि वे हस्तक्षेप करके संबद्ध अधिकारियों को हित की अभिव्यक्ति करने वाली उस सूचना को वापस लेने का निदेश दें, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखाओं के संकलन, संपरीक्षा, ई-फाइलिंग आदि करने के लिए ईओआई की अभिव्यक्ति हेतु निमंत्रण दिया गया था और यह भी अनुरोध किया गया था कि उसे उपयुक्त संशोधनों के बाद पुनः जारी किया जाए।
- प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा बागबानी निगम लिमिटेड, त्रिपुरा को यह अनुरोध करते हुए कि वे हस्तक्षेप करके संबद्ध अधिकारियों को हित की अभिव्यक्ति करने वाली उस सूचना को वापस लेने का निदेश दें, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से वित्त वर्ष 2014-15 के

लिए लेखाओं के संकलन, संपरीक्षा, ई-फाइलिंग आदि करने के लिए ईओआई की अभिव्यक्ति हेतु निमंत्रण दिया गया था और यह भी अनुरोध किया गया था कि उसे उपयुक्त संशोधनों के बाद पुनः जारी किया जाए।

- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को, उन्हें इस संबंध में संक्षिप्त विवरण देते हुए कि वे किस प्रकार आईसीएआई के सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग तीन स्तर की पंचायतों में कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुकर बना सकते हैं।
- उप महाप्रबंधक, वित्त, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को, उन्हें वृत्तिक विकास समिति के इस विनिश्चय के बारे में सूचित करते हुए कि यदि किसी निविदा के लिए प्राप्त न्यूनतम बोली (जिस पर निविदा को अंततः आबंटित किया जाता है) और उससे अगली न्यूनतम बोली के बीच अत्यधिक (असामान्य) अंतर है तो उक्त समनुदेशन और/या संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट/फर्मों के पियर पुनर्विलोकन का आदेश दिया जा सकता है। अतः यदि आपकी ओर से मंगाई गई बोलियां पूर्वोक्त निर्णय के अंतर्गत आती हैं तो आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि आप कृपया उक्त बोली के ब्यौरे आवश्यक कार्रवाई हेतु हमें भेजें।
- उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, रांची को यह अनुरोध करते हुए कि वे अपने संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों पर ही विचार करें।
- उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीए की वृत्तिक विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित प्राधिकारियों के साथ भी, और अधिक वृत्तिक अवसरों की खोज करने और विद्यमान अवसरों में अनछुए क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठकें की गई थी :

- महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार
- कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक।
- प्रभारी सीजीएम और श्री एस.सी. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, भारतीय रिजर्व बैंक
- सलाहकार, वित्त, रेलवे बोर्ड और सीए आर.के. मनोचा, कार्यकारी निदेशक, रेलवे बोर्ड
- प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पीएसबी में सीएसएस की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।
- उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय (ओ/ओ सी एंड एजी) ; महानिदेशक (वाणिज्यिक) और महानिदेशक (वाणिज्यिक) से, बैंकों को उनके पीएसबी के लिए सीएसएस की नियुक्ति के लिए दी गई स्वायत्ता के परिणामों के संबंध में चर्चा करने के लिए।
- प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
- डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, डीबीएस, भारतीय रिजर्व बैंक।
- मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और महानिदेशक (वाणिज्यिक), ओ/ओ सी एंड एजी के साथ पब्लिक सेक्टर बैंकों के केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों को पैनलबद्ध करने और उनकी पात्रता और चयन के लिए संनियमों में अंतर्बलित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उक्त बैठक में, आईसीएआई ने पीएसबी के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति की नई प्रणाली के संबंध में अपनी चिंता को जोर-शोर से व्यक्त किया था। आईसीएआई द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।
- मुख्य महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के साथ, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, आईडीडी, नाबाई को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि वे आरआरबी के संपरीक्षकों को संदत्त की जाने वाली फीसों में वृद्धि करें क्योंकि वे काफी कम थी। यह भी विनिश्चय किया गया था कि आरआरबी और सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षकों के लिए विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए।
- उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री।
- कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और श्री आर.सी. लोढा, कार्यकारी निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ और उन्हें

यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भी भेजा गया था कि वे अपने-अपने सम्मानित बैंक की लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए कानूनी लेखा परीक्षकों को पर्याप्त समय अर्थात् 20 अप्रैल, 2015 तक का समय प्रदान करें।

- माननीय रेल मंत्री के साथ, जिसमें माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रबंधकीय स्वायत्ता की आड़ में बैंकों द्वारा कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही नई प्रणाली के विरुद्ध विरोध दर्शित किया गया था।
- महानिदेशक (वाणिज्यिक), सी एंड एजी के साथ, सी एंड एजी द्वारा अनंतिम पैनल वेबसाइट पर रखे जाने के कारण उदभूत होने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।
- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की लेखापरीक्षा फीस में वृद्धि करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।

वृत्तिक अवसरों और उनके साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए मानदंडों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट/फर्मों का पैनल उपलब्ध कराया गया था।

अपने सदस्यों के कौशल और उनकी योग्यता में सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट सहायता उपलब्ध कराने हेतु मार्ग और साधनों पर विचार करने के अपने प्रयास में समिति ने अवधि के दौरान निम्नलिखित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में सक्षमता निर्माण के लिए एक वेब आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संकाय सहयोग से आईआईटी मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- आईआईटी, मुंबई में प्रोडभवन आधारित लेखांकन और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मानकों के संबंध में 11 मई, 2014 को आयोजित एमएचआरडी कार्यक्रम को अध्यक्ष, पीडीसी द्वारा संबोधित किया गया था।
- गैर-बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के अनुरोध पर, “एनबीएफसी- संपरीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व” विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था। डीजीएम, डीएनबीएस, आरबीआई और प्रबंधक, डीएनबीएस, आरबीआई ने इस वेबिनार को संबोधित किया था।
- एमएचआरडी द्वारा त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला में उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित कार्यशाला के लिए संकाय समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- आईसीएआई भवन, उदयपुर में “नया वातावरण नई चुनौतियां” शीर्षक वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- लाभ गंगा सामुदायिक केंद्र, इंदौर में “ज्ञान को समृद्ध बनाना – वृत्ति को सशक्त बनाना” विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- वृत्तिक विकास समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ संयुक्त रूप से होटल ताजमहल, मानसिंह मार्ग, नई दिल्ली में एशियन विकास बैंक के तकनीकी सहयोग से “एडीबी में वित्तीय सम्यक् अनुपालन नियोजनों के लिए परामर्श संबंधी अवसर” विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी और इसमें लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था (मूल योजना से लगभग दोगुना)।
- बैंक लेखापरीक्षाओं से संबंधित सदस्यों के मुद्दों का समाधान करने के लिए बैंक लेखापरीक्षा संबंधी एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था। यह वेबकास्ट काफी सफल रहा था। इसमें देश भर से काफी बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों ने इस अवसर का अनुकूल लाभ उठाया था और साथ ही प्रश्नोत्तर सत्र भी काफी क्रियाशील रहा था।
- बैंक संपरीक्षा, कंपनी अधिनियम, राज्य और संघीय बजट जैसे विषयों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

5.23 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति विद्यमान शासकीय लेखांकन प्रणाली का पुनर्विलोकन करती है और उसके आधार पर लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के संबंध में पणधारियों, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, वृत्ति के सदस्य, मीडिया, एनजीओ और पूरा समाज भी है, के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए सुधारों का सुझाव देती है। समिति विभिन्न मंत्रालयों और वृत्तिक निकायों से सहयोग करती है और इस प्रकार लोक सेवा प्रदाय तंत्र और लोक हित को सर्वोपरि बनाए रखने सहित जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि करती है। समिति विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न निकायों को नीति, कार्यान्वयन और मानीटरी से संबंधित विषयों में क्वालिटी अंतःनिवेश उपलब्ध कराने में तथा सक्षमताओं के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करती है। समिति भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए विभिन्न राष्ट्रव्यापी अभियानों को समर्थन प्रदान करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी भागीदारी करती है। समिति का उद्देश्य शासकीय निकायों के भीतर प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसी पद्धतियों का विकास करना जो लेखांकन सुधार प्रक्रिया में

सहयोग देने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को समर्थ बनाएंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा नियंत्रक और महालेखाकार के साथ सहयोग और समन्वय करना है जिससे कि शासकीय लेखांकन प्रणाली के ढांचे में सुधार किया जा सके।

कार्ययोजना 2015-16

- ऐसी नीतियों, परियोजनाओं और ढांचों को विकसित करना, जो लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और आधुनिक पब्लिक सेक्टर दृष्टिकोण को उपदर्शित करें।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभागों और स्थानीय निकायों के साथ परस्पर क्रिया करना और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराना।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्रों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निकायों के साथ खोजबीन संबंधी अनुसंधान कार्य करने में तथा उसका संवर्धन करने में सहयोग करना।
- शासकीय लेखांकन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी), सीजीए और सी एंड एजी के साथ पद्धतियां तैयार करने हेतु बैठकें आयोजित करना।
- समिति के विकास के लिए लोक कृत्यकारियों और नीति निर्माताओं के साथ और अधिक तकनीकी तथा वहनीय अंतःनिवेशों के आदान-प्रदान हेतु परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन करना।
- सरकारी विभागों में सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और सहयोगी अनुसंधान करने के लिए देश के भीतर और बाहर संपर्क स्थापित करना तथा सूचना और प्रकाशनों के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ तकनीकी सहयोग हेतु करार करना।
- विभिन्न सरकारी विभागों में सक्षमता निर्माण के लिए उनके साथ परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और उनकी संभावनाओं का पता लगाना ताकि लेखांकन सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
- देश के सभी राज्यों में, समिति की पहलों और क्रियाकलापों को और अधिक बल देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यबलों का निर्माण करना।
- वित्तीय प्रशासन और लोक निधियों के प्रबंध हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के विषय पर ई-न्यूज लैटर, प्रकाशन और अनुसंधान सामग्री निकालना।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन से संबंधित मुद्दों पर समझ में वृद्धि करने के लिए वेबकास्ट के माध्यम से बेहतर सेवाओं के प्रदाय हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और यह उपयोग करते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और शिखर वार्ताओं का आयोजन करना।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के विषय पर जागरूकता कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन करना।

समिति के प्रमुख क्रियाकलाप

1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 तक की अवधि के दौरान समिति की मुख्य उपलब्धियां/पहले नीचे उल्लिखित की गई हैं :-

- समिति ने 30 और 31 दिसंबर, 2014 को जयपुर में, बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई की सीआईआरसी की जयपुर शाखा के माध्यम से "चुनौतियों से आगे बढ़ना - हमारी भूमिका को पुनःपरिभाषित करना" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- समिति ने वर्ष 2014 और 2015 के दौरान राजस्थान और झारखंड राज्यों के विधान सभा के सदस्य के लिए "वित्तीय प्रबंध : मूल्यांकन और निर्धारण" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया।
- समिति ने वर्ष 2014 के दौरान, आईसीएआई टॉवर, बीकेसी, मुंबई में वृहत् मुंबई नगर निगम के पदधारियों के लिए "प्रोदभव लेखांकन, बजट संबंधी नियंत्रण और लेखापरीक्षा ढांचे" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के 17 बैचों का आयोजन किया।
- समिति ने वर्ष 2014-15 के दौरान अखिल भारत आधार पर "नए कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में लेखांकन और लेखापरीक्षा उपबंधों" के विषय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय के साथ सहयोग किया और इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- समिति ने वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के साथ, उनके अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि करने हेतु पहल करने के विचार से सहयोग किया है और गुजरात तथा केरल के वित्त विभाग के पदधारियों के लिए प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन किया।

- समिति ने गुडगांव में "गैर वित्त के लिए वित्त" विषय पर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- समिति ने सूचना प्रणालियों और लेखापरीक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएसए), नोएडा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से "लेखा परीक्षा और नया कंपनी अधिनियम" विषय पर आईएएडी के समूह क और ख के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- समिति ने वर्ष 2014 और 2015 के दौरान "द डायनामिक्स ऑफ लोकल गर्वनेंस इन इंडिया", "गर्वनमेंट अकाउंटिंग रिफार्म : एन ओवरव्यू", "कामनली यूज्ड टर्म्स इन पब्लिक फाइनेंस एंड गर्वनमेंट अकाउंटिंग (अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में)" नामक प्रकाशन और "क्विक इन साइट आन अक्रूअल अकाउंटिंग" विषय पर एक पुस्तिका भी निकाली।
- समिति ने "लोक वित्त और शासकीय लेखांकन में चुनौतियों से ऊपर उठना" विषय पर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।
- समिति द्वारा "भारत में लोक वित्त प्रणाली - हाल की पहले, चुनौतियां और आगे का मार्ग" विषय पर वेबकास्ट का आयोजन किया।
- वर्ष 2014-15 के दौरान समिति ने नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर का प्रकाशन किया।

5.23 अनुसंधान समिति

अनुसंधान, किसी वृत्ति के ज्ञान आधार को व्यापक बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके एक ऐसा आधार तैयार करता है, जिस पर कोई वृत्ति विकसित होकर समृद्धि प्राप्त करती है। वृत्ति के लिए अनुसंधान के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1955 में हुई संस्थान की 17वीं बैठक में परिषद् ने एक अस्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति का गठन किया था। अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। इसके प्रारंभ से ही, यह समिति सदस्यों को वृत्तिक हित के विभिन्न क्षेत्रों, विशिष्ट रूप से लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु सदैव सक्रिय रही है। समिति ऐसे समकालीन मुद्दों, जो देश में आर्थिक सुधारों से संबद्ध विधियों में संशोधनों और अन्य घटनाओं के कारण सामने आते हैं, के संबंध में लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी सदैव सक्रिय रही है।

समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अनुसंधान अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि के रूप में प्रकाशनों को निकालती है। समिति देश में वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के विचार से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का भी आयोजन करती है।

समिति की उपलब्धियां

रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान, समिति ने संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन दो मार्गदर्शक टिप्पण तैयार किए थे :

1. 'जीएन (ए) 33 व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण'।
2. 'जीएन (ए) 34 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्ययों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (15 मई, 2015 को निकाला गया)'।

जीएन (ए) 33 व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण

यह मार्गदर्शक टिप्पण, अधिसूचित लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के संबंध में विभिन्न अस्तित्वों द्वारा व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन में अपनाए जाने वाले व्यवहारों में एकसमानता लाने के विचार से और इस संबंध में आज्ञापक मार्गदर्शन की कमी को ध्यान में रखते हुए व्युत्पन्न संविदाओं के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

जीएन (ए) 34 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्ययों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (15 मई, 2015 को निकाला गया)

यह मार्गदर्शक टिप्पण निगम सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों के संबंध में मान्यता, उनके मापमान, प्रस्तुतीकरण और व्यय के प्रकटन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

समिति ने 6 फरवरी, 2015 को चेन्नई में 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता की ओर' विषय पर एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य देश में अस्तित्वों की वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करना था। इस कार्यशाला में, शील्ड पैनल के सदस्यों द्वारा देश में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के विचार से एक प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें

उनकी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों और प्रतिस्पर्धा के लिए प्राप्त अन्य दस्तावेजों के मूल्यांकन से उद्भूत प्रमुख संप्रेक्षणों को प्रमुख रूप से दर्शित किया गया था।

समिति ने बैंकों के लिए 8 अप्रैल, 2015 को मुंबई में 'बैंककारी क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने हेतु' विषय पर एक अन्य तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया था, जो बैंककारी क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने के विचार से शील्ड पैनल पुनर्विलोकन से उद्भूत होने वाले संप्रेक्षणों पर आधारित था। इसमें पब्लिक सेक्टर और साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंकों के सीएफओ अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

समिति की विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर हैं, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

(क) चलचित्र फिल्मों के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड :

समिति ने चलचित्रों के क्षेत्र के विनिर्दिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए लेखांकन मानकों और अन्य साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को आरंभ किया था।

(ख) वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता : एक निदर्शी गाइड संबंधी प्रकाशन का पुनरीक्षण :

उपरोक्त परियोजना को, इस तथ्य पर विचार करते हुए आरंभ किया गया था कि उपरोक्त प्रकाशन वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के दौरान किए गए मुख्य संप्रेक्षणों के आधार पर वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और इसे सदस्यों और अन्य उपयोक्ताओं द्वारा उपयोगी माना गया था। तदनुसार, पश्चात्पूर्वी वर्षों के शील्ड पैनल के संप्रेक्षणों के आधार पर प्रकाशन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया था।

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त पदों संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण

उपरोक्त मार्गदर्शन टिप्पण को उसमें उन पदों को सम्मिलित करने हेतु पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया है, जिन्हें विद्यमान लेखांकन मानकों या इंड एस में परिभाषित नहीं किया गया है।

(घ) डाटकाम कंपनियों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण का पुनरीक्षण

उपरोक्त परियोजना को इस विचार के साथ आरंभ किया गया था कि इस बात की समीक्षा की जाए कि क्या डाटकाम कंपनियों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण इस समय सुसंगत है अथवा उसे वापस लिए जाने/संशोधित करने की आवश्यकता है।

(ङ) गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड का पुनरीक्षण और उसका लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के रूप में उन्नयन

यह विनिश्चय किया गया था कि पूर्वोक्त तकनीकी गाइड को पुनरीक्षित किया जाए और साथ ही लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के रूप में इसकी प्रास्थिति का उन्नयन किया जाए क्योंकि ये लेखांकन मानक मुख्य रूप से लाभ उन्मुख क्रियाकलापों के लिए तैयार किए गए थे जबकि गैर-लाभकारी संगठनों के लिए भी एकसमान लेखांकन मार्गदर्शन अपेक्षित हैं।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 और साथ ही इंड एस को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में प्रवृत्त लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणों को पुनरीक्षित करने/वापस लेने संबंधी परियोजना

इस परियोजना को इस विचार के साथ आरंभ किया गया है कि इस बात की समीक्षा की जाए कि क्या आज की तारीख में प्रवृत्त लेखांकन संबंधी किसी मार्गदर्शन टिप्पण को कंपनी अधिनियम, 2013 या इंड एस (जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ करते हुए कंपनियों के कतिपय वर्ग द्वारा अपनाए जाने आज्ञापक हैं) को ध्यान में रखते हुए वापस लिए जाने/पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है।

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची

इस परियोजना को इस विचार के साथ आरंभ किया गया है कि ऐसा एक प्रकाशन निकाला जाए, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटनों के संबंध में सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को एक सुगम संदर्भ उपलब्ध कराए।

(ज) लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची का पुनरीक्षण

समिति ने इस परियोजना को, वर्ष 2007 में जारी ऊपर नामित प्रकाशन को पुनरीक्षित करने के लिए आरंभ किया है ताकि 1 जनवरी, 2007 के पश्चात् की अवधि से संबंधित लेखांकन मानकों के अंतर्गत आने वाले विषयों से उद्भूत होने वाली किन्हीं और अन्य प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया जा सके क्योंकि मूल प्रकाशन में वर्ष 2007 तक की प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों हेतु वार्षिक प्रतियोगिता के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अस्तित्वों को एक 3 टियर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होता है। भाग लेने वाले अस्तित्वों की वार्षिक रिपोर्टों का प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों के एक पैनल द्वारा किया जाता है, जो आईसीएआई के ऐसे सदस्य होते हैं, जो लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों। इसके पश्चात् शील्ड पैनल और अनुसंधान समिति की एक उप समिति, जिसमें कुछ अन्य स्वतंत्र विख्यात लेखांकन और संपरीक्षा विशेषज्ञों के साथ अनुसंधान समिति के कुछ सदस्य सम्मिलित होते हैं, द्वारा अस्तित्वों का आगे और पुनर्विलोकन किया जाता है। अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों पर तकनीकी और कानूनी अनुपालन, गुणवत्ता, जानकारी की प्रस्तुति की प्रकृति और रीति, निगम शासन परिप्रेक्ष्य से रिपोर्टिंग जैसे विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है और ऐसा करते हुए मुख्यतः लागू लेखांकन मानकों, कानूनी अपेक्षाओं और सुसंगत विधियों के अनुपालन पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर अस्तित्वों को शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है और उन्हें ज्यूरी के समक्ष रखा जाता है। ज्यूरी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विख्यात व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। भाग लेने वाले सूचीबद्ध अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों पर दक्षता से विचार किया जाता है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के पुरस्कार विजेताओं का चुनाव किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए ज्यूरी की बैठक 22 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री के. रहमान खान, संसद सदस्य, राज्य सभा, संघ के पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और पूर्व उपसभापति, राज्य सभा द्वारा की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए ज्यूरी की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों में डॉ. भास्कर चटर्जी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (आईआईसीए), सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए टी.एस. विश्वनाथ, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री ए.के. अवस्थी, पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा, श्री एम नरेंद्र के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सुश्री सुभाश्री श्रीराम, सीएफओ और ईडी, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, प्रो आर नारायणस्वामी, संकाय, मैनेजमेंट, बंगलौर के भारतीय संस्थान (आईआईएम-बी), सीए राजेंद्र गोयल, पूर्व निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर।

पुरस्कारों के स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो।

'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 5 फरवरी, 2015 को चेन्नई में एक समारोह का आयोजन किया गया था। सीए. के. रहमान खान, संसद सदस्य, राज्य सभा, संघ के पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और पूर्व उपसभापति, राज्य सभा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुल 20 पुरस्कार, जिनमें 4 स्वर्ण शील्ड, 6 रजत शील्ड और 10 पट्टिकाएं प्रदान की गई थीं।

वर्ष 2013-14 के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेताओं की सूची

प्रवर्ग	पुरस्कार	अस्तित्व का नाम	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों के लिए
I	पब्लिक सेक्टर बैंक	स्वर्ण शील्ड	शून्य
		रजत शील्ड	शून्य
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	केनरा बैंक 31 मार्च, 2014
II	निजी बैंक (सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों सहित)	स्वर्ण शील्ड	एक्सिस बैंक लि.
		रजत शील्ड	शून्य
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	एचडीएफसी बैंक लि. 31 मार्च, 2014
III	इंश्योरेंस सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 31 मार्च, 2014
		रजत शील्ड	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. 31 मार्च, 2014
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 31 मार्च, 2014

		पट्टिका		
IV	वित्तीय सेवा सेक्टर (बैंकिंग और इश्योरेंस से भिन्न)	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया।		
V	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	संयुक्त रूप से : एसीसी लि. और ल्यूपिन लि.	31 दिसंबर, 2013 और 31 मार्च, 2014
		रजत शील्ड	केस्ट्रोल इंडिया लि.	31 दिसंबर, 2013
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि.	31 मार्च, 2014
VI	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपए या इससे कम की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	शून्य	शून्य
		रजत शील्ड	केवल किरन क्लार्किंग लि.	31 मार्च, 2014
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	सेंटम इलैक्ट्रॉनिक्स लि.	31 मार्च, 2014
VII	अवसंरचना और संनिर्माण सेक्टर (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	शून्य	
		रजत शील्ड	शून्य	
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	एनटीपीसी लि.	31 मार्च, 2014
VIII	अवसंरचना और संनिर्माण सेक्टर (500 करोड़ रुपए से कम की आवर्त के लिए)	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया		
IX	सर्विस सेक्टर (वित्तीय सेवा सेक्टर से भिन्न) (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	शून्य	शून्य
		रजत शील्ड	माइंड ट्री लि.	31 मार्च, 2014
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	इंफो ऐज (इंडिया) लि.	31 मार्च, 2014
			हेक्सावेयर एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी लि.	31 दिसम्बर, 2013
			जैन्सर टेक्नोलॉजी लि.	31 मार्च, 2014
X	सर्विस सेक्टर (वित्तीय सेवा सेक्टर से भिन्न) (500 करोड़ रुपए से कम की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	शून्य	शून्य
		रजत शील्ड	अल्फाजियो (इंडिया) लि.	31 मार्च, 2014
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	जस्ट डायल लि.	31 मार्च, 2014
XI	गैर लाभकारी सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	शून्य	शून्य
		रजत शील्ड	विद्या डेरी	31 मार्च, 2014
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	शून्य	शून्य
XII	स्थानीय निकाय	शून्य		
XIII	कृषि सेक्टर	शून्य		

5.25 रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति

रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं का पुनर्विलोकन करती है

जिससे कि वृत्ति की विश्वसनीयता के निर्माण और साथ ही उभरते क्षेत्रों में उसके लिए स्थान का सृजन करने के दीर्घकालिक भावी योजना की पूर्ति के लिए नीतिगत कार्यो जना में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकें ताकि वह समाज के लिए और अधिक उपयोग सिद्ध हो सके और साथ ही उसके विस्तार क्षेत्र में भी वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं पर भी विचार करती है, जो वृत्ति के लिए अभिप्रेत विनियमित क्षेत्रों पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं और ऐसे मुद्दों, जिनके संबंध में वृत्ति द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, पर विचार करके अन्य क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए मार्गों और उपायों का सुझाव देकर उसे आगे और अनुपूरित करती है।

5.26 इंड एएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति

जैसे-जैसे विश्व का वैश्वीकरण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) को अधिकाधिक रूप से वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है। लेखांकन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को छूने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण का विनिश्चय किया गया है। जुलाई, 2014 में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में, भारतीय कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक आधार पर तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 से आज्ञापक आधार पर आईएफआरएस – अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई ने आईएफआरएस – अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को स्थापित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

इंड एएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति, उसके गठन से ही, अथक रूप से इंड एएस के संपरिवर्तन को सुचारू बनाने हेतु कार्य कर रही है। भावी कार्य योजना और आईएफआरएस अभिसरित इंड एएस की अधिसूचना को देखते हुए, समिति ने यह विनिश्चय किया है कि सदस्यों और अन्य पणधारियों को इंड एएस के बारे में शिक्षित करने के लिए कड़े प्रयास करने की आवश्यकता है।

समिति भारतीय लेखांकन मानकों के संबंध में शैक्षणिक सामग्रियां जारी करके सदस्यों और अन्य पणधारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। किसी शिक्षण सामग्री में, संबंधित भारतीय लेखांकन मानक का संक्षिप्त विवरण और उससे संबंधित सभी मुद्दों को सम्मिलित करते हुए बहुधा पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न (एफएक्यू) अंतर्विष्ट होते हैं, जो मानक का कार्यान्वयन करते समय बार-बार उद्भूत होते हैं। हाल ही में, समिति ने इंड एएस 101, भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अपनाया जाना और इंड एएस 10, रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाओं के संबंध में शैक्षणिक सामग्री निकाली है। उपरोक्त प्रकाशनों के अलावा समिति ने लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) के साथ संयुक्त रूप से 'भारतीय लेखांकन मानक : एक पर्यावलोकन' नामक एक प्रकाशन निकाला है ताकि पणधारियों को इंड एएस से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, कतिपय इंड एएस से संबंधित शैक्षणिक सामग्रियों को पुनरीक्षित किया जा रहा है, जिन्हें पूर्व में समिति द्वारा जारी किया गया था और यह आशा की जाती है कि यह पुनरीक्षित शैक्षणिक सामग्रियां समिति द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएंगी। अन्य विभिन्न इंड एएस के संबंध में शैक्षणिक सामग्रियां तैयार की जा रही हैं।

समिति कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करके आईएफआरएस अभिसरित इंड एएस के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए सदस्यों और अन्य पणधारियों की जानकारी में अभिवृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय भी कर रही है। इस दिशा में, आईएफआरएस से संबंधित एक व्यापक 100 – घंटे का एक प्रमाणपत्र समिति द्वारा भारत और विदेश में चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा पर्याप्त कक्षा प्रशिक्षण के साथ इंड एएस/आईएफआरएस के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि सदस्यों को आईएफआरएस के इस आधुनिक युग में सक्षम बनाया जा सके। अप्रैल, 2014 से जून, 2015 की अवधि के दौरान आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 34 बैचों का संचालन किया गया है, जिनमें लगभग 1200 प्रतिभागियों ने कक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी तक, कुल 6100 सदस्यों को इस कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

समिति देश के विभिन्न अवस्थानों पर इंड एएस संबंधी एक/दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस श्रृंखला के पहले कार्यक्रम का आयोजन 8-9 मई, 2015 के दौरान कोलकाता में किया गया था। लगभग 200 प्रतिभागियों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया था। दूसरे कार्यक्रम का आयोजन 28-29 मई, 2015 के दौरान एर्नाकुलम में किया गया था, जिसमें लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने विभिन्न उद्योगों आदि के लिए निदेशक बोर्डों और संपरीक्षा समितियों के सदस्यों के लिए निगम प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने का भी विनिश्चय किया है।

परिषद् वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति ने युवा सदस्यों के सशक्तिकरण संबंधी समिति के साथ मिलकर "आईएफआरएस संबंधी प्रारंभिक कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम का आयोजन देश भर के अपने युवा सदस्यों के लिए किया था जिससे कि उनके ज्ञान आधार में अभिवृद्धि की जा सके और उन्हें आईएफआरएस में उल्लिखित सिद्धांतों को समझने में सहायता की जा सके।

समिति ने आईएफआरएस और कंपनी अधिनियम, 2013 संबंधी एक दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह आयोजन लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के लिए किया गया था। उक्त कार्यक्रम के दौरान आईएफआरएस के प्रमुख विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। पीएसयू के वित्तीय कार्यपालकों और अन्य वरिष्ठ पदधारियों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया था।

समिति ने कतिपय कंपनियों के लिए तैयार आईएफआरएस निगम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

उपरोक्त पहलों के अतिरिक्त, समिति इंड एस के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए इंड एस संबंधी वेबकास्टों की एक श्रृंखला का भी आयोजन कर रही है।

समिति इंड एस के संबंध में जानकारी और जागरूकता का सृजन करने और इस संपरिवर्तन को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास कर रही है।

5.27 जन संपर्क क्रियाकलाप

वर्ष 2014-15 के दौरान, समिति द्वारा वर्ष के दौरान की गई विभिन्न नई पहलों के परिणामस्वरूप मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई थी। प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे मीडिया के साथ लगातार परस्पर क्रियाएं करते रहें ताकि सदस्यों, छात्रों और पणधारियों को आईसीएआई द्वारा किए जा रहे उत्तम कार्यों के संबंध में जानकारी दी जा सके।

पीआर समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- संस्थान ने, 1 जुलाई, 2015 को अपना स्थापना दिवस मनाया था। पीआर समिति ने एक संरचनाबद्ध रीति में सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को "सीए दिवस" को मनाने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए प्रमुख पहले की थी। अध्यक्ष से एक संसूचना को सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को अग्रेषित किया गया था, जिसमें उनसे उनके द्वारा किए जाने वाले साधारण क्रियाकलापों के अतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संबंधी संकटों के बारे में जागरूकता का सृजन, कर क्लीनिकों का आयोजन, आईसीएआई द्वारा महिला सशक्तिकरण के मद्दे की, की गई पहलों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने, साइक्लोथोन, हरित मैराथोन, पौद्या रोपण, साक्षरता किटों का वितरण, रक्तदान जैसे विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करके सीए दिवस का आयोजन करने का अनुरोध किया गया था। इन क्रियाकलापों का उद्देश्य आईसीएआई की छवि में अभिवृद्धि करना और समाज तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना था। प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करने के लिए एक विशेष अनुदान भी मंजूर किया गया था।

इस अवसर को मनाने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें एक हजार से अधिक वृत्तिकों और पणधारियों ने भाग लिया था। सीए श्री पीयूष गोयल, संघ के माननीय विद्युत, कोयला और नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस समारोह के मुख्य अतिथि थे तथा उन्होंने श्रोताओं को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम को मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी।

- 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, आईसीएआई ने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग के महत्व से सभी सदस्यों और छात्रों को अवगत कराने तथा उन्हें इस संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की थी। सभी शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों को विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करने का अनुरोध किया गया था। इस पहल के संबंध में उत्तम प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी।
- 2 सितंबर, 2014 को दिल्ली में "वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखांकन सुधारों संबंधी सम्मेलन" के लिए एक संस्थागत भागीदार के रूप में आईसीएआई ने सीआईआई के सहयोग से "वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखांकन सुधार" विषय पर एक सीआईआई सम्मेलन का आयोजन किया था। पीआर समिति ने उक्त सम्मेलन के लिए सीआईआई के साथ परस्पर संपर्क किया था।
- 11 फरवरी, 2015 को संस्थान का 65वां वार्षिक समारोह नई दिल्ली में मनाया गया था। सीए श्री पीयूष गोयल, संघ के माननीय विद्युत, कोयला और नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम को मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी।
- 29-31 जनवरी, 2015 के दौरान बंगलौर में "लेखांकन वृत्ति : वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं का निर्माण ; विकास को प्रोत्साहन" शीर्षक वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। श्री सुरेश प्रभु, संघ के माननीय रेल मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इस कार्यक्रम को मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी।
- वर्ष के दौरान आमने-सामने साक्षात्कारों/प्रेस विज्ञप्तियों/प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई थी, जिसके दौरान मीडिया को पाठ्यचर्या में परिवर्तनों और उन्हें अद्यतन बनाने, आईएफआरएस भावी कार्ययोजना, कंपनी अधिनियम, सीए के लिए नए दिशानिर्देश, स्वच्छ भारत अभियान को अग्रसर करना, अनुशासन संबंधी मामलों को अद्यतन करना, अन्य क्रियाकलाप आदि जैसी पहलों के बारे में नवीनतम घटनाओं से निरंतर अवगत कराया गया था।
- आज के सक्रिय संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र और संभावनाओं को भी, विभिन्न प्रकाशनों में लेख, विज्ञापन आदि के द्वारा संवर्धित किया गया था।
- पीआर कार्य के भागरूप में, साधारण जनता और मीडिया को विभिन्न समाचार पत्रों/वित्तीय समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों और लेखों तथा विज्ञापन जारी करने के माध्यम से आयोजित की गई विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों से अवगत कराया

गया है।

- अगस्त-सितंबर, 2014 में आईसीएआई द्वारा आयोजित कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी को भी मीडिया के समक्ष रखा गया था। नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों को पूरे भारत में संगठनों द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम वेतन प्रस्तावों से संबंधित जानकारी को विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था।
- आईसीएआई ने 1 जुलाई, 2014 को अपने स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह को मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी।
- संस्थान के भीतर, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों के बीच संपर्क विकसित करने के विचार से विभिन्न विभागों को सांभार समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- आईसीएआई द्वारा की गई पहलों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए, सीए जर्नल के साथ-साथ वायुयान पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/कारबार पत्रिकाओं में विज्ञापनों को जारी किया गया था। इससे न केवल सदस्यों और पणधारियों के बीच जागरूकता का सृजन होता है अपितु इससे आईसीएआई के ब्रांड के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होती है।

5.28 महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति

महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् वर्ष 2014-15 के लिए परिषद् की महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सदस्यों के विकास के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है।

महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति, विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि का आयोजन करके महिला सीए के साधारण फायदे के लिए अपनी महिला सदस्यों को सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध है। 1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान, समिति ने पूरे भारत में और विदेशों में 37 कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत विश्व सीए महिला शिखर सम्मेलन भी था, जो कि दुबई में आयोजित एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

कार्यक्रमों की संरचना ऐसी रीति में तैयार की गई थी जिससे कि महिला सदस्यों को सामाजिक और साथ ही वृत्तिक क्षेत्र, दोनों में सशक्त किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सत्रों में, तकनीकी और साथ ही ऐसे गैर-तकनीकी, दोनों प्रकार के विषय सम्मिलित थे, जिन्हें मुख्यतः प्रमुख महिला संकाय सदस्यों द्वारा उठाया गया था।

एक अनन्य महिला पोर्टल, “महिला सदस्यों के लिए पोर्टल” को भी समिति द्वारा आरंभ किया गया है, जो हमारी महिला सदस्यों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा वे अपनी अपेक्षाओं को सामने रख सकती हैं और उन्हें उपलब्ध नमनीय कार्य संबंधी विकल्पों की तलाश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य हमारी महिला सदस्यों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना भी है, जो न केवल उनके ज्ञान को अद्यतन बना सके अपितु जहां वे अपने विचारों और चिंताओं का भी परस्पर आदान-प्रदान कर सकें।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- समिति ने नई दिल्ली में “महिला सीए का आगे की ओर मार्च” विषय पर ‘दक्षिण एशियाई अकाउंटेंट संघ (साफा) महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम’ का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला प्रतिनिधि-मंडलों को एक ऐसा अवसर प्रदान करना था, जहां उन्हें महिला नेतृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं से अवगत कराया जा सके।
- समिति ने दुबई में एक विश्व महिला सीए शिखर वार्ता – दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके दौरान महिला प्रतिभागियों को एक ऐसा अवसर और मंच उपलब्ध कराया गया था जहां वे अपने विचारों और चिंताओं का आदान-प्रदान करके एक-दूसरे से परस्पर क्रिया कर सकें।
- समिति ने साधारणतया चार्टर्ड अकाउंटेंट भ्रातृसंघ के फायदे के लिए छह वेबकास्टों का भी आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत 8 अप्रैल, और 10 जून, 2015 को क्रमशः संघ के माननीय रेल मंत्री सीए सुरेश प्रभु और संघ के माननीय विद्युत, कोयला और नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सीए पीयूष गोयल के साथ दो “लाइव परस्पर क्रियाशील बैठकें” भी हैं।
- समिति ने अपनी महिला सदस्यों को वृत्ति संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें महिला निदेशकों की भूमिका के लिए तैयार करने हेतु दिल्ली और मुंबई में “महिला निदेशकों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आयोजन किया था।
- समिति द्वारा मुंबई में “सेवाकर” संबंधी एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाकर उन्हें वर्तमान वृत्ति संबंधी चुनौतियों का सामना करने हेतु सशक्त बनाना था।
- समिति द्वारा, प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशलों संबंधी अध्यापन उपलब्ध कराने तथा इस क्षेत्र में होने वाली नई घटनाओं से अवगत कराने तथा वृत्ति के लिए अपेक्षित आवश्यक आईटी कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से महिला सदस्यों के लिए आईटी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया था।

5.29 युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति

युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति (वाईएमईसी), जो कि आईसीएआई की अस्थायी समितियों में से एक है, का गठन युवा सदस्यों की अथाह संभावनाओं को पोषित करने और उन्हें निजी तथा वृत्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करने तथा उन्हें विश्व स्तरीय वृत्तिक बनाने हेतु उत्साहित करने के लिए किया गया था।

वाईएमईसी युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि उन्हें अद्यतन ज्ञान से सुसज्जित किया जा सके और वृत्ति तथा सेवा के क्षेत्र में उन्हें विशेषज्ञ भी बनाया जा सके। समिति युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वृत्ति से संबंधित नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न पहलें कर रही हैं। समिति युवा सदस्यों को नई भूमिकाएं अपनाने या कैरियर संबंधी चुनौतियां स्वीकार करने हेतु सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों का आयोजन करती है।

वाईएमईसी का विजन

- वृत्ति में प्रवेश करने वाले युवा सदस्यों की भावी आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाना और ऐसे वृत्तिकों को परिवर्तनशील परिस्थितियों के लिए तैयार करना
- युवा सदस्यों को, जहां तक तकनीक और वृत्तिक कौशलों का संबंध है, समाज की प्रत्याशाओं पर खरा उतरने में सहायता करना
- युवा सदस्यों के लिए व्यवसाय/नियोजन/उद्यमशीलता के नए अवसरों का पता लगाना और उन्हें विकसित करना।

5.30 क्वालिटी पुनर्विलोकन

केंद्रीय सरकार ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अधीन एक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया था, जो निम्नलिखित कृत्य करेगा :-

- (क) परिषद् को संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करना ;
- (ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और
- (ग) संस्थान के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करना ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन परिषद् का एक कृत्य निम्नानुसार है “(ण) धारा 28ख के खंड (क) के अधीन बनाए गए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उसके संबंध में की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे”। तदनुसार, निम्नलिखित को रिपोर्ट किया जाता है :

परिषद् ने, 18 और 19 जून, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित अपनी 333वीं बैठक (आस्थगित) में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त प्रतिनिर्देशों/सिफारिशों पर विचार किया था और विचार किए जाने पर परिषद् द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में किस प्रकार आगे कार्रवाई की जाने चाहिए और इस संबंध में भावी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, के बारे में समिति को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विधिक राय प्राप्त करनी चाहिए। यह भी विनिश्चय किया गया था कि विधिक राय प्राप्त होने के पश्चात् परिषद् इस मामले पर पुनः विचार करेगी।

समिति ने, कोलम में 23-25 दिसंबर, 2014 को आयोजित अपनी 339वीं बैठक में विधिक राय को दृष्टिगत करते हुए तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख और धारा 15(2) के खंड (ण) में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया था। परिषद् ने ब्यौरेवार परिचर्चाओं के पश्चात् विधिक राय से सहमत होते हुए यह मत बनाया था कि क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त किसी प्रतिनिर्देश को अधिनियम की धारा 28ख के अधीन उसके द्वारा की गई सिफारिश के रूप में माना जाना चाहिए और परिषद् से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे सभी प्रतिनिर्देशों पर विचार करे ताकि भविष्य की कार्य योजना के संबंध में विनिश्चय किया जा सके। अतः, परिषद् ने यह विनिश्चय किया था कि क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त सभी प्रतिनिर्देशों को अगली बैठक में उसके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

तदनुसार, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त प्रतिनिर्देशों को निम्नलिखित रीति में पृथक् किया गया था और उन्हें 10-12 फरवरी, 2015 के दौरान आयोजित परिषद् की 340वीं बैठक में उसके समक्ष रखा गया था, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट थे -

- (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन परिषद् को सिफारिशें ;
- (ii) संस्थान को इस संबंध में अनुरोध कि वह तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा उठाए गए उसके सदस्यों से संबंधित मामलों के संबंध में मार्गदर्शन जारी करे ; और
- (iii) क्यूआरबी द्वारा फर्मों को दी गई यह सलाह कि भविष्य में फर्मों को तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किए गए संप्रेक्षणों का अनुपालन करना चाहिए।

परिषद् ने, 17-19 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित अपनी 341वीं बैठक में इस विषय पर पुनः विचार किया था, जिसके दौरान परिषद् ने मामले पर विचार करते हुए यह विनिश्चय किया था कि ऊपर क्रम सं. (i) के अंतर्गत आने वाले मामलों, अर्थात् धारा 28ख के खंड (क) के अधीन केवल क्यूआरबी की सिफारिशों को विचारार्थ उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। जहां तक ऊपर क्रम सं. (ii) और (iii) के अंतर्गत आने वाले मामलों अर्थात् संस्थान को उसके सदस्यों को मार्गदर्शन जारी करने के अनुरोध और क्यूआरबी द्वारा फर्मों को दी गई सलाह का संबंध है, परिषद् ने यह विनिश्चय किया था कि ऐसे मामलों को, फर्मों की पहचान को गुप्त रखते हुए विचारार्थ और भावी कार्रवाई संबंधी विनिश्चय करने के लिए लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड को अग्रेषित किया जाना चाहिए। परिषद् ने यह भी विनिश्चय किया था कि लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा इस संबंध में ऐसे मामलों पर की गई आगे की कार्रवाई को परिषद् के समक्ष उसके उल्लेख के लिए रखा जाएगा।

तत्पश्चात् ऊपर निर्दिष्ट बैठक में, परिषद् ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को विचारार्थ लिया था। परिषद् ने प्रतिनिर्देश सं. 1 “संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत सभी सीए फर्मों से, वर्ष दर वर्ष आधार पर संपरीक्षा संबंधी समनुदेशनों के ब्यौरे एकत्रित करने तथा उनका संकलन करने के लिए सिफारिश” पर विचार किया था। परिषद् ने यह उल्लेख किया था कि बोर्ड ने अपने तारीख 9 जुलाई, 2013 के पत्र द्वारा यह सिफारिश की है कि सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संपरीक्षा संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आईसीएआई सभी सीए फर्मों द्वारा निष्पादित विभिन्न संपरीक्षा समनुदेशनों के ब्यौरों को इलैक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक आधार पर एकत्रित कर सकेगा और उनका समेकन कर सकेगा। बोर्ड ने उक्त ब्यौरे एकत्रित करने के लिए प्ररूप की भी सिफारिश की है। परिषद् ने इस विषय पर विचार करते हुए यह विनिश्चय किया था कि क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की पूर्वोक्त सिफारिश को रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति को उसके विचारार्थ और सिफारिश करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए। समय की कमी के कारण शेष प्रतिनिर्देशों/सिफारिशों पर विचार को स्थगित कर दिया गया था।

5.31 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति का गठन : अध्यक्ष ने, फरवरी, 2015 में आयोजित परिषद् की 340वीं बैठक में उसे दिए गए प्राधिकार के निबंधनों में एक नई अस्थायी समिति अर्थात् निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति का गठन किया था। समिति की पहली बैठक का आयोजन 5 जून, 2015 को किया गया था जिसमें उसके उद्देश्यों, निर्देश निबंधनों और वर्ष 2015-16 के लिए उसकी कार्य योजना को अनुमोदित किया गया था।

अध्ययन समूहों का सृजन : समिति ने सीएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अध्ययन समूह का और सम्यक् प्रक्रियाओं के पश्चात् सीएसआर घंटों संबंधी अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक अन्य अध्ययन समूह का सृजन किया है।

माइक्रोसाइट को विकसित करना : समिति अपनी माइक्रोसाइट को विकसित करने की प्रक्रिया कर रही है, जो आईसीएआई, उसकी विभिन्न शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएगी, जहां वे सीएसआर से संबंधित उनके द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों को उपदर्शित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह माइक्रोसाइट, आईसीएआई के सदस्यों को एक अनन्य मंच/स्तंभ उपलब्ध कराएगी, जहां वे सीएसआर के भागरूप में उनके द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं को उपदर्शित कर सकेंगे।

स्वच्छ विद्यालय अभियान : समिति और वृत्तिक विकास समिति संयुक्त रूप से स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए कार्य कर रही हैं। उक्त पहल का शुभारंभ 28 जून, 2015 को अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा उपाध्यक्ष, आईसीएआई की उपस्थिति में उस समय किया गया था, जब वे तेलंगाणा के करीमनगर जिले में एनटीपीसी द्वारा सन्निर्मित विद्यालय शौचालय खंड/ईकाई का भौतिक सत्यापन कर रहे थे।

आईसीएआई, विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शासित केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ भी सहयोग कर रहा है। आज की तारीख तक, 625 से अधिक सदस्यों ने अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है और आईसीएआई के समक्ष इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है तथा इसे विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा ऊपर उल्लिखित सीपीएसयू के साथ भी शेयर किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त सूची को मंत्रालय की स्वच्छ विद्यालय अभियान संबंधी वेबसाइट – www.vidyutindia.in पर सदस्यों का नाम, सदस्यता संख्या, जिला और राज्य उल्लिखित करते हुए उपदर्शित किया गया है।

कार्यक्रम : समिति ने 26 मई, 2015 को परिषद् हाल, आईसीएआई भवन में “कंपनी अधिनियम, 2013 – सीएसआर, वार्षिक विवरणी, बोर्ड की रिपोर्ट, संपरीक्षक की रिपोर्ट, सीएआरओ-15” विषय पर वेबकास्ट का आयोजन किया था।

5.32 कैरियर परामर्श संबंधी समिति

कैरियर परामर्श संबंधी समिति, आईसीएआई की एक अस्थायी समिति है, जिसका सृजन फरवरी, 2015 मास में किया गया था। इस समिति का उद्देश्य माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करना है। मुख्यतः, समिति वाणिज्य शिक्षा, विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा तैयार करती है और उनका कार्यान्वयन करती है।

समिति की प्रमुख पहले

- एक अनन्य वेबसाइट का शुभारंभ

- आईसीएआई के सोशल मीडिया मंचों को आरंभ करना
- 'स्वयं को सामान्य प्रवीणता परीक्षा के लिए तैयार करें : एक उत्कृष्ट कैरियर के लिए सोपान' और 'चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को समझने के लिए एक गाइड : अथाह अवसरों के साथ उत्कृष्ट कैरियर पर ध्यान' नामक पुस्तिकाएं जारी करना
- विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस को मनाना
- वाणिज्य विशेषज्ञ – वाणिज्य योग्यता तलाश परीक्षा
- 'चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम : अथाह अवसरों के साथ उत्कृष्ट कैरियर पर ध्यान' विषय पर एक डीवीडी जारी करना
- कार्यबल और समूहों का गठन
- कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्तियों को पैनलबद्ध करना

5.33 प्रबंधन समिति

समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चयों में निम्नलिखित से संबंधित ऐसे विषय भी सम्मिलित थे, जिनके बारे में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को सिफारिश की गई थी :

- संस्थान की पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की भुज (गुजरात) में शाखा स्थापित करने, संस्थान की दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की ऐलुरु और कांचीपुरम् जिले में शाखाएं स्थापित करने।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईसीएआई एक स्वायत्त कानूनी निकाय है, "सरकारी विज्ञापन की अंतर्वस्तु के विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों" के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निदेशों का स्वयं और साथ ही आईसीएआई द्वारा भी पालन करने।
- मासिक ई-न्यूज लैटर आरंभ करने के लिए युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- संस्थान के अभिलेखों में सम्मिलित किए जाने के लिए 1.11.2014 से कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाले 12 शहरों और नगरों के नामों में परिवर्तन का अनुमोदन।

संबंधित समिति से प्राप्त सिफारिशें, जिन्हें प्रबंधन समिति की सिफारिशों के साथ परिषद् के समक्ष रखा गया था :

- युवा सदस्यों की पहचान करने के लिए आयु के मानदंड की परिभाषा के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- परिषद् की विभिन्न समिति द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रारूप दिशा-निर्देशों का वेबकास्टों के माध्यम से अनुमोदन और सीपीई घंटों के प्रत्यय को मंजूर करना।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए पहले

अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू :

- 18 जून, 2014 को आईसीएआई भवन, नई दिल्ली में साऊदी आर्गनाइजेशन फार सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- 8 नवंबर, 2014 को रोम में, विश्व अकाउंटेंट्स कांग्रेस 2014 के दौरान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण।
- 19 सितम्बर 2014 को, आईसीएआई के ऑस्ट्रेलिया (सिडनी) चैप्टर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ एमआरए का नवीकरण।
- 19 सितम्बर 2014 को आईसीएआई के ऑस्ट्रेलिया (सिडनी) चैप्टर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक पर हस्ताक्षर।
- आईसीएआई साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन किए जाने के बारे में वार्तालाप।
- आईसीएआई पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ, दोनों संस्थानों के बीच लेखांकन वृत्ति के क्षेत्र में परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है।
- आईसीएआई और कनाडा के संस्थान अब विद्यमान ठहराव के नवीकरण के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों को अग्रसर किया जा सके।

- आईसीएआई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अब विलय हो गए संस्थान के साथ परस्पर मान्यता ठहरावों के लिए बातचीत कर रहा है।

आईसीएआई की ब्रांड इकटिरी का वैश्वीकरण

- आईसीएआई ने 26 अक्टूबर 2014 से 2 नवंबर 2014 के दौरान यू.के. और आयरलैंड के लिए एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया था।
- आईसीएआई ने 23 नवम्बर, 2014 को ब्रिटिश कोलंबिया में अपने 24वें विदेशी चैप्टर का शुभारंभ किया था।
- 12 जनवरी 2015 को आईसीएआई के बैंकॉक चैप्टर का शुभारंभ किया गया था।
- 13 जनवरी 2015 को आईसीएआई के दारे एस सलाम चैप्टर का शुभारंभ किया गया था।

आईसीएआई में प्रतिनिधिमंडल के दौरे

- श्री जस्टिन वेस्ट, कारबार प्रचालनों के प्रधान, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) का 22 अप्रैल, 2014 को दौरा।
- 30 जून 2014 से 3 जुलाई 2014 के दौरान आईएफएसी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा।
- 16 सितम्बर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) से एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
- 15 नवंबर, 2014 को सुश्री जोआन मर्फी, प्रबंध निदेशक, एशिया प्रशांत, चार्टर्ड वैकल्पिक निवेश विश्लेषक (सीएआईए) संघ का दौरा।
- 2 दिसंबर 2014 को श्री श्रीनिवासन जनार्दन, वरिष्ठ वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ, एशियाई विकास बैंक का दौरा।
- 24 फरवरी 2015 को आईएसएसीए के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक।

सम्मेलन/कार्यक्रम

- 06-07 मार्च, 2014 के दौरान लेखा मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) के साथ बैठक और 8-9 मार्च, 2014 के दौरान आईएफएएस प्रादेशिक नीति मंच के साथ बैठक।
- 02-03 सितम्बर, 2014 के दौरान प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम।
- 10 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में साफा-आईएफएसी प्रादेशिक एसएमपी मंच और साफा महिला सम्मेलन।
- 29 से 31 जनवरी 2015 के दौरान बेंगलुरु में आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 28-29 जनवरी, 2015 के दौरान बेंगलुरु में साफा बैठकें।
- 23 फरवरी 2015 को "एशियाई विकास बैंक में वित्तीय सम्यक् कार्यपालन नियोजनों के लिए परामर्श संबंधी अवसर" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अविकसित देशों को तकनीकी सहयोग

आईसीएआई ने बिना लाभ हानि के सिद्धांत के आधार पर विकासशील देशों में लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता को विस्तारित करने संबंधी एक पहल की है। आईसीएआई परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं में सक्षमता निर्माण करने के लिए उत्साहित है ताकि लेखांकन के क्षेत्र में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में वृत्तिक ज्ञान की कमी को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके।

रचना खंडों के लिए कार्यकरण

आईसीएआई के भावी सदस्यों को प्रौद्योगिकी के इस युग में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए दुबई, कुवैत और मस्कट के अलावा दारे-अस-सलाम और कतर में "आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट" को जारी किया गया था। इन किटों की अवधारणा इस प्रकार की गई है कि वे वृत्तिक अवसरों के लिए विदेशों में जाने का आशय रखने वाले सदस्यों को विहंगम आरंभिक जानकारी उपलब्ध कराती है।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

मानव संसाधनों का विकास ऐसी प्रमुख अवधारणा है जिसके द्वारा कोई संगठन अपने परिमाणात्मक और गुणात्मक उद्देश्यों तथा संज्ञानात्मक पहलुओं में सुधार करता है। आईसीएआई, सदैव अविजीत योग्यता संबंधी मुद्दों, जिसके अंतर्गत नए योग्यता पूल तक पहुंच बनाना, विद्यमान कर्मचारियों और कौशलों का विकास करना आदि हैं और नेतृत्व सामर्थ्य की उभरती आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईसीएआई ने जून, 2015 में श्री वी. सागर को अपने नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य भर्ती अभियान भी सभी स्तरों पर आरंभ किए गए थे ताकि नए और उभरते उत्तरदायित्वों की अपेक्षानुसार जन शक्ति को एकत्रित किया जा सके। एक सुरक्षित और बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने के अपने आश्वासन को जारी रखते हुए आईसीएआई ने, पहली बार अपने सेवारत कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सीय बीमा पालिसी को आरंभ करके लागू किया है।

आईसीएआई, इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि उसके मानव संसाधनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है जिसके लिए यह आवश्यक है कि वे अनुकूल, नमनीय और दिशा परिवर्तित करने में त्वरित हों तथा उनका ध्यान पणधारियों पर केंद्रित हो। अपनी जनशक्ति को तीव्र गति से परिवर्तनशील कारबार परिस्थितियों में संवहनीय बने रहने में समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई ने दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पठन संबंधी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी संसारिकता से परे होकर सोचने में समर्थ बनें और व्यक्तिगत तथा वृत्तिक उन्नति के मार्ग पर गतिशील होने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें।

इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन संबंधी पहलों में समय पर परामर्शी सेवाओं, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए समुन्नत नीतियों को प्रवृत्त करने, कर्मचारी शिकायत समाधान, कठिनाइयों को दूर करने और आईसीएआई के कर्मचारियों के बौद्धिक विकास और इसके कार्यबल को पुनः कौशल से लैस करने के लिए एक पठन संगठन का सृजन करने संबंधी पहल को अनुपूरित करना आदि सम्मिलित है।

मानव संसाधन संपरिवर्तन समिति

मानव संसाधन प्रबंध प्रणालियों को नीतिगत रूप से संपरिवर्तित करने और बेहतर मानव संसाधन सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को आरंभ करने के विचार से समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए मानव संसाधन संपरिवर्तन समिति नामक एक विशेष प्रयोजन समिति का गठन किया था, जिसे वर्ष 2015-16 के लिए भी जारी रखा गया था। इस समिति का उद्देश्य वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन प्रवृत्तियों से संबंधित आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन और उनकी वैचमार्किंग करते हुए आंतरिक पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उन्हें प्रबंध मंडल के उद्देश्यों के साथ सुमेलित करने के लिए नवीन विचारों का पता लगाना है ताकि भविष्य में आईसीएआई कार्य योजना को पूरा किया जा सके।

समिति के निर्देश निबंधन निम्नानुसार हैं :

1. आईसीएआई के भीतर सर्वोत्तम योग्यता को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए नीतियां और प्रणालियां विकसित करना।
2. आईसीएआई के भीतर कर्मिकों के प्रत्येक स्तर के लिए नौकरी संबंधी विवरण और विनिर्देश विकसित करना ताकि उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरियों में स्थापित किया जा सके और जो सकल विकास के लिए एक पुनः संरचित संगठन में प्राधिकारी उत्तरदायित्व मैट्रिक्स के मद्दे कार्य करें।
3. आईसीएआई के भीतर प्रतिपूर्ति नियुक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नौकरी संबंधी मूल्यांकनों तथा कार्यपालन संबंधी प्रबंधन मानदंडों का पता लगाना और उन्हें विकसित करना।
4. विद्यमान मानव संसाधनों की कैरियर योजना और प्रबंधन के मद्दे कार्य करना।
5. सभी स्तरों के कर्मिकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए कार्य करना ताकि नौकरी के चक्रानुक्रम और प्रभावी उत्तरवर्ती योजना प्रणालियों के माध्यम से कमान की वित्तीय पंक्ति विकसित करके परिवर्तन परामर्शी के रूप में कार्य करना।
6. आंतरिक पणधारी सक्षमता का विकास करना, विकास उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना और आईसीएआई की बहु आयामी भूमिका के अनुरूप कार्य करना।
7. विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में विभिन्न मानव संसाधन नीतियों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना।
8. सूचना के आबाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आईटी उपकरणों को विद्यमान एचआर सेवाओं से एकत्रित करना।
9. प्रबंधन और आंतरिक पणधारियों की, उनके उद्देश्यों और आकांक्षाओं के निबंधनानुसार उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना।

मानव संसाधन संपरिवर्तन समिति के क्रियाकलाप

समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चार बैठकें की थी और उसने 18 सितंबर, 2014 से अक्टूबर, 2014 की अवधि के दौरान पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 365 कर्मचारियों ने भाग लिया है और उसे सभी प्रतिभागियों से सराहना प्राप्त हुई थी। समिति ने इस संबंध में कर्मचारियों से प्राप्त फीडबैक को भी उत्तम के रूप में उल्लिखित किया था। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

तारीख	विषय	संकाय	अंतर्गत आने वाले कर्मचारी	स्थान	उपस्थिति
18 सितंबर, 2014	ज्ञान संबंधी अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी प्रबंधन में नई सोच	डा. देबी एस. सैनी, प्रोफेसर और अध्यक्ष, मानव संसाधन प्रबंधन क्षेत्र, एमडीआई	वरिष्ठ उप सचिव – आईटीओ और विश्वास नगर कार्यालयों में अवस्थित कार्यपालक अधिकारी	आईटीओ सभागार	103 में से 84 (81.5 प्रतिशत)
19 सितंबर, 2014	रचनात्मक सोच और प्रभावी समस्या निदान	डा. मोनिका रस्तोगी, उत्साहवर्द्धक वक्ता, कास्मिक लिंक मोटीवेशनल अकादमी	वरिष्ठ उप सचिव- नोएडा सेक्टर-62 और सेक्टर-1 कार्यालयों में अवस्थित कार्यपालक अधिकारी	नोएडा सेक्टर-62 सभागार	144 में से 103 (71.5 प्रतिशत)
25 सितंबर, 2014	प्रभावी प्रस्तुतीकरण संबंधी कौशल	श्री विवेक बिन्द्रा, संस्थापक, ग्लोबल ऐक्ट	अनुभाग अधिकारी- आईटीओ और विश्वास नगर कार्यालयों में अवस्थित सहायक	आईटीओ सभागार	56 में से 46 (82.1 प्रतिशत)
1 अक्टूबर, 2014	एक विजेता दल का निर्माण	श्री अलोकेश बनर्जी, वरिष्ठ संकाय, एनटीपीसी	अनुभाग अधिकारी- नोएडा सेक्टर-62 और सेक्टर-1 कार्यालयों में अवस्थित सहायक	आईटीओ सभागार	73 में से 58 (79.4 प्रतिशत)
14 अक्टूबर, 2014	कार्य का मूल्य	डा. मोनिका रस्तोगी, उत्साहवर्द्धक वक्ता, कास्मिक लिंक मोटीवेशनल अकादमी	एलडीसी/यूडीसी और प्रवर्ग-IV कर्मचारियों के ग्रेड के सभी कर्मचारियों	आईटीओ सभागार	97 में से 74 (76.2 प्रतिशत)

आईसीएआई के ऐसे कर्मचारियों (उप सचिव और ऊपर के पंक्ति के अधिकारियों को छोड़कर) के लिए जिन्होंने 1 मई, 2013 को या उसके पश्चात् संस्थान में सेवा ग्रहण की है, 2-3 जुलाई, 2015 के दौरान आईटीओ सभागार में एक दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम, जिसमें प्रादेशिक कार्यालय के 12 कर्मचारियों सहित 52 कर्मचारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम को प्रतिभागियों से काफी सराहना प्राप्त हुई थी।

समिति, अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को संस्थागत बनाने के लिए निम्नानुसार प्रथम अवसर व्यवहार संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी :

क्रम सं.	अंतर्गत आने वाले कर्मचारी	संस्था
1.	अनुभाग अधिकारी के स्तर तक	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)
2.	कार्यपालक अधिकारी से उप सचिव	आईएमटी गाजियाबाद
3.	संयुक्त सचिव और ऊपर के पंक्ति के अधिकारी	आईआईएम लखनऊ (नोएडा परिसर)

7.2 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

वृत्ति के लिए पहले : भवन रचना के लिए कार्यकरण

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति पिछले छह वर्ष से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे भिन्न-भिन्न नगरों के अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आधुनिक वित्तीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्च मूल्य वाला कारबार वित्त में मास्टर संबंधी एक एकवर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एमबीएफ) का संचालन करती है। इसने सफलतापूर्वक 7 बैचों को पूरा किया है। इस समय समिति दिल्ली और मुंबई में एमबीएफ के आठवें बैच हेतु कक्षाओं का आयोजन कर रही है। एमबीएफ के आठवें बैच का शुभारंभ दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 10 और 11 जनवरी, 2015 को किया गया था।

अर्हता पश्च पाठ्यक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति 2 अर्हता पश्च पाठ्यक्रमों का संचालन करती है : 1. प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम, 2. निगम प्रबंध पाठ्यक्रम। समिति इन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, प्रदाय तंत्र आदि के पुनर्विलोकन के लिए सभी प्रकार की पहले कर रही है।

उद्योग/निगम पहले/कार्यक्रम

समिति नवंबर, 2014 से एचपीसीएल के कार्यपालकों के लिए सीए कार्यपालकों से संबंधित वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है। एचपीसीएल ने अगस्त, 2015 में उसके सीए कार्यपालकों के लिए एमबीएफसीसी के दूसरे बैच को आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/अन्य कार्यक्रम

समिति ने वृत्ति कर रहे सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से और आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की वसई शाखा, जलगांव शाखा और नासिक शाखा के सहयोग से विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

वृत्तिक मामलों पर मंत्रालयों/विनियामकों/सरकारी कार्यालयों के साथ परस्पर क्रियाएं : संबंधों को मजबूत बनाना

1. 28 और 29 जून, 2014 को दिल्ली और मुंबई में एमबीएफ – सातवें बैच का शुभारंभ। दिल्ली में इसके मुख्य अतिथि श्री नंद किशोर गर्ग, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा थे।
2. 7 अक्टूबर, 2014 को दिल्ली में एमबीएफ बैच का दीक्षांत समारोह। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री प्रवीन रावल, निदेशक, आईआर, समन्वयन, स्थापन, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली थे।
3. 14 अक्टूबर, 2014 को मुंबई में एमबीएफ बैच का दीक्षांत समारोह। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुश्री किरन महेश्वरी, माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार थी।
4. क्रमशः 24 और 25 जनवरी, 2015 को दिल्ली और मुंबई में मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर दिल्ली में मुख्य अतिथि श्री बाबू लाल वर्मा माननीय राज्यमंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार थे और अधिवक्ता अमित खेमका विशेष अतिथि थे।

प्रकाशन :

1. समिति ने सीए चरंतीमठ एन.ए., समिति के सहयोजित सदस्य द्वारा प्रारूपित “प्रबंध लेखांकन के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)” नामक एक पुस्तक का विमोचन 29-31 जनवरी, 2015 के दौरान बंगलौर पैलेस, बंगलूरु में आयोजित आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था।
2. समिति ने 11 फरवरी, 2015 को वार्षिक दिवस समारोह के दौरान एमबीएफ अध्ययन माड्यूल स्तर 1, प्रश्न पत्र 1 का भी विमोचन किया था।

महत्वपूर्ण निर्णय/पहले

समिति ने छह एमबीएफ अध्ययन सामग्रियों के प्रकाशन निकालने का विनिश्चय किया है, जिनमें से तीन प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

सदस्यों के लिए

समिति ने अपने त्रैमासिक जर्नल ‘प्रबंध लेखांकन और कारबार वित्त’ – जुलाई, 2014, अक्टूबर, 2014, जनवरी, 2015 का प्रकाशन किया था, जिसमें प्रबंध लेखांकन और लोक वित्त के क्षेत्र में हुई कुछ हाल ही की घटनाओं को सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के फायदे हेतु ज्ञान के प्रसार के लिए विशिष्ट रूप से दर्शित किया था।

7.3 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या, उसके साथ प्रदान किए जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ उसके सदस्यों में बहुमुखी प्रतिभा का प्रादुर्भाव करती है। इसके परिणामस्वरूप, चार्टर्ड अकाउंटेंट न केवल संपरीक्षा और कराधान के क्षेत्रों में व्यवसायी वृत्तियों के रूप में और उद्योगों में वित्तीय प्रबंध के प्रभारी के रूप में वृत्तिक कार्यपालकों के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अपितु वे समाज के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बड़ी संख्या विद्यमान है, जो अत्यंत सफल उद्यमी बन गए हैं। इसी प्रकार, लोक सेवाओं के क्षेत्र में भी चार्टर्ड अकाउंटेंटों का संसद् सदस्यों या विधान सभा सदस्यों, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधिकरणों के सदस्यों आदि के रूप में योगदान प्रशंसनीय रहा है।

वृत्तिक विकास समिति और उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई और वृत्ति तथा सेवारत सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण युगम के रूप में कार्य करती है। आईसीएआई और ऐसे सदस्यों के बीच, जो उद्यमों या लोक सेवाओं में कार्यरत हैं, ऐसे युगम उपलब्ध कराने के विचार से उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति का परिषद् वर्ष 2015-16 में पुनर्गठन किया गया है। इस गठन का उद्देश्य आईसीएआई और उद्यमों या लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच एक परस्पर फायदेमंद सक्रिय संबंध स्थापित करना है। इस समिति के कार्यकरण के माध्यम से, उद्यमों या लोक सेवाओं में कार्यरत सदस्यों को आईसीएआई की प्रमुख धारा में लाया जाएगा, जिससे आईसीएआई के क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी में अभिवृद्धि होगी। समिति ऐसे पहलुओं के संबंध में भी कार्य करेगी, जिससे आईसीएआई के अन्य सदस्यों और साथ ही ऐसे सदस्यों को परस्पर फायदे प्राप्त हों ताकि युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अतिरिक्त अवसरों के क्षेत्रों को दीप्यमान किया जा सके और इस प्रकार अन्य बातों के साथ, वृत्ति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

समिति ऐसे सीए सदस्यों के डाटा बेस को अद्यतन बनाने के लिए कार्य कर रही है जो उद्यमों या लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस संबंध में, आईसीएआई की वेबसाइट पर न केवल उद्यमों या लोक सेवा में कार्यरत सदस्यों के लिए अपितु साधारण सदस्यों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक उदघोषणा रखी गई है जिससे कि उद्योगों और लोक सेवा में कार्यरत सदस्य आईसीएआई के अभिलेखों में अपने प्रोफाइल को अद्यतन कर सकें और साथ ही अन्य सदस्य भी ऐसे सदस्यों के ब्यौरे उपलब्ध करा सकते हैं, जिनके संपर्क में वे अपने व्यौहारों के दौरान आए थे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कंपनी विधि बोर्ड, आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी), सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी), केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और आयकर महानिदेशक को भी इस अनुरोध के साथ संसूचना भेजी गई है कि वे उनके संबंधित संगठनों में कार्यरत ऐसे सदस्यों/अधिकारियों के ब्यौरे उपलब्ध करवाएं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

आज की तारीख तक, समिति ने लगभग ऐसे 353 सीए सदस्यों के डाटा बेस का संकलन किया है, जो लोक सेवा में हैं और 231 ऐसे सदस्यों के ब्यौरे का भी संकलन किया है जो उद्यमों में कार्यरत हैं।

समिति लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करने की योजना भी बना रही है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कतिपय विषयों पर परिचर्चा की जाएगी, जिन्हें आईसीएआई अनुसंधान और अग्रणी अध्ययन के लिए उठा सकता है और साथ ही वृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया किए जाने के लिए समकालीन महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

7.4 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति

सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति, जो संस्थान की एक अस्थायी समिति है, का सृजन फरवरी, 2011 में ऐसे मुद्दों और अवसरों तथा एनपीओ क्षेत्रों की पहचान करने तथा सदस्यों और अन्य पणधारियों को, उनके लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने में सुसज्जित करने और साथ ही सहकारिता और एनपीओ क्षेत्रों में प्रमुख सक्षमताओं का विकास करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए किया गया था।

विनियामकों के और उनके साथ कार्यक्रम

- 25 जुलाई, 2014 को एफसीआर प्रभाग के अधिकारियों के लिए एफसीआर संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम – गृह मंत्रालय, विदेशी व्यक्ति प्रभाग, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह मार्ग, समीप संसद् मार्ग, समीप जन्तर मन्तर, नई दिल्ली के 40 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था।
- 20 से 23 अगस्त, 2014 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ लिमिटेड, देहरादून के सहयोग से आवासीय सहकारिताओं के लेखाओं के प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 20 और 21 दिसंबर, 2014 को चेन्नई में डीसीसीडी और शहरी सहकारी बैंकों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसकी मेजबानी सहकारिता विभाग, तमिलनाडु द्वारा की गई थी।
- 7 फरवरी, 2015 को गोवा में, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के सहयोग से आवासीय सहकारिताओं के लेखांकन, आयकर और संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की गोवा शाखा द्वारा की गई थी।
- 7 फरवरी, 2015 से 14 मार्च, 2015 के दौरान हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति सहकारी सहायकों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसकी मेजबानी भेल कर्मचारी सहकारी प्रत्यय लिमिटेड सोसाइटी द्वारा की गई थी।

समिति द्वारा किए गए नए अभ्यावेदन

- समिति ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता विभागों को इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और उनकी आवश्यकताओं के संबंध में तथा सहकारिताओं की भूमिका को त्वरित करने के लिए अभ्यावेदन किए हैं।
- इन अभ्यावेदनों में सम्मिलित पहलू निम्नानुसार हैं :
 - सहकारी सोसाइटी प्रबंधन में ई-शासन
 - संबंधित राज्यों में सोसाइटियों की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा मैनुअल
 - वित्तीय विवरणों का प्ररूप
 - सहकारी सोसाइटी विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
 - बड़ी सहकारिताओं के लिए सहकारी शासन
 - अकृत्यशील सहकारी सोसाइटियों के लिए समापन स्कीम
 - आईसीएआई की स्थायी संयुक्त समिति और सहकारी विभाग
 - अकृत्यशील सहकारी सोसाइटियों के लिए समापन स्कीम
 - संपरीक्षकों का पैनल बनाना
 - चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा अभ्यावेदन
- ऊपर उल्लिखित पहलूओं को सम्मिलित करने वाला एक अभ्यावेदन सहकारी सोसाइटियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को भी प्रस्तुत किया गया था।
- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, विदेशी व्यक्ति प्रभाग को किए गए अभ्यावेदन में अधिनियम और विदेशी अभिदायों से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन में प्रचालनात्मक मुद्दों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया था और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए समर्थन की ईप्सा की गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि उनका समाधान अधिनियम, नियमों के संशोधन या किसी प्रशासनिक परिपत्र, जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, द्वारा किया जाना चाहिए।
- पूर्त न्यासों के संबंध में अधिनियमित किए जाने वाले प्रारूप विधेयक को केंद्रीय सरकार को सौंपा गया था।
- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को अभ्यावेदन।

इस अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुद्दों को सम्मिलित किया गया था :

- लेखांकन मानकों के लिए आरबीआई परिपत्र
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए पृथक् एलएफएआर
- सहकारी बैंकों को यथा लागू अधिनियम

कार्यबल और अध्ययन समूह

प्रत्येक राज्य को इस संबंध में प्रोत्साहित किया जाता है और वे सदस्यों द्वारा जानकारी के परस्पर आदान-प्रदान के लिए अध्ययन समूहों को निर्मित करने हेतु प्रक्रिया कर रहे हैं।

प्रत्येक राज्य में, सहकारी और एनपीओ क्षेत्रों, दोनों के लिए कार्यबलों को सृजित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप

15 सितंबर से 20 सितंबर, 2014 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में आईसीएआई की 11वीं प्रादेशिक सभा में भाग लिया। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संवहनीय विकास के लिए सहकारिताएं।

पुस्तकें और प्रकाशन

- सहकारिता और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति का प्रोफाइल
- इस परिषद् वर्ष में सहकारिता और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति द्वारा जारी प्रकाशन
 - भारत में पूर्त संगठनों को शासित करने वाली विधियों संबंधी गाइड
 - निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर
 - सहकारी क्षेत्रों संबंधी गाइड और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर
 - गैर-लाभकारी संगठन और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर

- निगम माध्यस्थम्
- भारत में विदेशी अभिदाय विनियमन का पर्यावलोकन
- आवासीय सोसाइटियों का पुनर्विकास
- गैर-लाभकारी संगठनों के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड
- सहकारी आवासीय सोसाइटियों के लिए संदर्भ मैनुअल

विकास संकाय

- समिति, दिलचस्पी रखने वाले और पात्र विशेषज्ञों को उपयुक्त मार्गदर्शन और समर्थन उपलब्ध कराके इन क्षेत्रों के लिए संकायों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है तथा उसे सुकर बना रही है।
- अधिकाधिक सदस्यों को विशेषज्ञ ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें विभिन्न संगोष्ठियां, कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में संकाय के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है।

पहला आईसीएआई सीएसआर पुरस्कार

सीएसआर कारबार द्वारा पालन की जाने वाली एक ऐसी सतत प्रतिबद्धता है, जिसके माध्यम से वे नैतिक रूप से कार्य करते हैं तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति योगदान करते हैं और इस प्रकार न केवल वे कार्यबलों तथा उनके परिवारों के जीवन अपितु स्थानीय समुदाय और संपूर्ण समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कारबार को ऐसी स्थायी सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो निवेश और व्यापार हेतु एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती हैं और इसलिए कारबार के मानवीय रूप को उपदर्शित करना उनके स्वहित में है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए इन पुरस्कारों के माध्यम से, हम आईसीएआई के द्वारा निगम, उद्यमों, गैर-लाभकारी संगठनों और व्यष्टियों आदि को मान्यता प्रदान करेंगे, जिन्होंने परस्पर प्रदत्त मूल्यों के सृजन के आदर्श पथ का चुनाव किया है और हम ऐसे संगठनों की ब्रांड ईक्विटी को बनाने में भी सहायता करेंगे।

समिति के सीएसआर प्रभाग ने गर्वपूर्वक 5 फरवरी, 2015 को होटल ललित, मुंबई में पहले आईसीएआई सीएसआर पुरस्कारों, 2014 की घोषणा की थी।

उसके लिए ज्यूरि की बैठक का आयोजन 2 फरवरी, 2015 को होटल सहारा स्टार, मुंबई में किया गया था। बड़ी संख्या में इन पुरस्कारों हेतु नामांकन प्राप्त हुए थे।

7.5 विधिक सलाहकार-सह-सुकदमेबाजी खंड

विधिक विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

- आईसीएआई की विभिन्न समितियों/विभागों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित रूप में विधिक रायों/अध्ययनों/रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करना।
- प्रचालन विभागों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुरक्षित करने के लिए आईसीएआई के प्रशासनिक कार्यकरण में उदभूत होने वाले सारवान और प्रक्रिया संबंधी विधि के विविध प्रश्नों के संबंध में उपयुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने को सुनिश्चित करना।
- आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का अधीक्षण और पर्यावलोकन करना।
- नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक बाध्यताओं का समाधान करने के लिए यथाअपेक्षित रूप में विभिन्न स्थाई और अस्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना।
- जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।
- न्यायालय मामलों के संबंध में कार्यवाही करना।

7.6 अवसंरचना विकास संबंधी समिति

आईसीएआई द्वारा शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों की अवसंरचना के विकास के लिए एक नीति की विरचना की गई है, जिसमें अवसंरचना विकास के लिए दिशा-निर्देशों, अंतर्वर्तित लागत कारकों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। समिति का गठन पिछले वर्ष, ऐसे भवन प्रस्तावों के संबंध में नीति के कार्यान्वयन के लिए किया गया था, जो आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त हों। समिति आईसीएआई के विभिन्न अवस्थानों पर अधिशेष भूमि/भवन का पुनर्विलोकन करती है। यह आईसीएआई की संपूर्ण विद्यमान अवसंरचना परियोजनाओं का भी पुनर्विलोकन करती है तथा उसके लिए सम्यक् प्रक्रिया का पालन करती है।

अवसंरचना नीति को तैयार करने के पश्चात् नई अवसंरचना का क्रय :

1. कन्नूर शाखा, एसआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
2. जालंधर शाखा, एनआईआरसी - सरकारी भूमि, जालंधर सुधार न्यास से
3. जबलपुर शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि जबलपुर विकास प्राधिकरण से
4. गोवा शाखा, डब्ल्यूआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
5. गुडगांव शाखा, एनआईआरसी - सरकारी भूमि एचएसआईआईडीसी से
6. मुरादाबाद शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से
7. पाली शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि नगर परिषद, पाली से
8. आगरा शाखा, सीआईआरसी - सरकारी भूमि उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद से

समिति द्वारा अनुमोदित संनिर्माण के प्रस्ताव

1. अजमेर शाखा, सीआईआरसी
2. सूरत शाखा, डब्ल्यूआईआरसी
3. हुबली शाखा, एसआईआरसी
4. राजामहेन्द्रवरम् शाखा, एसआईआरसी
5. सीओई, जयपुर

7.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याभूत है। तथापि, नागरिकों के लिए अधिकार के रूप में सूचना को सुनिश्चित करने के विचार से एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के विचार से संसद् ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम का आधारीक उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना है। आईसीएआई, जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुसरण में इस लोक प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई) और पारदर्शिता अधिकारी को पदाभिहित किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icaai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। उसके लिए लिंक <http://www.icaai.org/newpost.html?postid=1346&cid=203> पर उपलब्ध है।

केन्द्रीय सूचना आयोग को वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियों का सार, जिसे तत्पश्चात् सीआईसी द्वारा प्रकाशित किया गया था

त्रैमास	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या जिनका त्रैमास में उत्तर दिया गया था	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या जिन्हें अन्य पीए को अंतरित किया गया था	वहां निर्णय, जहां सूचना के लिए आवेदनों को नामंजूर किया गया था।	नामंजूरी का प्रतिशत
पहला त्रैमास	127	0	29	26.9%
दूसरा त्रैमास	221	1	38	17.8%
तीसरा त्रैमास	128	0	27	27.0%
चौथा त्रैमास	171	0	31	20.3%

7.8 एक्सबीआरएल

आईसीएआई द्वारा सुविधा प्राप्त एक्सबीआरएल इंडिया, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सेबी, आईआरडीए और आरबीआई की सक्रिय भागीदारी के साथ वर्ष 2007 से देश में एक्सबीआरएल क्रांति की अगुवाई कर रहा है। तब से विनियामक एक्सबीआरएल को मानक इलेक्ट्रॉनिक कारबार भाषा के रूप में अपनाए जाने के लिए कार्यकरण कर रहे हैं।

➤ विकसित किए गए क्षेत्र विनिर्दिष्ट वर्गीकरणों की प्राप्ति

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और विद्युत कंपनियों के लिए वर्गीकरणों को विकसित किया गया है। एनबीएफसी के लिए वर्गीकरण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है। दोनों वर्गीकरणों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को, उन्हें उसके एक्सबीआरएल फाइलिंग के विस्तार क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

बीमा कंपनियों, जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण को विकसित किया गया है। उसे अनुमोदनार्थ आईआरडीए को भेजा गया है। आईआरडीए से अनुमोदन के पश्चात्, उसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

➤ कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, वर्ष 2010-11 से कंपनियों के एक चुने हुए वर्ग के वित्तीय विवरणों को वार्षिक रूप से फाइल किए जाने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है।

तथापि, इस वर्गीकरण को कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों तथा अधिसूचित प्ररूपों के अधीन अधिकथित नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित सी एंड आई वर्गीकरण का उपयोग कंपनियों द्वारा वर्ष 2014-15 से वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए किया जाएगा।

एमसीए 21 के डाटा बेस का उपयोग करते हुए, जो एक्सबीआरएल और गैर-एक्सबीआरएल, दोनों प्ररूपों में डाटा स्वीकार करता है, प्राइवेट निगम क्षेत्र संबंधी उप समिति, जिसके अंतर्गत सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अधीन पीपीपी भी है, ने निगम क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी (एनएएस) का जनन करने के लिए एक्सबीआरएल डाटा के उपयोग के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उप समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए एमसीए 21 डाटा बेस से व्युत्पन्न गैर-वित्त प्राइवेट निगम क्षेत्र के लिए जीवीए का प्राक्कलन, एनएएस 2014 से अभिप्राप्त प्राक्कलन की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है। तथापि, गैर-वित्त सेवा सेक्टर के लिए एमसीए 21 डाटा बेस से जीवीए का प्राक्कलन, एनएएस 2014 से अभिप्राप्त प्राक्कलन की तुलना में 12.8 प्रतिशत कम है। एमसीए 21 डाटा बेस से अभिप्राप्त विनिर्माण उद्योग के लिए जीवीए का आकलन और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए वार्षिक रिपोर्ट, एएसआई 2011-12 डाटा से पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अभिप्राप्त जीवीए के प्राक्कलन से 40 प्रतिशत अधिक है।

➤ विकसित किए जा रहे वर्गीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय मानकों (इंड एएस) के आधार पर वर्गीकरणों के विकास के लिए हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित करने के लिए एक उदघोषणा आईसीएआई और एक्सबीआरएल इंडिया की वेबसाइट पर रखी गई थी। ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त, 2015 है। उक्त वर्गीकरण का उपयोग, आईएफआरएस के साथ अभिसरित मानकों अर्थात् इंड एएस के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए किया जाएगा।

➤ विनियामकों का सम्मिलित होना

- भारत में एक्सबीआरएल गतिविधियों के संबंध में नीतिगत सलाह उपलब्ध कराने के लिए एक्सबीआरएल इंडिया के तत्वावधान में एक एक्सबीआरएल इंडिया सलाहकार परिषद् (एक्सआईएसी) का गठन किया गया है, जिसमें एक्सबीआरएल इंडिया के बोर्ड सदस्यों के साथ एमसीए, आईआरडीए और आरबीआई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। हाल ही में, 15 जून, 2015 को एक्सआईएसी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में श्री पुर्णेन्दु कुमार, निदेशक, आरबीआई ने, एक्सबीआरएल के उपयोग से व्युत्पन्न फायदों के संबंध में आरबीआई के अनुभवों से संबंधित एक

प्रस्तुतीकरण किया था। उन्होंने यह सूचित किया था कि एक्सबीआरएल कार्यान्वयन के दूसरे चरण के पूरा होने के पश्चात्, कुल 299 विवरणियों में से, 95 विवरणियां (लगभग एक तिहाई) आरबीआई द्वारा एक्सबीआरएल प्ररूप में प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि तत्वों की संख्या के निबंधनों में 2/3 से अधिक तत्व एक्सबीआरएल प्ररूप में प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि विनियामक विवरणियों के अलावा आरबीआई ने बैंकों से यह भी अनुरोध किया है कि वे वर्ष 2013 से अपने वित्तीय विवरणों को भी एक्सबीआरएल प्ररूप में प्रस्तुत करें।

- संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया था कि वह सदस्यों और कंपनियों द्वारा अनुबंधित समय के भीतर लेखा न प्रस्तुत किए जाने के लिए शास्तियों के उदग्रहण के संबंध में सदस्यों और कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न संदेहों को देखते हुए अंतिम तारीख को विस्तारित करने पर विचार करें। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने साधारण परिपत्र सं. 10/2015, तारीख 13 जुलाई, 2015 के द्वारा वार्षिक रूप से फाइल किए जाने वाले प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित किया था और अतिरिक्त शुल्कों को शिथिल किया था। एमसीए ने 31 अक्टूबर, 2015 तक प्ररूप एओसी-4, एओसी-4 एक्सबीआरएल और एमजीटी-7 के संबंध में संदेय अतिरिक्त फीस को भी शिथिल किया है। ऐसी कंपनियों के लिए, जिनसे एक्सबीआरएल में फाइल करने की अपेक्षा नहीं है और जिनसे समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) को फाइल करने की अपेक्षा की जाती है, एक पृथक् प्ररूप एओसी-4 सीएफएस में अपने सीएफएस को फाइल करने की अंतिम तारीख को बिना किसी अतिरिक्त फीस के बढ़ाकर 30 नवंबर, 2015 कर दिया गया है।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों के प्रारूप बीमा वर्गीकरण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

➤ **एक्सबीआरएल संबंधी कार्यान्वयन**

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 11 जून, 2015 से शेयर धृति पैटर्न के आनलाइन फाइलिंग के लिए एक्सबीआरएल सोलुशन का शुभारंभ किया है। 21 जुलाई, 2015 की बीएसई की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार 1062 कंपनियों ने जून, 2015 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिए अपनी शेयर धृति पैटर्न को बीएसई एक्सबीआरएल सोलुशन का उपयोग करते हुए फाइल किया है।

➤ **अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप**

एक्सबीआरएल इंडिया नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय आयोजनों अर्थात् सम्मेलनों, एक्सबीआरएल एशिया कार्यशालाओं, अधिकारिता संबंधी नेतृत्व आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेता है।

एक्सबीआरएल इंडिया ने जनवरी, 2016 में भारत में एक्सबीआरएल एशियाई कार्यशाला और राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है।

8. अन्य मामले

8.1 शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम एक सक्रिय पाठ्यक्रम है और इसलिए इसका आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि समकालीन आर्थिक विकास की घटनाओं की तुलना में वृत्ति अपनी अग्रता बनाए रखे। तदनुसार, वर्ष 2013-14 में शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति का गठन किया गया था। इसे वर्ष 2014-15 के लिए पुनर्गठित किया गया था।

एक बहुआयामी नीति के भागरूप में, इसने सेवाओं के उपयोक्ताओं, विनियामकों और प्रत्येक क्षेत्र के शिक्षाविदों के साथ बैठकें की थी ; सदस्यों, छात्रों, सेवा उपयोक्ताओं, जिनके अंतर्गत विश्व के प्रमुख लेखांकन निकायों के विनियामक और शिक्षाविद् भी हैं, के लिए वेब आधारित प्रश्नोत्तर जारी किए थे ; शिक्षा और प्रशिक्षण की स्कीम का अध्ययन किया था जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों से मूल्यवान अंतःनिवेश प्राप्त हो सके तथा शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम तैयार करते समय आईएफएसी द्वारा जारी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के मापदंड तैयार किए जा सकें।

ऊपर स्पष्ट की गई ब्यौरेवार पद्धति को अपनाने के पश्चात्, परिषद् ने शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक स्कीम के प्रस्ताव का प्रारूपण किया था। इस स्कीम को 12 फरवरी, 2015 से 31 मार्च, 2015 के दौरान जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए रखा गया था। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष, आईसीएआई ने पांच केंद्रीय परिषद् सदस्यों को व्यवसायरत सदस्यों, सीए सेवाओं के उपयोक्ताओं और उद्योग में लगे सदस्यों, सभी क्षेत्रों में लगे एचआर विभागों के व्यक्तियों, विनियामकों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, छात्रों और माता-पिता के साथ आउटरीच बैठकें आयोजित करने के लिए प्रादेशिक समन्वयकों के रूप में नियुक्त किया था ताकि सभी पणधारियों से अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।

फरवरी, 2015 में आयोजित परिषद् की 340वीं बैठक में परिषद् द्वारा प्राधिकार के निबंधनों में अध्यक्ष, आईसीएआई ने शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम को अंतिम रूप प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समूह का गठन किया था। समूह ने उद्योग के प्रतिनिधियों, व्यवसायरत सदस्यों और अखिल भारत के आधार पर अन्य पणधारियों के साथ अप्रैल, -जून, 2015 के दौरान, शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रस्तावित स्कीम के संबंध में उनके विचार/अंतःनिवेश प्राप्त करने के लिए अनेक परस्पर क्रियाशील बैठकें की थीं। ऊपर उल्लिखित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मतों पर विचार करने के पश्चात् समूह ने शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी एक स्कीम का प्रारूपण किया था।

परिषद् ने, 24 और 25 जून, 2015 के दौरान हुई अपनी 343वीं बैठक में इस प्रारूप स्कीम पर विचार-विमर्श किया था। प्रारूप स्कीम पर विचार करने के पश्चात् समिति ने निम्नलिखित पुनरीक्षित स्कीम को अनुमोदित किया था :

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनरीक्षित स्कीम

पुनरीक्षित स्कीम : रूट 1 – फाउंडेशन पाठ्यक्रम¹

फाउंडेशन पाठ्यक्रम रूट के अधीन, निम्नलिखित कदम अपेक्षित हैं :

- बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने के पश्चात् 30 जून/31 दिसंबर तक अध्ययन बोर्ड (बीओएस) के पास रजिस्टर करें।
- बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् फाउंडेशन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बनें। पहली फाउंडेशन परीक्षा, बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आने वाले नवंबर/मई, जो भी लागू हो, दी जा सकती है।
- फाउंडेशन पाठ्यक्रम को अर्हित करें।
- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए बीओएस के साथ रजिस्टर करें।
- 8 मास के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करें।
- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के किसी एक या दोनों समूहों की परीक्षा में बैठकर उसे उत्तीर्ण करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधित चार सप्ताह के एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस) को सफलतापूर्वक पूरा करें।
- मध्यवर्ती के किसी एक या दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तीन वर्ष के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करें।
- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के दोनों समूहों को अर्हित करने के पश्चात् फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान चार सप्ताह के अग्रिम आईसीआईटीएसएस को सफलतापूर्वक पूरा करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण और अग्रिम आईसीआईटीएसएस पूरा होने के पश्चात् फाइनल परीक्षा में बैठें।
- सदस्य बनें।

पुनरीक्षित स्कीम : रूट 2 – सीधे प्रवेश रूट²

आईसीआईटी वाणिज्य स्नातकों/स्नातकोत्तरों (न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों वाले) या अन्य स्नातकों/स्नातकोत्तरों (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों वाले) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखा संस्थान के मध्यवर्ती स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सीधे मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है। पात्र स्नातकों और स्नातकोत्तरों से इस रूट के अधीन निम्नलिखित कदम उठाना अपेक्षित है :

- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए बीओएस के साथ रजिस्टर करें (स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात है)
- व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधित चार सप्ताह के एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस) को सफलतापूर्वक पूरा करें।
- तीन वर्ष के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करें।
- नौ मास के व्यावहारिक प्रशिक्षण के पश्चात् मध्यवर्ती परीक्षा में बैठें।
- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम अर्हित करें।
- मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के दोनों समूहों को अर्हित करने के पश्चात् फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान चार सप्ताह के अग्रिम आईसीआईटीएसएस को सफलतापूर्वक पूरा करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करें।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण और अग्रिम आईसीआईटीएसएस पूरा होने के पश्चात् फाइनल परीक्षा में बैठें।
- सदस्य बनें।

फाउंडेशन पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्रों का संख्यांक और नाम

प्रश्नपत्रों की संख्या – 4

प्रश्नपत्र 1 : प्रिन्सीपल्स एंड प्रैक्टिस आफ अकाउंटिंग (100 अंक)

प्रश्नपत्र 2 : मर्केटाइल लॉ एंड जनरल इंग्लिश (100 अंक)

भाग 1 : मर्केटाइल लॉ (60 अंक)

भाग 2 : जनरल इंग्लिश (40 अंक)

¹ टिप्पण : आईसीआईटी ने ऊपर उल्लिखित स्कीम का सिद्धांत रूप में विनिश्चय किया है। तथापि, स्कीम को सम्यक् अनुक्रम में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

² टिप्पण : ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आईसीएसआई या आईसीडब्ल्यूआई की मध्यवर्ती स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्होंने सीधे सीए मध्यवर्ती पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, को फाउंडेशन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के तत्समान समझा जाएगा।

- प्रश्नपत्र 3³ : बिजनेस मैथेमैटिक्स एंड लाजिकल रिजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स (100 अंक)
 भाग 1 : बिजनेस मैथेमैटिक्स एंड लाजिकल रिजनिंग (60 अंक)
 भाग 2 : स्टैटिस्टिक्स (40 अंक)
- प्रश्नपत्र 4⁴ : बिजनेस इकनोमिक्स एंड बिजनेस एंड कर्मशियल नॉलेज (100 अंक)
 भाग 1 : बिजनेस इकनोमिक्स (60 अंक)
 भाग 2 : बिजनेस एंड कर्मशियल नॉलेज (40 अंक)

टिप्पण

- उत्तीर्ण करने का प्रतिशत : कुल – 50 प्रतिशत और विषयवार – एकवार में 40 प्रतिशत
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के लिए एक या अधिक अंक
- परीक्षा : बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नवंबर और मई मास में।

मध्यवर्ती पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्रों का संख्यांक और नाम

प्रश्नपत्रों की संख्या – 8

समूह 1

- प्रश्नपत्र 1 : अकाउंटिंग (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 2 : कारपोरेट लॉज एंड अदर लॉज (100 अंक)
 भाग 1 : कारपोरेट लॉज (60 अंक)
 भाग 2 : अदर लॉज (40 अंक)
- प्रश्नपत्र 3 : कास्ट अकाउंटिंग (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 4 : डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इन्डायरेक्ट टैक्स लॉज (100 अंक)
 भाग 1 : डायरेक्ट टैक्स लॉज (60 अंक)
 भाग 2 : इन्डायरेक्ट टैक्स लॉज (40 अंक)

समूह 2

- प्रश्नपत्र 5 : अडवांस्ड अकाउंटिंग (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 6 : आडिटिंग एंड ऐश्वोरेंस (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 7 : फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकनोमिक एनवायरमेंट (100 अंक)
 भाग 1 : फाइनेंशियल मैनेजमेंट (60 अंक)
 भाग 2 : बिजनेस इकनोमिक एनवायरमेंट (40 अंक)
- प्रश्नपत्र 8 : इनफोरमेशन टेक्नोलाजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट (100 अंक)
 भाग 1 : इनफोरमेशन टेक्नोलाजी (60 अंक)
 भाग 2 : स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट (40 अंक)

चार सप्ताह का सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस)

- अवधि : चार सप्ताह (दो सप्ताह साफ्ट कौशलों के लिए और दो सप्ताह आईटी के लिए)
- कब पूरा करें : मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर करने वाले छात्रों से यह अपेक्षित होगा कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व आईसीआईटीएसएस को सफलतापूर्वक पूरा करें।

व्यावहारिक प्रशिक्षण

- व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि : तीन वर्ष
- चार सप्ताह का सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस) पूरा करने के पश्चात् और मध्यवर्ती के एक या दोनों समूहों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् आरंभ होगा।
- स्नातक और स्नातकोत्तर रूट से आने वाले सीधे प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण उनके द्वारा चार सप्ताह का आईसीआईटीएसएस पूरा करने के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होगा।

चार सप्ताह का सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस)

- अवधि : चार सप्ताह (दो सप्ताह साफ्ट कौशलों के लिए और दो सप्ताह अग्रिम आईटी के लिए)

³ प्रश्नपत्र 3 और प्रश्नपत्र 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र होंगे।

⁴ प्रश्नपत्र 3 और प्रश्नपत्र 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र होंगे।

- कब पूरा करें : व्यावहारिक प्रशिक्षण करने वाले छात्रों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतिम दो वर्षों के दौरान एआईसीआईटीएसएस को पूरा करें, किंतु उन्हें फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बनने हेतु उसे पूरा करना आवश्यक होगा।

फाइनल पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्रों का संख्यांक और नाम

प्रश्नपत्रों की संख्या – 8

समूह 1

- प्रश्नपत्र 1 : फाइनैशियल रिपोर्टिंग (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 2 : स्ट्रेटैजिक फाइनैशियल मैनेजमेंट (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 3 : एडवांस आडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 4 : कारपोरेट लॉज एंड अदर इकनोमिक लॉज (100 अंक)

समूह 2

- प्रश्नपत्र 5 : अडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (100 अंक)
 प्रश्नपत्र 6 : फाइनैशियल सर्विसिस एंड कैपिटल मार्किट्स एंड इनफोरमेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड आडिट (100 अंक)
 भाग 1 : फाइनैशियल सर्विसिस एंड कैपिटल मार्किट्स (50 अंक)
 भाग 2 : इनफोरमेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड आडिट (50 अंक)
 प्रश्नपत्र 7 : एडवांस्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन (100 अंक)
 भाग 1 : एडवांस्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज (70 अंक)
 भाग 2 : इंटरनेशनल टैक्सेशन (30 अंक)
 प्रश्नपत्र 8 : एडवांस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज (100 अंक)

8.2 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

संस्थान के 65वें वार्षिक समारोह का आयोजन 11 फरवरी, 2015 को अशोक होटल, नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि संघ के विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) सीए पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। संघ के मंत्री ने परिषद् की वृत्ति को क्रियाशील आकार प्रदान करने के लिए सराहना की थी, जिसमें अखंडता और पारदर्शिता के लिए अत्यंत उच्चतर मानक स्थापित किए हैं। मुख्य अतिथि द्वारा आईसीएआई की ऐसी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिन्होंने बीते वर्ष में विभिन्न प्रवर्गों के अधीन उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोत्तम के रूप में अधिनिर्णीत किया गया था। छात्र उपलब्धिकर्ताओं को भी विभिन्न सीए परीक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

8.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह – 1 जुलाई, 2015

आईसीएआई ने 1 जुलाई 2015 को अपने 66 स्वर्णिम वर्षों के पूरा होने पर अपने स्थापना दिवस को देश भर में की 150 शाखाओं और 5 क्षेत्रिय परिषदों तथा विदेशी चैप्टरों में धूमधाम से मनाया था। परंपरा के अनुसार, नई दिल्ली में आईसीएआई के ध्वजारोहण संबंधी आयोजन के साथ यह समारोह आरंभ हुआ था, जिसके पश्चात् सीए दिवस संबंधी समारोह प्रारंभ हुए थे, जिसमें हमारे सदस्यों में से एक सीए पीयूष गोयल, विद्युत, कोयला और नई और नवीकरणीय ऊर्जा के माननीय राज्य मंत्री (तंत्र प्रभारस्व) ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि की भूमिका अदा की थी। सचिव, श्री वी. सागर ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया था और अध्यक्ष ने परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए इस अवसर पर उन्हें संबोधित किया था। यह समारोह आईसीएआई के पूर्व गौरवपूर्ण अध्यक्षों, सीए टी.एस. विश्वनाथ और सीए. मुकुंद एम. चिताले के भाषणों के साथ समाप्त हुआ था। सीए टी.एस. विश्वनाथ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की वृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन के विषय पर गणमान्य श्रोताओं को संबोधित किया था। ऐसा करते हुए उन्होंने वृत्ति में परिवर्तनों और उसके विकास को विश्व की अर्थव्यवस्था और लेखांकन में हुए बदलाव की तुलना में उल्लिखित किया था। सीए. मुकुंद एम. चिताले ने प्रतिभागी सदस्यों को संवहनीयता के लिए रणनीति के विषय पर संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे मुद्दों को इंगित किया था, जिनके संबंध में संस्थाओं और संगठनों को अपने-अपने समय में संवहनीय बने रहने और विकास करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।

समारोह के दौरान, जीएसटी – भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान सहित अनेक नए प्रकाशनों, जिन्हें आईसीएआई की विभिन्न समितियों द्वारा प्रकाशित किया गया था, को सीए पाठ्यक्रम की शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी पुनरीक्षण स्कीम तथा धन शोधन निवारण विधियों संबंधी एक नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) का शुभारंभ किया गया था।

8.4 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

आईसीएआई का केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है, यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, मैगजीनों, ऑनलाइन डाटा बेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icaai.org पर “नो युअर इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है। वेबसाइट के अधीन ये सेवाएं स्वस्पष्टीकारक हैं। इनमें से कुछ लिंक, जैसे कि ऑनलाइन जर्नलों, ईपुस्तकों, चार्टर्ड एंकाउंटेड जर्नल से लेखों की सूची और पुस्तकों का ऑनलाइन डाटाबेस, पुस्तकालय में जर्नलों और लेखों की सूची उपर्युक्त ऑनलाइन डाटाबेस में आगे और सर्च का विकल्प उपलब्ध कराते हैं। कोई व्यक्ति आईसीएआई के विचारार्थ “पुस्तकों/जर्नलों के सुझाव का स्तंभ” के अधीन नई पुस्तकों/जर्नलों के लिए सुझाव भी दे सकता है।

स्तंभ “एकाउंटेड्स ब्राउजर” के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास “द चार्टर्ड अकाउंटेड” जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि “एकाउंटेड्स ब्राउजर” पिछले पंद्रह वर्षों से महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अभिलेखागार के साथ एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में सीपीटी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। आईसीएआई के विभिन्न निदेशालय और समितियों को दिए गए लघु पुस्तकालयों के साथ, आईसीएआई के सेक्टर-62 स्थित नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर कार्यालय में छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाइन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जो www.icaai.org –Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री की सर्च को सुकर बनाने के लिए प्रतिष्ठापित किया है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस को सभी प्रादेशिक पुस्तकालय डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर लिबर्टी को स्थापित किया गया है।

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सभी समितियों और साथ ही आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित चालू पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रकाशन/पुस्तकों का भी उपापन कर रहा है जिसके अंतर्गत सभी समितियों द्वारा प्रकाशनों/पुस्तकों का प्रावधान भी है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमशः प्रधान कार्यालय और नोयडा कार्यालय में अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय (प्रधान कार्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	अनुमानित आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	65
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	13
3.	आनलाइन संसाधन	10
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	654

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय (सेक्टर-62 नोएडा)

क्रम सं.	शीर्षक	अनुमानित आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय	44
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	09
3.	आनलाइन संसाधन	08
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	733

हम ई-पुस्तकों, ई-जर्नलों और अन्य आनलाइन डाटा बेसों की ग्राहकी प्राप्त करके केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय को आधुनिक बनाने के साथ ही केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय की सुसज्जा करने की कार्यवाही कर रहे हैं। छात्रों और सदस्यों आदि के लिए पुस्तकालय नियमों को तैयार किया गया है ताकि आईसीएआई के सभी पुस्तकालयों का कार्यकरण एकसमान हो सके।

8.5 संपादकीय बोर्ड

ज्ञान का अक्षरशः प्रसार

संपादकीय बोर्ड संस्थान की एक अस्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को निरंतर रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध विषयों, संस्थान और इसके क्रियाकलापों से संबंधित विषयों और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें शैक्षणिक/वृत्तिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाए, एक संरचित रीति में 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। यह जर्नल ई-जर्नल के रूप में ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जो आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) से भी संगत है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 264000 है और इसके वैश्विक पाठकों में विख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के चार्टर्ड एकाउंटेंट, सहबद्ध वृत्तिक, सीए छात्र और शैक्षणिक वृत्तिक सम्मिलित हैं। ऐड-आन सेवा के रूप में, जर्नल के प्रत्येक अंक की प्रमुख विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में दिए गए अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जाता है।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टकरा ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मित्र के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है।

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय बोर्ड निरंतर प्रयास कर रहा है।

1 अप्रैल, 2014 और 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

अंतर्वस्तु और ई-जर्नल :

- **व्यापक रूप से विषयों को सम्मिलित किया जाना :** अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन विषयक मुद्दों के अधीन विभिन्न विषयों पर 194 से अधिक लेखों का प्रकाशन किया गया था।
- **नवीनता विषयक मुद्दे :** अन्य नियमित विशिष्टियों के अलावा आईसीएआई कार्य योजना 2014-15/2015-16 के नीतिगत ध्यान केंद्रित विषयों के क्षेत्रों के अनुरूप कुछ नए और नवीनता विषयक मुद्दों की योजना बनाई गई थी। ये विषयक मुद्दे निम्नानुसार थे : 'नई सीमाओं की ओर', 'महिला सशक्तिकरण', 'युवा सदस्य सशक्तिकरण' 'नेतृत्व और प्रभाव', 'संघीय बजट 2014-15', 'आईसीएआई की उपलब्धियां', 'कर संपरीक्षा', 'सीए शिक्षा' तथा 'सीए और प्रौद्योगिकी', 'आईएफआरएस और भारत', 'आईसीएआई की पुनरुत्थानशील भारत को नया आकार प्रदान करने में भागीदारी' '2014-15 में आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियां', 'संघीय बजट 2015-16', 'आईसीएआई उत्कृष्टता का नेतृत्व और आईसीएआई वृत्ति के अंतःनिहित विकास के लिए'। विद्यमान विशिष्टियों जैसे कि 'फ्राम द प्रेजिडेंट', 'लीगल अपडेट', 'नेशनल अपडेट' और 'इंटरनेशनल अपडेट' आदि को और अधिक समृद्ध बनाया गया था।
- **संपादकीय बोर्ड कार्य योजना 2014-15 और 2015-16**
संपादकीय बोर्ड ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया था और उसे प्रभावी भी किया

है। इस कार्य योजना की प्रमुख विशिष्टियों में 'अनेक नए फीचर आरंभ करना', 'सीए दिवस के उपलक्ष्य में जुलाई, 2014 और जुलाई, 2015 में जर्नल का एक विशेष अंक निकालना', 'जर्नल की भाषा को और अधिक सरल तथा पाठक मित्र बनाना', 'सक्रिय सर्व प्रसुविधा के साथ जर्नल के 61 वर्षों की एक सुरक्षित एचटीएमएल रूप में डीवीडी निकालना', 'इंडेक्स पद्धति में जर्नल का विस्तार/प्रोन्नयन', 'आईसीएआई की कार्य योजना 2014 के नीतिगत रूप से विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों को प्रमुख रूप से दर्शित करना', 'जर्नल के डिजाइन और प्रस्तुतीकरण का प्रोन्नयन' और 'जर्नल के मुद्रण के लिए अधिक श्वेत ग्लोस कागज का प्रयोग करना' और ई-जर्नल में नए उपयोक्ता मित्र फीचरों को आरंभ करना आदि सम्मिलित है।

• प्रमुख विशिष्टियां

जुलाई, 2014 का विशेष अंक : जुलाई, 2014 के विशेष अंक में नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यसूची को प्रस्तुत किया गया था और साथ ही श्री अरुण जेटली, संघ के वित्त, कारपोरेट कार्य तथा रक्षा मंत्री, श्री निर्मला सीतारामन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य और उद्योग, राज्य मंत्री, वित्त और कारपोरेट कार्य और सीए पीयूष गोयल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, कोयला और नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोफाइल को भी सम्मिलित किया गया था। इस अंक में श्री अरुण जेटली, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक श्री शशिकांत शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के विशेष संदेशों को भी अंतर्विष्ट किया गया था। इस अंक में वर्ष 2014-15 के पहले चार मासों में आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया था। ऐसे विशिष्ट लेखकों में जिनके लेखों को इस अंक में सम्मिलित किया गया था, श्री पी.एन. विजय, श्री वारेन एलेन, अध्यक्ष आईएफएसी, श्री ब्रायन ब्लड, मुख्य कार्यपालक, सीएपीए, सीए सुबोध कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, एसएएआरसी और तुरंत पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए टी.एन. मनोहरन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए संजीव चौधरी सम्मिलित थे। अन्य विशिष्ट फीचरों में 'डाउन द मेमेरी लेन', 'वाट द लीडर्स सेड अबाउट आईसीएआई डयूरिंग 2013-14' आदि सम्मिलित थे।

जुलाई, 2015 का विशेष अंक : जुलाई, 2015 के अंक को 1 जुलाई को मनाए गए सीए दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष और बड़ा अंक बनाया गया था। इस अंक में, जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था उनमें आईसीएआई का पूर्व वर्तमान और भावी परिप्रेक्ष्य तथा भारत में लेखांकन वृत्ति के विषय सम्मिलित थे। इस अंक की प्रमुख विशिष्टियों में रेल मंत्री सीए सुरेश प्रभु के साथ एक विशेष साक्षात्कार, विद्युत मंत्री सीए पीयूष गोयल पर एक विशेष लेख तथा संसद् सदस्य सीए किरिट सौम्या, सीए के. रहमान खान, आईएफएसी अध्यक्ष ओलिविया कर्टली, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और पदमश्री सीए वाई.एच. मालेगम और एक्सबीआरएल इंडिया द्वारा लिखे गए विशेष लेख सम्मिलित थे। इस अंक के विशेष फीचरों में पिछले अनेक वर्षों के आईसीएआई की सीएसआर पहलों की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट, भारतीय लेखांकन वृत्ति के बारे में कुछ कम ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों की कवरेज, इस संबंध में रिपोर्ट की भारतीय राजनीति के नेताओं ने पिछले वर्ष के दौरान भारतीय लेखांकन वृत्ति के संबंध में क्या कहा, वर्ष 2014-15 में आईसीएआई की मीडिया छवि, ऐसे चार सीए को सम्मिलित करना, जिन्होंने सभी प्रकार की विसंगतियों, भौतिक निःशक्तताओं और अधिक आयु के दबाव का सामना करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और आईसीएआई के स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष सीए रामेश्वर ठाकुर को श्रद्धांजलि सम्मिलित थे। इसके मुख पृष्ठ को कलात्मक ढंग से सजाया गया था और उस पर 'आईसीएआई टर्न 66' नामक शीर्षक, भारतीय लेखांकन वृत्ति से संबंधित कुछ दुर्लभ चित्रों के साथ मुद्रित किया गया था।

- **द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के पूर्व अंकों की डीवीडी :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के पाठकों को एकल संदर्भ बिन्दु उपलब्ध कराने और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए संपादकीय बोर्ड ने जर्नल के पूर्व अंकों की एक डीवीडी दो चरणों में निकाली थी। पहले चरण में, जर्नल के पिछले दस वर्षों की डीवीडी (जुलाई 2002 से जून, 2012), को निकाला गया था और 25 रूपए प्रति डीवीडी + डाक खर्चों की सस्ती लागत पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया था। दूसरे चरण में, 61 वर्षों के द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल को अंतर्विष्ट करने वाली एक डीवीडी को जारी किया गया था। 63 वर्षों के जर्नल (जुलाई, 1952 से जून, 2015) को सम्मिलित करने वाली एक समुन्नत मास्टर डीवीडी भी विकसित किए जाने के अग्रिम प्रक्रम पर है और उसे शीघ्र ही 150 रूपए की कीमत, डाक व्यय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, जारी किया जाएगा। डीवीडी के इस एचटीएमएल पाठ में जुलाई, 1952 से जून, 2015 तक के जर्नल के अंक खोज पद्धति सुविधा के साथ उपलब्ध हैं। पाठक अंतर्वस्तु की खोज, लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि से संबंधित कुंजी शब्दों का उपयोग करते हुए कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त, मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विधिक निर्णयों आदि) लेखक आदि के माध्यम से भी खोज की जा सकेगी।

- **साहित्यिक चोरी निवारण नीति को स्थापित करना और अग्रिम साहित्यिक चोरी निवारण साफ्टवेयर उपापन :** शिक्षाविदों, आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों सहित लेखकों द्वारा साहित्यिक रूप से चोरी की गई अंतर्वस्तु को प्रस्तुत करने के मामले में अत्यधिक वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, जिसके कारण द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल की विश्वसनीयता और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, एक व्यापक साहित्यिक चोरी निवारण नीति को अंतिम रूप प्रदान करते हुए संपादकीय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया गया था। एक अति विश्वसनीय और लोकप्रिय साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले साफ्टवेयर को भी इस प्रयोजन के लिए उपाप्त किया गया है।

- **अनुक्रमणिका पद्धति में जर्नल का शुभारंभ :** 'अनुक्रमणिका पद्धति में जर्नल' की सुविधा को समुन्नत किया गया है, जिसमें पिछले दस वर्षों के सभी लेखकों को एक सक्रिय सर्च उपयोजन के साथ विषयों और टापिक के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसे आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।
- **'मोबाइल/आई पेड पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल को प्राप्त करने' की सुविधा :** 1 मार्च, 2013 से द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के एक निःशुल्क मोबाइल/आई पेड संगत पाठ को प्रचालनरत बनाया गया था। इस सुविधा को अब और अधिक समुन्नत किया गया था। इस उन्नयन के साथ आईसीएआई की ई-जर्नल अब आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रायड युक्तियों हेतु समर्थ है, जो हमारे पाठकों को कहीं भी और किसी भी समय एक बटन के साथ ही उपलब्ध हो जाएगा। मोबाइल समर्थ (आईओएस, एंड्रायड, टेबलेट प्लेटफार्म पर) ई-जर्नल के पाठ में नई पोडकास्ट और बुकमार्क की सुविधा को समाविष्ट किया गया है। श्रोता अब जर्नल को पढ़ने की बजाए उसकी पाठ सामग्री को सुन भी सकते हैं और इस प्रकार यात्रा करते हुए अपने समय का अनुकूल उपयोग कर सकते हैं। पाठक अब ई-जर्नल तक ऊपर उल्लिखित मंचों के माध्यम से बिना किसी विनिर्दिष्ट डाउनलोड अपेक्षा के पहुंच बना सकते हैं। इस तक पहुंच <http://www.icai.org/ke> अधीन "ई-जर्नल टेब" पर बनाई जा सकती है।
- **ई-जर्नल का उन्नयन :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल का इलैक्ट्रानिक पाठ, जो आईसीएआई की वेबसाइट <http://www.icai.org> पर आनलाइन रूप से उपलब्ध है, जो कि एक संपरिवर्तित नई उच्च प्रौद्योगिकी उपयोक्ता मित्र ई-मैगजीन है, को और अधिक समुन्नत किया गया था। ई-जर्नल के नए पाठ में, कोई व्यक्ति, अन्य सुविधाओं की श्रृंखला का उपयोग करने के साथ-साथ अब अंतर्वस्तु को 'सुन' भी सकता है। तथापि, पाठकों की और अधिक तथा वैकल्पिक सहूलियत के लिए, जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में भी वेबसाइट पर रखा जाता है।
- **लेखों की दोहरी जांच की नीति को लागू करना :** इस वर्ष, संपादकीय बोर्ड ने ऐसे लेखों की दोहरी जांच की प्रणाली को आरंभ किया है, जो जर्नल में प्रकाशन हेतु विचारार्थ बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। जांच का पहला चक्र कार्यालय द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि संपादकीय बोर्ड के सदस्य और पदाभिहित पुनर्विलोकक, प्रकाशन हेतु सर्वोत्तम लेखों का चयन करने के लिए दूसरे चक्र में लेखों की जांच करते हैं और उनकी संवीक्षा करते हैं।
- **जर्नल की प्रमुख विशिष्टियां ई-मेल के माध्यम से :** सदस्यों और पाठकों की बेहतर पहुंच और सुविधा के लिए जर्नल की प्रमुख विशिष्टियों को, अंतर्वस्तु के लाइव लिंकों के साथ पीडीएफ फोर्मेट में ई-मेल किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को यह जानकारी प्रदान करने में समर्थ बनाना है कि वे जर्नल की हार्ड कापी की प्रतीक्षा करने की बजाए जर्नल की प्रमुख विशिष्टियों को वास्तविक समय में माउस के एक क्लिक के साथ देख सकें। इस 'जर्नल की प्रमुख विशिष्टियों' के कैप्सूल को और अधिक उन्नत करके उच्चतर वृत्तिक मानकों के अनुरूप किया गया है तथा उसे और अधिक पाठक मित्र बनाया गया है।
- **बड़ी संख्या में मेल करने के लिए अध्यक्ष के संदेश के प्ररूप का उन्नयन :** आईसीएआई के सदस्यों तक सर्वोत्तम और अत्यधिक उपयोक्ता मित्र रीति में पहुंच बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग के अभियान के भागरूप में, अध्यक्ष के संदेश के प्ररूप की गुणवत्ता और उसकी आकृति और आकार को ई-पाठ में महत्वपूर्ण रूप से संवर्धित किया गया है। इस समुन्नत अध्यक्ष के संदेश को, मार्च, 2014 के अंक से सदस्यों को बड़ी संख्या में ई-मेल किया जाता है।
- **जर्नल में सम्मिलित उद्घोषणाओं की हस्ताक्षर रेखा में नाम प्रकाशित करने संबंधी नीति :** सर्वोत्तम शासन तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयासों के भागरूप में संपादकीय बोर्ड ने आईसीएआई जर्नल में प्रकाशित नियमित घोषणाओं की हस्ताक्षर रेखा में नामों के प्रकाशन के संबंध में नीति को पुनरीक्षित किया है।

लेआउट और डिजाइन :

- जर्नल के मुख पृष्ठ को पुनः अनुकूल तथा और अधिक रचनात्मक, अर्थपूर्ण और विचारों को जन्म देने वाले के रूप में समुन्नत किया गया था, ऐसा आईसीएआई और लेखांकन वृत्ति से सुसंगत विषयों और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त वैकल्पिक डिजाइन और अंतर्वस्तु विकास अभिकरणों को भी निरंतर सुधार हेतु आवश्यकता आधार पर नियोजित किया गया है। मुख पृष्ठ पर छपने वाले चित्रों और अंतर्वस्तु की अनुकूलता की जांच करने हेतु एक चार टियर तंत्र को आरंभ किया गया है।
- जर्नल को, उसके सभी पृष्ठों पर डिजाइन और प्रस्तुतीकरण संबंधी उन्नयन प्रदान किया गया था। जर्नल के मास्ट शीर्ष को प्रोन्नत किया गया है जबकि अंदर के पृष्ठों की डिजाइन और प्रस्तुतीकरण तथा फीचरों को पाठ की फोंट किस्म के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए संपूर्ण जर्नल के ले-आउट डिजाइन और फोंट किस्म आमुख को आगे और प्रोन्नत किया गया था।
- आवरण पृष्ठ और अंदर के पृष्ठों के मास्ट शीर्ष और आधारित टैम्पलेट में और अधिक सुधार किए गए थे।
- मई, 2014 के अंक से, सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप सकल अंतर्वस्तु की क्वालिटी, आकृति और आकार तथा जर्नल की

लोकप्रियता को बढ़ावा देने के सकल प्रयासों के भागरूप में इसके कागज को एक उच्चतर तथा अधिक श्वेत क्वालिटी की ग्लोस फिनिश वाले 65 जीएसएम कागज में परिवर्तित किया गया है।

- आईसीएआई की कार्यक्रम आयोजन करने वाली इकाईयों/समितियों की व्यावहारिक सुगमता के लिए और एकसमानता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय बोर्ड ने अगस्त, 2015 के जर्नल के अंक से द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में आईसीएआई के आयोजनों के प्रकाशन संबंधी प्ररूप को पुनरीक्षित किया है।

अन्य उपलब्धियां/पहले :

- **जर्नल का कुल परिचालन 264000 से अधिक हो जाना :** इसी दौरान जुलाई, 2015 के अंक में आईसीएआई के जर्नल के कुल परिचालन आंकड़े 2,64,000 के अंक को पार कर गए थे। तदनुसार, डाकघर संबंधी प्राधिकारियों से रियायती दरों पर डाक द्वारा भेजी जाने वाली प्रतियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विशेष अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
- **सदस्यों के आवासीय पते पर जर्नल प्राप्त करने की सुविधा :** सदस्यों की सुविधा के अनुसार जर्नल की पहुंच और पाठ्यता में अभिवृद्धि करने के प्रयासों के भागरूप में, जर्नल को अपने आवासीय पते पर प्राप्त करने की सदस्यों की सुविधा (पूर्व में जर्नल को केवल सदस्यों के आईसीएआई में अभिलिखित उनके वृत्तिक पते पर ही भेजा जाता था) को और अधिक सुदृढ़ किया गया था तथा उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति, जर्नल तथा आईसीएआई की वेबसाइट के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया था। 'आवासीय पते पर जर्नल प्राप्त करने' के अनन्य जर्नल संबंधी विकल्प को पुनः सक्रिय किया गया है और उसे बहुत बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा रहा है। आवश्यक पृष्ठभूमि परिवर्तनों के संबंध में आईसीएआई की वेबसाइट पर 'पते में परिवर्तन' से संबंधित लिंक को पहले ही इस संबंध में अद्यतन कर दिया गया है।
- **नई सुविधा : 'जर्नल की ग्राहकी के लिए आनलाइन संदाय, एयर मेल अधिभार' :** सदस्यों के लिए और अधिक सुविधा, आराम और बेहतर सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए समेकित प्रयासों के अनुरूप संपादकीय बोर्ड ने द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के लिए आनलाइन संदाय सुविधा को आरंभ किया था, जो पूरे विश्व में पाठकों को फायदा प्रदान करेगी। यह आनलाइन संदाय सुविधा अब आईसीएआई की वेबसाइट पर पाठकों के दस प्रवर्गों के लिए उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत ग्राहक, विदेशों में रह रहे सदस्य, वर्गीकृत विज्ञापनकर्ता, छात्र, ग्राहक आदि हैं। जर्नल के लिए यह चिरप्रतिक्षित आनलाइन संदाय सुविधा, उसके पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए अत्यंत फायदाप्रद और सुगम सिद्ध होगी।
- **जर्नल के मुद्रण और प्रेषण का सत्यापन :** सतत मानीटरी और जांच के भागरूप में, नवी मुंबई में स्थित एक नए संपरीक्षक को, जर्नल के मुद्रक के नवी मुंबई स्थित मुद्रणालय में मुद्रित प्रतियों की संख्या के सत्यापन के प्रयोजन के लिए और मुंबई में डाक विभाग के माध्यम से प्रेषित प्रतियों की संख्या के सत्यापन हेतु नियुक्त किया गया है।
- **निःशुल्क जर्नल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची को अद्यतन करना :** ब्रांड निर्माण प्रक्रिया के भागरूप में और आईसीएआई की पहुंच वृत्ति से सुसंगत प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों तक बनाने के विचार से ऐसे व्यक्तियों की सूची को, जिन्हें जर्नल निःशुल्क रूप से प्रेषित किया जाएगा, को एक सतत प्रक्रिया के रूप में पुनरीक्षित किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक पतों को अद्यतन किया गया है, पुरानी प्रविष्टियों का लोप किया गया है और विभिन्न प्रवर्गों के अधीन विभिन्न नामों को सम्मिलित किया गया है।
- **कागज की जांच की प्रणाली को अग्रसर करना :** इस बात को सुनिश्चित करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में कि जर्नल का मुद्रक करार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कागज की उचित क्वालिटी और विनिर्देशों को पूरा कर रहा है, विभिन्न मासों में जर्नल के लिए विभिन्न कागज के नमूनों को परीक्षण हेतु गर्वनमेंट सेंट्रल प्लप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया था।
- **एमआरए के माध्यम से सदस्य बनने वाले व्यक्तियों को जर्नल का प्रेषण आरंभ करना :** संपादकीय बोर्ड के सचिवालय ने ऐसे सभी सदस्यों को जर्नल की प्रतियां भेजना आरंभ कर दिया है, जो विदेशी लेखांकन निकाय के साथ हुए एमआरए/एमओयू के अधीन आईसीएआई के सदस्य बने हैं। चूंकि प्रणाली में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें पृथक् रूप से भौतिक अभिलेख रखकर नामांकित किया गया है।
- **भारत में समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन :** भारत में समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई), जिसके पास आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत है, की विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कार्यालय ने जर्नल के अबाध प्रकाशन और अपेक्षित कागज के सस्ते दाम पर प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए डीसीपी, अनुज्ञापन, दिल्ली के अभिलेखों में प्रकाशक के नाम के परिवर्तन के साथ पुनरीक्षित प्ररूप ख उपाप्त करने के अलावा जर्नल की आज्ञापक वार्षिक रिपोर्ट को आनलाइन रूप से प्रस्तुत किया है।
- **जर्नल के लिए कागज आयात अनुज्ञप्ति का अर्जन :** भारत में समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) की विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए जर्नल के अबाध प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय ने आरएनआई से इस वर्ष हेतु जर्नल के लिए मुद्रण कागज आयात करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। यह विदेश से अपेक्षित कागज के नियमित और सस्ते प्रदाय को सुकर बनाएगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दैनिक इतिवृत्त :** बंगलौर प्लैस में हुए आईसीएआई के तीन दिवसीय वृहत्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

के लिए एक समाचारपत्र किस्म के दैनिक इतिवृत्त को निकाला गया था, जिसमें इस आयोजन के दौरान हुए सभी विचार-विमर्शों, कार्यक्रमों और व्यक्तित्वों को सम्मिलित किया गया था।

8.6 भारत का लेखांकन संग्रहालय

आईसीएआई द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित भारत के लेखांकन संग्रहालय, जो लेखांकन वृत्ति की समृद्ध बौद्धिक धरोहर का एक अत्यधिक विशाल खजाना है, वर्तमान में, मानव इतिहास से लिए गए अनेकों लेख, दस्तावेजों/कहानियों को धारण करता है। इस वर्ष, संग्रहालय ने और अधिक लेखों को वरिष्ठ सदस्यों तथा भारत में स्थित निजी संग्रहणकर्त्ताओं से प्राप्त किया है, जिन्हें शीघ्र ही संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना प्रोटोटाइप आफ एएमआई को आगे और अग्रसर किया गया था - इस वर्ष आईसीएआई की शाखाओं को 43 प्रोटोटाइप सामग्रियां भेजी गई थी, इस प्रकार इसकी कुल संख्या देश भर में, जहां संग्रहालय के प्रोटोटाइप को स्थापित किया गया है, बढ़कर 87 हो गई है। संग्रहालय ने आईसीएआई के कार्यक्रमों अर्थात् लोक वित्त तथा शासकीय लेखांकन संबंधी समिति द्वारा जयपुर में आयोजित चुनौतियों का सामना करना - हमारी भूमिका को पुनः परिभाषित करने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सेवा संबंधी वैश्विक प्रदर्शनी के लिए समृद्ध कहानियां और मदों का संग्रहण उपलब्ध कराके अपना योगदान किया था। भारतीय मीडिया ने भी इस संग्रहालय को पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान की थी - संग्रहालय के संबंध में द हिन्दू में अगस्त, 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस संग्रहालय में आने वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ इस वर्ष संग्रहालय का दौरा करने वाले व्यक्तियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों - श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सत्यवती महाविद्यालय (सायंकालीन) के छात्र और संकाय सदस्य भी सम्मिलित थे। संग्रहालय निरंतर रूप से आईसीएआई के जर्नल, द चार्टर्ड एकाउंटेंट में भी कहानियों और लेखों का योगदान देता है।

8.7 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

कार्यालय ने उसके द्वारा 5 दिसंबर, 2013 को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की थी :

- (क) आर्टिकल सहायकों को संदेय वृत्तिका की दरों में वृद्धि करने के संबंध में विनियम 48 में संशोधन
- (ख) सी एंड एजी के कार्यालय के आईए और एएस अधिकारियों के तीन वर्ष के अनुभव को एक वर्ष के औद्योगिक प्रशिक्षण के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए विनियम 51 में संशोधन
- (ग) अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि को नौ मास से घटाकर आठ मास करने के लिए विनियम 28ड. का संशोधन
- (घ) अंकों के सत्यापन के लिए फीस की अधिकतम सीमा को बढ़ाने और मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और/या उनकी प्रमाणित प्रति के प्रदाय हेतु उपबंध के लिए विनियम 39 का संशोधन और नए विनियम 39क का अंतःस्थापन
- (ङ) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए विनियम 204 का संशोधन

जहां तक ऊपर (ख) में उल्लिखित किए गए अनुसार विनियम 51 में प्रस्तावित संशोधन का संबंध है, उसके पश्चात् परिषद् को यह महसूस हुआ था कि इस विषय के संबंध में एक वृहत्तर मत बनाया जाना आवश्यक था, इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि जहां तक इस विषय का संबंध था संशोधन प्रस्ताव को वापस लिया जाए।

उपरोक्त संशोधन प्रस्तावों के संबंध में केंद्रीय सरकार का सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के प्रारूप संशोधनों के, जिन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014, तारीख 10 सितंबर, 2014 में अधिसूचित किया गया था, संबंध में जनता से टीका-टिप्पणियां मांगी गई थी। परिषद् ने, 29-31 अक्टूबर, 2014 के दौरान हुई अपनी 337वीं बैठक में जनता, सदस्यों और छात्रों से प्राप्त प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में टीका-टिप्पणियों पर विचार किया था। इन टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् परिषद् ने यह विनिश्चय किया था कि प्रारूप संशोधनों को और अधिक स्पष्टीकारक बनाया जाना चाहिए तथा यह और विनिश्चय किया था कि प्रस्तावित संशोधनों के पीछे आशय को स्पष्ट करते हुए आईसीएआई की वेबसाइट पर एक समुचित स्पष्टीकारक टिप्पण रखा जाए। तदनुसार, परिषद् के विनिश्चय की संसूचना केंद्रीय सरकार को भेज दी गई थी। केंद्रीय सरकार ने, अपने तारीख 22 जनवरी, 2015 के पत्र द्वारा विनियम 39(4) और 39क में किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को छोड़कर प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

विनियम 28, 48 और 204 में संशोधनों को अंतर्विष्ट करने वाली अंतिम अधिसूचना को 23 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और वह उस तारीख से प्रवृत्त हो गई थी।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 10,295 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2015 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,39,974 हो गई है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष में 3,262 की संख्या की तुलना में 2,570 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए थे।

1.4.2015 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	63702	43498	107200
अंशकालिक व्यवसाय में	2906	5434	8340
जो व्यवसाय में नहीं हैं	12658	111776	124434
योग	79266	160708	239974

9.2 दीक्षांत समारोह

आईसीएआई, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। दीक्षांत समारोह का आयोजन पांचों प्रादेशिक मुख्यालयों में प्रत्येक में वर्ष में दो बार किया जाता है जिससे वित्तीय वर्ष की मार्च से अगस्त और सितम्बर से फरवरी तक की अवधि को उसमें सम्मिलित किया जा सके। इन समारोहों में उक्त अवधि के दौरान सदस्यता में लिए गए सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह के पहले चक्र 2015 का आयोजन मई-जुलाई, 2015 के मासों में निम्नलिखित स्थानों पर और समय-सूची के अनुसार प्रादेशिक कार्यालयों के तत्वाधान में किया गया था :

स्थान	तारीख	स्थान	तारीख
अहमदाबाद	22 मई, 2015	हैदराबाद	10 जुलाई, 2015
मुंबई	23 मई, 2015	कोलकाता	12 जुलाई, 2015
चेन्नई	19 जून, 2015	नई दिल्ली	16 जुलाई, 2015
पुणे	20 जून, 2015	कानपुर	19 जुलाई, 2015
जयपुर	22 जून, 2015		

इस दीक्षांत समारोह में, दिसंबर, 2014 से मार्च, 2015 के बीच नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। कुल 3385 अभ्यर्थियों ने इस दीक्षांत समारोह में भाग लिया था, जिनके अंतर्गत पूर्ववर्ती दीक्षांत समारोह में भाग न ले सकने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं।

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरणपोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2014 को कुल आजीवन सदस्य	119886
2.	31 मार्च, 2015 को कुल आजीवन सदस्य	123661
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान)	3794
4.	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 1,37,50,107 रुपए

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे*

		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)
--	--	---	---

1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,37,50,107	1,57,81,000
2.	प्रशासनिक खर्चें	22,966	24,991
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	55,65,697	(15,989)
4.	निधि का अतिशेष	21,64,314	(34,01,383)
5.	कोरपस का अतिशेष	16,00,92,797	14,44,41,795

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1000 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 117 छात्रवृत्तियां, आर्टिकलड प्रशिक्षण करने वाले छात्रों को दी जा रही हैं। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2014 को 5920 के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को बढ़कर 6932 हो गई थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2014 को 44,27,885/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को 43,12,077/- रुपए है।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 394 छात्रों (आर्टिकलड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र) को वित्तीय सहायता के रूप में एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रति मास मूल्य छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2014 को 7,63,38,248/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2015 को साधारण निधि में 9,70,88,753/- रुपए का अतिशेष जमा था।

10. छात्र

अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

1. शैक्षिक अंतःनिवेश

अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण : छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है। सीपीटी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री को नवंबर, 2014 में व्यापक रूप से पुनरीक्षित किया गया था। सभी विषयों के प्रैक्टिस मैनुअलों के साथ आईपीसीसी की अध्ययन सामग्री को जुलाई, 2014 में पुनरीक्षित किया गया था, जिसके पश्चात् अक्टूबर, 2014 में कराधान को पुनरीक्षित किया गया था। कराधान (अप्रत्यक्ष कर) और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पुनरीक्षित पाठ्यचर्या के आधार पर, बिजनेस लॉज इथिक्स एंड कम्प्युनिकेशन (बीएलईसी) और आडिटिंग एंड ऐश्वरस से संबंधित विषयों के लिए सामग्रियों को भी जुलाई, 2014 में पुनरीक्षित किया गया था जबकि बीएलईसी के प्रैक्टिस मैनुअलों को दिसंबर, 2014 में पुनरीक्षित किया गया था।

इसी प्रकार, सभी विषयों के प्रैक्टिस मैनुअलों के साथ फाइनल पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री का जनवरी, 2015 में पुनरीक्षण किया गया था। कारपोरेट और एलाइड लॉज तथा एंडवांस आडिटिंग और प्रोफेशनल इथिक्स विषयों से संबंधित पुनरीक्षित पाठ्यचर्या के आधार पर सामग्रियों को क्रमशः अक्टूबर, 2014 और जनवरी, 2015 के मासों के दौरान निकाला गया था।

इन्हें निःशुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था।

सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल के लिए अध्यायवार अध्ययन सामग्री अंतर्विष्ट करने वाली पाठ्यक्रमवार ई-लर्निंग डीवीडी को निकाला गया था, जिसमें छात्रों के अध्ययन को सुकर बनाने हेतु प्रैक्टिस मैनुअल, ई-व्याख्यानों, पोडकास्टों (एमपीथ्री आडियो), पावर पाइंट प्रस्तुतीकरणों (संक्षिप्त टिप्पणों) और स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरों को व्यापक रूप से पुनरीक्षित करते हुए, सम्मिलित किया गया था। इस डीवीडी को, संबंधित पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के समय अध्ययन सामग्री के सेट के साथ निःशुल्क जारी किया जाता है।

आईपीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रम की पुनरीक्षित अंग्रेजी अध्ययन सामग्री के आधार पर उनकी अध्ययन सामग्री को हिन्दी में अनुदित किया गया है।

उसे निःशुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था।

चयनित मामलों का संकलन : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मामलों के संकलन को अंतर्विष्ट करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित चयनित मामलों के डाइजैस्ट का, अक्टूबर, 2014 में प्रकाशन किया गया है और साथ ही उसे निःशुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया है।

कराधान विषयों में अनुपूरक अध्ययन सामग्री : फाइनल स्तर के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करें तथा आईआईपीसी स्तर के लिए कराधान के क्षेत्र में अनुपूरक अध्ययन सामग्री एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वर्ष के दौरान नवीनतम परिपत्रों और जारी अधिसूचनाओं के साथ वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन अंतर्विष्ट हैं। तदनुसार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा किए गए संशोधनों और क्रमशः 1 मई, 2013 और 30 अप्रैल, 2014 के बीच जारी महत्वपूर्ण बजट संबंधी अधिसूचनाओं/परिपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाली अनुपूरक अध्ययन सामग्री को, जो मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए कराधान से संबंधित अनुपूरक अध्ययन सामग्री है, छात्रों के फायदे के लिए निकाला गया था।

उसे निःशुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था।

पुनरीक्षण परीक्षा पत्र : आईपीसीसी/एटीसी और फाइनल परीक्षाओं के लिए पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) को समय से प्रकाशित किया गया था जिससे कि छात्रों को परीक्षाओं के लिए भलीभांति तैयारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। इन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

सुझाए गए उत्तर : छात्रों के लिए परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को सुकर बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी)/लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) और फाइनल पाठ्यक्रम परीक्षा की मई, 2014 और नवंबर, 2014 में कराई गई परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को पर्याप्त समय पूर्व मुद्रित किया गया था और उन्हें छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया था।

इन सुझाए गए उत्तरों को आईसीएआई की वेबसाइट पर, निःशुल्क डाउनलोड सुविधा के साथ परिणामों की घोषणा से काफी समय पूर्व रखा गया था।

हिन्दी माध्यम का विकल्प लेने वाले छात्रों के फायदे हेतु एक नई पहल के रूप में, संबद्ध परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों और पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों का हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया था।

इन्हें डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

सीए परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें : 'सामान्य प्रवीणता परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें' और 'सीए परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें - मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल' ऐसे वार्षिक प्रकाशन हैं, जो छात्रों को परीक्षाओं में बैठने और उन्हें सफलतापूर्वक अर्हित करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं और साथ ही इन्हें प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा आयोजित विशेष कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों के दौरान संवितरित किया जाता है।

इन्हें डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

छात्रों का जर्नल : अध्ययन बोर्ड, वर्ष 1997 से छात्रों के लिए 'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट' नामक एक मासिक जर्नल का प्रकाशन करता रहा है। छात्रों के इस जर्नल में सीए छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, थीम मुद्दों, प्रेरणात्मक लेखनों और अन्य महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं जैसे विषयों पर लेखों जैसे नियमित फीचर अंतर्विष्ट होते हैं। यह जर्नल छात्रों और साथ ही आईसीएआई के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

2. आईटी संबंधी पहले

आईसीएआई क्लाउड परिसर : बदलते समय के साथ परिवर्तित होते हुए, भौतिक ईट और पत्थरों से बना परिसर अब क्लाउड पर उपलब्ध है - आईसीएआई क्लाउड परिसर (<http://cloudcampus.icaai.org>) आईसीएआई क्लाउड परिसर क्लाउड की शक्ति का देश भर और विदेशों के छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए उपयोग करता है ताकि शिक्षा और प्रशिक्षण को उनके घर तक ले जाया जा सके और साथ उनकी शैक्षिक, प्रशासनिक, परीक्षा, नामांकन संबंधी और अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडो का प्रावधान किया जा सके। यह पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम रजिस्ट्रीकरण, शिक्षा, एक परीक्षा प्रारूप फाइल करने से परीक्षा परिणाम प्राप्त करने तक कि सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है।

क्लाउड परिसर, छात्रों द्वारा सुगम पहुंच के लिए 6 पोर्टलों तक पहुंच को एकीकृत करके एकल विंडो उपलब्ध कराता है, अर्थात् (क) ई पठन एलएमएस, (ख) बीओएस ज्ञान पोर्टल, (ग) वेबकास्ट, (घ) जीएमसीएस/ओपी/आईटीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, (ङ) परीक्षा पोर्टल और (च) आर्टिकलशिप नियोजन पोर्टल।

विषयों से संबंधित व्यावहारिक समयस्याओं के समाधान पर वीडियो व्याख्यान : लेखा, कराधान, वित्तीय प्रबंध, अग्रिम प्रबंध लेखांकन आदि जैसे विषयों से संबंधित व्यावहारिक समयस्याओं के समाधान पर वीडियो व्याख्यान अब क्लाउड परिसर पर उपलब्ध हैं जो बेहतर अवधारणात्मक स्पष्टता और समस्या समाधान कौशलों को उपलब्ध कराते हैं। इन व्याख्यानों का उद्देश्य, कदम दर कदम व्यावहारिक समस्या समाधान प्रक्रिया को पढ़ाना है, जो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से वर्तमान में एक प्रमुख दक्षता संबंधी अपेक्षा है। इस समय, 7 जुलाई, 2015 तक, 375 घंटों के 476 वीडियो व्याख्यान उपलब्ध हैं जिन्हें वेबसाइट पर रख दिया गया है।

ऑनलाइन परामर्श : क्लाउड परिसर पर उपलब्ध ऑनलाइन परामर्श सुविधा का उद्देश्य देश भर और विदेशों के छात्रों को, सीए पाठ्यक्रम के तीन स्तरों के लिए विषय और शीर्षकवार आनलाइन परामर्श सुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनाना है, जिसके अंतर्गत परामर्शी सेवाएं भी

हैं। छात्र सत्र/आयोजन के शीर्षक संबंधी प्रश्न पूछने में भी समर्थ होंगे, जिनका उत्तर समय की उपलब्धता और संगतता के आधार पर दिया जाएगा। आईसीएआई ने 7 जुलाई, 2015 तक ऐसे 61 सत्रों का आयोजन किया है।

आर्टिकल प्रशिक्षण संसाधन : संपरीक्षा संबंधी कार्यक्रमों, संपरीक्षा जांच सूचियों, दिशानिर्देशों आदि का उद्देश्य छात्रों को उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण में सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

छात्रों को एकल विंडो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उनके द्वारा सुगम पहुंच के लिए क्लाउड परिसर में छात्रों से संबंधित निम्नलिखित पोर्टलों को एकीकृत किया गया है :

छात्र – एलएमएस संबंधी ई पठन : आईसीएआई क्लाउड कैम्पस छात्र प्रबंध पठन प्रणाली (एलएमएस) से संबंधित सीए पाठ्यक्रम के लिए ई पठन सुविधा संबंधी एक लिंक <http://studentslms.icaai.org> पर उपलब्ध कराता है, जो छात्रों को स्वः पठन/विकास सुविधा उपलब्ध कराता है। छात्र एलएमएस का लक्ष्य पठन, पुनः पठन और पुनरीक्षण के लिए किसी भी समय देश और विदेश में किसी भी जगह, सुगमता से पहुंच वाली और सस्ती रीति में क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह एक ऐसी पठन प्रणाली है, जिसे व्यावहारिक/आर्टिकल प्रशिक्षण के साथ पूरा किया जाता है।

स्वःपठन/ई-शिक्षा के अतिरिक्त, ई-पठन सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक व्याख्यान के पश्चात् स्वःनिर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी है, जो छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए उनकी अध्यायवार और विषयवार तैयारी का निर्धारण करने में समर्थ बनाएगी। स्वःनिर्धारण के उपकरण के अलावा, स्वःनिर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता को “पुनर्विलोकन सुविधा” के माध्यम से एक पठन और विकास सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जिसके द्वारा छात्र उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना में सही उत्तरों का अध्ययन कर सकते हैं।

छात्र एलएमएस, उपलब्ध व्याख्यानों, प्रयास किए गए/पूरे किए गए स्वःनिर्धारण प्रश्नोत्तरों के निबंधनानुसार छात्र के पठन और विकास का लेखा-जोखा भी रखता है। यह ई-पठन अब मोबाइल समर्थ है – छात्र अब ई-व्याख्यानों को स्मार्ट फोनों/मोबाइलों/टैबलेटों पर देख सकते हैं। इस समय 784 घंटों का ई-पठन उपलब्ध है, जिसमें 7 जुलाई, 2015 तक सीपीटी, आईआईपीसी और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 185, 259 और 311 घंटों के व्याख्यान उपलब्ध हैं।

बीओएस ज्ञान पोर्टल : बीओएस ज्ञान पोर्टल, सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठ्यक्रमों के संबद्ध अध्यायों और विषयों के लिए अध्यायवार अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस मैनुअल, पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण, आडियो व्याख्यान (पोडकास्ट/एमपी 3) उपलब्ध कराता है। यह अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य संसाधन/प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है।

आर्टिकल नियोजन पोर्टल : आर्टिकल नियोजन पोर्टल, छात्रों को ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करने और उनके चुने गए नगर/शहर में रिक्तियां रखने वाली सीए फर्मों में आर्टिकलशिप प्रशिक्षण हेतु चुने जाने के लिए समर्थ बनाता है।

सीपीटी/मध्यवर्ती, आईपीसी और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए ई-पठन डीवीडी : अध्ययन बोर्ड ने सीपीटी/मध्यवर्ती, आईपीसी पाठ्यक्रम (समूह 1 और समूह 2) और फाइनल पाठ्यक्रमों (समूह 1 और समूह 2) के लिए ई-पठन डीवीडी जारी की है, जिनमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस मैनुअल, ई पठन, पोडकास्ट (एमपी 3 आडियो), पावर पाइंट प्रस्तुतियां (सक्षिप्त टिप्पण और स्वःनिर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं अंतर्विष्ट हैं)।

यद्यपि, इन डीवीडी को मल्टी मीडिया डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप पर कार्य करने हेतु तैयार किया गया है, इन्हें एक प्रतिक्रियाशील साइट के रूप में विकसित किया गया है और इसलिए ये आधुनिक मोबाइल फोनों और टैबलेटों (एंड्रायड 4+ आईओएस) पर भी कार्य कर सकती हैं, जब उन्हें मेमोरी/एसडी कार्ड में कापी किया जाए और मोजिला फायरफोक्स इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते हुए देखा जाए। इस प्रकार छात्र अब इंटरनेट की आवश्यकता, अंतर्वस्तु के डाउनलोड होने की प्रतीक्षा और उससे संबंधित लागत के बिना किसी भी समय/कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं।

वेबकास्टों का वीडो : आईसीएआई क्लाउड परिसर पर वेबकास्ट लिंक छात्रों को उनके संबंधित सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीसी), मध्यवर्ती (आईपीसी) पाठ्यक्रम और फाइनल पाठ्यक्रम और साथ ही लेखांकन मानकों को अर्हित करने तथा उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नीति तैयार करने के संबंध में और चुने गए विषयों के विनिर्दिष्ट टॉपिक पर, जहां पाठ्यचर्या में परिवर्तन हुआ है या छात्रों के समक्ष कठिनाईयां आ रही हैं, छात्रों को परामर्श देते हुए मांग किए जाने पर वीडियो उपलब्ध कराया जाता है।

जीएमसीएस/ओपी/आईटीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल : जीएमसीएस/ओपी/आईटीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, जो कि आईसीएआई क्लाउड परिसर पर उपलब्ध है, छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन रूप से रजिस्ट्रीकृत होने, अधिमानी अवस्थानों/शाखाओं पर अपनी सुविधा अनुसार बैचों का चयन करने, बैच का स्थानांतरण करने, संकाय आबंटन, पाठ्यक्रम का सूचीकरण, उनके संबंध में फीड बैक, प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति और उनका जनन आदि के लिए समर्थ बनाता है। इस ऑनलाइन पोर्टल में 4 माड्यूल अंतर्विष्ट हैं, अर्थात् “छात्र माड्यूल”, “संकाय माड्यूल”, “पीओयू माड्यूल” और “एचओ प्रशासन माड्यूल”।

3. अन्य पहलें

पठन कक्ष : अध्ययन बोर्ड सतत रूप से प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ आईसीएआई के छात्रों के फायदे के लिए अतिरिक्त पठन कक्षों को खोले जाने की संभावना का पता लगाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है। अभी तक 89 पुस्तकालय-सह-पठन कक्षों तथा 35 अतिरिक्त पठन कक्षों को प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है।

अध्ययन बोर्ड, इंदौर (मध्य प्रदेश), जलगांव (महाराष्ट्र), टुमकूर (कर्नाटक) में, प्रत्येक में एक-एक अतिरिक्त पठन कक्ष खोलने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

4. विकास कार्यक्रम

वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम : अध्ययन बोर्ड द्वारा ऐसे छात्रों के फायदे के लिए जिन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंसी की फाइनल/आईपीसीसी/पीसीसी/पीई2/ मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है और आर्टिकल प्रशिक्षण का अंतिम वर्ष पूरा कर रहे हैं या आर्टिकल प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है, एक वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम का आयोजन करता है। यह कार्यक्रम चार्टर्ड एकाउंटेंसी के छात्रों और नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों की, कारबार संगठनों और वृत्ति में प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित वृत्तिक कौशलों से लैस होने में सहायता करता है। इस कार्यक्रम के कारक, संपर्क कौशलों, व्यक्तिगत गुणों, अंतःव्यक्ति और दल के रूप में कार्य करने संबंधी कौशलों, समस्याओं का समाधान करने संबंधी कौशलों और नेतृत्व कौशलों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान, उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में इस कार्यक्रम के बारह बैचों का और एक बैच का राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम : जीएमसीएस को और अधिक प्रभावी बनाने के विचार से, परिषद् ने अपनी 331वीं बैठक में यह विनिश्चय किया था कि 1 अप्रैल, 2014 से विद्यमान जीएमसीएस को समाप्त कर दिया जाए और यह निदेश दिया था कि 30 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों से यह अपेक्षित होगा कि वे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 51क/72क के अनुसार आईसीएआई की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व विद्यमान जीएमसीएस पाठ्यक्रम की बजाए जीएमसीएस 2 पाठ्यक्रम पूरा करें।

आज की तारीख तक, साधारण प्रबंधन और संसूचना कौशल-1 का संचालन 145 कार्यक्रम आयोजक ईकाईयां (पीओयू) द्वारा देश भर में किया जा रहा है तथा साधारण प्रबंधन और संसूचना कौशल-2 का संचालन 85 कार्यक्रम आयोजक ईकाईयां (पीओयू) द्वारा देश भर में किया जा रहा है।

इस अवधि (अप्रैल, 2014 से जून, 2015) के दौरान, 140 पीओयू द्वारा देशभर में 15 दिवसीय साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम-1 के 1,275 बैचों का संचालन किया था, इन कार्यक्रमों में 58,313 छात्रों ने भाग लिया था।

इसके अतिरिक्त, (अप्रैल, 2014 से जून, 2015) के दौरान, 85 पीओयू द्वारा देशभर में 15 दिवसीय साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम-2 के 512 बैचों का संचालन किया था, इन कार्यक्रमों में 23,611 छात्रों ने भाग लिया था।

छात्रों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम : सीपीटी मार्ग के ऐसे छात्रों से, जो लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम के लिए अनन्य रूप से स्वयं रजिस्ट्रीकृत कर रहे हैं, यह अपेक्षित होगा कि वे एटीई में बैठने से पूर्व अनुकूलन कार्यक्रम पूरा करें। सीपीटी मार्ग से मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के लिए आने वाले छात्रों से यह अपेक्षित होगा कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व (समूह 1 की परीक्षा हेतु बैठने या उसे उत्तीर्ण करने या दोनों से पूर्व) अनुकूलन कार्यक्रम को पूरा करें। सीधे प्रवेश मार्ग से आने वाले अभ्यर्थियों से भी यह अपेक्षित होगा कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने से पूर्व अनुकूलन कार्यक्रम पूरा करें।

वर्तमान में, 148 कार्यक्रम आयोजक ईकाईयां (पीओयू) देश भर में अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं।

इस अवधि के दौरान (अप्रैल, 2014 से जून, 2015), 141 पीओयू द्वारा देश भर में अनुकूलन कार्यक्रमों के 1732 बैचों का आयोजन किया गया था, जिनमें 74,995 छात्रों ने भाग लिया था।

जीएमसीएस पाठ्यक्रम और अनुकूलन कार्यक्रम के संकाय के लिए दो दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम : अध्ययन बोर्ड ने 20 और 21 जून, 2014 के दौरान गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जैन हिल्स, जलगांव में ; 19-20 जनवरी, 2015 के दौरान रस रिजार्ट्स एंड अपार्ट होटल्स, सिलवासा में ; 22-23 जनवरी, 2015 के दौरान फोर्ट चन्द्रगुप्त हैरिटेज होटल, जयपुर में ; 28-29 जनवरी, 2015 को उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में ; 2-3 मई, 2015 के दौरान आईटीसी ग्रांड चोला, चेन्नई और 5-6 जुलाई, 2015 के दौरान रस रिजार्ट्स एंड अपार्ट होटल्स, सिलवासा में जीएमसीएस पाठ्यक्रम और अनुकूलन कार्यक्रम के संकाय के लिए 'दो दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम' का आयोजन किया था। इस एफडीपी का उद्देश्य अनुकूलन कार्यक्रमों और जीएमसीएस पाठ्यक्रमों के संकाय के व्याख्यान सत्रों के एकसमान और प्रभावी प्रदाय को सुनिश्चित करना और साथ ही उनका मानकीकरण करना भी था।

आईटीटी केंद्र : आईसीएआई ने 159 आईटीटी केंद्रों को स्थापित किया है, जो लगभग सभी शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिकतम कंप्यूटरों, साफ्टवेयर और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं से लैस हैं।

छात्रों के लिए आईटीटी पाठ्यक्रम : आईटीटी पाठ्यक्रम लेखांकन/संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों, जिनके अंतर्गत कार्यालय स्वचालन, लेखांकन, वेब प्रौद्योगिकी और ई-फाइलिंग भी है, से सुसंगत एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करता है। लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम के लिए अनन्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होने वाले छात्रों से, सीपीटी अर्हित करने के पश्चात् यह अपेक्षा की जाती है कि वे एटीई परीक्षा में बैठने से पूर्व आईटीटी पाठ्यक्रम को पूरा करें। मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठ्यक्रम के छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण (समूह 1 में या तो बैठने या उसे उत्तीर्ण करने या दोनों से पूर्व) के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने से पूर्व आईटीटी पाठ्यक्रम को पूरा करें। सीधे प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से भी यह अपेक्षित है कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व आईटीटी पाठ्यक्रम पूरा करें।

आईसीएआई ने प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों में आईटीटी तथा अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपेक्षित कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ 159 आईटीटी केंद्र स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान पांच (5) नए आईटीटी केंद्रों को स्थापित किया है।

वर्तमान में, आईटीटी पाठ्यक्रम 159 आईटीटी केंद्रों पर उपलब्ध है और 7 जुलाई, 2015 तक 68,000 से अधिक छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को 1,623 से अधिक बैचों के माध्यम से पूरा किया है।

छात्रों के लिए अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम : अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम को अक्टूबर, 2014 में आरंभ किया गया था, जिसे फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा पूरा किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वृत्ति के लिए सुसंगत कंप्यूटर एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत एमएस एक्सेस के माध्यम से डाटा बेस एप्लीकेशन, आधुनिक फीचर एमएस – एक्सेल, सीएएटी, मूलभूत बैंककारी समाधान (सीबीएस), उच्च संसाधन योजना (ईआरपी) और कार्यालय स्वचालन एप्लीकेशन और सीए कार्यालयों में आईटी सुरक्षा भी है।

वर्तमान में, अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम 111 आईटीटी केंद्रों पर उपलब्ध है और 7 जुलाई, 2015 तक 15,000 से अधिक छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को 83 से अधिक बैचों के माध्यम से पूरा किया है।

अध्ययन बोर्ड ने लैब प्रैक्टिस मैनुअल, पावर पाइंट प्रेजेंटेशनों और वीडियो व्याख्यानो के साथ अक्टूबर, 2014 में अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री को तैयार करके जारी किया था।

आईटीटी केंद्रों पर संकाय सदस्यों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम : बोर्ड ने अगस्त-सितंबर, 2014 के दौरान दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में आईटीटी केंद्रों के संकाय सदस्यों के लिए क्षेत्रवार तीन संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) का आयोजन किया था, जिसमें 82 आईटीटी केंद्रों से 126 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था।

पूरे भारत में प्रतिभागी संकाय को भौतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, बोर्ड ने आईटीटी केंद्रों पर संकाय सदस्यों को अनुकूलन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ईआरपी तथा सीबीएस पर दो लाइव वेबकास्टों का भी आयोजन किया था। इन वेबकास्टों की रिकार्डिंग, छात्रों को उनकी अध्ययन सामग्री के भागरूप में उपलब्ध कराई गई थी।

बोर्ड, पाठ्यक्रम के भागरूप में कक्षाएं लेने तथा व्यावहारिक कवरेज में अभिवृद्धि करने हेतु अपेक्षित अनुकूलन और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आईटीटी केंद्रों के संकाय सदस्यों के लिए आनलाइन एफडीपी का भी आयोजन कर रहा है। इस पहल के भागरूप में, (क) गुगल एचओए का उपयोग करते हुए पर्यावलोकन और क्यूए सत्रों का आयोजन और (ख) व्यावहारिक मामला अध्ययनों के संबंध में वीडियो व्याख्यानों को उपलब्ध कराया गया है। आज की तारीख तक छह (6) पर्यावलोकन और क्यू सत्रों तथा छह (6) वीडियो व्याख्यानों का आयोजन किया गया है।

अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार परस्पर संपर्क संबंधी अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशाला : 5 शाखाओं ने अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार संबंधी परस्पर संपर्क से संबंधित 8 अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

मौक परीक्षा : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से मई/नवम्बर और जून/दिसम्बर की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को, परीक्षाओं हेतु उनकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल और सीपीटी स्तर की मौक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 100 शाखाओं ने मई, 2014 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/पीसीसी और फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 124 शाखाओं ने जून, 2014 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 97 शाखाओं ने नवम्बर, 2014 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/पीसीसी और फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 110 शाखाओं ने दिसम्बर, 2014 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 107 शाखाओं ने मई, 2015 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 126 शाखाओं ने जून, 2015 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था।

विशेष परामर्शी कार्यक्रम (सीए परीक्षाओं की चुनौती का सामना कैसे करें ?) : वर्ष के दौरान 45 शाखाओं ने जिनके अंतर्गत प्रादेशिक परिषदें भी थी, 87 विशेष परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

5. एमबी/यू/एमआरए/मान्यता/अन्य ठहराव

सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता : विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों और आईआईटी, मद्रास के अलावा 99 विश्वविद्यालयों (कुल 106) से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

प्रत्यायन : आईसीएआई विभिन्न दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को, इसके प्रारंभ से ही देश भर में एक संगत रीति में शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों को, उनकी परीक्षाओं हेतु पर्याप्त रूप से तैयार होने में समर्थ बनाने के लिए शैक्षिक अंतःनिवेशों के व्यापक पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। यद्यपि पूर्वोक्त प्रयास केंद्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, प्रत्यायित केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली मौखिक कोचिंग आईसीएआई के प्रयासों को अनुपूरित करती है क्योंकि इसके द्वारा युक्तियुक्त लागत पर क्वालिटी कक्षा कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड ने, क्वालिटी कोचिंग कक्षाएं उपलब्ध कराने के विचार से संस्थान की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को मौखिक कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करने के लिए प्राधिकृत और प्रोत्साहित किया है। साथ ही अध्ययन बोर्ड विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, विद्यालयों, न्यासों/एनजीओ/सोसाइटियों और अन्य शैक्षिक संस्थानों को भी प्रत्यायन मंजूर करता है।

संस्थाओं को सीए छात्रों हेतु कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रत्यायन मंजूर करने संबंधी प्रत्यायन स्कीम को हाल ही में यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है कि छात्रों के फायदे के लिए बेहतर अवसंरचना और अध्यापन सुविधाओं वाली संस्थाओं को ही प्रत्यायन मंजूर किया जाए। अभी तक, अध्ययन बोर्ड ने सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए 50 संस्थाओं को प्रत्यायित किया है।

6. सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और अन्य क्रियाकलाप

सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सभा, अखिल भारतीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : इस अवधि के दौरान, हैदराबाद में एक अखिल भारतीय सम्मेलन और बंगलौर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा जयपुर, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, गुंटूर, सूरत, हिसार, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, लखनऊ, अहमदाबाद, गुडगांव, एनकुलम, फरीदाबाद, हुबली, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, बिलासपुर, रांची, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, लुधियाना, मेरठ, करनाल, पुणे, चेन्नई, तिरुपति, ठाणे और कटक में 36 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन किया गया था।

सीए छात्रों के लिए प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन/राष्ट्रीय सभा : इस अवधि के दौरान, 14 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन गोवा, कटक, विशाखापट्टनम, राउरकेला, पटना, भोपाल, जलगांव, राजकोट, आगरा, त्रिसूर, उडुपी, जमशेदपुर और श्रीगंगानगर में किया गया था। इसके अतिरिक्त, बसई और सलेम में दो प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों और तिरुवनंतपुरम् तथा अमरावती में दो उप प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था।

एकदिवसीय संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 75 शाखाओं द्वारा 296 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

दो दिवसीय बृहत संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, 9 शाखाओं द्वारा दो दिवसीय बृहत संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

वाद-विवाद प्रतियोगिता : प्रादेशिक परिषदों सहित 75 शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर और डब्ल्यूआईआरसी, एसआईआरसी, ईआईआरसी और सीआईआरसी द्वारा प्रादेशिक स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

सीए छात्र समारोह : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 51 शाखाओं द्वारा 55 सीए छात्र समारोह का आयोजन किया गया था।

खेल प्रतियोगिताएं : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 55 शाखाओं द्वारा 69 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

वक्तृता प्रतियोगिता : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 98 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन 28 जनवरी, 2015 को उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में किया गया था।

क्विज प्रतियोगिताएं : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 98 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 28 जनवरी, 2015 को उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में किया गया था।

विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां : अध्ययन बोर्ड ने भारत में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के साथ अपनी सतत परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप लेखांकन और वाणिज्य के समकालीन विषयों पर संयुक्त कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया था।

अध्ययन बोर्ड ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन किया था :

9 और 10 अक्टूबर 2014 को माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा, जम्मू के साथ "भारत में लेखांकन और वाणिज्य शिक्षा : समकालीन मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर एक दो दिवसीय संगोष्ठी ; 14 नवम्बर, 2014 मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर के साथ "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)" पर एक दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन ; 1 व 2 दिसंबर, 2015 के दौरान उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के साथ "न्यायलयीय लेखांकन और कपट परीक्षा" पर एक दो दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 30-31 जनवरी, 2015 के दौरान तेजपुर विश्वविद्यालय, असम के साथ 'कंपनी अधिनियम, 2013 और निगम शासन' पर एक दो दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 6 फरवरी, 2015 को टुमकूर विश्वविद्यालय, टुमकूर के साथ "नई नीति के कार्यान्वयन और प्रत्यक्ष कर और विदेश व्यापार में मुद्दे" पर एक दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 23 अप्रैल, 2015 को बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलुरु के साथ "आईएफआरएस के अधीन भारत में निगम रिपोर्टिंग के बदलते आयाम" विषय पर एक दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी।

7. सीए पाठ्यक्रम के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए उपाय

कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम : पाठ-विवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु और सीए पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2015 की अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों सहित 35 शाखाओं द्वारा देश भर में विभिन्न अवस्थानों पर 177 कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

वृहत कैरियर परामर्शी कार्यक्रम : वर्ष के दौरान शाखाओं द्वारा देश भर में 10 वृहत कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

8 छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

अध्ययन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रवर्गों में छात्रवृत्तियां प्रदान की थी :--

मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां : मई और नवंबर में आयोजित मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं में और जून तथा दिसंबर में आयोजित सामान्य प्रवीणता परीक्षा में प्रत्येक वर्ष, मेधावी छात्रों की उनकी उपलब्धि और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को करने में उनके द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों की सराहना करने के लिए योग्यता सूची में क्रम सं. 1 से 10 तक (उस दशा में जहां क्रम सं. 10, क्रम सं. 11 या क्रम सं. 12 तक या आगे के क्रम संख्याओं तक चलता है, ऐसे सभी रैंक धारकों को) रैंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां : आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों की सराहना और उनके द्वारा अध्ययनों को जारी रखने के लिए उनका संवर्धन करने के विचार से मई और नवंबर में आयोजित मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं में और जून तथा दिसंबर में आयोजित सामान्य प्रवीणता परीक्षा में प्रत्येक वर्ष उच्च रैंक धारकों को 60 योग्यता-सह आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को छात्रवृत्तियां : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों का सहयोग और समर्थन करने के लिए, अक्टूबर, 2014 से मध्यवर्ती (आईपीसी) छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 प्रतिवर्ष तथा फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए इनकी संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। साथ ही आईसीएआई के मृतक सदस्यों के ऐसे बालकों को, जो सीए पाठ्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे सदस्यों के पति/पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ) के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, भी उनके आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को छात्रवृत्तियां प्रवर्ग के अधीन छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

वृत्ति दान स्कीमों के अधीन छात्रवृत्तियां : वृत्ति के निर्माण के समान कारण के प्रति योगदान करने के लिए व्यष्टिक दानियों और दानियों द्वारा संयुक्त कार्पस के द्वारा वृत्ति दान निधियों का सृजन किया गया है। इन निधियों में अर्जित व्याज में से, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए लागू मापदंडों के आधार पर इन वर्गों के छात्रों के फायदे के लिए ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

वर्ष के दौरान, अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त वर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 1225 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 150 है।

इस समय, संस्थान के भारत से बाहर 26 चैप्टर विद्यमान हैं।

वर्तमान में, देश भर में 20 संदर्भ पुस्तकालय हैं।

11.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहयोग की भावना को विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के विचार से, संस्थान की परिषद् सदैव छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अभी तक छात्र संघों की 119 शाखाएं स्थापित की गई हैं।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रुचि दिखाती रही हैं। कुल मिलाकर 86 शाखाओं के अपने भवन हैं।

11.3 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा :

ये पुरस्कार संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2014 के लिए ये शील्डें 11 फरवरी, 2015 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

1. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्	
<ul style="list-style-type: none"> - पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् और पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् को संयुक्त रूप से सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद् ट्राफी और प्रमाणपत्र - दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् : अति सराहनीय प्रादेशिक परिषद् ट्राफी और प्रमाणपत्र - उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् और मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
2. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ	
<ul style="list-style-type: none"> - डब्ल्यूआईसीएएसए : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ ट्राफी और प्रमाणपत्र - ईआईसीएएसए तथा एसआईसीएएसए को संयुक्त रूप से : अति सराहनीय छात्र संघ ट्राफी और प्रमाणपत्र 	
3. प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा	
<ul style="list-style-type: none"> • बृहत शाखा प्रवर्ग (2501 और अधिक सदस्य) - अहमदाबाद और बंगलौर को संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - हैदराबाद और जयपुर को संयुक्त रूप से : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - गुडगांव : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
<ul style="list-style-type: none"> • बड़ी शाखा प्रवर्ग (1001 से 2500 सदस्य) - इंदौर : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - एर्नाकुलम : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - नागपुर : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	

<ul style="list-style-type: none"> ● मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग (501 से 1000 सदस्य) - सिलिगुडी : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - औरंगाबाद : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - भोपाल, पिंपरी चिंचवाड और रायपुर को संयुक्त रूप से : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
<ul style="list-style-type: none"> ● लघु आकार शाखा प्रवर्ग (201 से 500 सदस्य) - हुबली और सलेम संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - अहमदनगर : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - बीकानेर और भिलाई को संयुक्त रूप से : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
<ul style="list-style-type: none"> ● अति लघु आकार शाखा प्रवर्ग (201 सदस्यों तक) - रतलाम और उडुपी संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - तुतीकोरन : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - क्वीलोन और नादेड को संयुक्त रूप से : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :	
<ul style="list-style-type: none"> ● बड़ी शाखा प्रवर्ग (1000 से अधिक छात्र) - औरंगाबाद और नागपुर संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - बंगलौर और नासिक संयुक्त रूप से : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - इंदौर : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
<ul style="list-style-type: none"> ● मध्यम शाखा वर्ग (301 से 1000 छात्र) - रायपुर और सलेम संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - भिलाई और भोपाल संयुक्त रूप से : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - हुबली : अनुशंसा प्रमाणपत्र और ट्राफी 	
<ul style="list-style-type: none"> ● लघु शाखा प्रवर्ग (300 छात्रों तक) - सिलिगुडी : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र - तुतीकोरन : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र 	

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न हैं।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2014-2015 के दौरान परिषद् की सहायता की और वह प्रादेशिक समितियों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2014-2015 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, सीए सुरेश पी. प्रभु, संघ के माननीय रेल मंत्री, सीए पीयूष गोयल, संघ के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, कोयला, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीए के. रहमान खान, संसद् सदस्य, राज्य सभा, संघ के पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य सभा, श्री शिवराज चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, सुश्री किरण माहेश्वरी, माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री बाबू लाल वर्मा, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, डॉ नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री पी.के. दास, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, श्री प्रसेनजीत मुखर्जी, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और अध्यक्ष, संपरीक्षा बोर्ड, डॉ बी एस भंडारी, सदस्य, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, डॉ सुभाष चंद्र, अध्यक्ष, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्री राणा कपूर, अध्यक्ष एसोचैम और संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, श्री पवन कांत मुंजाल, उपाध्यक्ष, सीईओ और एमडी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, सीए टी.एस. विश्वनाथ, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए मुकुंद एम चिताले, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है। परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

समिति, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में

सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2005 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त अध्येता योग	26351 15834 42185	15724 12969 28693	6785 6146 12931	7552 8207 15759	11640 12338 23978	68052 55494 123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त अध्येता योग	28528 16385 44913	16700 13358 30058	7172 6313 13485	8480 8539 17019	12898 12573 25471	73778 57168 130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त अध्येता योग	31159 16896 48055	18237 13646 31883	7829 6488 14317	9642 8882 18524	14182 12880 27062	81049 58792 139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त अध्येता योग	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त अध्येता योग	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त अध्येता योग	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त अध्येता	38608	22998	9154	12329	18547	101636

	योग	19831	15612	7406	11182	14943	68974
		58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त अध्येता योग	45273	25505	11069	15963	23332	121142
		20510	16132	7578	11720	15431	71371
		65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त अध्येता योग	52846	28020	13258	20606	27743	142473
		21522	16918	7815	12327	16051	74633
		74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त अध्येता योग	56595	29401	14035	22978	29467	152476
		22313	17460	8007	12915	16508	77203
		78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त अध्येता योग	60229	30126	14514	24702	31137	160708
		22838	17864	8137	13441	16986	79266
		83067	47990	22651	38143	48123	239974

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी	एटीसी	योग
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712		85,053	2,099	2,96,379
2012-13	47,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642

परिषद् (2015-16)

	परिषद् के सदस्य (2015-16)	
अध्यक्ष	निर्वाचित सदस्य	
सी.ए. मनोज फेडनीस	सी.ए. अदुक्रिया राजकुमार एस.	मुम्बई
	सी.ए. अग्रवाल संजय	नई दिल्ली
	सी.ए. अग्रवाल श्याम लाल	जयपुर
उपाध्यक्ष	सी.ए. अग्रवाल सुबोध कुमार	कोलकाता
सी.ए. एम. देवराजा रेड्डी	सी.ए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्चि
	सी.ए. बंधोपाध्याय अभिजीत	कोलकाता
	सी.ए. चौधरी संजीव कुमार	नई दिल्ली
	सी.ए. छेयरा जय	सूरत
	सी.ए. छाजेद प्रफुल प्रेमसुख	मुंबई
अवधि	सी.ए. देवराजा रेड्डी एम.	हैदराबाद
12 फरवरी, 2015 से	सी.ए. फेडनीस मनोज	इन्दौर
	सी.ए. गर्ग विजय	जयपुर
	सी.ए. धिया तरुण जमनादास	मुम्बई
	सी.ए. गोयल अनुज	गाजियाबाद
परिषद् के सचिव	सी.ए. गुहा सुमंत्रा	कोलकाता
श्री वी. सागर	सी.ए. गुप्ता अतुल कुमार	दिल्ली
	सी.ए. गुप्ता नवीन एन.डी.	नई दिल्ली
	सी.ए. गुप्ता विजय कुमार	फरीदाबाद
	सी.ए. जैन पंकज इन्द्रचंद	मुम्बई
	सी.ए. जम्बुसरिया निहार निरंजन	मुम्बई
	सी.ए. जोशी श्रीनिवास यशवंत	मुम्बई
	सी.ए. कुशवाहा मुकेश सिंह	गाजियाबाद
	सी.ए. महेश्वरी संजीव कृष्णगोपाल	मुम्बई

	सीए मुरली वी.	चैन्नई
	सीए नन्दा चरणजोत सिंह	नई दिल्ली
	सीए रघु के.	बंगलौर
	सीए संथानाकृष्णन एस.	चैन्नई
	सीए शेखर जी.	चैन्नई
	सीए शाह धीनल अश्विनभाई	अहमदाबाद
	सीए वेंकटेशवरलू जे.	हैदराबाद
	सीए विकमसे निलेश शिवजी	मुम्बई
	सीए जावरे शिवाजी भीकाजी	पुणे
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	डा. भास्कर चटर्जी	नई दिल्ली
	श्री जे.एस. दीपक	नई दिल्ली
	श्री मनोज कुमार	नई दिल्ली
	श्री पी.के. मिश्रा	नई दिल्ली
	श्री पी. शेष कुमार (9.9.2015 तक)	नई दिल्ली
	श्री आर.के. जैन	नई दिल्ली
	श्री सलील सिंघल	गुडगांव
	श्री सिद्धार्थ कुमार बिड़ला	नई दिल्ली
	श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली

एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
www.asa.in	www.bmchatrath.com

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंध मंडल का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार, जिनके अंतर्गत संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक भी हैं, संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंध मंडल का है। इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत ऐसे वित्तीय विवरणों, जो संस्थान की वित्तीय स्थिति के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं और सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं, को तैयार करने तथा उनको उचित रूप से प्रस्तुत करने से सुसंगत संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए और कपटों तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखना ; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना ; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना, जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हों, ऐसे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना और उन्हें बनाए रखना भी है, जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों का निर्धारण करना भी है। ऐसे जोखिम निर्धारणों में, संपरीक्षक संपरीक्षा संबंधी ऐसी प्रक्रियाओं को, जो दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त हों, तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतीकरण हेतु संस्थान के सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों को भी विचार में लेते हैं, किंतु ऐसा इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता कि इस संबंध में राय व्यक्त की जाए कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी हैं। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त किए गए हैं जो हमारी संपरीक्षा संबंधी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
www.asa.in	www.bmchatrath.com

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये लेखा, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को संस्थान के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके अधिशेष और नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

अन्य विषय

हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, केंद्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं (जैसे एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 38,226 लाख रुपए की आस्तियां, 20,773 लाख रुपए का कुल राजस्व और 2450 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्गामी) उपदर्शित करते हैं और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में विचारार्थ लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधक मंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई थी। समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

	(क)	नियत आस्तियां				
	i)	मूर्त आस्तियां	8	48,885	46,246	
	ii)	अमूर्त आस्तियां	9	30	4	
	iii)	चालू पूंजी संकर्म		11,387	9,523	
				60,302	55,773	
	(ख)	गैर चालू निवेश	10	13,737	-	
	(ग)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	3,724	2,968	
	(घ)	अन्य गैर चालू आस्तियां	12	747	110	
				78,510	58,851	
(2)	चालू आस्तियां					
	(क)	चालू निवेश	10	72,657	77,572	
	(ख)	वस्तु-सूची	13	1,700	1,024	
	(ग)	नकद और नकद समतुल्य	14	6,027	6,886	
	(घ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	3,841	3,611	
	(ङ)	अन्य चालू आस्तियां	15	2,334	2,919	
				86,559	92,012	
		योग		1,65,069	1,50,863	

कृपया वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले संलग्न टिप्पणों को देखें।

ह./- एच.के. जैन संयुक्त सचिव	ह./- बी. सागर सचिव	ह./- सी.ए. एम. देवराजा रेड्डी उपाध्यक्ष	ह./- सी.ए. मनोज फडनीस अध्यक्ष
------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ सी.ए. प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ सी.ए. उमेश सी. पांडे भागीदार सदस्यता सं. 055252

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 1 सितंबर, 2015

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

					(लाख रुपए में)
		टिप्पण		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
I	आय :				

	(क) प्राप्त फीस	16		47,802	49,558
	(ख) संगोष्ठियों में भाग लेने की फीस			6,807	6,311
	(ग) अन्य आय	17		11,321	7,295
	कुल आय			65,930	63,164
II	व्यय :				
	(क) संगोष्ठियां			6,797	5,939
	(ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	18		12,568	7,693
	(ग) मुद्रण और लेखन सामग्री			7,103	6,921
	(घ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	8,9		2,348	2,026
	(ङ) अन्य व्यय	19		26,449	22,988
	कुल व्यय			55,265	45,567
III	पूर्वावधि समायोजनों से पूर्व शुद्ध अधिशेष (I-II)			10,665	17,597
IV	घटाएं : पूर्वावधि समायोजन			256	16
V	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष			10,409	17,581
VI	निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:				
	(क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.4(iii) देखें]			5,027	5,916
	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.4(iv) देखें]			39	37
	(ग) उद्दिष्ट निधि (व्ययों का शुद्ध योग) [टिप्पण 20.9(iv) देखें]			1,691	-
	(घ) साधारण आरक्षिती			3,652	11,628
	योग			10,409	17,581
कृपया वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले संलग्न टिप्पणों को देखें।					

ह./- एच.के. जैन संयुक्त सचिव	ह./- वी. सागर सचिव	ह./- सी.एम. देवराजा रेड्डी उपाध्यक्ष	ह./- सी.ए. मनोज फडनीस अध्यक्ष
------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ सी.ए. प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ सी.ए. उमेश सी. पांडे भागीदार सदस्यता सं. 055252

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 1 सितंबर, 2015

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

			लाख रुपए में
विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	

प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	10,409		17,581
छात्र संघों की आरक्षित/उद्दिष्ट निधि का आरंभिक अतिशेष	101		
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
अवश्ययण और परिशोधन	2,348		2,026
अधित्यक्त आस्तियां	58		24
व्याज संबंधी आय	(7,971)		(5,008)
पूंजी संकर्म परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	4,945		14,623
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(676)		(187)
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(1,336)		(709)
दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	1,691		908
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1,693		145
	6,317		14,780
स्रोत पर कटौती किया गया कर (वसूलनीय)	350		(513)
प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	6,667		14,267
निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
नियत आस्तियों का क्रय	(6,981)		(5,492)
निवेशों का अर्जन	(8,822)		(15,842)
प्राप्त हुई व्याज आय ³	7,919		5,572
पूंजी प्राप्ति	125		923
निवेश गतिविधियों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	(7,759)		(14,839)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
नए सदस्यों से प्रवेश शुल्क	165		183
सदस्यों से अभिदाय	68		178
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद (इ)	233		361
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	(859)		(211)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	6,886		7,097
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	6,027		6,886

टिप्पण :

- (1) नकद और नकद समतुल्य, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा धन को बताते हैं (टिप्पण 14 देखें)।
- (2) कोष्ठकों में दी गई रकमें अतिरेक को बताती हैं।
- (3) उद्दिष्ट निधियों से प्राप्त आय (व्ययों का शुद्ध) को सम्मिलित करता है।
- (4) छात्र संघों को पहली बार वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् से ही आरक्षितियों के आरंभिक अतिशेष को जोड़ा जाता है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
------	------	------	------

एच.के. जैन संयुक्त सचिव	वी. सागर सचिव	सी.ए. एम. देवराजा रेड्डी उपाध्यक्ष	सी.ए. मनोज फडनीस अध्यक्ष
----------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------------------

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ सी.ए. प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ सी.ए. उमेश सी. पांडे भागीदार सदस्यता सं. 055252

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 1 सितंबर, 2015

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल पांच प्रादेशिक परिषदों, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और 147 शाखाओं का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, एक विदेशी कार्यालय को भी स्थापित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.1 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदम्भवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.2 प्राक्कलनों का उपयोग

भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथा विद्यमान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्टित रकमों तथा आकस्मिक दायित्वों के प्रकटनों और वर्ष के दौरान आय और व्यय की रिपोर्टित रकमों को प्रभावित करें। ऐसे प्राक्कलनों के उदाहरणों में नियत आस्तियों का उपयोगी जीवन, कर्मचारियों का कल्याण, आकस्मिक दायित्व आदि सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलनों संबंधी किसी पुनरीक्षण को चालू और भावी अवधियों में भविष्यलक्षी रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

2.3 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदम्भवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान की प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.4 आरक्षितियों को विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

- (i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।
- (ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।
- (iii) दुरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।
- (v) उद्दिष्ट निधियों से निम्नलिखित अंतरण शिक्षा आरक्षित खाते को किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	अन्य नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों)

का शुद्ध, यदि कोई हो) का 50 प्रतिशत

2.5 नियत आस्तियां

i) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित अवक्षयण और हानिकरण हानियों (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी आस्ति की लागत में सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आश्रित उपयोग के अवस्थान और स्थिति में लाने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। पट्टाधृत भूमि की लागत में पट्टाधृत अधिकारों का अर्जन करने हेतु संदत्त कोई रकम भी सम्मिलित है। मूर्त आस्तियों से संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

पट्टाधृत भूमि की लागत को मूल पट्टा अवधि के पश्चात् परिशोधित किया जाता है। अन्य सभी मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण, संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर उनके उपयोगी जीवन के प्राक्कलन के आधार पर अंकित मूल्य पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

	आस्तियों का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i)	भवन	5%
(ii)	वातानुकूलक	15%
(iii)	इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v)	कार्यालय उपस्कर	15%
(vi)	कंप्यूटर	60%
(vii)	लिफ्ट	10%
(viii)	वाहन	20%
(ix)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

ii) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित परिशोधन और एकत्रित हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर अर्जन की लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छुट्ट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आश्रित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी अमूर्त आस्ति के क्रय/पूरा होने के पश्चात् होने वाले किसी पश्चातवर्ती व्यय को, जब उसे उपगत किया जाए, तब तक एक व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब तक कि ऐसी संभावना हो कि ऐसे व्यय के कारण उसके मूल रूप में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से अधिक ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी आर्थिक फायदे समर्थ होंगे और ऐसे व्यय का विश्वसनीय रूप से मापमान किया जा सकता है और आस्ति से जोड़ा जा सकता है, जिस दशा में ऐसे व्यय को आस्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है।

अमूर्त आस्ति की लागत का परिशोधन, तीन वर्ष के उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन से परे प्रत्यक्ष रूपरेखा के आधार पर किया जाता है।

iii) चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आश्रित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.6 निवेश

तुलन-पत्र की तारीख से बारह मास की अवधि के पश्चात् की भुगतान तारीख वाले बैंक निक्षेपों के रूप में निवेशों को गैर-चालू के रूप में तथा अन्य निवेशों को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निवेश संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार निरुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी कल्याण निधियों के योग की सीमा तक।

2.7 वस्तु-सूचियां

(क) प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है। वस्तु-सूचियों की लागत का अवधारण प्रथम आगम, प्रथम जावक (एफआईएफओ) पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(ख) पुरानी अध्ययन सामग्रियों और एक वर्ष से अधिक पुराने संस्थान के प्रकाशनों के स्टॉक की लागत पर 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वीओएस प्रकाशनों के शेष स्टॉक की लागत पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

2.8 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में नकदी और बैंकों में चालू तथा बचत खातों का अतिशेष सम्मिलित होता है।

2.9 राजस्व मान्यता

(i) सदस्यता फीस

(क) सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) वार्षिक सदस्यता और व्यवसाय प्रमाण-पत्र फीस को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे देय हो जाते हैं।

(ii) दुरस्थ शिक्षा और अर्हता पश्च पाठ्यक्रमों की फीस को संबंधित पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है।

(iii) परीक्षा फीस को संबंधित परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(iv) जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वह देय हो जाते हैं।

(v) प्रकाशनों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कार क्रेता को अंतरित किए जाते हैं जो कि सामान्यतः मालों के परिदान के समय हो जाता है। इस आय के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, छुट्टों और अन्य विक्रय संबंधी करों (यदि कोई हों) का शुद्ध भी है।

(vi) बैंक निक्षेपों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों से प्राप्त होने वाली व्याज आय को, बकाया रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.10 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग मुद्रा, अर्थात् भारतीय रुपए में प्रारंभिक रूप से दी गई मान्यता के आधार पर अभिलिखित किया जाता है। असमायोजित रिपोर्टिंग मुद्रा से भिन्न किन्हीं अन्य मुद्राओं में धनीय आस्तियों और दायित्वों का, तुलन-पत्र की तारीख को लागू विनिमय दरों के आधार पर पुनः मापमान किया जाता है। धनीय मदों के समायोजन पर उद्भूत होने वाले और धनीय मदों के पुनः माप पर होने वाले विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.11 आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर आस्तियों के अग्रणीत मूल्य का हानिकरण के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम का प्राक्कलन किया जाता है और हानिकरण को मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रणीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। भावी नकद प्रवाहों में छूट देते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर समुचित छूट कारक को गणना में लेते हुए उपयोग में मूल्य को संगणित किया जाता है। जहां कोई ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि किन्हीं पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में किसी आस्ति के लिए मान्य ठहराया गया कोई हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कमी हो गई है तो ऐसे हानिकरण की हानि के उत्क्रमण को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 कर्मचारी फायदे

i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

वेतन, भत्ते, अनुग्रह जैसे अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष के व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ii) परिभाषित अभिदाय योजनाएं

परिभाषित अभिदाय योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं, जहां संस्थान स्वतंत्र न्यास द्वारा प्रबंधित भविष्य निधि में नियत अभिदाय करता है। अभिदायों का संदाय, वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है और उसे वेतन और भत्तों की रूपरेखा के अनुसार ही व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यदि निधि में कर्मचारियों को संदाय/फायदे विस्तारित करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं हैं तो इस संबंध में आगे और अभिदाय करने के लिए संस्थान की कोई विधिक या परिलक्षित बाध्यता नहीं है।

iii) परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान अपने कर्मचारियों को उपदान, सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन और क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे फायदे उपलब्ध कराता है। उपदान संबंधी दायित्व का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। क्षतिपूरित अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन से संबंधित दायित्व वित्तपोषित नहीं हैं। इन परिभाषित फायदा संबंधी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को, लेखांकन मानक (एएस) - 15 कर्मचारी फायदा की अपेक्षाओं के अनुसार किसी स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराए गए दायित्व का मूल्य, तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदों संबंधी बाध्यता का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना आस्तियों (वित्तपोषित

योजनाओं के लिए) के उचित मूल्य को घटा दिया गया है तथा ऐसी पूर्व सेवा लागतों, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, के लिए समायोजनों किए गए हैं। पूर्व सेवा लागतों को तुरंत और फायदों के निहित होने की सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है। सभी वीमांकक अभिलाषों और हानियों को उस वर्ष में, जिसमें वे हुए हैं, पूर्ण रूप से आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

i) प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी कंपनी की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

ii) आकस्मिक दायित्व और आस्तियां

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उद्भूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

3. आरक्षितियां और अधिशेष

(लाख रुपये में)

31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान		शिक्षा	अवसंरचना	साधारण	अन्य*	योग
वर्ष के आरंभ में अतिशेष		29,739	4,571	67,826	604	1,02,740
जोड़े:	छात्र संघों की आरक्षितियों का आरंभिक अतिशेष	-	3	96	-	99
जोड़े:	आय और व्यय के विवरण से वित्तियोग	-	-	3,652	-	3,652
		29,739	4,574	71,574	604	1,06,491
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण		-	8	(96)	88	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण		2,411	(60)	(174)	(1)	2,176
दाखिला फीस और आबंटित प्रवेश फीस		-	165	-	-	165
भवनों के लिए प्राप्त सदान		-	68	-	-	68
(उपयोग)/परिवृद्धियां		-	(29)	(171)	(39)	(239)
वर्ष के अंत में अतिशेष		32,150	4,726	71,133	652	1,08,661
31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान		शिक्षा	अवसंरचना	साधारण	अन्य*	योग
वर्ष के आरंभ में अतिशेष		23,092	4,161	55,897	582	83,732

जोड़ें:	आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	11,628	-	11,628
		23,092	4,161	67,525	582	95,360
	साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	16	(26)	10	-
	उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	6,647	-	(178)	(1)	6,468
	दाखिला फीसों और आबटित प्रवेश फीसों	-	183	-	-	183
	भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	178	-	-	178
	(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	33	505	13	551
	वर्ष के अंत में अतिशेष	29,739	4,571	67,826	604	1,02,740

* अन्य आरक्षितियां, पुस्तकालय आरक्षितियों और कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियों जैसी आरक्षितियां हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

4. उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपये में)

31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	अनुसंधान निधियां	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	पदक और पुरस्कार निधि	छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां	कर्मचारी कल्याण निधि	अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और शाखाएं)	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,760	610	14,731	176	91	410	3,074	20,852
जोड़ें : छात्र संघों की आरक्षितियों का आरंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-	2	2
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	5,027	-	-	39	-	5,066
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	(2,411)	-	-	-	235	(2,176)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	4	17	-	343	364
वर्ष के दौरान आय	165	57	1,379	16	9	38	187	1,851
वर्ष के दौरान संदाय	(5)	-	-	(12)	(5)	-	(138)	(160)
वर्ष के अंत में अतिशेष	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703	25,799
31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	अनुसंधान निधियां	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	पदक और पुरस्कार निधि	छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां	कर्मचारी कल्याण निधि	अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और	योग

							शाखाएं)	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,603	556	14,088	171	89	341	2,508	19,356
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	5,916	-	-	37	-	5,953
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	(6,647)	-	-	-	179	(6,468)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	1	-	-	-	-	-	372	373
वर्ष के दौरान आय	156	54	1,374	17	9	33	174	1,817
वर्ष के दौरान संदाय	-	-	-	(12)	(7)	(1)	(159)	(179)
वर्ष के अंत में अतिशेष	1,760	610	14,731	176	91	410	3,074	20,852

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

5. अन्य दीर्घकालिक दायित्व

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
7	अन्य चालू दायित्व							
	क)	अग्रिम में प्राप्त फीस						
		i)	परीक्षा फीस				4,872	4,471
		ii)	जर्नल अभिदाय				19	23
		iii)	सदस्यता फीस				1,296	1150
		iv)	शिक्षा फीस				8,656	9,335
		v)	अर्हता पश्च पाठ्यक्रम फीस				108	145
		vi)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम फीस				18	9
		vii)	संगोष्ठी फीस और अन्य संग्रहण				1,171	1,719
							16,140	16,852
	ख)	व्यय और अन्य देय					5,653	3,176
	ग)	अन्य दायित्व						
		i)	नियत आस्तियों के क्रय के लिए देनदार				120	166
		ii)	कर्मचारियों से वसूलियां और कर्मचारियों के अभिदाय				111	85
		iii)	कानूनी देय				269	186
		iv)	निक्षेप				548	489
		v)	अन्य				1,027	1,217
							2,075	2,143
		योग					23,868	22,171

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

8. मूल्य आस्तियां									(लाभ रूप में)	
31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाभूत भूमि	घवन	लिफ्ट तथा इलेक्ट्री कल प्रतिष्ठा पन और फीटिंग्स	कंप्यूटर	फर्नीचर और फिक्सचर	वातानुकूलक और कार्वालय उपस्कर	वाहन	पुस्तकालय की पुस्तकें	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504
परिवृद्धियां	149	914	2415	135	528	356	424	30	78	5,029
विलोपन	-	-	-	(23)	(110)	(50)	(66)	(1)	-	(250)
वर्ष के अंत में लागत	15,690	5,399	26,932	1,757	4,463	3,765	4,236	134	907	63,283
वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
वर्ष के लिए प्रभार	-	80	1,131	96	376	236	324	11	78	2,332
विलोपन	-	-	-	(11)	(105)	(28)	(47)	(1)	-	(192)
वर्ष के अंत में अवक्षयण	-	499	4,325	873	3,958	1,535	2,219	82	907	14,398
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33	-	46,246
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	15,690	4,900	22,607	884	505	2,230	2,017	52	-	48,885
31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाभूत भूमि	घवन	लिफ्ट तथा इलेक्ट्री कल प्रतिष्ठा पन और फीटिंग्स	कंप्यूटर	फर्नीचर और फिक्सचर	वातानुकूलक और कार्वालय उपस्कर	वाहन	पुस्तकालय की पुस्तकें	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	15,376	3,701	13,421	1,552	3,760	3,055	3,484	103	759	45,211
परिवृद्धियां	165	784	11,096	96	328	431	405	2	71	13,378
विलोपन	-	-	-	(3)	(43)	(27)	(11)	-	(1)	(85)
वर्ष के अंत में लागत	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504

वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	-	355	2,182	699	3,478	1,118	1,641	64	759	10,296
वर्ष के लिए प्रभार	-	64	1,012	91	250	220	307	8	71	2,023
विलोपन	-	-	-	(2)	(41)	(11)	(6)	-	(1)	(61)
वर्ष के अंत में अवक्षयण	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	15,376	3,346	11,239	853	282	1,937	1,843	39	-	34,915
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33	-	46,246

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

9. अमूर्त आस्तियां				(लाख रुपए में)
31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान			साफ्टवेयर	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत			595	595
परिवृद्धियां			42	42
विलोपन			-	-
वर्ष के अंत में लागत			637	637
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन			591	591
वर्ष के लिए प्रभार			16	16
विलोपन			-	-
वर्ष के अंत में परिशोधन			607	607
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य			4	4
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य			30	30
31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान			साफ्टवेयर	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत				
			593	593
परिवृद्धियां			2	2
विलोपन			-	-
वर्ष के अंत में लागत			595	595
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन			588	588
वर्ष के लिए प्रभार			3	3
वर्ष के अंत में परिशोधन			591	591
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य			5	5
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य			4	4

				(लाख रुपए में)
	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
	गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
10. निवेश				
बैंकों में सावधि निक्षेप	13,737	-	72,657	77,572
	13,737	-	72,657	77,572
निवेशों में निम्नलिखित हैं				
- उद्दिष्ट निधियां	13,737	-	12,062	20,852
- कर्मचारी फायदे	-	-	5,780	4,087

					(लाख रुपए में)
		31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
		गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
11.	ऋण और अग्रिम				
	क) प्रतिभूति निक्षेप	307	270	234	-
	ख) वसूलनीय टीडीएस	1,965	1,640	-	675
	ग) अन्य ऋण और अग्रिम				
	i) सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी आस्तियां	-	-	19	46
	ii) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	854	814	454	477
	iii) अन्य प्राप्य	598	244	3,134	2,413
	योग	3,724	2,968	3,841	3,611

				31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
12.	गैर चालू आस्तियां				
	क) बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज			646	-
	ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज			101	110
	योग			747	110
13.	वस्तु-सूचियां				
	क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां			1,571	932
	ख) लेखन सामग्रियां और भंडार			129	92
	योग			1,700	1,024
14.	नकद और नकद समतुल्य				
	क) हाथ में नकदी			50	33
	ख) बैंकों में अतिशेष			5,977	6,853
	योग			6,027	6,886
15.	अन्य चालू आस्तियां				
	क) बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज			2,314	2,916
	ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज			20	3
	योग			2,334	2,919

			31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
16.	प्राप्त फीसें			
		क) शिक्षा	28,222	31,453
		ख) परीक्षा	11,211	10,061
		ग) सदस्यता	5,366	5,120
		घ) छात्र रजिस्ट्रीकरण	589	714
		ङ) प्रवेश	52	62
		च) छात्र संघ	401	535
		छ) अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	472	625
		ज) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1,489	988
		योग	47,802	49,558

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

17. अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
क)	प्रकाशन	1,495	936
ख)	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	6,044	4,941
ग)	उद्दिष्ट निधियां निवेश से प्राप्त ब्याज	1,851	-
घ)	कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज	76	67
ङ)	छात्र न्यूजलेटर	3	6
च)	जर्नल अभिदाय	202	155
छ)	न्यूजलेटर्स - प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं	55	56
ज)	कैम्पस साक्षात्कार	486	398
झ)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	30	16
ञ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	310	10
ट)	अन्य	769	710
	योग	11,321	7,295
18.	कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय		
क)	वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	11,597	7,185
ख)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अभिदाय	748	398
ग)	कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	223	110
	योग	12,568	7,693

19. अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

		रकम	रकम
		31/3/2015 को समाप्त वर्ष	31/3/2014 को समाप्त वर्ष
क)	डाक और टेलीफोन	2,660	2,513
ख)	किराया, दर और कर	3,611	2,768
ग)	यात्रा और वाहन अंतर्देशीय	1,714	1,487
घ)	विदेशी संबंध		
	i) विदेश यात्रा	251	217
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	332	338
	iii) अन्य	28	31
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	1,642	1,548
च)	प्रकाशन	1,131	962
छ)	परामर्शियों और परीक्षकों को संदत्त वृत्तिक फीस	7,204	6,644
ज)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	4,557	4,444
झ)	विज्ञापन और प्रचार	405	255
ञ)	बैठक व्यय	292	178
ट)	योग्यता छात्रवृत्ति	94	87
ठ)	संपरीक्षा फीस		
	i) प्रधान कार्यालय	11	6
	ii) अन्य कार्यालय	28	21
ड)	अन्य उद्दिष्ट निधियों का संदाय	160	-
ढ)	अन्य व्यय	2,329	1,489
	योग	26,449	22,988

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

20. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी**20.1 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :**

	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	1,378	1,440
ii) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	8,084	9,402

20.2 टिप्पण 11 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्ति में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआ, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अभी लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

20.3 प्रकाशनों और संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को, क्रमशः व्यय के इन शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है और इन क्रियाकलापों से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

20.4 छात्रों से, छात्र संघ फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

- 20.5** पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के जापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
- 20.6** संस्थान ने, सभी स्तरों पर संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य से एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसे "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस पहल के अनुसरण में और सम्यक् प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् संस्थान ने एक वैश्विक रूप से छातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता को नियुक्त किया था। इस संविदा में, कुल 3,981 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत से अपेक्षाओं संबंधी अध्ययन, साफ्टवेयर और हार्डवेयर के संबंध में सिफारिशें और उनका चयन, जहां कहीं आवश्यक हो, साफ्टवेयर का विकास, उपयुक्त साफ्टवेयर एप्लीकेशन उपलब्ध कराना और आईटी अवसंरचना का कार्यान्वयन और साथ ही चयन तथा अनुरक्षण भी सम्मिलित है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।
- एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने इस संबंध में विवाद उठाते हुए संविदा को रद्द कर दिया था। अंतिम समाधान के लंबित रहते हुए, संस्थान ने जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति को वापस ले लिया था, उसे वित्तीय विवरणों में टिप्पण सं. 11 के अधीन अन्य प्राप्य शीर्ष के अधीन (वर्तमान में) 31 मार्च, 2015 को प्राप्य के रूप में दर्शित किया गया है।
- उसके पश्चात् वसूल की गई बैंक प्रत्याभूति की रकम को घटाने के पश्चात्, वित्तीय विवरणों में 572 लाख रुपए (867 लाख – 295 लाख) की राशि को पूर्ण रूप से व्यय की गई राशि के रूप में दर्शित किया गया है और उसे टिप्पण सं. 19 में अन्य व्ययों में सम्मिलित किया गया है।
- 20.7** चालू पूंजी संकर्म के अतर्गत पूंजी अग्रिम भी हैं।
- 20.8** आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हुडा (हरियाणा) विचार किया जा रहा है।
- 20.9** संस्थान ने, उद्दिष्ट निधियों से आय और व्यय की प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप में जमा करने/विकलित करने से परिवर्तित करके उसे आय और व्यय की संबंधित मद में रखा है और इस प्रकार, शुद्ध अभिवृद्धि को उद्दिष्ट निधियों को अंतरित किया था।
- यदि प्रस्तुति की पद्धति को पूर्व वर्ष में भी अपनाया गया होता तो अन्य आय 1,817 लाख रुपए, अन्य व्यय 179 लाख रुपए और शुद्ध अतिशेष 1,638 लाख रुपए अधिक होते।
- 20.10** जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

21. लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

21.1 कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 327.65 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 326.37 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

		लाख रुपए में	
	विवरण	2014-15	2013-14
1.	बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान		
	क) वर्ष के आरंभ में बाध्यता	2,057	1,957
	ख) चालू सेवा लागत	167	147
	ग) ब्याज लागत	154	171
	घ) व्रीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	32	(63)
	ड) संदत्त फायदे	(197)	(155)

	च) वर्ष के अंत में बाध्यता	2,213	2,057
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	क) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,103	1,950
	ख) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	184	174
	ग) व्रीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	3	10
	घ) संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	239	91
	ङ) संदत्त फायदे	(297)	(122)
	च) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,232	2,103
3.	योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान		
	क) बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	2,213	2,057
	ख) योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,232	2,103
	ग) तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	19	46
4.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय		
	क) चालू सेवा लागत	167	147
	ख) व्याज लागत	154	171
	ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(184)	(174)
	घ) व्रीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	29	(73)
	ङ) वर्ष के दौरान माने गए व्यय	166	71
5.	निवेशों के ब्यौरे	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क) अन्य – भारतीय जीवन व्रीमा निगम के पास निधियां	100.00	100.00
		100.00	100.00

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

उपदान योजना के ब्यौरे (जारी....)									
	विवरण							2014-15	2013-14
6.	पूर्वनिमान								
	क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)							7.85%	9.10%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)							8.85%	9%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर							मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर							5%	5%
	ङ नश्वरता सूची							आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
								अंततः	अंततः
	सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे								(लाख रुपए में)
	विवरण							2014-15	2013-14
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान								
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता							1,406	1,489

	ख. व्याज लागत						110		134
	ग. वीमांकक (अभिलाभ)/हानि						1,169		(215)
	घ. संदत्त फायदे						(1)		(2)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं						2,684		1,406

2.	योजना आस्तिबों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान								
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य						2,684		1,406
	ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें						(2,684)		(1,406)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय								
	क. व्याज लागत						110		134
	ख. वीमांकक (अभिलाभ)/हानि						1,169		(215)
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय						1,279		(81)
4.	पूर्वानुमान								
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)						7.80%		9%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर						मूल 3%		मूल 3%
	ग. संनिघर्षण दर						5%		5%
	घ. नश्वरता सूची						एलआईसी 1996-98		एलआईसी 1996-98
							अंततः		अंततः

21.1 कर्मचारी फायदे (जारी....)

सतिपूरित अनुपस्थिति के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	विवरण	2014-15	2013-14
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान		
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	2,359	2,239
	ख. चालू सेवा लागत	338	104
	ग. व्याज लागत	175	199
	घ. वीमांकक (अभिलाभ)/हानि	259	(83)
	ङ संदत्त फायदे	(274)	(100)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	2,857	2,359
2.	योजना आस्तिबों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान		
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	2,857	2,359
	ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें	(2,857)	(2,359)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय		
	क. चालू सेवा लागत	338	104
	ख. व्याज लागत	175	199
	ग. वीमांकक (अभिलाभ)/हानि	259	(83)
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	772	220
4.	पूर्वानुमान		
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.85%	9.10%

	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : सीए 6%	मूल 3% : सीए 6%																																												
	ग. संनिघर्षण दर	5%	5%																																												
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08																																												
		अंततः	अंततः																																												
# यह केवल आस्थितित छुट्टी के संबंध में संगणित शीर्षकालिक दावित्व से संबंधित है। 239 लाख रुपए के संभावित अल्पकालिक दावित्व को इस आंकड़े में जोड़ा जाएगा।																																															
<p style="text-align: center;">भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण</p> <p>21.2 बंड रिपोर्टिंग</p> <p>संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति को अग्रसर करना" तक सीमित है और यह सुझाव: भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस-17) बंड रिपोर्टिंग के अर्थात्गर्त एकल बंड के अंतर्गत आते हैं।</p> <p>21.3 पूर्ववर्ति मदे</p> <table> <tr> <td></td><td></td><td>31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए</td><td>31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए</td></tr> <tr> <td></td><td>पूर्ववर्ति मदों के व्योरे</td><td>(लाख रुपए में)</td><td>(लाख रुपए में)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>i) आय</td><td>38</td><td>93</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>ii) व्यय</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(क) परिवर्तन परियोजना</td><td>-</td><td>(97)</td></tr> <tr> <td></td><td>(ख) सेवाकर</td><td>-</td><td>26</td></tr> <tr> <td></td><td>(ग) अन्य</td><td>294</td><td>180</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>294</td><td>109</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>256</td><td>16</td></tr> </table>						31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		पूर्ववर्ति मदों के व्योरे	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)						i) आय	38	93						ii) व्यय				(क) परिवर्तन परियोजना	-	(97)		(ख) सेवाकर	-	26		(ग) अन्य	294	180			294	109			256	16
		31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए																																												
	पूर्ववर्ति मदों के व्योरे	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)																																												
	i) आय	38	93																																												
	ii) व्यय																																														
	(क) परिवर्तन परियोजना	-	(97)																																												
	(ख) सेवाकर	-	26																																												
	(ग) अन्य	294	180																																												
		294	109																																												
		256	16																																												

ह./- एच.के. जैन संयुक्त सचिव	ह./- बी. सागर सचिव	ह./- सीए. एम. देवराजा रेड्डी उपाध्यक्ष	ह./- सीए. मनोज फडनीस अध्यक्ष
------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रध एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ सीए. प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ सीए. उमेश सी. पांडे भागीदार सदस्यता सं. 055252

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 1 सितंबर, 2015

बी. सागर, सचिव

[विज्ञापन/ III/4/असा. /104/15(219)]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2015

No.1-CA(5)/66/2014.—In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2015 is hereby published for general information.

66th ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the “Council”) has immense pleasure in presenting its 66th Annual Report for the year ended 31st March, 2015.

The Council, at the outset, commends the members and students for the position which the Chartered Accountancy profession has been occupying and the role it has played over the years for the growth and development of Indian economy.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2014-15, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for that year, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto early July, 2015.

1. THE COUNCIL

The twenty-second Council was constituted on 12th February, 2013 for a period of three years. Currently, the Council is composed of 32 elected members and 8 persons nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2015-16 has been shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12th February, 2014, Standing Committees and other Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. During the year ended 31st March, 2015, 231 meetings were held of various Committees of the Council.

3. AUDITORS

M/s.ASA & Associates LLP and M/s. B M Chatrath & Co. were the joint auditors of ICAI for the financial year 2014-15. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEE

4.1 Executive Committee

Some of the important decisions taken by the Committee including those recommended to the Council during the period under report related to matters on:

- Approval of proposal for a MoU between ICAI and the Institute of Chartered Accountants of Pakistan
- Setting up of ICAI Chapter at Dar Es-Salam
- Increase in number of Scholarships for the category of Need Based and Weaker Sections from 100 to 200 in respect of Intermediate (IPC) students and from 100 to 300 for the students of Final Course per year. Over and above the number of scholarships approved, the children undergoing CA Course of the deceased members of ICAI where financial assistance is provided to spouses of the deceased members from the Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) shall also be eligible for scholarship under Need Based and Weaker Sections category provided they apply in the prescribed application form by the Board of Studies.
- Increase in honorarium from Rs.10,000/- to Rs.15,000/- for setting up the Question paper i.e. 60 objective and 10 subjective questions and Rs.150 per question cum answer sheet booklet for their evaluation of Assessment Test of Certificate Course on International Taxation.

- Revision in the Guidelines for articleship training abroad
- Approval for proposal for arrangement of Microsoft office 365 for the members & students of ICAI provided by Microsoft Corporation at special terms
- Permanently debarring of the Students/ candidates from pursuing the Chartered Accountancy Course on submission of fictitious/ forged documents to the ICAI and not registering in any stream of the Course and forfeiting of the Course fee deposited by such candidates.
- Grant of an opportunity to certain categories of students who were exempted from passing the Common Proficiency Test (CPT) and were eligible for direct admission to the Chartered Accountancy Course for submitting the proof of having passed the graduation examination with specified percentage of marks within one month.

Recommendations received from respective Committee which were then brought before the Council along with the recommendations of the Executive Committee:

- Approval of proposal for launching of Certificate Course on Information Systems Security
- Relaxation in the requirement to undergo 9 months Practical Training to appear in IPC Examination in respect of students registered for IPCC under CPT Route and shifted to Direct Entry Scheme

4.2 Finance Committee

This Finance Committee – one of the Standing Committees of the Council – came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The said Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 414 and 302 centres respectively from 26th May, 2014 to 9th June, 2014. The total number of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed were as follows:

	Both Groups		Group I		Group II	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	66625	6326	125187	20537	121855	16878
Final	42533	3100	65792	8884	65706	7004

Further, the Examination of Post Qualification Course on Insurance and Risk Management (IRM) was conducted in May, 2014 wherein 65 candidates appeared and 46 passed the said examination.

Besides, the Common Proficiency Test (CPT) was held successfully on 22nd June, 2014 and on 14th/21st December, 2014 across the country and abroad at 414 and 383 examination centres respectively located in 163 and 167 cities respectively. The total number of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

	Appeared	Passed
CPT held on 22 nd June, 2014	130291	37303
CPT held on 14 th & 21 st December, 2014	100957	14880

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 421 and 308 centres respectively from 7th to 23rd November, 2014. The total number of candidates, who appeared in the said intermediate (IPC) and Final Examinations and passed, were as follows:

	Both Groups		Group I		Group II	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	47795	2963	123488	17603	104435	15982
Final	36254	2983	64972	15208	66552	6830

The examinations on Post Qualification Course in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO), Part 1 were also conducted in November, 2014.

During the year, Post Qualification Course - Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 28th June, 2014 all over the country in 61 Examination centres and another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 27th December, 2014 all over the country in 65 examination centres. The total number of candidates, who appeared in these examinations and passed were as follows:

	Appeared	Passed
ISA – AT held on 28 th June, 2014	3288	219
ISA – AT held on 27 th December, 2014	2684 (Old) 256 (New)	668 (Old) 125 (New)

The ICAI has continuously been improving its examination processes right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for over six decades, are maintained and further strengthened and developed.

The ICAI's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession.

By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, ICAI's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

International Initiatives: *Extending Helping Hand of ICAI Brand*

Special Examination: Arising out of the Mutual Recognition Agreement/ Memorandum of Understanding entered with the following foreign professional accounting bodies, the Special Examination for our members desirous of membership of the said bodies were successfully conducted on (i) 21st to 24th January, 2014, (ii) 10th to 13th June, 2014 and (iii) 6th, 7th & 9th January, 2015 in New Delhi.

1. The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)
2. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)
3. The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)
4. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
5. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)

Beside this, ICAI has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA).

The above Special Examination is open to the members of the above international accounting bodies.

Support to International Accounting Institutes: The Examination Committee provided technical assistance and support for the conduct of ISA Assessment Test to the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and The Institute of Chartered Accountants of Nepal. Besides infrastructure, administrative and manpower assistance was also extended to the Institute of Certified Public Accountants in Ireland for conduct of their examination in India.

Initiatives for Profession: *Working for Building Blocks*

Appointment of Checkers: With effect from the examinations held in May 2012, checking of answer books after evaluation by the examiners is required to be carried by a member of the ICAI from out of the panel drawn for the purpose. The checking involves, inter alia, whether answers to all questions/ sub-questions have been evaluated, the marks awarded have been carried to the cover page, there is no totalling error etc. The feedback received from the examiners, consequent to the above revised procedure, was encouraging. The said procedure was followed for the examinations held in May, 2014 and November, 2014.

IT Initiatives: *Taking Steps with the changing time*

Automation: Automation of examination processes covering, inter-alia, coding, capture of absentee data, reconciliation and capturing of marks (after evaluation by examiners), continued for May, 2014 and November, 2014 examinations.

Question Bank: The Question Banks for the Common Proficiency Test and the Information Systems Audit – Assessment Test have been further strengthened.

Development of Observers web Portal: A web portal <http://observers.icaiaexam.icaai.org> was developed and put in place for facilitating all activities relating to Observers appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/ daily reports/ claims for honorarium etc. effective from May, 2014 examinations. The same has been extended for the examinations held in November, 2014 as well.

Development of Examination Centre web portal: A web portal <http://centres.icaiaexam.icaai.org> was developed and put in place for the May, 2014 CA examinations for capture of absentee data online, on the day of the exam, on a daily basis. The same continued for November, 2014 examinations.

Payments through NEFT: Payment to examiners, examination centres, Observers and other resource persons, etc. through NEFT, was introduced during the year and implemented successfully.

Initiatives for Students: *Strengthening the Fundamentals*

Keeping in view that students are the future of the profession; for their welfare and convenience the following initiatives have been taken:

Reading Time: In line with the international best practices in the area of testing students, a 15-minute reading time given to candidates in the Chartered Accountants Examinations before the scheduled time of commencement of the examination with effect from May, 2011 Examinations, continued for May, 2014 and November, 2014 examinations.

Online Examination Application Form: Submission of examination applications forms online and payment of exam fees online through payment gateway, at <http://icaiaexam.icaai.org>, introduced in 2009, continued during 2014 also. The candidates who opted to fill up the examination form online were exempted for payment of the cost of application forms. Nearly 97% of all examination forms submitted are online.

Online Correction of entries in Exam forms Post- Submission: Even after submission of examination forms, students have another opportunity to correct the particulars online, i.e., at <http://icaiaexam.icaai.org>, including change of examination centre, group and medium etc. This link called correction window enabled them to communicate for making corrections in the examination forms.

Admit Cards: Downloading of Admit cards with scanned photographs and specimen signatures of the concerned students from the website has been facilitated with effect from November, 2012 CA Examinations and CPT, December 2012 and continued for May/ June, 2014 and November/ December, 2014.

Verification Applications: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of requests for verification of marks by candidates desirous of verification of their marks, post declaration of results, online at <http://icaiaexam.icaai.org> has been facilitated and continued in May, 2014 and November, 2014 as well. The outcome of their request also continues to be hosted on the same website.

Certified copy of Answer Books: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of applications for inspection of answer books and/or supply of certified copy of answer books, online at <http://icaiaexam.icaai.org> has been facilitated and continued in May and November, 2014 examinations also.

Further, suo-motu verification of marks, under Regulation 39(4) of the CA Regulations 1988, in respect of those who applied for certified copies of evaluated answer books, was introduced with effect from November, 2013 examination, continued for May, 2014 and November, 2014 examinations.

With effect from November, 2013 examination onwards, scanned copies of evaluated answer books of those examinees who sought them, are now made available online, on website, which can be accessed through a secure user ID and password by the respective examinee.

New Examination Centres: With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence as possible, new examination Centres were opened as follows:

New examination centres for CA Intermediate and Final exams opened:

- (a) With effect from May, 2014 examination onwards: Gandhinagar, Fatehabad, Kurnool, Neemuch, Karimnagar, Jhunjhunu, Chittorgarh and Jhansi.

(b) With effect from November, 2014 examination onwards: Tirunelveli, Ongole, Dhule and Anantapur.

(c) With effect from May, 2015 examination onwards: Bhiwandi and Ichalkaranji

New centres for CPT opened:

(i) With effect from June, 2014: Gandhinagar, Fatehabad, Kurnool, Neemuch, Karimnagar, Jhunjhunu, Chittorgarh, Jhansi and Navasari.

(ii) With effect from December, 2014 CPT: Tirunelveli, Ongole, Dhule and Anantapur

Results: The result, immediately after declaration, can be accessed through the designated site. The same is also facilitated through SMS. Besides, downloading of CPT result card (with photo and signature) has also been facilitated.

Help to differently-abled candidates: The ICAI now provides services of a writer/ scribe to its differently-abled candidates, with payment of honorarium by the Institute @ Rs. 500/- per paper. A city-wise panel of eligible writers/ scribes is hosted on our website i.e. www.icai.org. Facility of providing computers to differently-abled candidates for writing their answer in exams is underway.

Introduction of a web site for checking the “Exemption” status:

Candidates who fail in a Group in the examination but secure a minimum of 60 per cent marks in one or more papers, are granted “Exemption” in that paper or in those paper/s subject to certain criteria. The status of such exemption is indicated in their statement of marks issued to them. With a view to provide further clarity and to remove difficulties/ doubts that the candidates may face, a website <http://exemption.icaiexam.icai.org> has been developed and put in place effective from May, 2014 exams, wherein the status of those who are eligible for exemption in the forthcoming examination, is also made available to them, online.

Feedback form:

With a view to encourage feedback on the question papers from the candidates, a format has been designed and hosted at www.icai.org through which candidates can give their opinion on the quality/ difficulties faced, if any in respect of question papers of the CA examinations, to the Exam Department, within a week from the date of the last exam. A dedicated email ID examfeedback@icai.in is also opened for the purpose.

4.4 Disciplinary Committee

Further to the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the concept of disciplinary mechanism has undergone a radical change and the ICAI presently has two quasi-judicial arms through which it undertakes its main disciplinary functions as provided under the said Act viz. (i) Board of Discipline (under Section 21A) and (ii) Disciplinary Committee (under Section 21B). Further in so far as the old disciplinary cases are concerned, the transitional provisions under Section 21D are applicable whereby the Disciplinary Committee under Section 21D looks into the residual cases pending as of prior to the amendments carried out in the Act and Regulations framed thereunder. The detailed activities of Board of Discipline (under Section 21A)/ Disciplinary Committee (under Section 21B) and Disciplinary Committee (under Section 21D) are provided below:

Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Board of Discipline has been constituted by the Council of the ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and/or cases wherein the members are held *prima facie* NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the year under review, the Board held seven (7) meetings at different venues across the country. In the said meetings held during the said year, the Board concluded its enquiry in 9 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the functioning of the Board of Discipline is given below:

Cases dealt with under the New Disciplinary Mechanism

Board of Discipline (under Section 21A)
Period from 1st April, 2014 to 31st March, 2015

S.No.	Particulars	No. of cases
(a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	7
(b)	Number of Complaint/ Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	58*/20
(c)	Out of the above, number of Complaint/ Information cases referred by the Board of Discipline for further enquiry.	11/1
(d)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	8/2
(e)	Number of cases (Complaint/ Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	12/0

*including cases dealt with under Rule 6/12 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of cases) Rules, 2007

Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of both and only Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. During the year under review, this Committee held 21 meetings spanning 22 days at venues covering the various regions of the country. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 53 cases, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the functioning of the Disciplinary Committee is given below:

Disciplinary Committee (under Section 21B)
Period from 1st April, 2014 to 31st March, 2015

S.No.	Particulars	No. of cases
(a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	21
(b)	Number of Complaint/ Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	18/8
(c)	Out of the above, number of Complaint/ Information cases referred by the Disciplinary Committee for enquiry.	18/8
(d)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which enquiry was completed by the Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	37/16
(e)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years)	16/5

Disciplinary Committee under Section (21D)

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the Act in 2006. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie* opinion, during the year under review, this Committee held one meeting at Delhi and is engaged in the process of expediting and concluding the hearings in the three residual cases pending before it.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2014 to 31st March, 2015

S.No.	Particulars	No. of cases
1.	Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period (out of the total pending cases with the Committee for enquiry).	-
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	04
3.	Out of the above.	
	(a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	--
	(b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	02
	(c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/ other misconduct.	--
	(d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	--
	(e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct.	02
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	01
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6).	07

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT**5.1 Accounting Standards Board**

The Accounting Standards Board (ASB) was constituted by the ICAI in 1977 with a view to formulate Accounting Standards to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system and to harmonise the diverse accounting policies and practices in India. The ASB, since its inception, has been constantly working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Standards in line with the International Accounting Standards (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB with a view to provide guidance on the uniform applications of the Accounting Standards in increasingly complex business environment, also issues various guidance material from time to time.

Legal recognition to the Accounting Standards formulated by the ICAI was granted in October, 1998 with insertion of Section 211(3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section 211(3C) of the Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the proviso to the section, till the notification of the Accounting Standards by the Government, the Accounting Standards issued by the ICAI were required to be followed by companies. In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 prepared by the ICAI were notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India. These were made effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7, 2006). The Ministry of Corporate Affairs in the Companies (Accounts) Rules, 2014, vide its notification dated 31st March, 2014, specified that the standards of accounting as specified under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall be deemed to be the accounting standards until accounting standards are specified by the Central Government under Section 133.

As the number of business dealings across the border in different ways such as lending, borrowings, sales, purchases, etc., has increased tremendously in the recent times as a result of globalisation and liberalisation, for an economy to

achieve sustainable growth, a strong and transparent financial reporting framework is required. As a result of operating in multiple jurisdictions, the business structure has become complex from the point of view of allocation and optimum utilisation of economic resources amongst the various business units. As the sources of funding an organisation are not restricted to a particular jurisdiction, financial information conveyed by the financial statements of an entity to its various stakeholders, apart from presenting a true and fair view, is also required to be comparable across the globe. Globally comparable financial information helps in assessment and evaluation of proper allocation and optimum utilisation of economic resources achieved by the entity's management. Such information also helps the present and potential investors, creditors and other users in arriving at rational decisions for their investments and interests in entity. Further, the way Indian Government in the recent past has liberalized its Foreign Direct Investment (FDI) policy by enhancing the FDI limits in various key sectors of Indian economic growth such as retail, defense, etc., to attract foreign funds in India, the need for providing the investors from cross the border a platform to analyze and evaluate financial performance of the Indian corporates is necessary. The investor from cross borders should be provided globally comparable financial information about the venture they are going to invest in. Therefore, to maintain and achieve comparability in financial reporting, a need for a single set of globally accepted and high-quality Accounting Standards is the need of the hour. The International Financial Reporting Standards being issued by the IASB are increasingly being recognised as the global financial reporting standards. Many countries have either adopted or have permitted adoption of IFRS for preparing financial statements of various entities. Though the Accounting Standards issued by ICAI are primarily based on IAS/IFRS, in certain cases, the Accounting Standards have departed from IASs/IFRSs in view of legal and regulatory requirements apart from the economic conditions prevailing in the country.

Convergence with International Financial Reporting Standards has gained worldwide momentum in recent years. Financial Accounting Standards Board (FASB) of USA and IASB have also worked towards convergence of US GAAP and IFRS. The Securities and Exchange Commission (SEC) of USA has decided to permit filing of IFRS-compliant financial statements without requiring presentation of a reconciliation statement between the US GAAP and IFRS. In this scenario, with India being an important emerging global economy, the ICAI decided in 2007 to converge with IFRS from 1st April, 2011 for certain class of companies. The Ministry of Corporate Affairs also agreed to do so. Convergence, among other things, would help Indian entities raise capital from abroad at a low cost. It will also benefit chartered accountants in increased opportunities abroad.

The ICAI accomplished the task of formulation of IFRS-converged Indian Accounting Standards. The Ministry of Corporate Affairs hosted thirty five Indian Accounting Standards on its website in February, 2011. However, due to tax implications and other unavoidable reasons, these Indian Accounting Standards were not notified by the Government.

In the year 2013, the Government of India, considering the need of the economy to have an updated and modern set of regulation for the Indian corporates, has finalised and issued the long discussed and awaited Companies Act, 2013, which superseded its predecessor statute Companies Act, 1956, which was there from more than last five decades. Section 133 to the Companies Act, 2013 prescribes that the Central Government may prescribe the standards of accounting as recommended by the ICAI in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority (NFRA). The said section itself shows the faith and belief of Indian Government in the work done by the ICAI for formulating a high class accounting standards for the Indian financial reporting system.

The enactment of Companies Act, 2013, paved the way for IFRS-converged Ind AS environment as it incorporated various provisions compatible with the requirements contained in IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS).

The Hon'ble Finance Minister of India, Shri Arun Jaitley, in his Budget Speech in July, 2014 stated that –

“There is an urgent need to converge the current Indian accounting standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS). I propose for adoption of the new Indian Accounting Standards (Ind AS) by the Indian companies from the financial year 2015-16 voluntarily and from the financial year 2016-17 on a mandatory basis. Based on the international consensus, the regulators will separately notify the date of implementation of Ind AS for the Banks, Insurance companies etc. Standards for the computation of tax would be notified separately”.

Pursuant to the above announcement, various steps have been taken by the ICAI to facilitate the implementation of IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS).

In this regard, it is worthwhile to note that the convergence is a continuous process. Accordingly, the ICAI has been constantly working towards convergence with IFRS. In order to remain converged with IFRS, Ind ASs were formulated/ revised on the basis of the amendments and new IFRS issued by the IASB subsequent to hosting of Ind AS on MCA's website in 2011. These new/ revised Ind AS finalised by the ICAI were submitted to National Advisory Committee on

Accounting Standards (NACAS) which has been reconstituted till the constitution of National Financial Reporting Authority. After consideration and recommendation by NACAS, these Ind AS have been notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) as Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 vide Notification dated February 16, 2015.

As requested by the Ministry of Corporate Affairs, it has also been decided to upgrade the existing Accounting Standards (AS) to bring them nearer to Ind AS. These AS would apply to entities to which Indian Accounting Standards (Ind ASs) would not apply, i.e., primarily the unlisted entities having turnover less than Rs. 250 crores. The Approach of upgrading the existing Accounting Standards in phased manner for the Second Set of accounting standards has been finalized. The existing Accounting Standards are being revised.

The ASB with a view to mark Indian presence internationally and raise various issues faced by the Indian economy, being a developing economy, is also participating and contributing in various research activities undertaken by the International Accounting Standards Board and other bodies such as Asian Oceanian Standards Setters Group (AOSSG), International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) and Emerging Economies Group (EEG).

A brief overview of various activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

Formulation/Revision of Indian Accounting Standards (Ind ASs)

During the year, Accounting Standards Board finalised the following amendments to Indian Accounting Standards (Ind ASs) corresponding to the amendments to IASs/IFRSs and formulated new Ind AS corresponding to new IFRSs:

- Indian Accounting Standard (Ind AS) 101, *First-Time Adoption of Indian Accounting Standards*
- Indian Accounting Standard (Ind AS) 109, *Financial Instruments*
- Indian Accounting Standard (Ind AS) 115, *Revenue from Contracts with Customers*
- Further Amendments to Indian Accounting Standards (Ind ASs): Consideration of Carve outs/ins
- Amendments to Indian Accounting Standards (Ind ASs): Consideration of Carve outs/ins
- Agriculture: Bearer Plants (Amendments to Ind AS 16) (corresponding to Bearer Plants: Amendments to IAS 16)
- Indian Accounting Standard (Ind AS) 41 *Agriculture* (corresponding to IAS 41)
- Indian Accounting Standard (Ind AS) 114, *Regulatory Deferral Accounts* (Corresponding to IFRS 14)
- Amendments to Ind AS 16 And Ind AS 38 (Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation) (Corresponding to Amendments to IAS 16 And IAS 38)
- Striping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (Amendments to Ind AS 16) (corresponding to IFRIC 20)
- Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to Indian Accounting Standard (Ind AS) 111, *Joint Arrangements* (Corresponding to Amendments to IFRS 11)
- Amendments to Indian Accounting Standards (Corresponding to Annual Improvements to IFRSs 2011-13 Cycle)
- Amendments to Indian Accounting Standards (Corresponding to Annual Improvements to IFRSs 2010-12 Cycle)
- Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to Ind AS 19)
- Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to Ind AS 39)
- Amendments to Indian Accounting Standards
- Appendix B-1, *Levies*, to Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
- Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to Ind AS 36)
- Investment Entities (Amendments to Ind AS 110, Ind AS 112 and Ind AS 27)
- Amendments to Indian Accounting Standard (Ind AS) 107 *Financial Instruments: Disclosures*
- Amendments to Indian Accounting Standard (Ind AS) 32 *Financial Instruments: Presentation*

Revision of existing Accounting Standards (ASs)

During the year, Accounting Standards Board has finalised the Draft of *Revised AS 10, Property, Plant and Equipment*

Contribution to the Activities of the International Accounting Standards Board (IASB) and Participation in Other International Developments

The Board interacts with the IASB at various levels, such as:

- Active participation in the meetings of the World Standard-Setters (WSS) and Regional Standard-Setters with the IASB. ICAI representatives participated in the World Standard Setters Meeting held on 29th-30th September, 2014, at London. At the meeting, apart from updates on various IASB projects, discussion on

- various technical topics such as Conceptual Framework, Disclosure Initiative, Revenue, Rate Regulated Activities, etc., took place. The Indian representatives also raised various technical issues with regard to IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, Discussion Paper on Rate Regulated Activities, etc.
- The Board circulates and hosts on the website, various Exposure Drafts/ Discussion Papers issued by the IASB for comments by various stakeholders.
 - The Board is regularly examining the progress made by IASB in respect of the various projects, such as:
 - (i) Leases
 - (ii) Insurance Contracts
 - (iii) Rate-regulated Activities
 - (iv) Conceptual Framework
 - The ICAI representatives participated in the following meetings of Emerging Economies Group (EEG) of the IASB:
 - (a) Seventh meeting of EEG held on 28th-29th May, 2014 in Moscow, Russia. At the meeting, discussion of various technical topics such as equity method of accounting, conceptual framework took place. The ICAI proposed to present a short paper on the Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) to highlight the Indian concerns relating to the accounting treatment given under IAS 32.
 - (b) Eighth meeting of EEG held on 11th-12th December, 2014, at Jakarta, Indonesia. At the meeting, a presentation on the subject 'Accounting for Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs)' was made by the ICAI representatives. At the meeting, discussion on various technical topics such as accounting for extractive activities, non-financial assets etc., took place.
 - (c) Ninth meeting of EEG held on 25th-26th May, 2015 at Mexico City: At the meeting, amongst others issues in 'Present Value Measurement in IFRS' were discussed.
 - A meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) was held on 30th September and 1st October, 2014 at London, UK. At the meeting, a presentation on the subject '*Income recognition during Construction Phase under IFRIC 12*' was made by the ICAI representatives. At the meeting, discussion on various technical topics such as equity method of accounting, employee benefits, cash flow statements took place.
 - ICAI representative also made a presentation on '*Accounting and Financial Reporting System in India*' at the International IFRS Seminar held on 27th May, 2014 at Moscow, Russia.
 - ICAI representatives participated at the IFRS Conference held on 23rd-24th, June 2014 in London, United Kingdom. At the Conference, discussion on various topics such as Conceptual Framework, Leases, Equity Method, Financial Instruments, etc., were discussed in detail.
 - Sixth meeting of Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) was held on 26th-27th November, 2014 at Hong Kong. The ICAI representatives participated at the meeting. At the meeting, a presentation on the subject '*IFRS convergence in India- an update*' was made by the ICAI representatives. At the meeting, discussion on various technical topics such as emission rights, conceptual framework, rate regulated activities, etc., took place.
 - An interim meeting of the AOSSG members was held on 28th September, 2014, at London. From India, ICAI representatives attended the meeting. At the meeting, discussion on various technical topics such as *Financial Instruments*, IFRS 15, *Revenue from Contracts with Customers*, etc., took place.
 - The ICAI representatives participated in a teleconference of the CAC of AOSSG held on 28th April, 2014 and 23rd July, 2014. At the teleconference, along with the draft of AOSSG strategic plan, the Agenda for the various upcoming meeting and events of the AOSSG was discussed in detail.

Comments on the following IASB Exposure Drafts/ Discussion Papers were sent to the IASB:

- (a) Exposure Draft on Effective Date of IFRS 15 Proposed amendments to IFRS 15
- (b) Exposure Draft of Measuring Quoted Investments in Subsidiaries Joint Ventures and Associates at Fair Value
- (c) Exposure Draft on Disclosure Initiative: Proposed Amendments to IAS 7
- (d) Exposure Draft on Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
- (e) Exposure Draft on Classification of Liabilities, proposed amendments to IAS 1
- (f) Discussion Paper: Reporting the Financial Effects of Rate Regulation
- (g) Exposure Draft on Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Proposed amendments to IAS 12)

- (h) Exposure Draft Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Proposed Amendments to IFRS 10 and IAS 28)
- (i) Draft of Disclosure Initiative (Proposed amendments to IAS 1)

Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI, through ASB, interacts with various regulatory bodies from time to time and expresses its views on various accounting matters.

The ICAI on the request of Ministry of Corporate Affairs has also recommended to the Government revised Roadmap for the applicability of Indian Accounting Standards (Ind ASs). The ASB also held meetings with the officials of the various regulators such as RBI, SEBI, C&AG to discuss the revised roadmap for the applicability of Ind AS.

In addition to the above, regular meetings are held with MCA on various accounting issues.

- An interactive meeting on implementation of Ind AS was organised by the ASB on 15th January, 2014 at Mumbai, inviting various interested stakeholders to identify any implementation issues which may be encountered by them so that the Board may provide necessary guidance and/or any other assistance in this regard. More than 40 members from more than 20 companies attended the meeting.
- A one-day Awareness Programme on IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) was held on 7th February, 2015, at Mumbai. Representatives of various companies were invited with a view to create awareness about the upcoming Ind ASs and to identify any implementation issues, for smooth implementation of Ind AS in the country. 63 representatives from approximately 40 companies attended the Programme at which salient features of new Ind AS were covered.

Other Projects

Other Documents under consideration.

- Guidance Note on Accounting for *Service Concession Arrangements by the Concessionaires*
- *Upgradation of the set of the existing Accounting Standards to bring them nearer to Ind ASs*
- Updation of Indian Accounting Standards
- Guidance Note on Issues arising from application of Schedule II to the *Companies Act, 2013*.
- Formulation of Ind AS compliant Schedule III to the *Companies Act, 2013* for Non Banking Financial Institutions.
- Formulating Ind AS-compliant Illustrative financial statements.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The ICAI, being a premier accounting body in the country, is also involved in the on-going accounting reforms in the Government, particularly at the local body level. For this purpose, ICAI constituted the Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in the year 2005 with the main objective to formulate the Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs). Since its inception, the Committee has issued '*Preface to the Accounting Standards for Local Bodies*' and eleven ASLBs out of which four ASLBs have been issued during the current Council year. These ASLBs are recommendatory in nature and will become mandatory for the Local Bodies in a State from the date specified by the State Governments concerned. Many other ASLBs are at different stage of finalisation.

Other Publications of the Committee include Status Paper on '*Accounting Reforms in Local Bodies in India and Role of Chartered Accountants*' and English and Hindi versions of Booklet on '*Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives and Stakeholders*'.

Apart from formulation of ASLBs, CASLB is also involved in creating awareness amongst the Local Bodies and various Stakeholders such as end users and citizens about the benefits of accounting reform process in Government and Local Bodies. In this regard, various workshops have been organised in collaboration with the Ministry of Urban Development.

The President, ICAI, is a member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) since its inception. Technical Director, ICAI acts as Technical Advisor to the President, ICAI, in GASAB. President, ICAI along with Technical Director, ICAI, participates in the meetings of the GASAB and contributes to the technical activities of the Board.

Brief note on the important activities of the Committee on Accounting Standards for Local Bodies during the period (April 1, 2014 to July 7, 2015) is as follows:

Publication Released:

- Compendium of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs)

ASLBs Issued:

- ASLB 3, 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors'
- ASLB 17, 'Property, Plant and Equipment'
- ASLB 19, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'
- ASLB 31, 'Intangible Assets'

5.3 Audit Committee

The constitution of Audit Committee of the ICAI is governed by the Council. The Council, in the year 2001, had constituted the Audit Committee as a non-standing Committee. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the ICAI to ensure that the financial statements are true and fair. The ICAI has five Regional Audit Committees at each of the Regional Council. The Audit Committee ensures the independence and integrity while appointing auditors at various regions of the ICAI. The Committee reviews the Internal and Statutory Audit Reports of all the regions/ various units and holds regular interaction with the auditors as well as with the auditee departments to ensure adequacy of internal control within the ICAI.

5.4 Auditing & Assurance Standards Board

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to growing complexity of business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the various stakeholders.

The ICAI recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively. The ICAI through its Auditing and Assurance Standards Board develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. These Standards not only codify the best practices in audit, they also provide the benchmark against which the performance of the auditors can be measured. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing, with the prime objective of providing guidance to the auditors. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council of the ICAI. The auditing standards issued by the ICAI are harmonized with the International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance to the members in the implementation of Standards on Auditing, the Board also brings out Implementation Guides to those Standards. The following is a comprehensive overview of important achievements of the Board till date:

Engagement and Quality Control Standards

- ◆ Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"
- ◆ 37 Standards on Auditing
- ◆ 2 Standards on Review Engagements
- ◆ 2 Standards on Assurance Engagements
- ◆ 2 Standards on Related Services

Statements on Auditing

- ◆ 2 Statements on Auditing

Guidance Notes on Auditing

- ◆ 30 Guidance Notes on Auditing

Publications**Industry Specific Guidance Notes**

- ◆ Audit of Banks
- ◆ Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges
- ◆ Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
- ◆ Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business

Implementation Guides

- ◆ Implementation Guide on Reporting Standards (SA 700, SA 705 and SA 706)
- ◆ Implementation Guide to SQC 1
- ◆ Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements
- ◆ Implementation Guide to SA 530, Audit Sampling
- ◆ Implementation Guide to Materiality in Planning and Performing an Audit

- ◆ Implementation Guide to SA 230, Audit Documentation
- ◆ Implementation Guide to SA 501, Audit Evidence - Specific Considerations for Selected Items
- ◆ Implementation Guide to SA 570, Going Concern
- ◆ Compendium of Implementation Guides (As on 1st July, 2013)

TECHNICAL GUIDES / GUIDES

- ◆ Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies
- ◆ Technical Guide on Audit in Hotel Industry
- ◆ Technical Guide on Audit in Automobile Industry
- ◆ Technical Guide on Audit in Telecom Industry – Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs
- ◆ Technical Guide on E-Commerce - Considerations for Audit of Financial Statements
- ◆ Technical Guide to Audit in a Shared Service Centre Structure
- ◆ Compendium of Industry-specific Audit Guides (As on 1st September, 2013)
- ◆ Practitioner's Guide to Audit of Small Entities
- ◆ Guide to Audit of Complex Financial Instruments
- ◆ Guide to Reporting on Proforma Financial Statements (Pursuant to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009)

STUDIES

- ◆ A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective
- ◆ A Study on Basel II and Risk-based Supervision

OTHER PUBLICATIONS

- ◆ Handbook of Auditing Pronouncements 2014 edition
- ◆ Background Material for Audit Training Workshops and Seminars
- ◆ What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements
- ◆ Convergence with the International Standards of IAASB: Position Paper and Work Plan

The Year 2014-15

- Six meetings of the Board were held during the year.
- The Board brought out a number of important publications, e.g, Handbook of Auditing Pronouncements 2014 edition, Background Material for Audit Training Workshops and Seminars 2014 edition, Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (*The Guidance Note is currently under revision*), Guidance Note on Audit of Banks 2015 edition, Guidance Note on Reporting on Fraud under Section 143(12) of the Companies Act, 2013, Guidance Note on Reporting under Section 143(3)(f) and (h) of the Companies Act, 2013.
- The Board organised a number of seminars, workshops on auditing standards and auditing aspects across the country. Programmes were held at Alwar, Siliguri, Lucknow, Delhi, Kolkata.
- The Board issued the Revised Standard on Review Engagements (SRE) 2400, 'Engagements to Review Historical Financial Statements'.¹
- The Board issued the Revised Standard on Related Services (SRS) 4410, 'Compilation Engagements'.²
- The Board issued the Illustrative Formats of the Independent Auditor's Report under the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder.
- The Board issued the Illustrative Formats of the Audit Engagement Letter under the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder.
- The Board issued the following announcements for guidance of the members:
 - CARO 2003 and Additional Reporting under the Companies Act, 2013.
 - Clarification on Auditor's Report in respect of Financial Statements of a Company for Accounting Years Beginning Before 1st April, 2014.
 - Guidance on Reporting under the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 (CARO, 2015) and Consequential Amendment to the Format of the Auditor's Report of a Company.
 - Auditor's Report on Consolidated Financial Statements under the Companies Act, 2013.
 - Applicability of the Provisions of Section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013 and the Related Rules.
 - Applicability of the Provisions of Section 143(12) of the Companies Act, 2013 and the Related Rules to Periods beginning on or before 31st March, 2014.
 - Applicability of Section 143(12) to Financial Years beginning on or after 1st April, 2014.
 - Manner of Reporting by the Auditors in Respect of RBI's Circular on Deferred Tax Liability on Special Reserve created under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961
 - Applicability of the Companies Act, 2013 to Auditor's Report to FY 2014-15 and onwards.

¹ Under finalisation.

² Under finalisation.

- Chairman, AASB represented the ICAI at the annual IAASB-NSS meetings held at New York in May, 2014 and May, 2015.
- The Board submitted to the RBI, the draft Format of the Auditor's Report of Urban Cooperative Banks.
- The Board submitted to the SEBI, the Draft Format of the Auditor's Report on financial information to be included in the Proposed Annual Information Memorandum (AIM) as technical inputs from AASB.
- The Board submitted the draft format of auditor's report under service tax law to Indirect Tax Committee for submission to the Central Board of Excise and Customs.
- The Board submitted to the Ministry of Corporate Affairs, the following representations under the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder:
 - List of issues requiring clarification regarding reporting on Internal Financial Controls under Section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013.
 - List of issues requiring clarification and suggested materiality threshold regarding reporting on frauds under Section 143(12) of the Companies Act, 2013.
 - Issues regarding Forms prescribed in the Rules issued under the Companies Act, 2013.
 - ICAI's views on Order to be issued under Section 143(11) of the Companies Act, 2013 in respect of Financial Year 2014-15.
 - Various issues in the auditor's report on consolidated financial statements.

Projects under Progress

In addition to these, the Board also undertook several other projects during the year.

Other Initiatives and Development

Interaction with Regulatory Bodies

The Board regularly interacts with the various regulators and Government institutions/ Ministries such as Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to discuss critical issues relating to auditing standards, formats of audit reports/certificates, other auditing aspects.

Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments

The ICAI is actively involved in the developments taking place at international level. The ICAI being the founder member of the International Federation of Accountants (IFAC), the Board, through its Chairman remained in touch with the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the IFAC and provided its inputs to the IAASB from time to time. Chairman, AASB represented the ICAI at the annual IAASB-NSS meetings held at New York in May, 2014 and May, 2015. At the May, 2014 meeting, Chairman, AASB made a presentation on "Audit of Banks" in the context of Agenda Item on "Audit of Financial Institutions" of the Agenda of the said meeting. The ICAI representative also contributed his views on all the other items of the Agenda. In addition, the Board also submits comments on the various exposure drafts issued by the International Auditing and Assurance Standards Board.

Creating Awareness and Capacity Building

Creating awareness on auditing standards among the members was one of the main agenda for the Board during the year 2014-15. In this process, to facilitate one to one interaction with the members on issues faced by them in auditing and also to impart knowledge on auditing standards issued by the ICAI, the Board organised a number of seminars, workshops etc. on auditing standards and auditing aspects at various places across the country.

Future Strategy and Work Program

The Board will focus on creating awareness about auditing standards among the members. For this purpose, the Board will adopt two prong strategies. It will organise seminars/ training programs/ workshops on auditing standards and other auditing aspects and will continue to issue implementation guides to Standards so as to help the members to better understand and implement the Standards. The Board will also develop other technical literature on auditing like Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Other Guides to guide the members on auditing issues, generally as well as in specific industry sectors.

5.5 Committee on Banking, Insurance & Pension

- The Chairman and Vice-Chairman of the Committee on Banking, Insurance & Pension met Shri Hemant G. Contractor, Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority and other members/ senior officers of PFRDA and discussed among others, various matters related to establishing a sound monitoring and compliance management system for various intermediaries involved in management of various Pension Schemes which inter alia auditing of activities of the intermediaries and reporting on compliance with guidelines and directions issued by the PFRDA/ NPS Trust from time to time.

- The Chairman of the Committee met Shri Anup Wadhawan, Joint Secretary, Department of Financial Services (Ministry of Finance) to discuss various issues related to banking, insurance and pension sector and matters of mutual interest.
- Considering the specific request of PFRDA, the Chairman of the Committee and a member of the Committee, have been nominated as member to the Pension Advisory Committee and Sub-Group constituted by the PFRDA respectively.
- The Chairman of the Committee met CA. S.N. Jayasimhan, Joint Director (Investment) of IRDAI to discuss various matters of mutual interest.
- A meeting with select experts of insurance sector was organised for inviting suggestions on revising the Course material of the DIRM Course.
- The Committee organised a two days' National Conference for members on the theme "Rising to the Challenges – Redefining our Role" on 30th-31st December, 2014 at Birla Auditorium, Jaipur jointly with the Committee on Public Finance and Government Accounting of ICAI which was hosted by Jaipur Branch of CIRC of ICAI. The Conference was attended by more than 3700 members from across the country.
- The Committee organised a Seminar on "Unlocking the Potential in Insurance and Pension Sector" on 26th June, 2015 in Kolkata. The seminar was hosted by Eastern Indian Regional Council of ICAI. The programme was addressed by Dr. B.S. Bhandari, Member, PFRDA, Shri A. Ramana Rao, Jt. Director (Inspections), IRDAI, Shri M. Vasantha Krishna, Director & General Manager, National Insurance Co. Ltd., Shri Sohanlal Kadel, President, Insurance Brokers Association of India, amongst other dignitaries.
- The Committee was conference partner of Indian Merchants' Chamber for the conference "Indian Banking at the Crossroads - Challenge of Risk Management from Globalisation to Financial Inclusion" held on 8th May, 2014 at Hotel Taj President, Mumbai.
- A webcast on Bank Loan and Advances and Regulatory restrictions under the Banking Regulations Act, 1949 and by Reserve Bank of India was conducted on 2nd May, 2015.
- A webcast on "Audit of Non Banking Finance Companies and National Pension System – A Journey towards New Era" was conducted on 29th June, 2015 to provide guidance to members on audit of non banking finance companies and to spread awareness of National Pension System amongst members and others concerned.
- To foster the initiatives of IRDAI in spreading the insurance awareness in general public, the Committee has been organising insurance awareness programmes through Regional Councils/ Branches of ICAI. Details of the insurance awareness programme organised during the period is given below:

S.No.	Name of the RC/Branch	Date and Place
1.	Dhule Branch of WIRC of ICAI	16 th April, 2014 at Dhule
2.	Salem Branch of SIRC of ICAI	19 th April, 2014 at Salem
3.	Siliguri Branch of EIRC of ICAI.	10 th May, 2014 at Siliguri
4.	Bikaner Branch of CIRC of ICAI	25 th June, 2014 at Bikaner
5.	SIRC of ICAI	16 th October, 2014 at Chennai
6.	Guwahati Branch of EIRC of ICAI	20 th June, 2015 at Guwahati

- An article "Insurance Sector – Anchoring Economic Growth" submitted to IRDA for inclusion in the booklet titled "Vision 2025 for Insurance Sector", a compilation of thoughts from senior officials/ experts who have contributed to the industry proposed to be brought out on the occasion of the "Insurance Awareness Day".
- The Committee uploads daily news update in banking, insurance and pension at the homepage of the Committee at ICAI Website for the information of all concerned.
- The Committee brought out its PR Kit for disseminating the information of the functioning of the Committee amongst various stakeholders of banking, insurance and pension sector. The PR Kit was sent to senior functionaries of Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, banks, insurance companies, Pension Fund managers, Mutual Funds and other stakeholders of the financial sector.

- **Post-Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management**

- The Committee organized five batches of the Orientation Programme for the DIRM Technical Examination passed members whose detail is given below:-

Sl.No.	Date	Place
1.	28 th April – 3 rd May, 2014	Noida
2.	12 th – 17 th May, 2014	Mumbai
3.	17 th – 22 nd November, 2014	Kolkata
4.	11 th – 16 th May, 2015	Mumbai
5.	25 th – 29 th May, 2015	Kolkata

- Suggested Answers for the DIRM Technical Examinations held in November, 2014 prepared and hosted at ICAI website for the benefit of the members pursuing the DIRM Course.
- The total number of registrations to the Post Qualification Course of Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) Course has reached to 4690 as on 10th July, 2015.

5.6 Committee for Capacity Building of Members in Practice

Overview

The Committee for Capacity Building of CA Firms of Members in Practice is a non-standing Committee of the ICAI formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. This Committee was established for facilitating consolidation and capacity building of CA firms in order to address various problems faced by CA firms and to conceptualize and implement various measures for strengthening their capacity as well as developing comprehensive guidelines for consolidation of CA firms. Similarly, the Committee also aims to empower Small & Medium Practitioners to assimilate and apply ways for carrying out their profession in efficient & competitive manner. The Committee also focuses to enable our members in industry for development of soft skills.

Initiatives

A) **Financing**

Arrangement of specialised loan scheme for Members of ICAI & Educational Loan Scheme for students of ICAI

The Committee has taken a major initiative for arranging the specialized loan scheme for the members of ICAI & arrangement of Educational Loan scheme along with Board of Studies of ICAI for the students. The women members & students would avail 1% discount in the aforesaid scheme from the prevailing rate of interest offered by Bharatiya Mahila Bank Ltd., New Delhi.

Specialised loan scheme ‘Corp CA’ Scheme

The Committee has taken a major initiative to arrange financial assistance to all members in practice /firms in the form of specially designed loan scheme through Corporation Bank. Through the scheme, eligible Chartered Accountants can avail finance for setting up of offices including cost of furniture/ fixture/ office equipments-computers and other accessories.

B) **Promotion Practitioners’ Capacity**

Compliance

Busy Accounting Software at special price

The Committee has arranged Busy Business Accounting Software at special price for the members. The offer price for Members of ICAI at Rs.4,500/- + applicable Taxes. The vendor company has also offered 50% discount on all upgrades.

IT Auditor software at special price

The Committee has arranged IT auditor software i.e. a Income Tax compliance with e-filing of Tax Audit Report at special price for practicing members & CA Firms. The offer price for members of ICAI at Rs 2,100/- for first assessment year. License renewal charges Rs 2,100/- plus applicable taxes.

Cloud based Service Tax, TDS & PDF Signer software at special price

The Committee has arranged cloud based Service Tax, TDS & PDF Signer software i.e. online TDS and Service TAX software along with PDF signer to digitally sign the documents at special price of Rs 2,100/- for first assessment year for practicing members & CA Firms of ICAI. License renewal charges Rs 2,100/- plus applicable taxes.

Indian Financial Reporting Manager (IFRM) at special price

As an ongoing attempt to enable the members to keep pace with the latest developments in financial reporting, the Committee has arranged the IFRM, the web based research & solutions kit to the members at a special price of Rs.3500 plus taxes per user per year. List price of India Financial Reporting Manager is Rs.9995 plus taxes per user per annum.

ICAI-Tax Suite: A Tax Compliance software

The Committee has arranged to provide the Tax Compliance software namely 'ICAI-Tax Suite' for the Practitioners & CA Firms, which combines facility for Income Tax, TDS, Audit Reports, Project Report/ CMA, Form Manager, AIR (Annual Information Return), Service Tax and Document Management.

XBRL software

The Committee has arranged the software on XBRL named as ICAI-XBRL software to provide the CA Firms for MCA mandate XBRL filing. The XBRL software is a solution for converting financial information of a Company in XBRL format as per MCA mandate.

Litigation**CTR Library for Direct Taxes at Special price**

As an ongoing attempt to enable the members to keep pace with the latest developments in Direct Tax Cases, the Committee has arranged to provide single DVD of CTR Library of Tax Cases - comprehensive coverage on direct taxes to the members at a special price of Rs.1500/- including all the applicable taxes (valid for one year) along with the Direct Tax Tracker. List price of single DVD of CTR Library of Tax Cases is Rs.3600/-.

(C) Office Management**Arrangement of the 'Quick Heal Total Security for Android enabled Mobile phones' software at special price for the Members & Students of ICAI**

The Committee has made an arrangement for Quick Heal Total Security for Android enabled Mobile phones' software for the members & students of ICAI from M/S Quick Heal Technologies Pvt. Ltd., Pune at discounted price. The price of the aforesaid software is Rs 250/- plus applicable taxes for 2 years.

(D) Social Security**Office Protection Shield Insurance**

The Committee has Office Protection Shield Insurance for members. The scheme has become effective from 18th September, 2013 for the Members in practice/firms. Members and CA firms desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may please visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.

Health Insurance Scheme for Members

The Committee has taken a major initiative for arranging in the form of specially designed Health Insurance Scheme with the special features like no health check-up, no age limit & entry barrier, premium discount in lieu of cumulative bonus, 5% discount in premium to be paid to the insurance company, where the member has not preferred any claim in the expiring policy in case of renewal of the policy, wide coverage for pre-existing diseases etc. for members & students. The scheme has been effective from 12th March, 2013 for the members. For details, member can visit <http://icai.newindia.co.in>, to apply online for insurance policy & to view other formalities as well as details about the aforesaid insurance scheme.

Professional Indemnity Insurance for Members & CA Firms

The Committee has arranged insurance protection for members in practice/ firms in the form of specially designed professional indemnity insurance at a reasonable premium i.e. 85% discount in market rate. For details, members can visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.

Motor Insurance at Special premium for members

Motor Insurance scheme is made available for vehicles of members on discounted rate with further 55% discount on own damage premium irrespective of the previous claims in respect of private four wheelers and two wheelers. The facility

for online purchase of the motor policy for ICAI members has been enabled, the link for ICAI members to buy online policies on the link: <http://www.orientalinsurance.org.in/BuyNewWeb/faces/AvailablePolicies.jsp>

Personal Accident Insurance for Members

The Committee has taken a major initiative for arranging in the form of specially designed Personal Accident Insurance through the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi for Members.

Householder's Insurance for Members

The Committee has taken a major initiative for arranging in the form of specially designed householder's insurance through the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi for Members of ICAI.

(E) Knowledge sharing & Enhancement

ICAI Connect – A self service portal for members of ICAI

The Committee has launched the ICAI Connect, a self service portal for the members. The features of the aforesaid single window self service portal includes viewing personal profile and firms constitution, Announcements of ICAI, details of payments of fees and regulatory charges to ICAI, My Articles details, tracking regulatory forms and application status, e-Services, My Firms, My Software(s), Letters & Certificates, CPE Hours credited, Guidelines of Networking, Merger & Demerger etc.

e-Samadhan portal for resolving the professional queries raised by members of ICAI

The Committee has launched the e-Samadhan portal for resolving the professional queries of the members. The empanelled professionals will answer the queries raised by the members in various areas of the profession. Members need to log in to SSP and click on 'e-samadhan' to register their query.

Committee's exclusive website - www.icaai.org.in

The Committee has developed a website namely - www.icaai.org.in, where the firms and practitioners may create their portals as per the norms laid down by the Council of the ICAI. The website provides a platform for the CA Firms to upload their firms' details and gives them an opportunity to reach out to the members and CA firms practicing worldwide. As on 3rd February, 2015, more than 6852 CA firms have created their websites in the aforesaid website.

The website also acts as a forum for consolidation of the members and CA Firms by providing for consolidation measures like Networking, Merger and Corporate Form of Practice. The members may visit portals of other members and firms and like-minded persons may join hands to grow big to compete in the international front.

A portal for Senior Members - www.seniormembers.icaai.org

The Committee has developed a website namely, seniormembers.icaai.org. The website provides a platform for senior members for getting flexi working hours assignment as well as fulltime assignment after their retirement. At the same time, it will also help industry to tap experienced talent pool which might not be accessible otherwise in normal course. The said portal would be useful & handy to all the senior members.

“Practiquer”- Quarterly e-Newsletter for the Chartered Accountants

The Committee has taken an initiative to bring out an e-Newsletter quarterly for the CA fraternity, highlighting the latest developments in the profession. The e-Newsletter is a perfect tool which will provide the Chartered Accountants with all requisite information. It compiles information on all important areas of the profession and will be of great benefit to the members.

‘CA Professionals & SMEs in Make In India: A handbook for the Practitioners’

The Committee has published a book on ‘CA Professionals & SMEs in Make In India: A handbook for the Practitioners’. The Committee has brought out this book to provide the members with insight into the role of CA professionals in Make in India in tune to the objective of the mission “Make In India” for providing conducive environment for investment in India & aimed at reviving the job-creating manufacturing sector — key to taking the economy on a sustainable high growth path.

“Handbook on Project Financing as an area of practice for Small and Medium Practitioners”

CAs generally carry out high quality industry research and analysis because of their strong foundation in Commerce and economics. This helps CAs in rationally evaluating the risks associated with any project financing deal being evaluated. The Committee has brought out the book on ‘Handbook on Project Financing as an area of practice for Small and Medium Practitioners’ for the same.

E-book on Quick Insight

The Committee has taken an initiative to prepare and publish E-book on 'Quick Insight 2014'. The Quick Insight contains important information on tax, accounting & auditing standards, limited liability partnership, management consultancy services, statements and standards and standards on audit as well as information on important forms related to CA students.

(F) Networking & Merger

Revised Guidelines of Network

The Committee has considered practical difficulties in consolidation of CA firms through medium of Networking. The Committee has appropriately finalized the revised Guidelines of Networking facilitating members and firms for its easy adoption. The details of the Revised Guidelines of Networking is available at http://www.icai.org/post.html?post_id=7710. The details of the Rules on Merger is uploaded at www.icai.org.in.

(G) Brochure on Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities

The Committee has prepared a Brochure on Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities. The aforesaid Brochure is already circulated to the CA Firms in India for their reference.

(H) Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning

The Committee has launched the Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning at Mumbai on 8th February, 2015. The objective of this Course is to equip the members with the principles of Management of Wealth as well as devising effective investment strategy and the practical procedural aspects and to build the competency level of the members to position them as multidisciplinary financial consultants.

Professional Development Programmes held by the Committee since 1st January 2015

- 3 CPE hours training programme on Capacity Building Measures of CA Professionals with special focus on CAs in Make in India at Kerala on 15th January, 2015
- 6 CPE hours National Seminar on CA Professionals in Make in India & Swachh Bharat on 7th February, 2015 at ICAI Bhawan, Dhanbad, Jharkhand.
- Summit on Capacity Building Measures of Practitioners with special focus on Make in India on 7th February, 2015 at R Singhi Hall, EIRC Premises, Kolkata.

5.7 Continuing Professional Education Committee

The ICAI has all along endeavored to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe, in this ever changing economic environment, through the process of continuous skill honing, in the form of continuous learning by way of classroom teaching, e-Learning mode, in-house Executive Development Programmes, teleconferences, awareness programmes and webinars, seminars and conferences etc.

To keep pace with the global requirements, CPE requirements have been made mandatory for all the members of the ICAI, whether he/she be in practice or service and such system is measured, monitored and managed scientifically.

Major initiatives taken by the CPE Committee

- Increase in financial assistance available to Regional Council and their Branches by way of reimbursement of expenditure only for organizing CPE National Programmes and Non-National Programmes under the aegis of CPE Committee.
- The Committee has finalised the following topics for bringing out Background Materials so as to have uniform delivery of Technical Material for the CPE Programmes /Chain Seminars to be organized by POU:-

S.No.	Details of Topic
1.	GST
2.	ICDS
3.	Companies Act 2013 - Reporting Requirements and CARO
4.	Standards on Auditing - Mandatory under Companies Act 2013
5.	Accounting Standards - Ind AS

6.	Transfer Pricing and International Taxation (Basic level for 'B' cities & Advance level for 'A' cities)
7.	Risk Based Internal audit
8.	Depreciation under new Companies Act, 2013
9.	Compliance requirements for Pvt Ltd Companies under new Companies Act
10.	Checklist of major compliances – (i) by Companies (ii) by Auditors while carrying out the audit of corporates along with penal provision thereto
11.	Related party transactions, disclosures and implications
12.	Provisions relating to acceptance of deposits and loans by Corporates under Companies Act, 2013
13.	Loans to Directors, subsidiaries, associates, related parties and others
14.	FEMA – compliance requirements and restrictions on foreign Nationals and Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin (PIOs)
15.	Taxation of Non-Resident Indians
16.	Service Tax – Issues on Cenvat Credit
17.	Service Tax – Issues on Negative List
18.	Anti-Money laundering
19.	Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)
20.	Forensic Accounting and Audit
21.	Income Tax – TDS (issues and controversies)
22.	Income Tax – Survey, search and seizure
23.	Taxation and Real Estate Transactions
24.	Recent Decision – Indirect Tax Laws
25.	Issues in Capital Gains
26.	Assessment of Business Income
27.	Place of effective management in determining the residence of companies and taxation of non-resident Companies.

- The CPE Committee has sent an intimation to all the Study Circles communicating them the following decision of the Council –

“That the Council of the Institute has decided that while determining the service tax liability of the ICAI in regard to the CPE programmes conducted, the service tax liability in relation to the activities carried out by the Study Circles shall not be accounted for and that the service tax liability in regard to the activities carried out by the Study Circles shall be borne by the study circles themselves and while doing so the study circles shall not use the Service Tax Registration Number and PAN Number of the ICAI rather they will obtain their separate service tax registration and PAN Number for all related compliances. Every Study Circle shall itself ensure all the tax related compliance e.g. separate tax registration if the total turnover exceeds the threshold limit of Rs. 10 Lacs.”

- The Committee decided that a member who acts as a faculty in a CPE programme will be granted CPE hours credit twice of the quantum of the duration of technical sessions subject to a maximum of 4 hours per CPE programme.
- The CPE Committee has implemented the Standardized Policy/ Guidelines/ Parameters for conducting the Certificate Courses by the Central Committees. The same have also been hosted on the ICAI Website and on the CPE Portal. A communication has been sent to all members of the Council and to the Secretaries of all the non-standing Committees of ICAI.
- The Committee decided to grant exemption on temporary basis for one calendar year to female Chartered Accountants on the grounds of pregnancy on receipt of a request from them.
- The Committee decided to grant exemption from Structured Learning on case to case basis to differently-abled Chartered Accountants on receipt of a written request from them duly forwarded by the concerned Regional Council. The Committee further decided that permanent disability means those persons who are having not less than 40% of any permanent disability. The applicant is required to submit a medical certificate issued by competent medical authority i.e. any hospital or institution specified for this purpose by the government, as defined under the Income Tax Act.
- The Chairman of the CPE Committee has sent a communication to all the Study Circles to adhere to the compliance of the norms with regard to the terms of the Convenor and Dy. Convenor of the Study Circles.

CPE Calendar

The Committee has finalised the CPE Calendar for the year 2015-16 which contains 600 topics on various areas of professional interest. The same has been hosted on the Website of ICAI for information of all.

E-Newsletter

Five editions of the quarterly e-newsletter (CPE Bulletin) have been brought out since April, 2014 onwards and the same have been hosted on the website of ICAI.

Monitoring of Continuing Professional Education Programmes

Chairman, CPEC has reconstituted the CPE Regional Monitoring Committees for the year 2015-16 in all the 5 regions.

Transparency in Continuing Professional Education Programmes

The Committee has also addressed the issue of transparency in CPE programmes. The Committee introduced Management Information System on the CPE Portal using IT Tools to increase the awareness in public about the various activities performed and major events being taken up by the ICAI. This enables the members to view a city wise list of the forthcoming CPE programmes with the contact details of the POU's for registration.

Conducting of Survey

To conduct survey to seek opinion of the members for long term goal setting of the organization, the CPE Committee has designed a standardized feedback form and requested all the POU's to obtain the said feedback form from the members in each CPE programme organized by them. The said feedback form has also been hosted on the ICAI Website.

Initiatives for professionalisation in conducting CPE Programmes

The Committee has sent the following communications to all the POU's for professionalisation in conducting CPE Programmes –

- To adhere with the following guidelines:
 - A CPE programme shall always start at the announced time and punctuality shall be adhered to.
 - No time shall be spent on introduction purposes. The CPE programme shall start directly with the Technical session by the Faculty.
 - Mementos shall be given preferably in the form of useful books.
 - Details of the programme should be uploaded on the CPE Portal well in advance (i.e. at least 3 days prior to the programme).
 - Back dated events would not be considered for approval of CPE hours (i.e. programme details uploaded after holding of the event).
- To submit the following details:-
 - Details of the Convenor and Deputy Convenor for the last 3 years along with details for the current year.
 - List of members attached with the Study Circle as on date.
 - Audited Accounts for the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14.
- To plan the programmes to be organised and to upload the details of the forthcoming programmes at least 2 months in advance so that the members may find it easier to plan time out of their busy schedule to attend the programmes.
- To strictly adhere to the following norms:

“To elect every year a Convenor and a Deputy Convenor to look after the day-to-day affairs/ activities of the CPE Study Circles as well as, maintaining proper accounts of the CPE Study Circles and a person can serve as Convenor/ Dy. Convenor of a CPE Study Circle for, a maximum of three terms of one year each.”
- Guidelines for holding Regional Conference and Sub-Regional Conference by the Regional Councils & Branches :-
 - Regional Conference can be organized by Regional Councils only once in a year in their respective regions. Duration of such Conference should be minimum of one day.
 - Sub-Regional Conference/ State Level Conference can be organized by the Regional Councils to be hosted by Branch. Duration of these Conferences should be minimum of one day.

- One Sub-Regional Conference can be organized in each State during a year.

A communication was sent to all the Regional Councils and Branches informing them the Guidelines for holding the Regional and Sub-regional Conference in line with the above guidelines.

- The Committee has hosted an undertaking on the CPE Portal to be given by all the concerned persons at CPE POU's before uploading the attendance of the CPE Portal. The undertaking is as under:

"It is hereby certified that data being uploaded here is true and correct and is based on the attendance sheet signed by the members who have attended the programme".

- A provision has been made on the CPE Portal, for uploading the soft copy of the BGM by the POU's which is circulated in their respective CPE Programme.
- The Committee constituted a Central Quality Inspection Team to enhance the level of CPE Programmes.
- The Committee decided to find out the areas of new professional opportunities for small and medium practitioners and to organize the programmes in those areas and also in the special economic zones.
- A system has been introduced on the CPE Portal for sending auto-generated mails to all the POU's on each Friday of the month informing them about the programmes pending for uploading the attendance at their end and requesting them to upload the same urgently.

CPE Mega Programmes

A total of 34 mega programmes have been organized by the CPE Committee since April, 2014 to July, 2015.

CPE Teleconferencing Programmes

The CPE Committee has organized a total of five CPE teleconferencing programmes at IGNOU, New Delhi from April, 2014 to June, 2014.

CPE National Live Webcasts

Due to discontinuation of the Gyan Darshan Channel – II at IGNOU, the Committee has decided to organize more and more CPE National Live Webcast Programmes in line with the CPE teleconferencing programmes. Accordingly, since March 2015, the Committee is organizing two CPE national webcast programmes per month. The Committee has organized 12 webcasts so far during this year since March, 2015 to July, 2015 covering various topics on professional interest.

In-house Executive Development Programmes

The CPE Committee is also promoting the in-house Executive Development Programmes for the benefit of the members working in various Corporate on various topics. The CPE Committee had organized a total of three in-house Executive Development Programmes since April, 2014 to February, 2015.

CPE Orientation Programmes organized

The Committee decided to convene the meeting of all the Convenors and Deputy Convenors of all the Study Circles/ Chapters in all the 5 Regions. Following are the details of two Orientation Programmes organised by CPEC:-

- With the Convenors/Deputy Convenors of all the Study Circles of Western Region was organized on 12th June, 2014 at Mumbai.
- Of the Heads of CPE POU's on 15th-16th July, 2015 hosted by the Ernakulam Branch of SIRC of ICAI. The Committee invited the Chairmen and Secretaries of SIRC, Branches and the Convenors/ Deputy Convenors of CPE Study Circles/ Chapters/ Groups from the States of Tamil Nadu, Kerala and three nearby Branches of Karnataka (Udupi, Mangalore and Mysore) at Ramada Resort, Cochin so that the CPE programmes can be made more effective and member-friendly and to adhere to best practices in CPE Programmes.

5.8 Corporate Laws & Corporate Governance Committee

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee has the vision to become an instrument towards empowerment of the profession as well as to accelerate & facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee examines Corporate Laws/ Limited Liability Partnerships/ Rules/ Regulations/ Notifications/ Schemes issued vis-à-vis best practices and makes appropriate representations/ suggestions to the concerned Ministries of Government and participates in the law making process.

The Committee is conducting Certificate Course on Valuation at various centres in the country spreading to Tier I, II and III cities and the registration for the course received overwhelming response. Outside the country, the course is launched in Dubai and Bahrain.

The Committee organizes programmes/ seminars/ workshops/ covering a wide range of contemporary topics in Corporate Laws and Corporate Governance especially on the Companies Act, 2013 at various places across the country for making the implementation of the Act smooth. The Committee also conducts programmes for Directors and Independent Directors. The Committee brings out Guidance Notes/ Application Guides/ Bulletins on the Companies Act and other publications for the benefit of the members.

Significant Achievements

1. The Companies Act, 2013

- Helping Ministry of Corporate Affairs, Government of India in implementation of the Companies Act, 2013.
- Addressing issues in the Companies Act, 2013 of the members by making suitable representation to the Ministry.
- Providing suggestions/ input/ framework on various provisions of the Companies Act to the Ministry. Also, providing inputs on the opportunity areas for the profession to the Ministry.

2. Development and Maintenance of Independent Directors Repository Portal

- As per Section 150 of the Companies Act, 2013, Independent Directors Repository Portal has been developed under the active encouragement of the Ministry of Corporate Affairs. The Committee is maintaining the portal regularly.

3. Webcast on the Companies Act, 2013 and Rules thereon in 2014

- The Committee organized series of Webcasts on the individual topics in The Companies Act, 2013 and Rules thereon.
- The 1st Webcast was organized on 16th April, 2014 on the topic “The Companies Act 2013 and Rules thereon” which was taken by the Chairman, CL&CGC. The members and corporates were also addressed by the then President, ICAI and the then Vice President, ICAI
- The 2nd Webcast was organized on 23rd April, 2014 on the topic “Impact of the Companies Act, 2013 on Private Companies” which was taken by the then Vice Chairman, CL&CGC.
- The 3rd Webcast was organized on 30th April, 2014 on the topic “Provisions of Accounts and Audit in The Companies Act 2013”.
- The 4th Webcast was organized on 7th May, 2014 on the topic “Role and Responsibilities of Directors, Independent Directors and KMPs in The Companies Act 2013”.
- The 5th Webcast was organized on 4th June, 2014 on the topic “Opportunities for Professionals under the Companies Act, 2013” which was taken by the Chairman, CL&CGC.
- The 6th Webcast was organized on 11th June, 2014 on the topic “Provisions of Corporate Social Responsibility under the Companies Act 2013”.

4. E-book on the Companies Act 2013 and Rules thereon.

- Launched an E-Book on The Companies Act, 2013 and Rules thereon for the benefit and convenience of the members.

5. Programme on the Companies Act, 2013 jointly with the Regional Councils and Branches

- **For the year 2014-2015:** The Committee decided that since the Companies Act, 2013 and Rules thereon have been notified for most of the Chapters by the Ministry of Corporate Affairs and there is a need that members should be aware of the provisions of the new Act, programmes on the Companies Act, 2013 will be conducted by the Committee jointly with the Regional Councils and Branches. The Committee has conducted around 86 programmes on the Companies Act 2013 across the country at following places:
Kolkata (2 programmes), Vadodara, Hubballi, Akola, Ghaziabad, Jalandhar, Ahmedabad, Nanded, Alwar, Bhilai, Vishakhapatnam, Durgapur, Himachal Pradesh, Surat, Udaipur, Kota, Jaipur, Jalgaon, Sangrur, Siliguri (2 programmes), Ranchi, Agra, Mysore, Guwahati, Cuttack, Mangaluru, Bareilly, Bhilwara, Bikaner, Coimbatore, Mathura, Navi Mumbai, Hyderabad, Guntur, Sambalpur, Dehradun, Panipat, Ernakulam, Pune, Dibrugarh, Gandhidham, Nashik, Jamshedpur, Patna (3 programmes), Ludhiana, Amravati, Kakinada (2 programmes), Sangli, Ambala, Lucknow, Tirunelveli, Bharuch, Faridabad, Jabalpur, Rajamahendravaram (2 programmes), Ujjain (2 programmes), Pondicherry, Bhavnagar, Hisar, Kozhikode, Jamnagar, Vasai, Erode, Goa (2 programmes), Thane (2 programmes), Tinsukia, Salem, Ongole, Nagpur, Chennai, Coorg, Dispur, Madurai, Palghat, Ballari, Latur, Kaloore and Salem.

- **For the year 2015-2016:** The Committee decided to conduct training programme on the implementation of the Companies Act, 2013 and Rules thereon so that implementation of the Companies Act becomes smooth jointly with the Regional Councils and Branches. The programmes on the Companies Act, 2013 have already been organized at around 35 places across the country at following places:
Chandigarh, Delhi, Patiala, Karnal, Jalandhar, Hyderabad, Coimbatore, Palghat, Visakhapatnam, Anantapur, Trichur, Udupi, Erode, Rourkela, Guwahati, Raniganj, Durgapur, Bhubaneswar, Asansol, Siliguri, Jamnagar, Ahmedabad, Akola, Vapi, Jamshedpur, Bilaspur, Patna, Jodhpur, Ghaziabad, Ranchi, Vellore, Sambalpur, Tinsukia, Agra and Mathura
- National Conference on the Companies Act, 2013 jointly with the Bangalore Branch of Southern India Regional Council of ICAI was conducted in October, 2014.

6. **Bulletins on the Companies Act, 2013:**

- The Committee is bringing out Series of Bulletins on the Companies Act, 2013. Fourteen Series of the Bulletins have already been issued and uploaded on ICAI website and ICAI Knowledge Gateway.
- Series 1- Summary of Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs till August, 2014.
- Series 2- Summary of Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs till August, 2014.
- Series 3- Summary of Rules issued by the Ministry of Corporate Affairs till August, 2014 and Annotated Text of Rules pertaining to that Chapter.
- Series 4- Comparison between the provisions of the Companies Act, 2013 and corresponding provisions in the Revised Clause 49 of Listing Agreement by SEBI incorporating amendments. Also, Difference between Revised Clause 49 of the Listing Agreement and the Amendments in Revised Clause 49 of the Listing Agreement vide Circular dated 15.09.2014. Further, Annotated Text of Revised Clause 49 of the Listing Agreement by SEBI after incorporating amendments vide Circular dated 15.09.2014
- Series 5- Summary of Companies Removal of Difficulties, Order, 2014 issued by the Ministry of Corporate Affairs till August, 2014.
- Series 6- Penalties on Companies and Professionals under the Companies Act, 2013.
- Series 7- Comparative Analysis of the important provisions of the Companies Act 1956 and the Companies Act, 2013.
- Series 8- Summary of Rules issued by the Ministry of Corporate Affairs from August, 2014 to November, 2014 and Annotated Text of Rules pertaining to that Chapter.
- Series 9- Summary of Notifications and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from August, 2014 to December, 2014.
- Series 10- Provisions incorporated in the Companies Amendment Bill, 2014 and the final text of the section after incorporating amendments.
- Series 11- List of Sections where Special Resolution is required and List of Sections where Central Government Approval is required.
- Series 12- Provisions incorporated in the Companies Amendment Bill, 2015 and the final text of the section after incorporating amendments.
- Series 13- Summary of Circulars, Notifications and Companies (Removal of Difficulties) Order, 2015 from November, 2014 to April, 2015
- Series 14- Summary of Amendment in Rules issued by the Ministry of Corporate Affairs from November, 2014 and April, 2015 and Annotated Rules of chapters of the respective sections.

7. **Guidance Note on Schedule III to the Companies Act, 2013**

The Committee is revising the Guidance Note on Revised Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent of changes being brought out in the Schedule III to the Companies Act, 2013.

8. **Application Guide on the provisions of Schedule II to the Companies Act, 2013**

The Committee has released the Application Guide on the provisions of Schedule II to the Companies Act, 2013.

9. **Frequently Asked Questions on the provisions of Corporate Social Responsibility u/s 135 of the Companies Act, 2013**

The Committee has prepared the FAQs on the provisions of Corporate Social Responsibility u/s 135 of the Companies Act 2013 and uploaded on ICAI website.

10. **Application Guide on various provisions of the Companies Act, 2013**

The Committee is bringing out the following Application Guide on various provisions in the Companies Act, 2013 soon:

- ✓ Application Guide on Managerial Remuneration.
- ✓ Application Guide on the provisions of Directors and Independent Directors.

- ✓ Application Guide on the provisions of Private companies
- ✓ Application Guide on the provisions of Related Party Transactions

11. Notification to give exemptions to private companies under the Companies Act, 2013

- The much awaited notification to give exemptions to private companies under Section 462 of the Companies Act, 2013 has been issued by MCA dated 5th June, 2015. In this regard, the members were informed vide sending mass SMS, mass mail, as well as hosting of announcement on ICAI website.
- Summary of provisions was prepared that were notified by Ministry of Corporate Affairs and the same was hosted on ICAI website.

12. Companies (Amendment), Act, 2015

- The Companies (Amendment) Act, 2015 has been notified and made applicable from 29th May, 2015. Suggestions have been sent for prescribing the threshold limit above which the fraud has to be reported to the Central Government.
- Summary of provisions was prepared as per Companies (Amendment) Act, 2015 and it was brought out in Series 12 of the Bulletins of the Companies Act, 2013 and the same was hosted on ICAI website.

13. ICAI-NFCG Work Plan

Submitted Work Plan for the year 2015-16 for organizing joint programmes with National Foundation for Corporate Governance.

14. Representation to MCA

- Submitted representation on cap on number of audit assignments under The Companies Act, 2013 to the Ministry of Corporate Affairs.
- Submitted representation regarding resolving issues arising in filing new Forms under the Companies Act, 2013 with MCA-21 where COP number of members is being asked to the Ministry of Corporate Affairs.
- Submitted representation to Secretary, Ministry of Corporate Affairs on the Key Issues and Concerns of ICAI in the Companies Act, 2013 and Rules thereon in July, 2014
- Submitted representation on the issues in the Companies Act, 2013 and Rules thereunder that have an impact on the profession like cap on number of audit, fraud reporting, penalties under the Companies Act, Reporting on Internal Financial Control Systems, Relative definition, extension of filing of DPT- 4, extension of Company Law Settlement Scheme etc. The Committee has till date submitted 29 representations on various issues of the Companies Act, 2013.
- Submitted representation on various issues in the Companies Act, 2013 - Suggestions for amendments/modifications/ clarifications
- Submitted representation on filling of vacancy in Company Law Board in Mumbai
- Submitted comments/ views on various aspects relating to CSR implementation and monitoring under the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013
- Submitted representation on ease of doing business in India - Changes required in the Companies Act to the Hon'ble Finance Minister.
- Submitted representation on ease of doing business in India - Changes required in the Companies Act to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs and also a representation was submitted on harsh penalties and issues in constitution of NFRA.

15. Certificate Course on Valuation

- The Committee has so far conducted 54 batches of the Certificate Course on Valuation.
- Till date 2600 members have been registered for the Course.
- The Committee has launched the Course in July, 2015 at Meerut and Kanpur.
- For the year 2015-16, the Committee has planned to conduct 12 batches.

16. Peak Filing of Balance Sheets/ Annual Reports

- The Ministry of Corporate Affairs requested ICAI in 2014 to facilitate in creating awareness among the members about the early filing of company's Balance Sheet and Annual Return for the current year preferably before the due date to avoid last minute rush. An announcement in this regard was hosted on the website of the Institute.

17. Interaction with Ministries/ Regulators/ Govt. Offices on Professional Matters

Regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act, 2013.

18. Meetings with important dignitaries on professional matters in 2014-15

- Meeting in April and June, 2014 with the Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding issues relating to implementation Issues in the Companies Act, 2013.
- Meeting in June, 2014 with Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding Accounting and other Issues in provisions of Corporate Social Responsibility, popularising the Concept of One Person Company, maintenance of database of Independent Directors and Investor Awareness Programmes.
- Meeting in June, 2014 with Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding organising training programmes on Independent Directors.
- Meeting in July, 2014 with Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding issues in the Companies Act, 2013.
- Meeting in April, 2015 with Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding giving suggestions on AOC-4 and MGT-7.
- Meeting in April, 2015 with Hon'ble Finance Minister and Secretary, Ministry of Corporate Affairs on the subject of Ease of doing business in India – Changes required in Companies Act, 2013.

19. Training Programmes for Government Department/ Govt. Officials in 2014-15

The Committee is regularly organising programmes jointly with Department of Public Enterprises, Government of India for the Independent Directors of CPSEs on the provisions of the Companies Act, 2013 on:

1. 5th ICAI-DPE programme on 24th September, 2014 at Delhi
2. 6th ICAI-DPE programme on 9th February, 2015 at Delhi

20. Workshops on the Companies Act, 2013 for CFOs of Tamil Nadu Government in 2014

The Committee is organising Workshops for CFOs of Tamil Nadu Government. One such Workshop was organized in Chennai in October, 2014.

21. National Seminar and Workshops on Valuation at the backdrop of the Companies Act, 2013 in 2014-15

- The Committee has organized 2 National Seminars on Valuation at the backdrop of the Companies Act, 2013 at Mumbai and Delhi in November, 2014 and January, 2015 respectively.
- The Committee has organized 2 Workshops on Valuation at the backdrop of the Companies Act, 2013 at Delhi and Chennai in November, 2014.

22. Series of Two Days Certification Programme for Directors in 2015

- The Committee has organized 1st programme of the series of Two Days Certification Programme for Directors in March, 2015 at Bangaluru. The 2nd programme of the series was conducted in May, 2015 at Coimbatore.
- The 3rd programme of the series was conducted in June, 2015 at Mumbai.
- The 4th programme is planned in August, 2015 at Chennai.

23. Interactive meeting on Legal and practical issues in Company Law and way forward in 2015

Considering many queries, confusions and practical issues arising out of the Companies Act, 2013, the Committee is conducting Interactive meeting on Legal and practical issues in Company Law and way forward. Till date, 5 meetings were held at Mumbai, Chennai and Hyderabad in May, June and July, 2015. The 6th Interactive meeting is planned in Delhi in July, 2015.

INITIATIVES /PROJECTS IN PROGRESS

- Rating of Corporate Governance/ Formation of Association of Audit Committee members/ Formation of new Forum for Registered Valuers/ Discussion forum for Directors.
- Revising Guidance Note on Certification of Corporate Governance (based on Revised Clause 49 of the Listing Agreement)
- The Committee is planning to launch Certificate Course on Restructuring and Company Liquidation.

5.9 Direct Taxes Committee**Activities undertaken****A. Representations/ interactions with CBDT**

1. New formats of tax audit reports
2. Letter from Director, ITRA (RA-I)
3. 5th Standing Committee Meeting on TDS held on 29th September, 2014
4. Electronic Verification Code (EVC) by Chartered Accountants
5. Suggestions on ITR forms and other reports notified under Incomes-tax Rules, 1962
6. Meeting with Indian Council for Research on International Economic Relations

7. Request to amend JAVA utility to allow FRN containing 8 digits – 3CA/3CB
8. Reduction of rate of compounding fee w.r.t. section 276B
9. Inputs on Draft of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) released by CBDT
10. Seminar on Reducing Litigation held on 9th February, 2015
11. Change in password on Income-tax e-filing portal
12. Updation of e-TDS/ TCS RPU (Version 4.2)
13. Suggestion for inclusion of certain details in the tax audit format utility for the AY 2016-17 and introduction of a suitable control mechanism in the IT system to adhere to the ceiling limit on tax audits
14. Inputs submitted for amendments to be made in the provisions of section 115JB (Minimum Alternate Tax) of the Income-tax Act, 1961 due to implementation of Ind AS
15. Feedback on Arrear Demand Verification Portal
16. Exclusion of fee under section 234E in demand notices issued under section 200A upto 31st May, 2015
17. Consequential amendment in Rule 37BB and related forms
18. Enabling online rectification in Form 26QB (TDS on purchase of property)
19. Tax audit data for the Assessment Years 2013-14 and 2014-15
20. Suggestions on 'The Black Money (undisclosed foreign income and assets) and Imposition of Tax Act, 2015'
21. Hardships faced by an assessee due to revision of stamp duty in the Maharashtra Stamp Act

B. Activities relating to Union Budget

1. Budget Viewing Workshop
2. Live Webcast on tax proposals of Union Budget
3. Articles on Direct taxes proposals of Union Budget for the Budget Special issue of CA Journal
4. Suggestions of ICAI accepted in Union Budget 2014-15
5. Suggestions on Pre-Budget Memorandum - 2015
6. Submission of Post Budget Memoranda – Direct Taxes

C. Other Initiatives

1. Inputs relating to DTC Economic Survey 2013-14
2. Communications with CPC (TDS)
3. Cases for verification sent by C&AG office
4. Revision of Publication titled "Guidance Note on Tax Audit u/s 44AB of the Income-tax Act, 1961"
5. Trouble Shooting guide for problems in accessing the e-filing website
6. Note received from Quality Review Board
7. Articles on Tax Audit for CA Journal
8. Updation of List for issuing complimentary copies of ICAI Journal
9. Inputs on W.P. (Civil) No.621/2007, The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) & Anr. Vs. Union of India & Others pending in Supreme Court of India
10. Observations on Quick Insight
11. Webcast on "Facilitating e-filing - Issues & Resolutions"
12. Draft observations on the report (No.32 of 2014) of Comptroller & Auditor General of India's report on "Performance Audit on Appreciation of Third Party (Chartered Accountant) reporting in Assessment Proceedings"
13. Request to contribute in the area of Direct Taxes

D. Seminars/ Conferences/ Tax Awareness programmes

A number of Seminars, Conferences, Tax Awareness programmes and workshops were held throughout the country.

5.10 Committee on Economic, Commercial Laws & WTO

The Committee on Economic, Commercial Laws & WTO is a non-standing Committee of the ICAI and its mandate inter-alia includes serving the multifunctional task of analysis, knowledge dissemination, inputs to policy formulation, organization of various programmes on contemporary issues in the fields of economic, commercial and business laws and WTO. The Committee also administers one Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO and two

Certificate Courses namely Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation) and Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (Anti-Money Laundering Specialist.)

Workshops/ Seminars/Conferences

During the year 2014-15, the following Workshops/ Seminars /Programmes have been organised by the Committee:

- Webcast on Arbitration (Emerging Professional opportunities in ADR Mechanism) on 25th July, 2014.
- Webcast on Competition Law and Emerging Professional opportunities for CAs on 23rd August, 2014.
- Webcast on professional opportunities for CAs in Prevention of Money Laundering Act for CAs on 23rd September, 2014
- One Day Conference on Foreign Exchange Management Act (FEMA) and Competition Act was organised by the Committee and hosted by the Northern India Regional Council of the ICAI on 18th October, 2014 at New Delhi.
- Awareness Programme on Professional Opportunities in Australia was organized by the Committee on 4th December, 2014 at Indore. The same was hosted by the Indore Branch of CIRC of ICAI
- The Committee for Members in Industry & Committee on Economic, Commercial Laws & WTO of the ICAI jointly organized a Comprehensive Conference on Professional Opportunities in ADR Mechanism, IPR, WTO, FEMA, Competition & other Economic, Commercial Laws on 13th and 14th December, 2014 at Mumbai.
- Webcast on Overview and Latest Developments in the field on ADR Mechanism & Professional Opportunities for CAs was organised by the Committee for the members on 24th January, 2015 at Chennai.
- Technical Workshop on the emerging topics of the economic, commercial laws and WTO and professional opportunities for CAs was organized on 23rd May, 2015 at Amritsar.
- Conclave on Emerging Global Professional Opportunities for CAs in economic and commercial laws was organised on 13th June, 2015 at New Delhi for the members.
- Technical Workshop for the members was organized on 20th June, 2015 at Jammu. The same was hosted by the Jammu & Kashmir Branch of NIRC of ICAI.
- A Seminar on New Black Money Law (Under Income Tax Act), Reverse Charge and tax on work contract (Service Tax) & Latest Amendment in Company law and CARO” was organized on 26th June, 2015 at Ludhiana. The same was hosted by the Ludhiana Branch of NIRC of ICAI

Service Conclave-2014

The Ministry of Commerce & Industry, Government of India along with CII, SEPC, FIEO and IIFT, organized Services Conclave, 2014 with the theme “Promoting Services Export from India - Opportunities” on 12th & 13th November, 2014 at New Delhi wherein the Chairman, CECL&WTO represented the ICAI and addressed the participants.

ICAI – Global Exhibition of CA Services from 23rd-25th April, 2015 at New Delhi

The Committee has taken initiative for promoting Export of CA Services and positioning Indian CA Brand across the Globe. In this direction ICAI – Global Exhibition of CA Services was organized by the ICAI as Global Exhibition on Services Partner from 23rd-25th April, 2015 at Pragati Maidan, New Delhi. The Global Exhibition of Services (GES) 2015 was the initiative of the Government of India wherein more than 40 countries participated.

Certificate Course on Arbitration

The Committee organized 3 batches at Nagpur, Agra and Meerut of the Certificate Course on Arbitration in association with the respective Branches of the Regional Council. There are at present 648 members who are empanelled on the ICAI Panel of Arbitrators.

Revision of the existing Publications of the Committee

The publications of the Committee titled, ‘A Study on Prevention of Money Laundering Act, 2002’ and ‘A Study on Foreign Contribution Regulation Act, 2010’ have been revised and updated keeping in view the recent developments and amendments taken place in the laws.

Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti-Money Laundering Specialist)

Keeping in view the efforts and initiatives of the Government to curb the generation of the black money in various sectors and to closely work with the Government as a partner in the nation building and help the Government to achieve its objectives in Prevention of Money Laundering. The Committee has launched a new Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti-Money Laundering Specialist) for the members.

Restructuring of the Certificate Course on ADR/ Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO

- Keeping in view of the latest developments taken place and appreciating the importance of the matter and to equip the members in this niche area, the Committee has revised and restructured the Certificate Course on Arbitration with the change of name as Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation). This course is meant for the Members of the ICAI, who are desirous of consolidating their expertise and skills in Arbitration, Mediation & Conciliation and related areas to position them as multidisciplinary consultants in

the global service market. The Course covers the wide area of domestic, international Arbitration, Mediation and Conciliation. Apart from the comprehensive theoretical aspects, this course will sharpen the expertise and excellence of participants through intensive training on the practical and procedural aspects with multiple case studies and mock ADR proceedings. Participants will have to undergo a test at the end of the course for getting a completion certificate.

- The exiting Course Contents and Syllabus of the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO was formulated in 2005 when this Course was launched. During the current year, the Committee restructured the Course keeping in view of the current market scenario, latest developments, expectations of the members, professional opportunities etc.

5.11 Ethical Standards Board

The ICAI was granted the statutory authority to regulate the profession of chartered accountants in India, vide the Chartered Accountants Act, 1949. This development was in fact not an isolated one, but was one among the series of events that had started much earlier. Back in 1866, the law relating to maintenance of accounts and audit was introduced and formal qualification as auditor was required. Later, the Indian Companies Act, 1913 was enacted, which specified the procedure to maintain the books of accounts. Two set of rules, i.e. The Auditors' Certificates Rules, 1932 and The Restricted Certificates Rules, 1932 were framed under Section 144(2) of the said Companies Act.

With this legacy of the profession, ICAI, constituted under the young and democratic India, had the significant responsibility to regulate the chartered accountants in the country, which would in turn, contribute to India's growth story. "Regulation", as the name suggests, implies the right behaviour by chartered accountants, and penalizing them for professional misconduct. To serve this purpose, The Chartered Accountants Act, 1949, along with the two Schedules to the Act, set out norms for permissible activities for the members of the profession. Section 22 of the Act defines and describes what constitutes 'professional misconduct'. The two Schedules mention in detail the various acts and omissions entailing professional/ other misconduct, which are dealt with punishment in accordance with Chapter-V of the Act. The Disciplinary mechanism of the Institute is provided in the Act, which has effectively been followed since the enactment of the Act without any difficulty.

Even with the above system well in place, it was thought to bring a Code of Ethics also, given the dynamics and complexity of profession in the modern times. Hence the ICAI brought the first edition of the Code of Ethics for members, then '*Code of Conduct*' in November, 1963. *Code of Ethics* supplemented the Chartered Accountants Act in setting professional ethical standards regulating the relationship of Chartered Accountants with others. The incorporation of provisions from International Federation of Accountants (IFAC) *Code of Ethics* in 2009 is yet another milestone achieved with regard to synchronizing the Code of Ethics as per international standards.

Further, the Ethical Standards Board of the ICAI was constituted in 1975, to establish standards on ethics for the members of the profession. It has been involved with various exercises to equip the members to vitalize their competitive edge through various professional means and methods. The Ethical Standards Board is entrusted with the updation of Code of Ethics for members. The mission of the Board deserves a mention:

"To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".

The Ethical Standards Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. Besides Code of Ethics, also reviews and revises its publications namely '*FAQ on Ethical Issues*' and '*Guidance Note on Independence of Auditors*'. The Board promotes public awareness and confidence in the fundamental principles viz. integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members.

5.12 Expert Advisory Committee

Expert Opinions

In times of economic growth, the business transactions have become more complex and intricate. Further, the accountants and auditors have to perform their functions within the framework of various accounting and auditing standards, which are gaining much importance and acceptance over the past few years. In such complex environment, the accounting professionals are often posed with certain tricky situations, where an authentic view is required. Keeping these situations in mind, the Council of the ICAI constituted the Expert Advisory Committee for answering the queries of the members of the ICAI on wide ranging issues relating to accounting and/or auditing principles and allied matters. However, the Committee does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. It also

does not answer queries which concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the ICAI, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. The Committee answers the queries in accordance with Advisory Service Rules, which are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142 or can be obtained from the ICAI's Head Office at New Delhi.

The opinions of the Expert Advisory Committee are the opinions or views of the members of the Committee on the given facts and circumstances of the query, arrived at on the basis of the applicable accounting/ auditing standards, guidance notes, and other pronouncements of the ICAI as well as the relevant laws and regulatory environment applicable under the circumstances of the query, as on the date of finalisation of the opinion. Every opinion, therefore, must be read and applied after taking into account any amendments and/or other developments subsequent to the date of finalisation of the opinion by the Committee which is mentioned thereagainst.

Although the opinion given or a view expressed by the Committee represents the opinion or view of the members of the Committee and not the official opinion of the Council of the ICAI, it carries an authoritative guidance which is well recognised by various government/ regulatory bodies, such as, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Ministry of Corporate Affairs and also relied upon by Courts, etc.

During the period from 01.04.2014 to 07.07.2015, the Committee finalised 61 opinions received from the members of the ICAI and 6 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities. Various issues on which the Committee opined during the period were treatment of interest paid on compensation for lands acquired, disclosure requirements as per AS 15 in respect of employees seconded to subsidiary company by the holding company, accounting treatment of borrowing costs, administrative and other general overhead expenses incurred during the period when the construction work of the project is interrupted, applicability of paragraph 46A of AS 11 to buyer's credit/ suppliers' credit repaid through a long-term liability, accounting for unspent expenditure towards Corporate Social Responsibility and sustainability activities as per Revised DPE Guidelines, accounting treatment of lease deposits received for lease of land by the company engaged in development of software technology parks, restatement of foreign currency monetary liabilities covered (hedged) by plain vanilla call option, treatment of foreign exchange fluctuations and interest cost on issuance of FCCB, whether amortisation of premium paid on foreign currency (USD) forward covers can be treated as borrowing cost, recognition of deferred tax asset on unabsorbed business loss and unabsorbed depreciation, accounting for Principal Only Currency Swaps, accounting treatment of borrowing cost for oil & gas assets acquired directly and through overseas subsidiary companies, etc.

The opinions issued by the Committee are also published in the Compendium of Opinions. Till now, thirty-four volumes of the Compendium have been released for sale. A CD containing around 1350 opinions contained in all the thirty-four volumes of Compendium of Opinions with advanced and user friendly search facilities to locate the opinions on desired subject(s) and/or the opinions issued during a particular period has also been released, which is available with Volume XXXIV of the Compendium of Opinions.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of the ICAI's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the knowledge sharing page of the Committee on the website of the ICAI.

5.13 Committee on Financial Markets & Investors' Protection

The Committee on Financial Markets and Investors' Protection is a non-standing Committee of the ICAI. The Committee is entrusted with the task of undertaking various activities which are as follows:

1. The Committee is conducting Investor Awareness Programmes under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
2. The Committee is also organizing various Seminars, Workshops, Training Programmes.
3. The Committee is presently conducting two Certificate courses i.e. Certificate course on Forex and Treasury Management and Certificate course on Derivatives.
4. The Committee has launched two more Certificate courses i.e. Certificate course on Financial Markets and Securities Law and Certificate course on Fundamental Analysis and Technical Analysis including Equity Research.
5. The Committee conducts research and brings out publications on matter pertaining to the Committee.
6. The Committee organizes Live Webcasts and Google Hangouts.
7. The Committee is updating stakeholders on financial markets through its Website.

1. Investor Awareness Programmes

The Committee organizes 'Investor Awareness Programmes' under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Keeping in view the

importance of the investor education and protection, the Committee organizes Investors Awareness Programmes to educate the investors all over India.

The Committee has been organizing Investors Awareness Programmes under the aegis of Ministry of Corporate affairs through its various Programme Organizing units POU's (Regional Council, Branches, Study Circles, Study Chapters & Study Groups) and RPs (Resource Persons).

In total, 849 programmes were conducted between 1st April, 2014 to 7th July, 2015 out of which 91 programmes were organized by the POU and remaining 751 by the Resource persons.

The Committee has also conducted three Mega Investors' Awareness Programmes.

The Committee has been organizing Investors Awareness Programmes under the aegis of 'National Stock Exchange – Investor Protection Fund Trust (NSEIPFT)' through its various Programme Organizing units POU's. A total of 4 programmes were conducted during the captioned period.

During the current financial year 2015-16, The committee is planning to conduct more than 1000 Investor Awareness Programmes.

2. Seminars, Workshops and Training Programmes

The Committee plays a pro-active role in conducting various Seminars, Workshops and Training Programmes relating to Companies Act, 2013, Amendments in Direct Tax and Indirect Tax as per budget 2015, Financial Planning, Bank Audit etc for the professional updation of members.

During the period from 1st April, 2014 to 7th July, 2015, a total of 38 Seminars, Workshops and Training Programmes have been successfully conducted.

The Committee successfully conducted the training programme for the officers of Central Bureau of Investigation from 27th May to 30th May, 2014 in Mumbai. The training programme received an overwhelming response and appreciation from the participants.

3. Certificate Courses

(A) Certificate course on Forex and Treasury Management

With the latest developments that is taking place in the Capital, Money, and Foreign Exchange Markets affecting volatility in exchange rates and accentuating liquidity constraints, corporates and banks have started paying closer attention to the treasury and forex management function. The globalization of the economy with mobilization and deployment of funds from/in other countries is also necessitating growing attention in the area of treasury and forex management. So, keeping this in view Certificate course on Forex and Treasury Management was launched. The committee has successfully completed 27 batches of Forex and Treasury Management course till date. During the period from 1st April, 2014 to 7th July, 2015, the Committee has successfully completed 7 batches (i.e. from 20th batch to 27th batch) and 28th, 29th, 30th and 31st batches are running successfully in Kolkata, Kanpur, Mumbai and Delhi respectively.

(B) Certificate Course on Derivatives

Over the last three decades, the derivatives market has seen a phenomenal growth. A large variety of derivative contracts have been launched at exchanges across the world. So for imparting knowledge in this field, Certificate course on Derivatives was launched. The Committee has successfully completed 2 batches till date. During the captioned period, the Committee has successfully completed 1st batch of residential course conducted at Centre of Excellence, Hyderabad. The Committee has proposed to schedule 2nd batch of Derivatives course (Residential) at Centre of Excellence, Hyderabad during the month of August, 2015.

4. Recently launched two Certificate courses:

(A) Certificate course on Financial Markets and Securities Laws

The Committee has recently launched Certificate course in the field of "Financial Markets and Securities Laws". The objective of introducing this course is two-fold - on one hand it undertakes to help those members who are willing to make career as intermediaries in the financial markets and on the other, to increase the efficiency of the participants associated with the financial market and to enable them to keep pace with the changing environment.

(B) Certificate course on Fundamental Analysis and Technical Analysis including Equity Research

The Committee has also newly launched Certificate course in the field of "Fundamental Analysis and Technical Analysis including Equity Research". This course is launched for the young brigade of upcoming analysts in the industry of share market, stock market and includes technical and basic fundamental analysis.

5. Publication and Research

The Committee has recently released one publication with nomenclature “Investment Avenues and Investor Awareness” on CA day celebration i.e. on 1st July, 2015. The objective of launching this publication is to give awareness to the public at large on how to invest their wealth in various securities by earning more returns with lesser risk. The Contents of the publication include Money's Magical Mantra, Individual - Investor & Money, Financial & Tax Planning, Art of Investing, Knowledge on Investment, IEPF & Investor Awareness, PM's Jan Dhan Yojna, Tax provisions.

6. Webcasts and Google Hangout

The Committee has conducted 18 Webcasts and 1 Google Hangout so far to enhance the knowledge and skill sets of our members. During the captioned period, the Committee has conducted 6 Webcasts and 1 Google Hangout. The details of the same are mentioned below:

- a. The 13th Webcast was organized on 9th May, 2014 on the topic “Corporate Debt Restructuring (CDR) and Joint Lenders Forum (JLF)”.
- b. The 14th Webcast was organized on 30th May, 2014 on the topic “Financial Planning And Wealth Management”.
- c. The 15th Webcast was organized on 12th December, 2014 on the topic “Investing in stock market through Technical analysis and Pitfalls of investing in stock markets”.
- d. The 16th Webcast was organized on 2nd March, 2015 on the topic “Amendments in Direct and Indirect Tax as per Union Budget 2015”.
- e. The 17th Webcast was organized jointly with Professional Development Committee on 11th May, 2015 on the topic “Role of C&AG in Accountability & Good Governance - Changing Pattern of Audit, Relevance to the CA. Fraternity” which was taken by Shree Shailendra Pandey, Ex. Deputy Comptroller & Auditor General of India and others.
- f. The 18th Webcast was organized on 1st June, 2015 on the topic “Live Webcast on Critical Issues on Companies Act, 2013” at ICAI, New Delhi.
- g. The 1st Google hangout was organized on 25th May, 2015 on the topic “An Overview of Goods & Service Tax (GST) in India” at ICAI, New Delhi.

7. Committee's Website:

The Committee is regularly updating its financial markets website i.e. www.financialmarket.icai.org. Website is user-friendly and members can easily access to get the latest updations going on in the Committee.

5.14 Financial Reporting Review Board

The ICAI through the Financial Reporting Review Board (FRRB) endeavors to improve the financial reporting practices in the country. Functioning for more than thirteen years, the FRRB has been able to create a niche position among the regulators and members of the ICAI.

The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon selected either on suo-motu basis or on a reference made to it by regulatory body(ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

- (a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;
- (b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- (c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon.

Review of General Purpose financial statements and auditors' report thereon

Suo Motu

During the period, the Board has completed the review of 52 cases, out of which 4 cases have been referred to the Director Discipline of the ICAI. For 42 cases, it decided to issue an appropriate note on non-compliances observed during the review of the financial statements to the auditors of the related enterprises.

Special Cases



Financial statements referred by SEBI

The Board reviewed 3 financial statements referred to it by SEBI in accordance with its terms of reference.

- ❖ **Cases selected on the basis of certain media reports/ other facts highlighting accounting or financial irregularities**
6 financial statements were selected on the basis of media reports and the Board has already completed the review of three financial statements.
- ❖ **Review of audited accounts of Political Parties referred by the Election Commission of India**
The Election Commission of India had referred the audited accounts of 35 political parties to the ICAI to find if they comply with the accounting standards. The Board has completed the review of referred audited accounts and submitted its report to the Election Commission of India.

Review of cases referred by QARC of SEBI

In its endeavour to improve the quality of financial reporting by listed entities, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has set up the Qualified Audit Report Review Committee (QARC). Its role will be to guide SEBI in processing the qualified annual audit reports referred to it by the stock exchanges. The SEBI has sought the support from ICAI-FRRB to review significant audit qualification. The FRRB submits its opinion on whether the qualification is justified or not. The SEBI-QARC based on deliberations held at QARC meetings and after considering FRRB's opinion, may direct the listed enterprise to revise its financial results by way of pro-forma financial results.

The FRRB is associated with QARC for such reviews since Dec 2013. During the period, the Board has considered specific audit qualifications referred to it for 103 cases along with additional information, if any, received by the company and/or the auditor, as the case may be, and finalised its views on 100 cases.

Constitution of Financial Reporting Review Groups

The Board constituted twenty one Financial Reporting Review Groups for consideration and finalisation of the preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon in the respective years. During the period, the review reports of 79 enterprises were allocated to these groups out of which the groups have submitted the review reports of 70 enterprises.

Imminent Releases

Articles in Institute's Journal "The Chartered Accountant"

With a view to apprise the members of the ICAI and others concerned about the non-compliances observed during the review, note on 'Non-Compliance with Reporting Obligations' as observed by the Financial Reporting Review Board relating to Revised Schedule VI to the Companies Act, 1956 was published in May 2015 issue of the ICAI's Journal.

Conduct of Awareness Programmes on Financial Reporting Practices

With an objective to enhance the knowledge of the preparers of the financial statements and auditors and to update them about the changes made in accounting standards as well as standards on auditing issued by the Institute and/or other regulatory authorities, during the period, the Board had organised 11 Awareness Programme on Financial Reporting Practices, in Thane, Jhansi, Bhayandar, Vasanthnagar, Kolkata, Chennai, Jodhpur, Ahmedabad, Mumbai, Rajkot, Jalgaon which were well attended by 1881 members.

Conducted Programme on 'Financial Reporting Practices for Political Parties'

To enhance the financial reporting skills of the auditors of financial statements of Political Parties and to acquaint them with major non-compliance observed by the FRRB during review of financial statements of political parties, a programme on "Financial Reporting Practices for Political Parties" was organised on 23rd June, 2015 at New Delhi. The programme was inaugurated by Dr. Nasim Zaidi, Chief Election Commissioner along with Shri P.K. Dash, Director General, Election Commission of India, besides President, ICAI and Vice-President, ICAI. The programme was attended by the auditors of 27 political parties.

5.15 Indirect Taxes Committee

Initiatives towards Partner in Nation Building

- (i) **Suggestions on tax administration issues to TARC:** The Government has set up a Tax Administration Reform Commission (TARC) under the Chairmanship of Dr. Parthasarathi Shome with a view to review the application of Tax Policies and Tax Laws in India in the context of global best practices. In this regard, the Committee submitted suggestions on administrative issues relating to indirect taxes to the Chairman, Tax Administration Reforms Commission (TARC) on 17th April, 2014.
- (ii) **Preliminary Draft of Audit Report under Service Tax to CBEC:** A representation along with preliminary draft of service tax audit report was submitted to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) on 8th May, 2014 with a suggestion to introduce service tax audit.

- (iii) **Condensed form of Audit Report - AR-1 to Commissioner, Delhi:** The Committee submitted a draft condensed Delhi VAT Audit report format (AR-1) to the Commissioner, Delhi VAT for its implementation on May 29th, 2014. The format was submitted based on the discussion of Chairman, Indirect Taxes Committee in a meeting with Commissioner, DVAT.
- (iv) **Pre & Post Budget Memorandum**
- (a) **Pre-Budget Memoranda, 2014 & 2015 - Indirect Taxes**
The Pre-Budget memoranda, 2014 & 2015 on Indirect Taxes were submitted to the Ministry of Finance on 2nd June, 2014 and 15th December, 2014 respectively. The memoranda contained suggestions to improve tax collection, reduce/ minimize litigations, rationalize provisions of taxation laws and removing administrative and procedural difficulties.
- (b) **Pre-Budget Meetings with Ministry of Finance**
Chairman, Indirect Taxes Committee and members of Committee attended the Pre-Budget meetings convened by Ministry of finance on 2nd June, 2014 and 15th December, 2014 at North Block, New Delhi and presented the gist of recommendations made in the Institute's Pre-Budget Memoranda, 2014 and 2015 respectively.
- (c) **Post Budget Memoranda, 2014 & 2015 - Indirect Taxes**
The Committee submitted its Post Budget Memoranda, 2014 & 2015 on Indirect Taxes to the Government on 22nd July, 2014 and 27th March, 2015 respectively. The Memoranda contained suggestions for removing the practical difficulties which may arise in implementing budget proposals.
- (v) **Representation to Haryana & Himachal Pradesh Government to introduce VAT Audit**
A representation was submitted to Haryana & Himachal Pradesh Government on 8th July, 2014 for introducing VAT Audit in their respective States. In the representation, the benefits which would accrue if audit is done by Chartered Accountants were duly highlighted.
- (vi) **Submission of Tax Administrative Issues to CBEC**
In response to the letter from Central Board of Excise and Customs, the Committee submitted suggestions on Tax Administrative Issues relating to Indirect Taxes to Central Board of Excise and Customs 19th September, 2014.
- (vii) **Representation to CBEC to extend due date of filing Service Tax Return for the half year ended September, 2014**
The Committee submitted a representation to the CBEC on 7th October, 2014 requesting to extend the due date of filing Service Tax Return for the half year ended Sep, 2014. Accordingly, CBEC has vide Order No. 02/2014-ST dated 24th October, 2014 extended the due date of filing Service Tax Return, for the period April, 2014 to September, 2014, from 25th October, 2014 to 14th November, 2014.
- (viii) **Representation to Government on proposed GST Constitutional Amendment Bill**
The Committee submitted a representation to the Government on proposed GST Constitutional Amendment Bill on 27th November, 2014. Various suggestions like defining the term services, inclusion of petroleum product in GST, subsuming of entry tax into GST etc. were incorporated in the Bill introduced by the Government in the Parliament.
- (ix) **Representation to CBEC seeking clarification regarding utilization of Education Cess & SHEC**
The Committee submitted a representation to the TRU, CBEC on 28th April, 2015 requesting to clarify following issues:
- Treatment of old unutilized credit of EC & SHEC with the assessee;
 - Treatment for excisable goods in transit on 1st March 2015, which involves an element of Cess in the billing; and
 - Disparity between effective dates of withdrawal of Cess under the Service Tax and the Central Excise which will lead to accumulation of credit in the hands of the manufacturer as there would be no cess on excise duty but only on Service Tax.

In this regard, following few issues with respect to utilisation of credit of EC and SHEC for payments of basic excise duty were addressed vide *Notification No. 12/2015 Central Excise (N.T.), Dated: April 30, 2015*:

- (a) Education Cess and Secondary & Higher Education Cess on inputs or capital goods received in the factory of manufacture of final product on or after the 1st March, 2015;
- (b) Balance 50% Education Cess and Secondary & Higher Education Cess on capital goods received in the factory of manufacture of final product in the financial year 2014-15; and
- (c) Education Cess and Secondary & Higher Education Cess on input services received by the manufacturer of final product on or after the 1st March, 2015.

Accordingly, a new representation was submitted to the CBEC on 25th June, 2015 requesting to clarify following balance issues:

- a) Treatment of old unutilized/ accumulated credit of EC & SHEC of Excise duty with the assessee as on 28th February, 2015.
 - b) Treatment of old unutilized/ accumulated credit of EC & SHEC of Service Tax with the assessee as on 31st May, 2015.
 - c) Treatment of Education Cess & SHEC in respect of input services availed by Service Provider on or after 1st June, 2015.
- (x) **Extension of MOU with CBEC for Certified Facilitation Centre**
The MOU with CBEC in respect of Certified Facilitation Centre (CFC) have been extended for a further period of 2 years i.e. till 31st March, 2017. Under this scheme, a practicing Chartered Accountant may register as CFC and can upload returns and other documents for central excise and service tax assesseees.
- (xi) **Suggestions on 122nd Constitution Amendment (GST) Bill, 2014 to Select Committee**
The Committee submitted a representation to Select Committee on 122nd Constitution Amendment (GST) Bill, 2014 on 7th July, 2015 as the Bill has been referred by Rajya Sabha to it.
- (xii) **Training Programme for officials of Excise and Service Tax Commissionerate**
With a view to help the Government in its capacity building and partner them in Nation Building, the Committee has been regularly organising training programmes for officials of Excise and Service Tax Commissionerate. During the period, the Committee organised the 37 training programmes for the various Commissionerates and NACEN.

Further, the Committee assisted as a knowledge partner in the interactive session with hoteliers, travel agents and tour operators organised by Bhubaneswar Commissionerate of Central Excise on 1st May, 2014 at King's Court, Hotel Crown, Bhubaneswar.

Such a training programme will go a long way in strengthening the association of ICAI with the Government.

Technology Driven Initiatives

- (i) **Live Webcasts**
During the period, the Committee organised 18 webinars as a nationwide outreach programme for members. The live webcasts have been viewed by more than 1 lac members and appreciated by them. The recording of these webcasts can be viewed at http://www.icai.org/post.html?post_id=9656.
- (ii) **E-learning on Customs, Service Tax, Excise Duty & Central Sales Tax**
With a view to facilitate the learning for the members from anywhere and anytime on just a click of mouse, the Committee launched e-learning on *Central Excise Duty* and *Central Sales Tax*. Further, E-learning on service tax and customs duty were revised with Finance Act, 2014.
- (iii) **Committee Website Portal www.idtc.icai.org**
The Committee has developed an Indirect Taxes Committee portal www.idtc.icai.org to provide doorstep services to members such as E-Test facility for Certificate Course on Indirect Taxes, to invite members for authoring and reviewing of publication, seeking suggestions from members for further submission to the Government etc.

Programmes, Seminars, Conferences and Courses organised**(i) International Programme - Study Tour to UK and Ireland**

The Indirect Taxes Committee jointly with International Affairs Committee organized a study tour to UK and Ireland from 26th October to 2nd November, 2014. The study tour includes a programme on VAT, interaction with the institutional stakeholders at UK and Ireland.

(ii) National Conferences on Indirect Taxes

With a view to update the members and assist them to continue to enjoy the edge over other profession, the Committee organised National Conference at Bhubaneswar, Surat, Gurgaon, Ernakulam, Bengaluru, Vadodara, New Delhi and Chandigarh. These national conferences were attended by 4000 delegates.

(iii) Certificate Course on Indirect Taxes

The Committee has been organising 12 days Certificate Course on Indirect Taxes with a view to facilitate members by providing specialized and updated knowledge of indirect taxes in a systematic manner to enable them to take up various professional opportunities offered by this area. During the period, the Committee has organised 21 batches of the Course across the country, which have been attended by 820 members.

(iv) Faculty Development Programme - An effort to develop new faculties

The Committee organised Faculty Development Programme at New Delhi, Hyderabad, Mumbai and Kolkata with a view to increase its faculty base and provide a well set platform to new aspirants to contribute as an indirect taxes faculty. Further, a National Faculty Development Programme was organised at Mumbai wherein participants of all the earlier Faculty Development Programme were invited to participate.

(v) Residential Programme

The Committee organised three residential programmes at Goa, Dharmshala, Jhansi and Jim Corbett Park on how to assess taxability of services and procedures under service tax. These programmes were attended by 200 participants.

(vi) Other Seminar & Conferences

With a view to update the members and assist them to continue to enjoy the edge over other professional, the Committee has been regularly organising various seminar and conferences on Indirect Taxes and proposed GST Regime. During the period, the Committee has organised 96 such seminars and conferences have been organised by the Committee.

Release of Publications**(i) Technical Guide/ Background Material on Service Tax**

With a view to assist the members working in the field of Service Tax, following publications have been released by the Committee:

- a) Technical Guide on Service Tax – Works Contract
- b) Technical Guide on CENVAT Credit (Revised)
- c) Technical Guide on Service Tax - Insurance Sector
- d) Background Material on Service Tax - Entertainment Sector

(ii) Technical Guide on State VAT

With a view to assist the members working in the field of VAT, the Committee has decided to develop Technical Guide VAT Law for every State. In this direction, following publications have been released by the Committee:

- (a) Technical Guide on Rajasthan VAT
- (b) Technical Guide on Gujarat VAT
- (c) Technical Guide on Jharkhand VAT
- (d) Technical Guide on Mizoram VAT
- (e) Technical Guide on Assam VAT
- (f) Technical Guide on Uttarakhand VAT
- (g) Technical Guide on Delhi VAT
- (h) Technical Guide on Karnataka VAT
- (i) Technical Guide on Goa VAT
- (j) Technical Guide on Odisha VAT

(iii) Background Material on GST

With a view to update the members with the development made on GST in the country, the Committee has developed and released a background material on Goods & Services Tax. Further, the background material has been revised wherein 122nd Constitution Amendment Bill, standardized PPT and annexures like the IT Strategy for GST, List of Countries implementing VAT/GST has been added.

(iv) GST Kit

The Committee launched GST Kit at the International Conference at Bangalore on 29th January, 2015 to facilitate easy understanding of the subject. The Kit contains:

- Background Material on GST
- Standardized PPT on GST
- Recording of LIVE Webcast – A talk on GST

(v) A New Publication: GST – A Boon for Indian Economy

A new publication - GST—A Boon for Indian Economy was released at Annual Function of the Institute on 1st July, 2015. It has been specifically designed for Members of Parliament & Legislative Assemblies of State and briefly elucidates the concept of GST, its benefits for Indian Economy with illustrations. The Concepts of Revenue Neutral Rate, IT Strategy of GST, Comparison between present & proposed tax regime, GST in other countries etc. has also been explained.

(vi) E-Flash on Amendment made by Union Budget 2014-15

With a view to update the members on the changes made by Union Budget 2014-15, the Committee along with Direct Taxes Committee, Committee on International Taxation and Committee on Public Finance and Govt. Accounting released E-Flash on Amendment made by Union Budget 2014-15.

(vii) Compliances of Service Tax in Banking Sector - Revision

The Committee has revised its publication “Compliance of Service Tax in Banking Sector”. It inter-alia, contains Questionnaire for Service Tax Audit of Banks, which would be helpful for the members in checking the compliance of service tax in Banking Sector.

(viii) Background Material on Training Programme for CBEC Officials

The Committee has thoroughly revised Background Material on Training Programme for CBEC Officials with amendment made till April, 2015.

(ix) CBEC Kit

The Committee has developed CBEC Kit to facilitate the Excise and Service Tax Commissionerates to understand the need, objective and benefit of the training programme organised for their officials as an initiative to partner the Government in Nation Building. The Kit contains brief of training programme, its objective and Background Material.

5.16 Committee on Information Technology

The Committee on Information Technology has been constituted by the Council of the ICAI as a non-standing Committee in the year 2000 to identify Information Technology challenges facing the profession and convert them into gainful professional opportunities for members by conducting Post-Qualification and Certificate Courses, Conferences, Seminars, and Practical Workshops, Training programmes, ERP/ IT courses apart from Practice Guides, Training Aids, Software's and Publications on Information Technology for the benefit of members.

1. Programmes/ Seminars/ Conferences/ RRCs organized

The Committee organizes many IT related workshops, Seminars and conferences which are of flexible duration and help the members in keeping abreast with latest developments in IT related fields. Details of various seminars is as follows:-

S.No.	Date	Programme Name	Location	No. of Participants
1	23-02-2014	IT Security in CA's office	Mumbai	22
2	08-03-2014	Workshop on Advanced Excel 2010	Vashi, Maharashtra	28
3	05-04-2014	Workshop on MS Excel	Siliguri	45
4	17-05-2014	Practical Workshop on Information Technology	Vadodara	35

5	17-05-2014	Workshop on Information Technology	Jamnagar	8
6	17-05-2014	Workshop on Advance Excel	Dhule	11
7	30-05-2014	Seminar on Digital Threats and Security	Panaji	33
8	31-05-2014	Workshop on Advance Excel	Latur	26
9	14-06-2014	Advance Course on Optimum Use of Tally.ERP9	Siliguri	50
10	11-07-2014	National Seminar on Information Technology	Hubbali	286
11	26-07-2014	Seminar on Forensic & Digital Investigations in an IT Environment	Delhi	121
12	04-10-2014	National Conference on Information Technology	Pune	164
13	18-10-2014	Seminar on Information technology	Kolkata	127
14	21-11-2014	Workshop on Cyber Security	Bhubaneshwar	27
15	07-12-2014	Cyber Crime Investigations & Tools used for Digital Forensics Audit	Mumbai, BKC	26
16	20-12-2014	Excel with Workshop on Macros and VBA Training	Mumbai, BKC	10
17	28-03-2015	IT Security in CA's Office	Mumbai, BKC	27
18	04-04-2015	Workshop on Excel as an Audit Tool	Mumbai, BKC	35
19	25-04-2015	Workshop on IT Security in CA's Office	Surat	34
20	12-05-2015	Training Programme on Fraud Detection and Prevention by Internal Auditors	Mumbai, BKC	29
21	29-05-2015	2 nd Faculty Development Programme – Forensic Auditing and Fraud Prevention	Mumbai, BKC	24
22	06-06-2015	Seminar on Forensic Accounting and Fraud Prevention	Hyderabad	30
23	11-06-2015	Seminar on Forensic Accounting and Fraud Prevention	Goa	42
24	18-06-2015	Seminar on Information Technology	Kolkata	40
25	03-07-2015	2 nd Faculty Development Programme for ISA Course	Mumbai	24

2. Certificate Courses

A. Post Qualification Course on Information System Audit 2.0

The Post Qualification Course on Information Systems Audit has been the first and foremost important initiative launched by the Committee to enable members to offer value added services in the field of IS Audit.

The Committee has launched the Post Qualification Course on Information Systems Audit 2.0 which is conducted through a good blend of e-learning (online and facilitated), class room training, hands-on training with practical case studies and project work to ensure practical application of knowledge.

The objective of updated ISA 2.0 course is to meet the increasing market needs of CAs with solid IT skills that can provide consulting/assurance services. The study material has a companion DVD which includes all the reading material, E-learning, supplementary reference materials and checklists in soft copy.

B. Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Prevention: The Committee offers Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Prevention. This programme is now rolled out across the country. The course is a blend of hands on training, case studies, presentations by faculties, project presentations (having weightage of 20 Marks), PPT submission (having weightage of 20 Marks) and preparation of 2 Forensic Reports by the participants carrying weightage of 60 marks. At the end of course, a 100 Marks objective test is conducted. This course is very popular amongst the members and the Committee is regularly conducting courses across the country.

S.No.	Date	Venue	No. of Participants
1	08-05-2014 to 18-05-2014	Indore	47
2	30-05-2014 to 05-06-2014	Kolkata	41
3	12-06-2014 to 22-06-2014	Mumbai	52
4	16-07-2014 to 22-07-2014	Ludhiana	44
5	01-08-2014 to 07-08-2014	Bengaluru	48
6	10-10-2014 to 19-10-2014	Mumbai	51
7	27-10-2014 to 02-11-2014	Hyderabad	48
8	06-11-2014 to 12-11-2014	Chandigarh	39
9	09-01-2015 to 15-01-2015	Mumbai	47
10	22-01-2015 to 30-01-2015	Bhopal	36
11	31-01-2015 to 06-02-2015	Chennai	34
12	25-04-2015 to 10-05-2015	Rajkot	39
13	01-5-2015 to 17-05-2015	Lucknow	47
14	09-05-2015 to 17-05-2015	Thane, Maharashtra	44
15	21-05-2015 to 07-06-2015	Indore	40
16	30-05-2015 to 21-06-2015	Bhubaneswar	46
17	08-06-2015 to 18-06-2015	Nagpur	26
18	12-06-2015 to 28-06-2015	Aurangabad	21
19	13-06-2015 to 05-07-2015	Jaipur	29
20	27-06-2015 to 26-07-2015	New Delhi	40
21	03-07-2015 to 26-07-2015	Bhilai	30

3. **IT Awareness Programmes, Workshops, Seminars, and Conferences**

The Committee organizes many IT related workshops, Seminars and conferences which are of flexible duration and help the members in keeping abreast with latest developments in IT related fields.

4. **DISA Faculty Meet**

The Committee has organized 4 DISA-Faculty meets for the review of DISA course & improvement of DISA Course Background material. The Committee asked the faculty for compilation of best case studies & Model Test papers for ET & AT Exams.

Details of DISA- Faculty Meet are as follows:

- DISA-Faculty Meet on 31st May, 2014 at Manipal, Udupi attended by 25 faculties.
- DISA-Faculty Meet on 5th June, 2015 at BKC, Mumbai attended by 28 faculties.
- DISA-Faculty Meet on 30th June, 2015 at COE, Hyderabad attended by 20 faculties.
- DISA-Faculty Meet on 1st July, 2015 at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, Delhi attended by 21 faculties.
- DISA-Faculty Meet on 15th July, 2015 at Kolkata (EIRC Premises) attended by 19 faculties.

5. **Forensic Accounting Course for Government organisations**

The Committee has decided to organize training programmes on Fraud Investigation and Forensic Accounting for Government organizations and other Institutions. The central objective of this course and training programmes is to provide the officers and senior members an insight into the world of fraud, financial wrong doings and possible ways of detecting them. This course is meant for recognizing early warning bells of frauds, examining them and investigating them as and when deemed necessary. New and uncommon methods will be explained and discussed to make the investigating officers better prepared and equipped to tackle such situations.

- Conducted training programme on Forensic Accounting and Fraud Detection for officials of State Bank of India
- Training Program on Analysis of Financial Statement for Officers of Serious Fraud Investigation office on 11th March, 2015 to 14th March, 2015 at IICA, Manesar.

Significant Achievements

1. **Post Qualification Course on “Information System Audit (ISA)”**

Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit (ISA) has been a great unifying force bringing together members for a unique information sharing, professional development and training initiative. The ISA PT Batches, ISA Eligibility Test & ISA Assessment Test were organized across the country. The Committee conducted following ISA Eligibility Tests:

- On 10th May, 2014 at 42 Centers including Sri Lanka and Nepal.
- On 15th November, 2014 at 38 Centers including Sri Lanka.
- On 9th May, 2015 at 42 Centres including Sri Lanka.

2. **Faculty Development Programme**

The Committee conducted 2 Faculty Development Programme at ICAI Tower, BKC, Mumbai for FAFP & ISA from 29th May to 31st May, 2015 & 3rd July to 5th July, 2015 respectively and invited 20 & 22 ISA Faculties FAFP-FDP & ISA-FDP respectively. The objective of the Faculty Development Programme was to standardize the teaching methodology. It was very well received by the participants and also received very good feedback and suggestions for the improvement of the Certificate course on FAFP & ISA.

3. **Launch of Revised ISA Course**

The Committee has launched the new ISA Course 2.0 and the ISA PT batch with new course launched on 5th July, 2014 at ICAI Bhawan, Sector 62, Noida. The overall objective of the DISA course 2.0 is to provide relevant practical knowledge and skills for planning and performing various types of assurance or consulting assignments in the areas of Governance, Risk management, Security, Controls and Compliance in the domain of Information Systems and in an Information Technology environment by using relevant standards, frameworks, guidelines and best practices. The DISA course is conducted through a good blend of e-learning (online and facilitated), class room training, hands-on training with practical case studies and project work to ensure practical application of knowledge. The Committee has conducted 36 batches of revised syllabus, till 12th February, 2015.

4. **Maintenance of existing E-Learning courses**

The Committee is maintaining the following e- Learning Courses:

- Service Tax
- Transfer Pricing

- Standards on Audit
- Standards on Audit - Phase-II
- Standards on Audit - Phase-III
- Standards on Audit - Phase-IV

5. **Webcasts**

3 Webcasts were conducted on Big Data-Governance and Compliance, Effective use of various Forensic Audit Tools for bankers & FIs with latest technologies and Data Privacy & Protection: An Auditor's Perspective.

5.17 **Technology Development Committee**

The Technology Development Committee was constituted on 1st April, 2014 with the following terms of reference:

1. To Identify the Business Process Gaps, Plan Business management strategy, focusing on Business process re-engineering within the ICAI aimed to help ICAI to improve service to ICAI stakeholders and Cut Operational Cost.
2. To Identify, develop and monitor technology driven social media platform for ICAI.
3. To Identify, implement and develop IT platform including mobile platform for ICAI and setup the new communication platform anytime, anywhere access.
4. To identify the cutting edge technology tools available in market and suggest committee to advise and implement in ICAI for the benefit of ICAI.
5. To Review, monitor and implement various IT Initiatives.
6. To Keep Track of latest advances in technology space and harnessing them for benefit of ICAI.

Significant Activities and Achievements

The Committee in its 2nd meeting held on 12th March, 2015 and 3rd meeting held on 22nd April, 2015 has decided to promote Google Hangout on Air in ICAI for various committee meetings, events. Accordingly, the Committee has created integrated You Tube Channel & Google Plus Page for various Committees and Departments. Also, multiple events has been organized via Google Hangout on Air successfully for Committee meetings, events etc. The Committee also conducted its 3rd Committee meeting through online Google hangout to promote technology initiatives.

The Committee has published ICAI Mobile Application "ICAI Now" on all mobile platform (Android, iOS, Windows and BlackBerry 10). ICAI Now facilitates key updates like Announcement, Events, Photo, Video gallery, ICAI News, Institute Programme, President Message, Tender etc. Latest version of ICAI mobile Application may be downloaded from ICAI Website www.icai.org/mobile or respective mobile application store. The ICAI Mobile application is available free of cost on all platform.

The Committee updated latest version of ICAI Mobile Application Android 1.12 (Published on 10th June, 2015), iOS 1.6 (Published on 10th June, 2015), Windows 1.3 (Published on 10th June, 2015). The Blackberry 10 supported version is also added on 20th February, 2015.

ICAI Mobile applications are listed on Top Free categories on all platform and currently rated as 4.2/5. ICAI mobile application is successfully downloaded by more than 2,30,000 students and Members as on 1st July, 2015.

The Committee has enabled ICAI on Social Media on "Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus and YouTube. The Committee is regularly monitoring ICAI social media accounts.

ICAI Members and Students may connect to ICAI social network from ICAI Website www.icai.org/follow-us. ICAI social media sites is followed by 1,65,000+ students and members as on 1st July, 2015. (YouTube Channel 3,500+, Google Plus Page 9800+, Facebook 42,000+, Twitter 3500, and LinkedIn 1,06,000+).

5.18 **Internal Audit Standards Board**

Internal audit is a key pillar in effective corporate governance and risk management. It provides assurance that there is transparency in reporting as a part of good governance. Internal audit's scope is expanding because the expectations that boards and management place on it have increased in the new regulatory environment. The ICAI has constituted Internal Audit Standards Board in 2004 to provide valuable content on best practices and topical issues within the internal auditing profession. The Board helps the members working as internal auditors to take a serious look at audit quality and ensure that it is practiced consistently and professionally.

Apart from codifying internal audit best practices in the form of Standards on Internal Audit, it has also been the endeavour of the Board to help the members possess an always expanding tool-kit of technical literature. In this direction, the Board has been working relentlessly to issue generic and industry-specific technical guides, which comprehensively covers detailed procedures to be undertaken by the internal auditor in respect of industry specific and

other contemporary areas. With a view to disseminate knowledge among the members, the Board also organises Seminars, Conferences, Workshops, Webinars and also conducts Certificate Course on Concurrent Audit of Banks.

The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board till date:

Standards on Internal Audit

Eighteen Standards on Internal Audit

Compendium of Standards on Internal Audit (As on July 1, 2013)

Industry Specific Technical Guides

23 Industry Specific Technical Guides on Internal Audit

[Compendium of Industry Specific Internal Audit Guides \(As on January 1, 2015\)](#)

Generic Guidelines

17 Generic Guides on Internal Audit

[Compendium of Generic Internal Audit Guides \(As on January 1, 2015\)](#)

Knowledge Booklet

2 Knowledge booklets on internal audit and related areas

The major endeavors of the Board in this reporting period are given below:

- In its Action Plan/ Road Map 2014-15, the Board has endeavoured to align its activities for the year with the areas of strategic focus outlined in the ICAI Action Plan, to the extent applicable to the working of the Board.
- During the period, five meetings of the Board were held.
- The Board has issued *Compendium of Industry Specific Internal Audit Guides* which contains text of all the Twenty Two technical guides, issued by the Board.
- The Board has also issued *Compendium of Generic Internal Audit Guides* which contains text of all the Ten Generic guides, issued by the Board.
- The Board has issued *Guide on Risk Based Internal Audit Plan* which provides practical guidance on the subject.
- Dissemination of Knowledge about the Standards on Internal Audit among members is necessary, so the Board has organized a number of seminars, conferences.
- The Board has organized eight webinars on internal audit and related areas.
- During the period, the Board has issued sixth edition of its e-newsletter “Internal Audit and Beyond”.

A. Technical Literature

- **Technical Guide on Internal Audit of IT Software Industry**
During the last decade, India has seen a steady growth of IT Software Industry, which is constantly witnessing changes due to emerging technologies, such as, social media, mobility, analytics and cloud computing, etc. This unique sector faces complexity of processes which give rise to a spectrum of strategic, economic, operational, compliance, disaster, political, human capital and reputational risks. Internal auditors can play an important role in governance, risk and compliance aspects, which are essential to ensure that the IT Software industry remains on the growth path. Keeping this in view, the Board has issued “*Technical Guide on Internal Audit of IT Software Industry*”, which is aimed to equip the internal auditors with deeper understanding of this unique and complex industry.
- **Guide on Risk Based Internal Audit Plan**
Risk management has emerged as an important aspect of an organization’s governance, management and operations as it helps the organizations to understand the risks they are exposed to, put controls in place to counter threats, and also to effectively pursue their objectives. Risk based internal audit mainly report on the risk management that includes identification, evaluation, control and monitoring of the risk. Keeping this in view, the Board has issued “*Guide on Risk Based Internal Audit Plan*” to help internal auditors in embedding risk based approach thereby enabling them to meet stakeholder’s expectations.
- **General Guidelines on Internal Audit (Revised 2015 Edition)**
In order to incorporate changes brought out by the Companies Act, 2013 and revised Clause 49 of the Equity Listing Agreement, General Guidelines on Internal Audit has been thoroughly revised by the Board. The revised corporate governance norms have surely led to sweeping changes in the corporate governance environment in India. Nevertheless, these new requirements seek to raise governance standards and thereby, enhance the role internal audit is expected to play in this new regulatory environment. The Board has issued this

publication to provide updated guidance for the benefit of the members. These revised General Guidelines form the base for internal auditors to understand their roles and responsibilities in the changed scenario, and strive to meet the expectations of the stakeholders.

B. Knowledge Booklets

Knowledge Booklet II: A New Era in Internal Audit- Companies Act, 2013

This knowledge booklet highlights enhanced role of internal auditor in areas such as, Stronger Support for Audit Committee or Board, Effective Risk Management, Internal control Systems and Ensuring Compliance. Chartered accountants possess skill sets and knowledge which help them to demonstrate their competence and professionalism in the internal audit field.

C. Certificate Courses

The Board also organises the following Certificate Courses:

I. Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board conducts Certificate Course on “Concurrent Audit of Banks” to enable members to have in-depth knowledge of concurrent audit of banks. The Board has, till date, successfully completed one hundred seventy six batches of the Certificate Course at various places covering around 9100 members all over country. The Board has introduced OMR checking for examination of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks. Panel of expert faculties for Certificate Course on Concurrent Audit of Banks has also been formed.

II. Certificate Courses on Enterprise Risk Management

The Board offers Certificate Course on “Enterprise Risk Management” as internal auditor’s full potential can be exploited by developing his ability to provide advice and assurance on risk management to audit committee and executive management. The Board has successfully completed four batches of the Course organised at Delhi, Mumbai and Hyderabad respectively. The course is being restructured by the Board.

III. Certificate Course on Internal Audit

Educational experience, applicable knowledge and business tools that can deliver a positive impact on any organization or business environment are the end results of the Certificate Course on Internal Audit to its members offered by the Board. The Board has successfully completed the first batch of the Course organised at Hyderabad. The Course is being restructured by the Board.

D. Quarterly E-newsletter “Internal Audit and Beyond”

The Board has issued sixth edition of its’ quarterly E-newsletter “Internal Audit and Beyond”. This e-newsletter aims at enlightening professionals and other relevant members with the updates, technical pronouncements and opportunities in the mainstream internal audit world.

E. Programmes, Seminars, Conference for Awareness on Internal Audit

The Board also organizes conferences, seminars, training programmes, workshops on internal audit in various parts of the country which are hosted by the concerned Regional Council/ Branches of the ICAI. Following programs were organised by the Board during this period:

1. Seminar on Internal Audit on 9th April, 2014 at Amritsar
2. Seminar on Internal Audit on 10th April, 2014 at Patiala
3. Residential Refresher Course on 26th & 27th May, 2014 at Tirupati
4. National Seminar on “Audit, Risk and Governance” on 8th November, 2014 at New Delhi
5. ICAI Internal Auditor’s Interactive Meet on 14th May, 2015 at New Delhi.

F. Live Webinars on Internal Audit and Related Areas

The Board has conducted following Live Webinars:

- [Thirteenth on “Internal Audit Reporting” on 23rd May, 2014](#)
- [Fourteenth on “Demonstrating the Value of Internal Auditing to the Audit Committee” on 25th June, 2014](#)
- Fifteenth on “The Changing Paradigm of Internal Audit” on 9th October, 2014
- Sixteenth on “Practical Approach to Internal Audit of SMEs” on 7th November, 2014
- Seventeenth on “Positioning for Future Success: Transforming Internal Audit” on 27th December, 2014
- Eighteenth on “Enterprise Risk Management Framework and Internal Control Framework” on 28th January, 2015
- Nineteenth on “Internal Audit of Not-for-Profit Organisations (NPOs)” on 9th February, 2015

- Twentieth on "Expectations of Audit Committee from Internal Auditor" on 8th May, 2015

G. Faculty Development Program

The Board has conducted the Faculty Development Program for Certificate Course on Concurrent Audit of Banks in August, 2013 at Hyderabad. The Board conducted this program in order to improve the quality of the Certificate Course to match the expectations of the regulators and bankers. Further, the Board is planning to conduct more such programs during the year 2015-16.

H. Survey on Internal Audit

The Board has decided to conduct survey on internal audit and has constituted a study group. The perceived objectives of the survey are to gain insight on current trends and challenges facing the internal audit profession in the country.

I. E-learning on Risk Management

The Board has taken up the project of launching "*E-learning on Risk Management*". The objective is to help the members understand various issues relating to risk management and in developing necessary skills to provide value added services in this area.

J. National Conclave on Internal Audit

The Board is also planning to organize "National Conclave on Internal Audit" with the objective to provide a platform to share relevant business practices, discuss critical issues, and address other market dynamics affecting the role of internal auditors in corporate India.

5.19 Committee on International Taxation

Activities undertaken

A. Representations/ interactions with Government

- Representation on Form No. 3CEB
- Representation - Finance Act, 2014 - Key Transfer pricing amendments and their implementation
- Representation on the Draft scheme of the proposed rules for computation of Arm's length price (ALP) of an International Transaction or Specified Domestic transaction undertaken on or after 1st April, 2014.
- Submissions of inputs in a meeting held on 15th June, 2015 with the High Level Committee on Tax Laws formed under the Chairmanship of Shri Ashok Lahri on issue of MAT on FIIs.
- Representation for amendment to Rule 37BB and transitional relief u/s 119
- Submissions of inputs w.r.t. MAT on FIIs to the Committee on direct taxes matter formed under chairmanship of Shri A.P. Shah in a meeting held on 1st July, 2015

B. Activities relating to Budget - 2015

Suggestions on Pre-Budget Memorandum - 2015

Like every year, this year also Pre-Budget Memoranda was submitted to the Central Board of Direct Taxes. The suggestions for inclusion in the Pre-Budget Memorandum-2015 were sought from members all over India through an announcement on ICAI's website. The suggestions so received were compiled and submitted to the Direct Taxes Committee for inclusion thereof in the Pre-Budget memorandum. Accordingly, the Pre-Budget Memorandum was submitted to the Central Board of Direct Taxes in a meeting held with officials wherein major proposals relating to International taxation along with others were put forth.

Budget Viewing Workshop:

The Union Budget 2015-16 was presented on 28th February, 2015 and as a regular practice, the Committee along with the Direct Taxes Committee and Indirect taxes Committee organized a budget viewing session on the date of release of the budget wherein all the Council members and special invitees were invited. The budget proposals were discussed therein in detail. The highlights of the significant international taxation proposals were prepared and hosted on the website on the same day. The press release on Union Budget 2015-16 was also prepared and sent to Public Relations Committee.

Live Webcast on tax proposals of Union Budget, 2015-16

The Committee organised a 'Live Webcast' on tax proposals of Union Budget 2015-16 jointly with Direct Taxes Committee and Indirect Taxes Committee on 28th February, 2015 wherein the expert discussed the budget proposals at length. A mass mail and mass sms were sent well in advance to all the members informing about the said webcast. The webcast was well received by the members and was viewed by approximately 16000 members.

C. Other Initiatives

Approval for Diploma Course in International tax from Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Since ICAI has received approval for Diploma Course in International tax from Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Committee is working towards launching the course by December, 2015.

Certificate Course on International Taxation

The Committee has conducted batches of Certificate Course on International Taxation during the period 1st April, 2014 to 7th July, 2015 in New Delhi (2), Mumbai, Hyderabad, Jamnagar, Rajkot, Kolkata, Ahmedabad, Coimbatore, Kathmandu (Nepal), Vadodara, Surat, Thane and Pune.

E-Learning on International Taxation

The Committee, recognizing the significance of spreading knowledge of the International Taxation throughout the country, has developed e-learning modules to facilitate the learning of the subject by any member residing in remotest area. Accordingly, the e-learning module on Introduction to International Tax and Transfer pricing have been developed and is available to the members.

e-Newsletter

The Committee had released the second edition of the e-newsletter of the Committee in August, 2014.

Special Arrangements For Members

- (a) **Arrangement with ACE TP online** - The Committee has entered into an arrangement with Accord Fintech Pvt. Ltd. to offer a deep discounted subscription rate of Ace TP online version of their transfer pricing database to our esteemed members. Ace TP is available for subscription to all our members at Rs. 14,000/- (excluding all Taxes) per annum.
- (b) **Global Tax Guide of BNA Bloomberg for the Members of ICAI (without any Cost)**: As per the tie up of the ICAI with BNA Bloomberg, the Global Tax Guide is now effectively available to approximately all 2,30,000 members. The Global Tax Guide is an online service that will keep our chartered accountants updated with practical tax information, including tax rates, filing deadlines, and key developments, in more than 100 countries. It will significantly save the time it takes to find the right tax rate and compare regimes.

Fellowship meeting with delegates of 68th IFA Congress

With the ever increasing globalisation of world economics, International Taxation is getting all the more important and complicated. Expertise in this domain assumes particular importance for our members because India, as a growing hub of International companies, is also fast getting deeply integrated with the world economy. Being fully alive to this urgent need, ICAI has been taking continuous efforts to build capacities of our members in international taxation. Taking this drive forward, ICAI associated itself with the International Fiscal Association (IFA), a Netherland based highly trusted international organisation representing 110 countries which works for the advancement of international and comparative fiscal law and the financial and economic aspects of taxation. An interactive meeting between our members and delegates of IFA was organised, who had gathered for the 68th IFA Congress, 2014 in Mumbai.

Research on International Taxation

The Committee has taken an initiative and invited members to do research work on International Taxation in any of the following topic:

- I. Base Erosion Profit Shifting
- II. Permanent Establishment attribution
- III. Electronic Commerce
- IV. Transfer Pricing
- V. Digital Economy

In response, the Committee had received more than hundred applications to conduct research work from the members. On the basis of synopsis received, the research papers were called from selected candidates. The review of the same is in process.

Webcast on International Taxation

The Committee has taken an initiative to organize Live Webcast on various topics on International Taxation, Transfer Pricing and FEMA. The objective of these webcasts is to spread awareness of the subject and the developments on

regular basis to all the members. Video of the webcast is uploaded at www.icaity.com. During the period 1st April, 2014 to 7th July, 2015, the Committee has conducted total 13 webcast on various topics on International Taxation.

D. Seminars/ Conferences/ Tax Awareness programmes

A number of seminars, conference and tax awareness programmes were held throughout the country.

5.20 Committee for Members in Industry

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

I. Career Assistance Programmes organised for the benefit of the Members of the ICAI

The Committee organizes Campus Placement Programmes for newly Qualified Chartered Accountants twice a year.

For the year 2014-2015

1. Orientation Programmes

The Committee had conducted two round of Orientation Programme during 2014- 2015:

- (1) For the candidates who had appeared in the Campus Placement Programme - February-March, 2014 at 16 centres namely Bhubaneswar, Chandigarh, Ernakulam, Nagpur, Indore, Coimbatore, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Pune, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Kolkata, Hyderabad and New Delhi.
- (2) For the candidates who had appeared in the Campus Placement Programme - August-September, 2014 at 20 centers namely Ernakulam, Ahmedabad, Chandigarh, Kanpur, Coimbatore, Nagpur, Indore, Jaipur, Pune, Baroda, Thane, Vasai, Navi Mumbai, Bhubaneswar, Kolkata, Hyderabad, Mumbai, Bengaluru and New Delhi.

In the Orientation Programmes, eminent faculties were invited to address the candidates on various topics such as expectations of the Corporates from the Chartered Accountants, Soft Skill required for Fresh Chartered Accountants, How to succeed in Personal Interviews, Opportunities for Chartered Accountants in various industries etc.

2. Campus Placement Programmes

The Committee had conducted 39th edition and 40th edition of the Campus placement programme for the Newly Qualified Chartered Accountants

- (1) *39th edition of the Campus placement programme* was conducted for the Newly Qualified Chartered Accountants who had passed CA final examination in November, 2013. It was conducted in two phases at 15 centres across the country and around 2600 candidates had registered for the programme. Prominent organizations including public limited companies, public sector undertakings, banks, etc had participated and offered lucrative compensations to the Newly Qualified Chartered Accountants. On an overall basis, more than 700 jobs were offered to the candidates registered for this programme. Also, 80 top entities from the industry had participated in this programme with total number of 136 interview teams across all the centres. The selected Chartered Accountants have been offered rewarding salary packages for the international as well as the domestic posting. Highest salary under international posting was made by Sharaf Shipping Agency LLC at Chennai center to 3 candidates, i.e. Rs. 20.25 lacs per annum and, under domestic posting, it was offered by Bharti Airtel at New Delhi center to 2 candidates i.e. Rs. 21 lacs per annum.
- (2) *40th edition of the Campus Placement Programme* was conducted for newly qualified Chartered Accountants who passed CA final examination in May, 2014 at 6 bigger centres namely Chennai, Kolkata, Hyderabad, New Delhi, Mumbai and Bengaluru and at 13 smaller centre namely Ahmedabad, Vadodara, Bhubaneswar, Chandigarh, Coimbatore, Ernakulam, Indore, Jaipur, Nagpur, Navi Mumbai, Pune, Thane and Vasai. Around 4800 candidates had registered for the programme which had the participation of prominent organizations. On an overall basis, more than 1018 jobs were offered to the candidates registered for this programme. Also, 86 top entities from the industry had participated in this programme with total number 154 interview teams across all the centres. The Selected Chartered Accountants have been offered rewarding salary packages for the international as well as the domestic posting. Highest Salary offered for Domestic

posting in the Campus Placement Programme is Rs. 17 Lacs per annum and for International posting is Rs. 24 Lacs per annum.

3. ICAI - Industry HR Meet

The Committee has organized ICAI - Industry HR Meet on 29th April, 2014 at Mumbai. The objective of organizing ICAI - Industry HR Meet was to discuss certain critical issues relating to the organization of Campus Placement Programme throughout the country at various centres.

For the Year 2015-2016 (till 7th July 2015)

1. Orientation Programme

The Orientation Programme was organised at 20 centres across the country at Ahmedabad, Vadodara, Bhubaneswar, Chandigarh, Coimbatore, Ernakulam, Indore, Jaipur, Nagpur, Navi Mumbai, Pune, Thane & Vasai, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Kolkata, Hyderabad and New Delhi. In the Orientation Programmes, eminent faculties were invited to address the candidates on various topics such as expectations of the Corporates from the Chartered Accountants, Soft Skill required for Fresh Chartered Accountants, How to succeed in Personal Interviews, Opportunities for Chartered Accountants in various industries etc.

2. Campus Placement Programme

The 41st edition of the Campus Placement Programme for the Newly Qualified Chartered Accountants was conducted in two phases at 19 centres across the country and around 5591 candidates had registered for the programme which had the participation of prominent organizations including public limited companies, public sector undertakings, banks, etc. offered lucrative compensations to the Newly Qualified Chartered Accountants.

On an overall basis, more than 1300 jobs were offered to the candidates registered for this programme. Also, 90 top entities from the industry had participated in this programme with total number of 183 interview teams across all the centres. The selected Chartered Accountants had offered rewarding salary packages for the international as well as the domestic posting. Highest salary offered for International posting in the Campus Placement Programme is Rs.30.00 Lacs per annum offered by Tolaram Group at Bengaluru & Kolkata center to 8 candidates and, under domestic posting, it was offered by Bharti Airtel at New Delhi center to 2 candidates - Rs. 21.50 lacs Per Annum.

3. HR Meet

The Committee has organized ICAI Industry HR Meet on 26th June, 2015 (01:00 P.M to 04:00 P.M) at Hotel Lalit, New Delhi to reinforce the alliance between ICAI and the Corporates and to have Corporate feedback/suggestions about the norms and process of Placement for the next Campus Placement Programme August-September 2015. 43 representatives from various corporate have participated in the meet and provided their suggestions and feedbacks about Campus placement Programme.

II. Developing Competencies amongst the Members of Institute in Industry

For the Year 2014 -15

1. Mentor to guide the young aspiring and willing CAs - Launched Mentorship Programme

The Committee has launched the Mentorship Programme soliciting the experienced Members of the ICAI to take up the mentorship roles & make his/her humble contribution for the sustenance and growth of the noble profession and to enable more competitive edge to the profession. Senior & Experienced CA professionals were sent a request to volunteer for mentorship to recently qualified and other aspiring and willing CAs based on their merits and suitability with the belief that their kind presence and hand holding attributes will facilitate a high quality counseling and guidance to the aspiring and willing CAs and they will be able to choose a right career path in future by developing their skills, knowledge and attributes through effective mentorship and interactive learning process. Amidst huge responses received from both the senior members and newly qualified & aspiring chartered accountants, the Committee has started the implementation of the Mentorship Programme by reaching out to both the interested mentors and mentees. A total number of 54 mentors and mentees have enrolled for the Mentorship Programme.

2. Released 12th issue of CMII e-Newsletter

The Committee had released the 12th issue of e-newsletter which is available at link <http://220.227.161.86/33552cmii-e-newsletter23183main.pdf>. This e-newsletter is a window to the recent accomplishments by the Committee in 2014-15, as well as it seeks to enlighten the members about the new initiatives being undertaken for the benefit of the Members working in the Industry.

3. Launched ICAI Reconnect

The Committee had launched ICAI reconnect with the aim to communicate the privileges and other benefits of being members of the ICAI so that the Chartered Accountants who are not keeping the membership status active understands its importance and renew it on continuous basis.

4. CPE Study Circles for Members in Industry

ICAI has notified the norms for CPE Study Circles, which caters exclusively for the members in Industry. These CPE Study Circles are being contemplated to help Members who are in Industry to achieve the objectives of maintaining their core competencies and exchange professional knowledge amongst the members apart from fostering and developing fellowship. Please visit <http://www.cmii.icaai.org/cpe.asp> to see the entire norms of the CPE Study Circle for Members in Industry.

The Committee has been empowered to approve, guide and supervise the CPE Study Circles for Members in Industry, which will conduct Continuing Professional Education Programmes for the Members in industry. The norms provide for the minimum number of members required and the application procedure, rules for functioning, administration and accounts of these CPE Study Circles. 111 CPE Study Circle for Members in Industry had been formed so far by the Committee.

5. Outreach programme

The Committee organizes Outreach Programmes for members for half a day or full day, in the premises of the Corporate having number of Chartered Accountants. The programme has been conceived with an idea of bringing the Members in Industry closer to ICAI so as to share a common platform for various activities. Through these programmes, ICAI reaches the doorstep of the organizations and discuss the problems being faced by the members in industry.

The Committee had organized the following Outreach Programmes:

- (1) Outreach programmes in the premises of GAIL and Engineers India Limited on 16th April, 2014 at New Delhi.
- (2) Outreach programme in the premises of Syntel Limited on 6th May, 2014 at Mumbai
- (3) Outreach programme in the premises of Essar Limited on 10th May, 2014 at Mumbai.
- (4) Outreach programme in the premises of IDBI Bank on 6th June, 2014 at Mumbai.
- (5) Outreach programme in the premises of ONGC Limited on 2nd July, 2014 at Mumbai.
- (6) Outreach programme in the premises of Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited on 21st July, 2014 at Mumbai.
- (7) Outreach programme in the premises of John Deere Private Limited on 6th September, 2014 at Pune.
- (8) Outreach programme in the premises of Indian Oil Corporate Limited on 9th September, 2014 at Mumbai.
- (9) Outreach programme in the premises of J. M. Financial Ltd. on 19th September, 2014 at Mumbai.
- (10) Outreach programme in the premises of Blue Dart Express Ltd. on 12th October, 2014 at Mumbai.
- (11) Outreach programme in the premises of Edelweiss Financial Services on 7th November, 2014 at Mumbai.
- (12) Outreach programme in the premises of Navi Mumbai SEZ Pvt. Ltd. on 23rd November, 2014 at Mumbai
- (13) Outreach programme in the premises of Castrol India Ltd. on 25th November, 2014 at Mumbai

6. State Task Force

To give more visibility to the initiatives of the Committee and ICAI as a whole, the Committee has constituted State Task Forces. Activities of the State Task Forces comprise of the following:-

- To hold placement seminars.
- Recognise and project CA beyond traditional fields.
- Popularising the Job Portal being maintained by the Committee.
- Popularising and functioning of mentorship scheme.
- To hold liaison meetings of the members in industry with various industries.
- To co-ordinate with various branches regarding holding of the Programmes being organized by the Committee.
- To report back special problems of members in industry of different states to the Committee.
- To hold programmes for the members in industry.
- To constitute and run industry specific study groups.
- To form CPE Study Circles for members in industry.
- To conduct counselling sessions for the members who switch over from industry to practice and vice-versa.
- To discuss the various exposure drafts issued by the Institute.
- To have a dialogue with Chamber of Commerce, trade associations and discuss holding of job fairs etc.
- To popularize the activities of the Committee for Members in Industry.

Other salient features of the State Task Force are:-

1. Maximum number of members in a State Task Force would be twenty only.
2. Each State Task Force might constitute and run a maximum of two industry specific study groups, whose strength should not exceed ten.
3. Industry specific study groups might focus on the following aspects:
 1. Business Knowledge – covering National and International outlook, production, marketing, finance, HRD, general management,
 2. Accounting and Auditing issues,
 3. Direct and Indirect taxes etc.,
4. Heads of Branch of the ICAI to coordinate the conduct of meetings and submission of Reports to the Committee.

The Committee had formed State Task Forces in the states of Maharashtra, Gujarat and Goa.

7. Programmes on Contemporary topics for the benefit of the Members in Industry

The Committee had organised the following programmes on contemporary topics:

- (1) Seminar on “Industry Gear up- Roadmap for Implementation of New Company Law” on 27th April, 2014 at Mumbai.
- (2) Seminar on “Industry Gear up- Roadmap for Implementation of New Company Law” on 3rd May, 2014 at Thane.
- (3) Two Days National Seminar on Companies Act on 26th & 27th May, 2014 at Ernakulam.
- (4) Seminar on 'Corporate Social Responsibility' at Bandra Kurla Complex, Mumbai on 21st June, 2014 jointly with Committee for Cooperatives & NPO Sectors.
- (5) One Day National Conference on “Recent Developments Impacting the Corporate Sector” on 19th July, 2014 at Bangalore.
- (6) Seminar on Mergers & Acquisitions on 13th December 2014 at Mumbai
- (7) Comprehensive Conference on Professional Opportunities in WTO, FEMA, Intellectual Property Rights & other Economic, Commercial Laws' hosted by WIRC of ICAI on 13th & 14th December, 2014 at DirectiPlex, Mumbai.
- (8) Lecture Meeting on Redevelopments of Properties on 17th December, 2014 at Mumbai.
- (9) Seminar on IFRS, Appellate proceedings under ITax & MVAT on 21st December, 2014 at Thane.

8. Residential Refresher Course

The Committee had organised the 7th International Residential Refresher Course from 12th–17th August, 2014 at Tashkent.

9. Residential Interactive Meet

The Committee had organised Residential Interactive Meet for Members in Public Services on 2nd, 3rd & 4th January, 2015 at Pune.

10. Members in Industry Meet/ CFO/ CEO Meet

To improve the relationship between the Institute and the members working in Industry and to discuss the issues of contemporary importance and mutual concern, the Committee is organizing meetings of the Members who are at the helm of affairs in the Corporates in all major cities.

Interactive Meet of the Members in Industry organised – 16th May 2014 at New Delhi, 1st June, 2014 at Rajkot, 27th June, 2014 at Mumbai, 4th July, 2014 at Baroda, 6th July, 2014 at Jalgaon, 17th July, 2014 at Kolkata and 12th September, 2014 at Navi Mumbai

11. Publications/ Compilations

The Committee had released following publications:

- CMII Activities - A Platform for Members in Industry
- Revised edition of Handbook for Newly Qualified Chartered Accountants
- Mentorship Programme
- ICAI Re-Connect

12. Recognition and Appreciation to the Members in Industry who have completed two decades of their professional contribution

The Committee had sent a special letter to recognize and appreciate the Members in Industry who had completed two decades of their professional contribution on the eve of 1st July, 2014.

13. Jury Meet for ICAI Awards 2014

The Committee had organised Jury Meet for ICAI Awards 2014 on 19th December, 2014 in Hotel Sahara Star, Mumbai to select the best amongst the best Chartered Accountants in Industry amongst the nominations received for ICAI Awards 2014.

List of Jury Members for Jury Meet for ICAI Awards 2014

- Shri Pawan Kant Munjal, Vice Chairman, CEO & MD, Hero MotoCorp Limited (Jury Chairman)
- Shri Tapan Singhel, CEO & MD, Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.;
- Smt. V.R. Iyer, CMD, Bank of India;
- Shri Ashish Chauhan, MD & CEO, Bombay Stock Exchange Limited;
- Shri G. Srinivasan, CMD, New India Assurance Company Ltd.;
- Shri D. K. Sarraf, CMD, Oil & Natural Gas Corporation Ltd.;
- Dr. Ashok Kumar Balyan, MD & CEO, Petronet LNG Ltd.;
- Shri D R Dogra, MD & CEO, Credit Analysis & Research Ltd.,
- Ms. Schauna Chauhan, CEO, Parle Agro Pvt. Ltd.,
- Shri Ramesh Nair, CEO & Whole Time Director, Bharat Aluminium Co. Ltd.,
- Shri. Rashesh Shah, Chairman, Edelweiss,
- Shri Anand Aggarwal, CEO & Whole Time Director, Sterlite Technologies Ltd.,
- Smt. Paru M. Jaykrishna, Chairperson and Managing Director, Asahi Songwon Colors Ltd. & Aksharchem (India) Ltd.,
- Shri Yaduvendra Mathur, CMD, Export-Import Bank of India etc.

14. 8th ICAI-CMII Corporate Forum and Awards 2014 (www.corporateforum.icai.org)

The Committee had organized Annual Corporate Forum 8th time in a row at Mumbai on 31st January, 2015 and 1st February, 2015 comprised of following high profile events:

- (1) **Corporate Conclave (31st January, 2015 & 1st February, 2015):** ICAI-CMII Corporate Conclave - In pursuit of Excellence - Two days National Convention with theme Transformation towards Excellence - This Convention focused on various important topics of relevance to the members of the ICAI and beneficial in keeping them updated in this dynamic environment. The topics of the Corporate Conclave were Fund Raising through BSE, SME Platform; Foreign Direct Investment: Emerging Markets in India, Benefits, Issues, Challenges and Opportunities for the Chartered Accountants; Automated Fraud Detection and Prevention: Systems and methods for dynamic detection and prevention using technology to implement real-time fraud prevention and detection programs and dependence of businesses on fraud detection technologies; NBFCs - Funding avenues - Stringent regulations - way forward; Media Industry: Overview, Business Models, Funding Options, Restructuring and Professional Opportunities for the Chartered Accountants; REITs - impetus to real estate market, limitations and tax issues; Recent developments in legal, tax and accounting issues in real estate industry including key issues and taxation of redevelopment; Facelift of a CA from traditional role to transformational role: Flourishing in New age requirements like Business Process core competency and in IT; Business Partnering: A new direction for CA professionals, understanding the business issues in partnering arrangements and partnering success; Knowledge Process Outsourcing – Expanding Frontiers — roadmap for industry, profession; USD - INR: A Perspective; Companies Act, 2013: New Concepts, Challenges, Opportunities; Expanding Role of Private Equity Funding: Avenues for Industry, Role of CAs; How Indian Agriculture and Economy is unfolding. The sessions were taken by eminent faculties. More than 250 participants had attended this convention.

Shri Rana Kapoor, President ASSOCHAM & Founder, MD & CEO, Yes Bank Limited was the Chief Guest of the programme.

- (2) **Financial Services Expo (31st January, 2015 & 1st February, 2015)** - A platform where Chartered Accountants and Corporates from all over India had marked their presence. This enabled various organizations to interact with Chartered Accountants, Investors, Finance Fraternity, and Corporate Decision Makers.

Following organizations had participated:

- (1) Yes Bank
- (2) Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
- (3) Power Grid Corporation of India Limited
- (4) HDFC Limited
- (5) Oil India Limited
- (6) BSE Limited
- (7) NHPC Limited

- (8) HPCL
- (9) ONGC Limited
- (10) ONGC Videsh Limited
- (11) GRUH Finance Limited
- (12) Tata Consultancy Services Ltd.
- (13) Finolex Industries Limited
- (14) Power Finance Corporation Limited
- (15) Novartis India Limited
- (16) L&T IDPL, Chennai
- (17) REC Limited
- (18) National Small Industries Corporation (NSIC)
- (19) SBI Capital Markets Ltd
- (20) IDBI Bank
- (21) Indraprastha Gas Limited
- (22) Blue Dart Express Ltd.
- (23) HPCL
- (24) Engineers India Limited
- (25) Petronet LNG Limited
- (26) State Bank of Travancore
- (27) The Cotton Corporation of India Limited

3) ICAI Awards 2014 (1st February, 2015) - The ICAI Awards 2014 honoured the contribution of Chartered Accountants across various sectors, corporate houses and MNCs in India. This Award Ceremony was inaugurated by Chief Guest, Dr. Subhash Chandra, Chairman, Zee Entertainment Enterprises Ltd. The Guests of Honour include the Galaxy of Industrialists and high profile dignitaries in public life.

There were three main categories of awards namely; CA Business Leader, CA CFO and CA Professional Achiever.

The Business Achiever Award appreciated the professionals from the genre of CEO, Directors or equivalent positions from sub categories across companies in Financial Services, Corporate, Public Sector, SME, CA Global Achiever, Woman and others.

Appreciating the noteworthy work by CFO's (Chief Financial Officer) the CFO award category was felicitated to professionals in sub categories from sectors like Manufacturing, Financial Service, Information Technology, Media and Entertainment, Telecom, FMCG Sector, Infrastructure & Construction, Banking Sector, Government Department, Insurance Sector, Power Sector, Oil & Gas Sector, Service Sector, NGO & Cooperative Sector, Agriculture Sector, Woman, Healthcare, Engineering & Capital Goods, Public and others.

Professional Achiever Award was given to appreciate managers in the early or middle stage of their careers. The sub-categories included sectors like Manufacturing, Financial Service, Information Technology, Media and Entertainment, Telecom, FMCG Sector, Infrastructure & Construction, Banking Sector, Government Department, Insurance Sector, Power Sector, Oil & Gas Sector, Service Sector, NGO & Cooperative Sector, Agriculture Sector, Woman, Healthcare, Engineering & Capital Goods, Public and others.

For the year 2015-2016 (till 7th July, 2015)

1. Formation of CPE Study Circle for Members in Industry

The Committee had formed 2 more CPE Study Circle for Members in Industry namely Infosystems CPE Study Circle and Technosmart Sector-1 CPE Study Circle. Thus, total numbers of CPE Study Circle for Members in Industry formed so far are 113.

2. Outreach Programme

The Committee had organized the following Outreach Programmes:

- (a) Outreach programmes in the premises of GAIL Barclays Shared Business Private Limited
- (b) Outreach programme in the premises of HCL Technologies Limited.
- (c) Outreach programme in the premises of HCL Infosystem Limited

3. Programmes organized

The Committee had organized Seminar on "Amendments in Corporate & Tax Laws and Compliance" on 19th April, 2015 at Chittorgarh

4. Members in Industry Meet/ CFO/ CEO Meet

The Committee had organized the following programmes:

- (a) ICAI CMII – Industry Interactive Meet on 22nd April, 2015 at ICAI Bhawan, New Delhi
- (b) ICAI CMII – Industry Interactive Meet on 12th May, 2015 at ICAI Bhawan, New Delhi
- (c) ICAI CMII – Industry Interactive Meet jointly with Board of Studies on 9th June, 2015 at Hotel Le-Meridien, New Delhi.

5. Webinar

The Committee had organized the following Webinar:

- (a) Webinar on 'Principal based leadership and its benefits' on 12th February, 2015
- (b) Webinar on 'NHB subsidy scheme for cold storage and role of Chartered Accountants' on 13th February, 2015

6. Publications/ Compilations

The Committee had released third edition of Business Planning.

5.21 Peer Review Board

The Peer Review Board of the ICAI set up by the Council in the year 2002 has been a successful endeavour. It aims to maintain and enhance the quality of assurance service. It has been able to achieve its objectives for which it was set up.

The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignments, the members of the ICAI (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services.

The planned effort of the Board couples with effective performance of the Peer Reviewers not only inspired the practice units to continually improve the quality of service that they render to the society at large also attract the attention of and received recognition from various regulatory authorities. The requirements in recognition of the Board's endeavour, of two regulators such as, SEBI and C&AG are stated below:-

- The Securities & Exchange Board of India (SEBI), has made mandatory with effect from 1st April, 2010 for the listed entities, that limited review/ statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the ICAI.
- The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has recognized Peer Review Board's work; as it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore from last few years, the C&AG annually seeks details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Peer Review Board.

Key Statistics

- 1799 Practice Units being 100% of Category I & Category II firms as per Professional Development Committee Peer Review initiated during the year (total practice units selected under peer review across India: 11475).
- 340 Practice Units/ firms of Peer Reviewers having done at least 3 Peer Reviews being initiated during the year.
- 1875 Peer reviews of firms initiated during the year.
- 924 Peer Reviews completed during the year and peer review certificates issued to the practice units.
- 22 Follow on reviews recommended.
- 890 new Peer Reviewers Trained.

The Board started the year 2014-15 with "House Keeping" exercise and consequently 127 Reviewers (out of total 4770 reviewers) who ceased to be in full time practice removed from panel and 422 Practice Units on Peer Review Board panel were found ceased to exist as per M&SS Section for reasons such as Merger/ Closure.

Improvements in Peer Review Process & Reporting

With a view to improve the quality of review & reporting by Peer Reviewers six study groups were constituted in different regions under convenorship of Board members to study best international practices followed across jurisdictions & incorporate same by Peer Review Board to bring overall improvements. Meetings of study groups were held at New Delhi, Hyderabad, Indore, Mumbai, Patna and Noida. Based on feedback considered by the Board, the following improvements are incorporated:

- Declaration to be filed by Practice Unit for Peer Review intimating current profile & level before allotment of Panel
- Questionnaire for Practice Unit made comprehensive incorporating Companies Act, 2013 & updated SA
- Final Report by Peer Reviewers made elaborate for Level I Practice units
- Content of the Training Programme Schedule revised putting special emphasis on Technical Standards, sharper focus on compliance with audit documentation, and review process and reporting.
- Criterion prescribed for change in panel of Peer Reviewers to Firms after first allotment.

E-Initiatives: To improve the Quality of Peer Review

E-book of Peer Review Manual in line with the action plan of the President, ICAI was launched on CA Day, so as to facilitate the peer reviewers and practice units to refer E-manual on real time basis viz. when the peer reviewer is onsite of the Practice Unit to improve the Quality of Peer Review it can be accessed on their smart phones, tablets etc as and when required.

Web enabled Form for Profile updating by reviewers: Statement on Peer Review Para 10.1 (f) requires peer reviewer of Level I entity should be a member in practice having conducted audit of Level I entities for at least 7 years, this data was found during “housekeeping” to be separately available for peer reviewers. As such, to facilitate online updation of details of peer reviewers, so as to appoint the reviewers matching to the level and profile of practice units. This has improved the quality of Peer Review. The reviewers can update their profiles with regard to their level of work/ audit done regularly on real time basis.

Peer Reviewers Training Programme:

- In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review. This year the Peer Review Board has organized 22 Training Programmes at Ghaziabad, Agra, Lucknow, Indore, Noida, Patna, Raipur, Thiruvananthapuram, Kolkata, Delhi, Allahabad, Varanasi, Mumbai, Jalandhar, Gwalior, Kanpur, Vadodara, Chennai, Jaipur, Bikaner, Bhubaneshwar, Jamshedpur, Dhanbad and trained 890 (approx) peer reviewers, with this total of 5363 reviewers have been trained so far in 151 peer review training programmes organized by the Peer Review Board.
- Peer Review Board had also organized a Conclave on Technical Standards on 6th December, 2014 at New Delhi in which Shri Prasenjit Mukherjee, Deputy Comptroller and Auditor General (CAG) & Chairman, Audit Board and Shri P. Sesh Kumar, Director General (Commercial Audit) were the Chief Guest and the Guest of Honour respectively.
- In view of regular changes in regulatory environment and technical standards and resultant need for reviewers to be updated with developments, it is decided by Board that Peer Review Training will have validity of 5 years.

5.22 Professional Development Committee

An introduction

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee by the ICAI. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the ICAI which has always been making vigorous efforts towards exploring and making available ample opportunities for the members of the ICAI in different sectors of the economy. It determines the professional developmental needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, the Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the ICAI by exploring/ pursuing new/ existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

- Representations have been sent to senior officials of Central Government and Ministers and senior officials of all State Governments stating the legal status and strength of ICAI & its members with a brief submission to utilise professional expertise of CAs to strengthen the Indian Economy.
- The Committee took many initiatives during the year, like holding meetings with different officials of Ministry of Finance, in different government departments, regulatory bodies etc. Besides meetings, the Committee organized seminars and workshops with the objective of improving the skills of the members, keeping them abreast of the new rules & regulations and bringing members and regulators closer to each other.

- The Professional Development Committee Knowledge Portal which is available at the link www.pdcai.org continues to provide its services to the members with timely and essential information on new professional opportunities in different sectors to the members.

The major endeavours of the Committee in this reporting period are given below:

- Professional Development Committee has over the years expressed its concerns on the issue of appointment of auditors of Public Sector Banks by the Banks' Board themselves. In order to fulfil its obligations to set high standards of corporate governance and to bring transparency in appointment of statutory auditors of Public Sector Banks, the ICAI has been representing at highest competent authorities
- Office of the Comptroller Auditor General of India (O/o C&AG) has accepted suggestions to discontinue applicability of minimum compensation criteria in respect of sole proprietor firms.
 - As per our suggestions, O/o C&AG for the first time hosted the Provisional panel of Chartered Accountant firms/LLPs for the year 2015-16 for indicating the position (detailed point score) of the firms. Provisional empanelment status/ Point Score of the firm were subject to verification of online data with documents submitted in support of online application and ICAI data. The provisional panel was available from 27th April to 6th May, 2015. All representations/ queries received in this regard was forwarded to the O/o C&AG as and when received.
- Pursuant to our meeting, National Highways Authority of India (NHAI), New Delhi has accepted to reduce the Earnest Deposit Money from Rs. 10,000 to below Rs. 2,000 in their future RFPs.
- A letter has been sent to the then Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India requesting to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) under Statutory Audit by restoring the threshold (Advances) limit for audit of branches of public sector banks to Rs. 6 crore. A follow-up letter has also been sent.
- A representation has been sent to Hon'ble Union Minister of Finance, Government of India requesting to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) under Statutory Audit by restoring the threshold (Advances) limit for audit of branches of public sector banks to Rs. 6 crore.
- A representation was sent to Deputy C & AG (Commercial), Office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi requesting for empanelment of those firms which are being disqualified from the panel maintained by the O/o C&AG due to the application of minimum compensation criteria while deciding whether or not to consider a partner as full time partner with the applicant firm.
- A letter has been sent to the then Executive Director, Reserve Bank of India requesting to issue necessary instructions to all the Public Sector Banks that the statutory audit work cannot be taken up by the concurrent auditor and the concurrent audit work cannot be taken up by the statutory auditor.
- A representation has been sent to Governor, Reserve Bank of India requesting to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) under Statutory Audit by restoring the threshold (Advances) limit for audit of branches of public sector banks to Rs. 6 crore.
- A Meeting was held with the then Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to discuss matters of mutual professional interest.
- A representation has been sent to Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India requesting to adopt same mechanism for appointment of Branch Statutory Auditors of Public Sector Banks (PSBs) as done for appointment of Central Statutory Auditors (CSAs) of PSBs.
- A representation has been sent to Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance requesting them to adopt a transparent and equitable process for appointment of CSAs of PSBs.
- Conference for Central Statutory Auditors (CSAs) was organised in Mumbai. The program was well attended by RBI officials including Ms. Meena Hemchandra, Principal Chief General Manager, Department of Banking Supervision, RBI and Shri S C Mishra, Chief General Manager-In-Charge, Department of Banking Supervision, RBI and saw a huge and motivated participation from CSAs.

- As part of the Corporate Social Responsibility to be undertaken by the Public Sector Undertakings (PSU) governed by the Ministry of Power, all PSUs will send their CSR funds for construction of toilets facilities in such schools which falls in the jurisdiction of their offices/ workshops/ factories etc. and not having or having insufficient toilet facilities. It has been desired by the Ministry of Power that the amount spent under such activity be verified suitably and services of chartered accountants be utilized for the purpose on *Pro Bono* basis.
 - In this regard, acceptance from Chartered Accountants to conduct these audits has been hosted on ICAI website for inviting expression of interest from the interested members. Till date, we have received the acceptance from more than 625 members.
- A meeting was held with Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance to discuss the matters of mutual professional interest. Subsequently, a representation was submitted to Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance requesting to consider the issues related to managerial autonomy and to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) under Statutory Audit.
- A letter was sent to then Principal Chief General Manager, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India with reference to the draft minutes of the meeting held at RBI, Mumbai, on 8th April, 2015 which was received from RBI vide e-mail dated 17th April, 2015 wherein as per point no 2 of Annex 1, it is mentioned that “Both CISA/ ISA qualified partners and CA employees should be full time so that full services of both CISA/ ISA qualified partner/ paid CA may be available during the bank audit, which will improve audit quality. In this regard it was reiterated vide our e-mail and letter, that such a change should be applicable for appointments for the FY 2016-17 only as the current data submitted for allotment of audit for the FY 2015-16 is as of 1.1.2015 and any change made now would give the retrospective effect to the provision.
- A letter was sent to ACS and Head of the Department, Madhya Pradesh State Tech-e Panchayat Society (MPSTEPS), O/o the Commissioner, Panchayat Raj Directorate, Bhopal regarding the tender floated by the organization for conducting concurrent audit of PRIs wherein it was suggested that a working may be carried out as per the assignment and value of assignment may be estimated internally and all the (frivolous) bids received for the said assignment, which are below the said internally worked upon cost, may be rejected.
 - Subsequently, a letter no. 617/PRD/MPSTEPS/Audit/51-B/15 Bhopal dated 22nd April, 2015 has been received from Commissioner, GoMP, Panchayat Raj Directorate & CEO, Madhya Pradesh State Tech-e Panchayat Society (MPSTEPS) wherein they have recommended that ICAI should take up the training of public representatives on audit and accounts to bring accountability, transparency for all the public money spent on Development of Public assets.
 - A reply to this was sent vide letter dated 14th May, 2015 saying that ICAI would like to offer a range of training programs tailor made for their esteemed organization too to take the capacity building measure to the grass root level. ICAI would be happy to provide experts to ensure more accountability in the entire process.
- A Round Table Interface of Independent CA Directors: A Collaborative Learning was organised at Hotel Claridges, Aurangzeb Road, New Delhi. Deputy Comptroller & Auditor General of India, O/o Comptroller & Auditor General of India (C&AG) graced the occasion as Chief Guest. The Meet saw the presence of large number of directors.
- A Two-day National Conference on Emerging Professional Opportunities in modern era was organised at Bhopal. Hon’ble Chief Minister, Madhya Pradesh Shri Shivraj Chauhan graced the occasion as Chief Guest. Minister of Revenue and Rehabilitation and a Member of Parliament, Madhya Pradesh were among the few dignitaries who attended the program. More than 727 delegates attended the Conference.

To explore more professional avenues, representations were sent to:

- Principal/Chief Secretaries of Finance Department of all States/ UTs regarding organization of training program for Gram Pradhan/ Secretary of Gram Panchayats on fundamentals of accounting, voucher preparation, maintenance of mandatory registers, recurring accounting entries etc as mandated under MGNREGA.
- official liquidator attached with high courts of various States with CD containing Panel of Chartered Accountants to utilise their services.
- CMDs/ MDs of all PSBs with CD containing Panel of Chartered Accountants/ firms (submitted to RBI) for utilization of services of Chartered Accountants/ firms for various internal assignments.
- Executive Director, Reserve Bank of India, requesting to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) under Statutory Audit by restoring the threshold (Advances) limit for audit of branches of public sector banks to Rs. 6 crore.
- Chief General Manager-In-Charge, DBS, Reserve Bank of India requesting them to make available information about number of audits and percentage of advances covered by audit in Public Sector Banks.

- The Assistant General Manager (Audit), State Bank of India, Chandigarh requested to reconsider the Empanelment Notification for outsourcing concurrent audit wherein Chartered Accountants/ firms appearing in Category II and III only of Bank Branch Auditors' Panel have been made eligible to apply, and allow Category I & IV also to apply for the panel.
- Executive Director, Allahabad Bank to suitably revise audit fees for conducting Stock Audit of Borrowal Accounts being offered to various Chartered Accountants firms by Allahabad Bank.
- Deputy General Manager & CCO, State Bank of India, LHO, New Delhi to consider authorising only Chartered Accountants for conducting Internal Audit in their esteemed bank.
- The Deputy General Manager (IA), Dena Bank to inform that the restrictions/ disqualifications imposed on the statutory auditors cannot be ipso facto imposed on the concurrent auditors.
- General Manager Inspection, Punjab & Sind Bank to bring their kind attention to the fact that the concurrent auditor of the bank can not undertake the statutory audit or any other related assignment of the bank for the relevant period.
- The Chief General Manager, State Bank of India, Bhopal requesting for exclusion of penalty clause from empanelment of concurrent auditors - Madhya Pradesh & Chhattisgarh.
- Hon'ble Finance Minister, Government of Haryana to consider authorising only Chartered Accountants for conducting VAT Audit in the State.
- Principal Secretary, Department of Finance, Government of Himachal Pradesh to consider authorising only Chartered Accountants for conducting VAT Audit in the State.
- Chief Secretary, Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh to consider authorising only Chartered Accountants for conducting VAT Audit in the State.
- The Registrar of Cooperative Societies, Rajasthan to consider utilizing the services of Chartered Accountants in Co-operative Sector of Rajasthan.
- Chief General Manager (F&A), Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd. to revise audit fee and to waive off the requirement of security deposit for empanelment as Internal Auditor for FY 2014-15 & 2015-16.
- Chief Accounts Officer (IA), Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited to consider authorising only Chartered Accountants for conducting Revenue Audit in their esteemed organisation.
- General Manager (Internal Audit), Power Grid Corporation of India Limited to consider authorising only Chartered Accountants for conducting Internal Audit in their esteemed organisation.
- Director General (C), O/o C&AG requesting to devise a system so that members can rectify any mistake (at a later stage) done in the online form of Empanelment of auditors for audit of PSUs.
- The General Manager, Bank of India to suitably revise audit fees for conducting Stock Audit of Borrowal Accounts being offered to various Chartered Accountants firms by the Bank.
- Chairman, All India Council for Technical Education to include Fellow Members of ICAI in eligibility criteria prescribed by AICTE in its faculty norms for management schools.
- Deputy C&AG, O/o C&AG requesting that whatever may be the process adopted for appointment of CSAs of PSBs, it should be transparent, equitable and effective and suggesting that at least for the current financial year the present system of Selection Committee should be continued and after proper consideration of all issues, any new system should be evolved.
- The General Manager, Inspection & Audit Department, Andhra Bank requesting them to consider authorizing only Chartered Accountants to conduct stock & receivable audit of your borrowers.
- The Senior Finance Manager, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Noida, Uttar Pradesh requesting them to withdraw the invitation requiring Chartered Accountants meeting all the pre qualification criteria to submit Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 25000.
- Principal Chief General Manager, Department of Banking Supervision, RBI requesting them to give direction to all the public sector banks (PSBs) to give preference/priority to those applicants who have undergone the maximum period of cooling.
- The Commissioner-cum-Secretary to Government, Panchayati Raj Department, Government of Odisha requesting to lay down criteria that should be followed in such a way so that there is equitable distribution of work amongst the firms in order to bring transparency and objectivity in the allotment process and each firm shall get an equal chance to get the assignments.
- The Managing Director, Tejaswini Rural Women Empowerment Programme, Madhya Pradesh, Mahila Vitta Evam Vikas Nigam suggesting them that the audit of 12500 Women Self Help Groups (SHGs) may be distributed among a set of eligible firms instead of a single firm.
- The Registrar, Office of Registrar of Cooperative Societies, Rajasthan requesting to reduce the cost of tender document to a reasonable amount i.e. to recover the cost for processing of application only.
- The Chief Municipal Auditor, Kolkata Municipal Corporation suggesting that though the selection criteria by the Corporation may prevail, however, the scale of fees should have been decided by the KMC based on the scope of work and the type of the professionals required.
- Assistant General Manager, Central Bank of India, Mumbai requesting exclusion of penalty clause from the offer letter for concurrent audit assignment.

- Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi requesting to take up the initiative of ICAI to offer a range of training programmes tailor made for educational institutions to make their accounts/ finance personnel more conversant with relevant accounting standards & the prescribed formats and same can be implemented across the board for better disclosure of financial statements to take capacity building measure to the grass root level, on top priority basis so as to create more awareness amongst accounts/ finance personnel of educational institutions.
- Principal CGM, DBS, RBI requesting to provide sufficient time to auditors to study the systems and processes prevailing in the bank and complete their audit till 20th April, 2015.
- General Manager, Department of Banking Supervision, RBI informing them the matter relating to concurrent auditors being asked to issue NPA Certificate was examined and we are of view that a concurrent auditor will give NPA figures of the branch for which he is the concurrent auditor, however, the same is not a certificate to be issued by the concurrent auditor. Further, it was suggested that the additional fee may be paid to the concurrent auditors for this additional work.
- Principal CGM, DBS, RBI to ensure that the RBI guidelines are being followed by bank branches and appointments are being made for such statutory branch audits, whose advances gets increased to Rs. 20 crores and above on 31st March, 2015.
- Principal CGM, DBS, RBI to request the banks to ensure that big firms (for e.g. Category I firms) must be allotted larger branches to ensure utilization of the expertise and infrastructure of such firms in order to get the quality deliverables as well.
- The Chief General Manager (Accounts), Food Corporation of India, New Delhi requesting to waive the earnest money and security deposit from their notice inviting online bids for engagement of consultant to assess the existing internal control system & suggest/evolve improved system.
- The Group General Manager (Finance), Mangalore Refinery and Petrochemical Limited, Mangalore to make suitable amendments in the tender for hiring auditors for conducting internal audit for the financial year 2015-16.
- Chairman & Managing Directors of all the PSBs to extend the time for completing the audit assignment i.e. till 20th April, 2015.
- The Chairperson, State Bank of Bikaner & Jaipur to extend the time line to complete audit assignments, i.e. till 20th April, 2015 and convey the same to their statutory auditors.
- The General Manager, Inspection & Audit Department, Andhra Bank requesting them to reissue the tender document for empanelment of CA firms for conducting concurrent audit assignments of their esteemed bank.
- A representation was submitted to Shri Manish Srivastava, Commissioner & Registrar, Cooperative Societies of Madhya Pradesh requesting for fixation of audit remuneration for Statutory Audit of Co-operative Banks in Madhya Pradesh.
- Chairman & Managing Director of Andhra Bank requesting them to get the tax audit assignments done by statutory auditors itself of Andhra Bank. Subsequently, a copy of the letter was sent to all the Central Statutory Auditors of the bank requesting them to use their good office in impressing upon the bank.
- A letter was sent to all the Statutory Branch Auditors of all the Public Sector Banks to inform them to conduct Bank Branch Audit for the year 2014-15 in a reasonable time and not to feel pressurised to complete the assignment in limited time limit set by the banks.
- Executive Director, Reserve Bank of India requesting to use their good offices to instruct banks to withdraw their offer of concurrent auditors to conduct the quarterly review of Financial Statements of their branches itself for the quarter ended March, 2015 and consider the material fact as and when offers are being made in future also.
- Director General (C), Office of the Comptroller & Auditor General of India to submit ICAI's views on the issue referred by the O/o C&AG to ICAI regarding "Refusal to accept/surrender of audit".
- Director General (C), Office of the Comptroller & Auditor General of India representing ICAI's views on the change suggested by RBI in the existing norms of SCAs of PSBs viz. "at least two partners of the firm or its paid Chartered Accountants must possess CISA/ISA qualification"
- Chief General Manager, Institutional Development Department, National Bank for Agricultural & Rural Development (NABARD) to represent the following issues :
 - Increase in Audit Remuneration for Statutory Audit of Regional Rural Banks (RRBs)
 - No separate fees for tax audit
 - Limiting of number of branches to each auditor
 - Criteria for selection of auditors
 - Allotment of audit to Sole proprietorship firms
 - Joint Seminars
 - Linking of circulars of NABARD to ICAI's websites.
- The General Manager (Audit), State Bank of Bikaner and Jaipur, Inspection Department requesting them to reconsider the criteria for selection of Concurrent Auditors in State Bank of Bikaner & Jaipur for 2015-16 to bring transparency and objectivity in allotment process.

- The General Manager (Audit), Dena Bank, Inspection Department requesting them to reconsider the criteria for selection of Concurrent Auditors in Dena Bank for 2015-16 to bring transparency and objectivity in allotment process.
- The General Manager, Punjab National Bank to reconsider the notice inviting applications for empanelment of concurrent audit in Punjab National Bank for the year 2015-16.
- Chairman & Managing Director, Punjab & Sind Bank, IDBI Bank Ltd. & Indian Bank to revise remuneration paid to concurrent auditors.
 - A reply dated has been received from IDBI Bank stating that IDBI Bank reviews the fees structure of the Concurrent Auditors from time to time and fixes the fee payable to the Concurrent Auditors accordingly. The last such review/ revision was carried out during February, 2015.
- The Deputy General Manager, Finance, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. to bring their kind attention to the Notice Inviting Tenders (NIT) hosted by their organisation to conduct internal audit wherein apart from Chartered Accountants, Cost Accountants have also been made eligible to conduct the said audit.
- Chairman & Managing Director, Andhra Bank and Chairman & Managing Director, Bank of Maharashtra requesting the revision in audit fees being paid to concurrent auditors.
- The Deputy Commissioner, Navoday Vidyalaya Samiti, Pune Region suggesting them to prohibit tendering system while availing services of CAs for auditing, taxation & allied areas, rather a working may be carried out as per assignment and value of assignment may be estimated internally.
- The CEO, State Level Nodal Agency, Integrated Watershed Management Programme (IWMP), Department of Land Development & Water Resources, Lucknow requesting them to make suitable amendments in the notice inviting Expression of Interest for selection of Chartered Accountant firms for audit of various schemes under their department and reissue the same giving reasonable time to the applicants. Subsequently, a meeting was also held with Shri S.C. Diwedi, Additional Commissioner, State Level Nodal Agency, Integrated Watershed Management Programme (IWMP), Department of Land Development & Water Resources, Lucknow.
- The Project Director, (Additional DM & Collector), DRDA, Dhalai, Ambassa, Tripura requesting them to withdraw the notice inviting tenders wherein Chartered Accountants firms are invited to audit the accounts of all Centrally Sponsored Schemes operate through DRDA, Dhalai for the financial year 2014-15 including compilation thereof and reissue the same after making suitable amendments.
- The Managing Director, M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Limited, Bhopal requesting them to make suitable amendments in RFP for appointment of Agency for support of Finance & Accounts Cell of M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
- Deputy C&AG, Office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi regarding the issues relating to empanelment & appointment of Bank Branch auditors of Public Sector Banks which are arising out of autonomy given to the bank's Board and quoting the instances. A reference to provisions in Companies Act, 2013 and Banking Regulation Act, 1949 was also made in support of our request.
- Managing Director, Tripura Forest Development & Plantation Corporation Ltd., Tripura requested to intervene and instruct concerned officials to withdraw the notice inviting Expression of Interest (EOI) wherein Chartered Accountants firms are invited to submit EOI for compilation of accounts, tax audit, e-filing, etc. for the financial year 2014-15 and re-issue it after making suitable amendments.
- The Managing Director, Tripura Horticulture Corporation Ltd., Tripura requested to intervene and instruct concerned officials to withdraw the notice inviting Expression of Interest (EOI) wherein Chartered Accountants firms are invited to submit EOI for compilation of accounts, tax audit, e-filing, etc. for the financial year 2014-15 and re-issue it after making suitable amendments.
- Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow giving a brief view about the ICAI to avail services of Chartered Accountants in three level Panchayat and to facilitate better financial management of Panchayati Raj Institutions of the state of Uttar Pradesh.
- The Deputy General Manager, Finance, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd., New Delhi to inform them of the decision of Professional Development Committee that if there is a huge (abnormal) differences between the lowest quote received for a tender (on which the tender is ultimately allotted) and the next lowest quote, then peer review of the said assignment and/or concerned chartered accountants/ firm thereof can be ordered. Therefore, in case a bids invited by your end fall in the above decision, you are requested to please forward the said details to us for necessary action at our end.
- Dy. General Manager (Fin. & Acct.), Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited, Ranchi requesting them to consider Chartered Accountants only to conduct the internal audit of their organization.
- Hon'ble Chief Minister State of Uttarakhand to utilise professional expertise of CAs to strengthen the Indian economy.

Besides the above, meetings were held with the following authorities with the objective to explore more professional avenues and to focus on the untouched areas in the existing avenues:

- Director General (Commercial), Office of the Comptroller and Auditor General of India
- Principal Secretary, Department of Finance, Govt. of NCT of Delhi

- Executive Director, RBI.
- CGM-In-charge and Shri S.C. Mishra , CGM, DBS, RBI.
- Advisor, Finance, Railway Board & CA. R.K. Manocha, Executive Director, Railway Board.
- Chief General Manager-In-Charge, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India to discuss issue of appointment of CSAs of PSBs.
- Deputy C&AG, Chairman, Audit Board, Office of the Comptroller General of India (O/o C&AG); Director General (Commercial) and Director General (Commercial) to discuss consequences of autonomy being given to banks for appointment of CSAs of PSBs.
- Chief General Manager-In-Charge, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India.
- Deputy Governor, Reserve Bank of India and Principal CGM, DBS, RBI.
- Chief General Manager, General Manager & Director General (Commercial), O/O C&AG, to discuss the issues involved in norms for empanelment, eligibility & selection of Central Statutory Auditors of Public Sector Banks. In the said meeting, ICAI very strongly expressed its concern over the new system of appointment of Statutory Auditors of PSBs. All the issues of ICAI were minutely discussed in detail with the officials of RBI.
- Chief General Manager, Deputy General Manager & General Manager wherein, a representation was submitted to Chief General Manager, IDD, NABARAD requesting them to increase the fees paid to auditors of RRBs as it was very low. It was also decided to hold Seminars at various places for auditors conducting the audit of RRBs and Co-operative Societies.
- Hon'ble Chief Minister State of Uttarakhand.
- Executive Officer, Bank of Maharashtra and Shri R.C. Lodha, Executive Director, Central Bank of India and a letter was sent to them requesting to provide sufficient time, i.e. till 20th April, 2015 to the statutory auditors of their esteemed bank to complete the audit.
- Hon'ble Minister of Railways wherein a representation was also submitted to Hon'ble Minister of Railways requesting protesting against the new system of appointment of statutory auditors being adopted by banks in advent of managerial autonomy.
- Director General (Commercial) C&AG to discuss the issues arising out of hosting the provisional panel by C&AG.
- Principal Secretary, Cooperative Department, Madhya Pradesh to discuss the issues of increase in audit fees of cooperative institutions in Madhya Pradesh.

To ensure professional opportunities and equitable distribution thereof, panels of chartered accountants/ firms were provided to Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai and various other authorities as per the criteria specified by them.

In its endeavour to consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skill and talent of our members, the Committee organized the following Conferences/ Seminars/ Workshops/ training programmes during the period:

- Faculty support is being given to the Ministry of HRD in the web-based training program for Capacity Building for Central Educational Institutions for Implementation of Accounting Standards being organised at IIT-Mumbai.
- MHRD Programme held on accrual accounting and Standards for educational institutions at IIT, Mumbai was addressed by Chairman, PDC on 11th May, 2014.
- On request of the Department of Non-Banking Supervision, RBI, a webcast on "NBFC- Role and Responsibility of Auditors" was held. DGM, DNBS, RBI and Manager, DNBS, RBI addressed the webinar.
- Faculty support provided for Workshop at Tripura University, Agartala organised by MHRD regarding implementation of Accounting Standards in higher educational institutions.
- A National Conference on the title "New Environment, New Challenges" was organised at ICAI Bhawan, Udaipur.
- A National Conference on "Enriching Knowledge - Empowering Profession" was organised at Labh Ganga Convention Centre, Indore.
- A training programme on "Consulting Opportunities for Financial Due Diligence Engagements in ADB" was organised by Professional Development Committee jointly with International Affairs Committee at Hotel Taj Mahal Mansingh Road, New Delhi in technical collaboration with Asian Development Bank. The program witnessed a huge response with 150 delegates attending the programs (almost double the pre original plan).
- A Webcast on Bank Audit was organized to address the issues of members relating to bank audits. The webcast was a huge success. It received outstanding participation from the members all across the nation. The members made optimum use of the opportunity and the query sessions were also very interactive.
- Several programs are held on topics like Bank Audit, Companies Act, State & Union Budget.

5.23 Committee on Public Finance & Government Accounting

The Committee on Public Finance & Government Accounting reviews the existing Government Accounting system and on that basis suggest improvements along with creating awareness regarding Public Finance & Government Accounting

to the stakeholders including employees of the Government, members of the profession, media, NGO's and the society at large. The Committee collaborates with various Ministries and professional bodies to draw synergies in enhancing accountability and transparency including public service delivery mechanism and uploading public interest. The Committee is actively involved in providing quality inputs and building capacities of various ministries and regulatory bodies in the matters related to policy, implementation and monitoring. The Committee also participates in boosting the national economy by supporting the various nationwide campaigns of the country to give Indian economy a global recognition. The Committee aims to provide training within Government bodies, to evolve methods which would enable in use of present day information technology in assisting the accounting reform process, collaboration and coordination with Comptroller & Auditor General of India (CAG) and Controller General of Accounts (CGA) to bring improvements in the framework of Government Accounting System.

Action Plan – 2015-16

- To develop policy, projects and frameworks that streamline processes and reflect a modern public sector approach in Public Finance & Government Accounting.
- To interact with Ministries/ Departments and Local Bodies, State & Central Government in the areas of Public Finance & Government Accounting and to provide technical support in implementation of various schemes of Central & State Government.
- To promote and conduct exploratory research in collaboration with State & National Level Bodies in the areas of Public Finance & Government Accounting.
- To organize meetings with Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB), CGA and C&AG for working out the modalities to carry out the Government Accounting Reforms.
- To organize interactive meetings with public functionaries and policy makers for exchange of more technical and viable inputs for the development of the Committee.
- To tie up for technical association with International Financial Institutions/ Universities/ Research & Training Institutes to strengthen the reform process in Government departments and to forge linkages within and outside the Country for undertaking collaborative research and exchange of information and publication.
- To explore the possibility of entering into Memorandum of Understanding (MoUs) with different government departments for capacity building of these departments to carry out accounting reforms.
- To build State Level Taskforces in all the States of the country to give impetus to the initiatives and activities of the Committee.
- To provide assistance to Central and State Government to develop effective mechanism for financial administration and management of public fund.
- To come out with e-newsletters, publications and research material on Public Finance & Government Accounting.
- To undertake and organize training courses, Seminars, Workshops and Summits and harnessing technology to deliver better services through Webcasts to enhance understanding of issues concerning Public Finance & Government Accounting.
- To organize Awareness Programmes/ Conferences on the theme of Public Finance & Government Accounting.

Major Activities of the Committee

The major achievements/ initiatives of the Committee during the period 1st April 2014 to 7th July 2015 are given as below:-

- National Conference on the theme “Rising to the Challenges - Redefining our Role” was organized by the Committee jointly with Committee on Banking, Insurance and Pension and hosted by Jaipur Branch of CIRC of ICAI on 30th & 31st December 2014 at Jaipur.
- The Committee organised Workshop on “Financial Management: Evaluation and Assessment” for the Members of Legislative Assembly of Rajasthan and Jharkhand during the year 2014 and 2015.
- The Committee has organized 17 batches of Training Programmes on “Accrual Accounting, Budgetary Control & Audit Framework” for officials of Municipal Corporation of Greater Mumbai at ICAI Tower, BKC, Mumbai during the year 2014.
- The Committee collaborated with the office of Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and organised Training Programmes on the theme “Accounting and Audit Provisions with respect to New Companies Act, 2013” on PAN India basis during the year 2014-15.
- The Committee has collaborated with various State Government Departments with a view to enhance the capacity building initiatives for their officials and organised Training Programmes for the officials of Finance Department of Gujarat and Kerala during the year 2014.
- The Committee organized a Training Programme on the theme “Finance for Non Finance” for the officials of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL) at Gurgaon.
- The Committee jointly with the office of Comptroller & Auditor General (C&AG) of India organised a Training Programme on “Audit and the New Companies Act” for Group A & B Officers of IAAD at International Centre for Information Systems and Audit (iCISA), Noida.

- The Committee brought out Publications on “The Dynamics of Local Governance in India”, “Government Accounting Reforms: An Overview”, Commonly Used Terms in Public Finance & Government Accounting (in English & Hindi) and a Handout on “Quick Insight on Accrual Accounting” during the year 2014 and 2015.
- The Committee also organised Awareness Programmes on the theme “Rising to the Challenges in Public Finance & Government Accounting”.
- Webcast on “Public Finance System in India - Recent Initiatives, Challenges and A Way Forward” was also organised by the Committee.
- During the year 2014-15, the Committee also released its quarterly e-newsletter regularly.

5.24 Research Committee

Research forms the foundation on which a profession grows and prospers. It also plays a crucial role in widening the knowledge base of a profession. Realising the importance of research for the profession, the Council of the ICAI constituted the Research Committee as a non-Standing Committee in the year 1955. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. It has been proactive in responding to the need for accounting guidance on contemporary issues, which arise due to amendments in laws and other developments related to economic reforms in the country. Since its inception, the Committee has been actively involved in providing guidance to the members in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing.

The Research Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee, through its sub-committee, the Shield Panel, also conducts an annual competition, ‘ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting’ with a view to improve the presentation of financial statements.

Achievements of the Committee

During the period covered under report, the Committee formulated two Guidance notes under the authority of the Council of the Institute:

1. ‘GN (A) 33 Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts’
2. ‘GN (A) 34 Guidance Note on Accounting for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities (Issued 15th May, 2015)’.

GN (A) 33 Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts

It provides guidance on accounting for derivative contracts considering the lack of mandatory guidance in this regard with a view to bring about uniformity of practice in accounting for derivative contracts by various entities in the context of the requirements of the notified Accounting Standards.

GN (A) 34 Guidance Note on Accounting for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities (Issued May 15, 2015)

It provides guidance on recognition, measurement, presentation and disclosure of expenditure on activities relating to corporate social responsibility.

The Committee organised a technical workshop on the topic ‘Towards Excellence in Financial Reporting’ at Chennai on 6th February, 2015, with an objective to improve the financial reporting of entities in the country. At the workshop, a presentation was made by the members of the Shield Panel highlighting their major observations arising out of their evaluation of published Annual Reports and other documents received for the competition, with a view to enhance the quality of preparation and presentation of financial statements in the country.

The Committee also organised another technical workshop ‘Towards Improving Financial Reporting in the Banking Sector’ at Mumbai on 8th April, 2015, for banks based on the observations arising out of the Shield Panel review with a view to improve financial reporting in the banking sector going forward. It was attended by CFOs and other representatives of public as well as private sector banks.

Important Projects in progress

The Committee has various other projects at different stages. These are listed below:

(a) Technical Guide on Accounting for Motion Picture Films

The Committee took up this project to provide accounting guidance in accordance with Accounting Standards and other generally accepted accounting principles to address issues peculiar to motion picture sector.

(b) Revision of publication Excellence in Financial Reporting: An Illustrative Guide to Presentation and Disclosures

The above project has been undertaken since the publication, formulated in the year 2010, based on key observations made during the review of the annual reports for the year 2007-08 and 2008-09, was regarded useful by members and others. Accordingly, it was decided to revise the publication based on observations of the Shield Panel of later years.

(c) Revision of Guidance Note on Terms used in the Financial Statements

The above Guidance Note has been decided to be revised to include those terms that are not defined in the existing Accounting Standards or Ind ASs.

(d) Revision of Guidance Note on Accounting for dotcom companies

The above project has been undertaken with a view to examine whether the Guidance Note on Accounting for Dot-com companies is currently relevant or the same needs to be withdrawn/ amended.

(e) Revision of the Technical Guide on Accounting for Not-for-Profit Organisations (NPOs) and its upgradation as a Guidance Note on Accounting

It was decided to revise the above Technical Guide as well as upgrade its status to that of a Guidance Note on Accounting considering that the Accounting Standards are primarily formulated for profit oriented activities while uniform accounting guidance is required for not-for profit organisations also.

(f) Project to revise/ withdraw the Guidance Notes on Accounting in force as on date in view of the Companies Act, 2013 as well as the Ind ASs

The above project has been undertaken with a view to examine whether any of the Guidance Notes on Accounting in force, as on date, needs to be withdrawn/ revised in view of the Companies Act, 2013 or the Ind ASs (which are mandatory to be followed for a certain class of companies beginning April 1, 2016).

(g) Checklist for Disclosures under Schedule III to the Companies Act, 2013

The project has been undertaken with a view to bring out a publication which may serve as a ready referencer for disclosures to be made in the financial statements as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, for easy reference of members and others.

(h) Revision of Checklist for Disclosures under Accounting Standards

The Committee has undertaken the project to revise the abovementioned publication issued in the year 2007, with a view to incorporate any further disclosure requirements arising out of a matter covered by an Accounting Standard related to the period after 1st January, 2007, since the original publication incorporate disclosure requirements till that period.

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for financial year 2013-14

As per modalities of the annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting', the participating entities pass through a robust three-tier evaluation process. The annual reports of participating entities are primarily reviewed by a panel of Technical Reviewers, who are members of the ICAI and experts in the areas of accounting & auditing. The entities are further reviewed by the Shield Panel, a sub-committee of the Research Committee which comprises of few members of Research Committee along with few other independent eminent accounting and auditing experts. The financial statements of entities are considered on various criteria such as technical and statutory compliances, quality, nature and manner of presentation of information, reporting from corporate governance perspective, with emphasis being primarily on the compliance with accounting standards, statutory requirements and relevant applicable laws. At the final level of evaluation process, the entities shortlisted by the Shield Panel, are presented before the Jury. The Jury comprises of eminent personalities from various walks of life. The financial statements of short listed participant entities are meticulously considered to select the awardees of the competition.

Jury Meeting for the competition year 2013-14 was held on 22nd January, 2015 at New Delhi and was chaired by Shri K. Rahman Khan, M.P. Rajya Sabha, Former Union Minister of Minority Affairs and Former Deputy Chairman, Rajya Sabha. Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees were: Dr. Bhaskar Chatterjee, DG & CEO, Indian Institute of Corporate Affairs(IICA), CA. Amarjit Chopra, Chairman, National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) & Past President, ICAI, CA. T.S. Vishwanath, Past President, ICAI, Shri A.K. Awasthi, Former Deputy C&AG, Shri M. Narendra, Former Chairman and Managing Director, Indian Overseas Bank, Ms. Subhasri Sriram, CFO & ED, Shriram City Union Finance Ltd, Prof. R. Narayanaswamy, Faculty, Indian Institute of Management, Bangalore (IIM-B), CA. Rajendra Goyal, Former Director, State Bank of Indore.

As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on 8th February, 2015 at Chennai. CA. K. Rahman Khan, M.P., Rajya Sabha, Former Union Minister of Minority Affairs & Former Deputy Chairman Rajya Sabha, was the Chief Guest at the occasion. A total of 20 awards – four Gold Shields, six Silver Shields and ten Plaques were given away.

List of Awardees of Competition 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the Year 2013-14

Category		Award	Name of the Entity	Annual Report and Accounts for the year ended
I	<i>Public Sector Banks</i>	Gold Shield	Nil	Nil
		Silver Shield	Nil	Nil
		Plaque for commended Annual Report	Canara Bank	March 31, 2014
II	<i>Private Banks (including Co-operative banks and Foreign Banks)</i>	Gold Shield	Axis Bank Limited	March 31, 2014
		Silver Shield	Nil	Nil
		Plaque for commended Annual Report	HDFC Bank Limited	March 31, 2014
III	<i>Insurance Sector</i>	Gold Shield	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	March 31, 2014
		Silver Shield	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	March 31, 2014
		Plaque for commended Annual Report	SBI Life Insurance Company Limited	March 31, 2014
IV	<i>Financial Services Sector (other than Banking and Insurance)</i>	Decided not to give any award in this category		
V	<i>Manufacturing Sector (Turn over equal to or more than Rs. 500 crore)</i>	Gold Shield	Jointly to : ACC Limited & Lupin Limited	December 31, 2013 & March 31, 2014
		Silver Shield	Castrol India Limited	December 31, 2013
		Plaque for commended Annual Report	Hindustan Unilever Limited	March 31, 2014
VI	<i>Manufacturing Sector (Turn over less than Rs. 500 crore)</i>	Gold Shield	Nil	Nil
		Silver Shield	Kewal Kiran Clothing Ltd.	March 31, 2014
		Plaque for commended Annual Report	Centum Electronics Limited	March 31, 2014
VII	<i>Infrastructure and Construction Sector – (Turnover equal to or more than Rs. 500 crore)</i>	Gold Shield	Nil	
		Silver Shield	Nil	
		Plaque for commended Annual Report	NTPC Limited	March 31, 2014
VIII	<i>Infrastructure & Construction Sector (Turnover less than Rs. 500 crore)</i>	Decided not to give any awards in this Category		
IX	<i>Service Sector (other than financial services sector) (Turn over equal to or more than Rs. 500 crore)</i>	Gold Shield	Nil	Nil
		Silver Shield	Mindtree Limited	March 31, 2014
		Plaque for commended Annual Report	Info Edge(India) Limited	March 31, 2014
			Hexaware Technologies Limited	December 31, 2013
			Zensar Technologies Limited	March 31, 2014

X	<i>Service Sector (other than financial services sector) (Turn over less than Rs. 500 crore)</i>	Gold Shield	Nil	Nil
		Silver Shield	Alphageo (India) Limited	March 31, 2014
		Plaque for commended Annual Report	Just Dial Limited	March 31, 2014
XI	<i>Not-for- Profit Sector</i>	Gold Shield	Nil	Nil
		Silver Shield	Vidya Dairy	March 31, 2014
		Plaque for commended Annual Report	Nil	Nil
XII	<i>Local Bodies</i>	Nil		
XIII	<i>Agricultural Sector</i>	Nil		

5.25 Strategy and Perspective Planning Committee

Strategic and Perspective Planning Committee review emerging developments nationally and internationally, to improvise the strategic work plan to achieve the long-term vision of building up profession's credibility and create a niche in emerging areas as well, so as to be of value to society and expand our horizon. Further Committee considers all the emerging developments nationally and internationally which may have possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in other areas by flagging issues wherein profession needs to devote attention.

5.26 Ind AS (IFRS) Implementation Committee

As the world globalised, International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) are increasingly being recognised as globally accepted accounting standards. Continuing with its endeavour to achieve international benchmarks of accounting, convergence with International Financial Reporting Standards (IFRS) had been decided. Pursuant to the Budget Speech of the Finance Minister in July, 2014, for adoption of the IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) by the Indian companies from the financial year 2015-16 on voluntarily basis and from the financial year 2016-17 on mandatory basis, the ICAI has taken various steps in order to bring IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) in place.

The Ind AS (IFRS) Implementation Committee, since its constitution, is relentlessly working to make this transition to Ind AS smooth. In view of the notification of roadmap and IFRS-converged Ind AS, the Committee has decided that rigorous efforts need to be made to educate the members and other stakeholders about Ind AS.

The Committee is working to provide guidance to the members and other stakeholder by issuing Educational Materials on Indian Accounting Standards. An Educational Material contains summary of the respective Indian Accounting Standard and the Frequently Asked Questions (FAQ) covering the issues, which are expected to be encountered frequently while implementing the Standard. Recently, the Committee has brought out Educational Materials on Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* and Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*. Apart from the above publications, the Committee jointly with the Accounting Standards Board (ASB) has also brought out a publication 'Indian Accounting Standards: An Overview' so as to give stakeholders an overview of various aspects related to Ind AS.

In addition to above, Educational Materials on certain Ind ASs are also being revised that were previously issued by the Committee and the revised Educational Materials are expected to be issued by the Committee shortly. Educational Material on various Ind AS are under formulation.

This Committee is also taking adequate steps to enhance the knowledge of the members and other stakeholders for proper implementation of IFRS-converged Ind ASs by conducting workshops, seminars and Certificate Course. In this direction, an extensive 100-hour Certificate Course on IFRS, is being conducted by the Committee in India and abroad to impart knowledge about Ind ASs/ IFRSs with sufficient classroom training to make the members competent in this era of IFRS. From April, 2014 to June, 2015, 34 batches of Certificate Course on IFRS have been conducted wherein around 1200 participants have undergone the class room training. So far, around a total of 6100 members have been trained under this programme.

The Committee is organising chain of One/ Two Days Awareness Programmes on Ind AS across various locations in the country. The 1st programme in the series was organised on 8th-9th May, 2015 at Kolkata. Around 200 participants attended the said programme. The 2nd programme was organised on 28th-29th May, 2015 at Ernakulam, around 50 participants attended the said programme.

In addition to above, the Committee has also decided to conduct Corporate Training Programmes and training programmes for members of Board of Directors and Audit Committees of various industries, etc.

During the Council year 2014-15, the Committee organised “Introductory Programme on IFRS” jointly with Young Members’ Empowerment Committee for young members to enhance the knowledge base of members and help them to understand principles enunciated in IFRS across the country.

The Committee organised Two Days awareness programme on IFRS and Companies Act, 2013 with for Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE). The said programme training was imparted on vital topics of IFRS. CFOs, Finance executives and other senior officials of PSUs participated in the said programme. The Committee also organised customised IFRS corporate training programmes for certain companies.

In addition to above initiatives, the Committee is conducting series of webcasts on Ind AS to create awareness on Ind AS.

The Committee is making every possible effort to create knowledge and awareness about Ind AS and to make this transition smooth.

5.27 Public Relation Activities

In the year 2014-15, there was an increased interaction with Media as a result of various new initiatives undertaken during the year. The Regional offices & Branches were also urged to have constant interaction with the media so as to keep the members, students & stakeholders informed about the good work being done by the ICAI.

Some of the important activities undertaken by the PR Committee during the aforesaid period include the following:

- The ICAI celebrated its Foundation Day on 1st July, 2015. The PR Committee took the major initiative of motivating all Regional Councils & Branches to celebrate “CA Day” in a structured manner. A communication from the President was forwarded to Chairmen of all Regional Councils and Branches asking them to celebrate CA Day by undertaking specified activities like taking forward the Swachh Bharat Abhiyaan, creating awareness about environment hazards, organizing Tax clinics, creating awareness about initiatives undertaken by ICAI towards Women Empowerment, cyclothon, green marathon, tree plantation, distribution of literacy kits, blood donation etc. in addition to the general activities. These activities aim at enhancing the image of ICAI and contribute towards society and nation building. A special grant was sanctioned to the Regional Councils & Branches for undertaking the specified activities.

A function was organized at New Delhi to commemorate the occasion which was attended by over 1000 professionals & stakeholders. Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Power, Coal and New & Renewable Energy was the Chief Guest at the function and addressed the audience. The program was widely covered by the media.

- To commemorate International Yoga Day on 21st June, 2015, ICAI had taken an initiative to encourage all members and students to inculcate Yoga for a healthy body and mind. All the Branches and Regional Councils were asked to undertake specified activities. A very good response was received to this initiative.
- CII Conference on “Financial Reporting and Auditing Reforms”: ICAI associated with CII as an Institutional partner for the “Conference on Financial Reporting and Auditing Reforms” held on 2nd September, 2014 in Delhi. PR Committee liaised with CII for the said conference.
- The 65th Annual function of the ICAI was celebrated on Feb 11, 2015 in New Delhi. Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Power, Coal and New & Renewable Energy was the Chief Guest on this occasion. The program was widely covered by the media.
- International Conference titled “Accountancy Profession: Building Global Competitiveness; Accelerating Growth” was organized in Bangalore from 29th-31st January, 2015. Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister for Railways inaugurated the function and the event was widely covered by the media.
- The Media interactions increased during the year through one on one interviews/ Press Release/ Press Conferences by way of which the media was constantly apprised of the latest developments regarding the new initiatives like Change and updation in the curriculum, IFRS Roadmap, Companies Act, new guidelines for CAs, taking forward Swachh Bharat Abhiyaan, updates about Disciplinary cases, other activities and alike.
- The scope and potential of Chartered Accountancy Profession in today’s dynamic context was also promoted by way of contributing articles, advertisements in various publications.

- As a part of the PR exercise, general public and media has been apprised of the different Seminars/ Programs/Events organized by the way of releasing advts in various news/ financial newspapers, Press Releases and articles.
- The Campus Placement programme was also organized by ICAI in Aug-Sept, 2014 and was widely covered by the media. The top salary packages offered by the organizations to the newly qualified Chartered Accountants all over India were highlighted.
- The ICAI celebrated its Foundation Day function on 1st July, 2014. The function was widely covered by the media.
- Logistic support was provided to various departments within the ICAI, to the Regional Offices and Branches with a view to develop a communication link between the ICAI & its offices/ related organizations.
- To create an awareness about the initiatives undertaken by ICAI, the advts were released in the In-flight/ News/ Business magazines as well as in CA Journal. This not only creates awareness amongst members & stakeholders at large but also helps in building brand ICAI.

5.28 Women Members Empowerment Committee

In order to encourage empowerment of women Chartered Accountants, Women Members Empowerment Committee was formed in the Council Year 2014-15 with the main objective to formulate and implement plans, policies and programmes for development of women members.

Women Members Empowerment Committee is committed towards its objective of empowering women members by conducting various workshops/ Seminars/ Conferences for the benefit of CA Women fraternity at large. During the period 1st April, 2014 to 7th July, 2015, the Committee has conducted 37 Programmes/ Seminars all across India and abroad including the World CA Women Summit – Two Days International Conference held at Dubai.

The programme structures were formulated in such a manner so as to empower women members in both social as well as professional field. The sessions discussed during the programmes included both technical as well as non technical topics taken up mostly by eminent lady faculty members.

A dedicated Women Portal, 'Portal for Women Members' has also been launched by the Committee, which provides our women members a medium through which they can post their requirements and can explore flexi working options available for them. It also aims to provide a common platform to our women members to update their knowledge and share their views and concerns.

Significant Achievements:

- The Committee had conducted 'South Asian Federation of Accountants (SAFA) Women Empowerment Programme' at New Delhi on the theme "CA Women Marching Ahead". The programme aimed to give women delegates an opportunity to know about the significant global developments pertaining to women leadership.
- The Committee also organized World CA Women Summit – Two Days International Conference at Dubai which provided an opportunity to the women participants to have a common platform to interact and share their views and concerns.
- The Committee has organized 6 Webcasts including 2 "Live Interactive Meet" with Hon'ble Minister of Railways CA. Suresh Prabhu and with Hon'ble Minister of State (I/C), Ministry of Power, Coal, New & Renewable Energy CA. Piyush Goyal, on 8th April & 10th June, 2015 respectively for the benefit of Chartered Accountant fraternity at large.
- The Committee had conducted "Training Programme on Women Directors" in Delhi and Mumbai to provide up to date knowledge about the pertinent topics in the profession to Women Members and to prepare them for the role of Women Directors.
- 2 Days Training Programme on Service Tax" was organized by the Committee in Mumbai. The programme aimed to empower members to face the present professional challenges by updating their knowledge.

- IT Workshops for Women Members were also organized by the Committee with the objective to teach hands-on skills to participants, provide learning about new developments in this field and to enhance their IT skills which they require in the profession.

5.29 Young Members Empowerment Committee

Young Members Empowerment Committee (YMEC), one of the non-standing Committees of ICAI has been constituted with the objective to nurture the untapped potential of the young Chartered Accountants and channelize it towards the achievement of their professional goals and to encourage them to become world class professionals.

YMEC focuses on young Chartered Accountants to equip with the updated knowledge and expertise in the field of practice and service. The Committee has been taking various initiatives to equip young Chartered Accountants with the latest developments relating to the profession. To strengthen young members in transitioning into a new role or career challenge, the Committee organizes various Seminars/ Programs/ Workshops/ Short Term Training Programmes/ Conferences.

Vision of YMEC

- To visualize the future needs of the young members entering into the profession and to gear up the professionals for dynamic environment.
- To help the young members in meeting the evolving expectations of the society as far as the technical and professional skills are concerned.
- To explore and develop new avenues of practice/employment/entrepreneurship for Young Members.

5.30 Quality Review

The Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted a Quality Review Board to perform the following functions u/s 28B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (a) to make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute;
- (b) to review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services; and
- (c) to guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under Section 15 of the Act, is “(o) consideration of the recommendations of the Quality Review Board made under clause (a) of Section 28B and the details of action taken thereon in its annual report”. Accordingly, the following is reported:

The Council, at its 333rd (Adjourned) meeting held on 18th and 19th June, 2014 at New Delhi, considered the references/recommendations received from the Quality Review Board, and on consideration, the Council decided to take legal opinion for guiding the Council as to how to move forward and what should be the roadmap in the matter of the recommendations made by the Quality Review Board. It was also decided that once the legal opinion was made available, the matter shall be considered again by the Council.

The Council, at its 339th meeting held on 23rd-25th December, 2014 at Kollam considered the matter in light of the legal opinion and the provisions as contained in Section 28B and clause (o) of Section 15(2) of the Chartered Accountants Act, 1949. The Council after detailed deliberations, while agreeing with the legal opinion was of the view that any reference received from the Quality Review Board should be treated as its recommendation under Section 28B of the Act and all such references are required to be considered by the Council so as to take a decision about the further course of action. The Council, therefore, decided that all references received from the Quality Review Board should be placed before it for its consideration at its next meeting.

Accordingly, the references received from the Quality Review Board were segregated in the following manner and were placed before the Council at its 340th meeting held on 10th-12th February, 2015, containing –

- (i) Recommendations to the Council under clause (a) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949
- (ii) Request to the Institute to issue guidance to its members on matters raised by Technical Reviewers; and
- (iii) Advice given by QRB to the firms that in future the firms should comply with the observations made by Technical Reviewers

The Council took up the matter for consideration at its 341st meeting held on 17th-19th March, 2015, whereupon the Council, on a consideration of the matter, decided that the cases falling under Sl.No. (i) above, i.e. containing recommendations of the QRB under clause (a) of Section 28B should only be placed before it for its consideration. In regard to cases falling under (ii) and (iii) above, i.e. requesting the Institute to issue guidance to its members and advice given by QRB to the firm, the Council decided that such cases be forwarded to the Auditing & Assurance Standards Board after masking the identity of the firms for its consideration and further course of action. The Council also decided that the further action taken by the Auditing & Assurance Standards Board on such cases be placed before the Council for its noting.

Thereafter, at the above-referred meeting, the Council took up consideration of the recommendations made by the Quality Review Board under clause (a) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949. The Council considered the Reference No.1, "Recommendation for collecting and compiling details of audit assignments, on year to year basis, from all the CA firms registered with the Institute". The Council noted that the Board vide its letter dated 9th July, 2013, has recommended that with a view to improving the quality of audit services provided by the members, the ICAI may collect and compile on an annual basis, in electronic form, details of various audit assignments performed by all the CA firms. The Board has also recommended the format for collecting the said details. The Council on a consideration decided that the aforesaid recommendation of the Quality Review Board be referred to the Strategy and Perspective Planning Committee for its consideration and recommendation. Consideration of rest of the references/recommendations was deferred due to paucity of time.

5.31 Committee on Corporate Social Responsibility

Constitution of Committee on Corporate Social Responsibility: The President, in terms of the authority given to him by the Council at its 340th meeting held in February, 2015, constituted a new non-standing Committee, Committee on Corporate Social Responsibility. The 1st meeting of the Committee was held on 5th June, 2015 wherein its objective, terms of reference and its Action Plan 2015-16 were approved.

Formulation of Study Groups: The Committee has formulated a Study Group on strengthening the Certificate Course on CSR and a study group for the formulation of Concept Paper on CSR Hours after due procedures.

Development of Micro-site: The Committee is in a process of developing its micro site which shall provide a platform to the ICAI, its various branches and Regional Councils to showcase the various activities undertaken by them related to CSR. Further, this micro site would also provide a dedicated corner/ column to the members of the ICAI wherein they can display the projects undertaken by them as a part of CSR.

Swachh Vidyalaya Abhiyaan: The Committee and the Professional Development Committee have been jointly working for the Swachh Vidyalaya Abhiyaan. The said initiative has been launched on 28th June, 2015 by the President, ICAI by conducting the physical verification of the completed school toilet block/ unit constructed by the NTPC at Karimnagar district in Telangana in the presence of Vice President, ICAI.

ICAI has been coordinating with the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) governed by the Ministry of Power, New, Coal and Renewable Energy. As of date, more than 625 members have already expressed their interest and confirmed their commitment to the ICAI and the same has been shared with the Ministry of Power, New, Coal and Renewable Energy and the above mentioned CPSUs. It is to inform that the said list has been hosted by the Ministry at the website of Swachh Vidyalaya Abhiyaan - www.vidyutindia.in, displaying the name, membership number, district and state of the members.

Programmes: The Committee organized the Webcast on "topic Companies Act 2013 - CSR, Annual Return, Boards Report, Auditor's Report and CARO-15", on 26th May, 2015 at Council Hall, ICAI Bhawan.

5.32 Committee for Career Counselling

The Career Counselling Committee is a non-standing Committee of the ICAI formed in the month of February, 2015. The Committee aims to promote Commerce Education with special focus on CA course amongst secondary, senior/ higher secondary, graduate/ post graduate students as well as other stakeholders. Primarily, the Committee conceptualizes and implements various means for promoting commerce education particularly Chartered Accountancy Course.

Major initiatives of the Committee

- Launching of an Exclusive website
- Launching of ICAI in social media platform

- Releasing of booklets on ‘Prepare yourself Common Proficiency Test: A Ladder for an excellent Career Ahead’ & ‘A Guide to Understand Chartered Accountancy Course: An Excellent Career in Focus with endless opportunity’.
- Celebration of World Commerce Education Day
- Commerce Wizard – Commerce Talent Search Examination
- Releasing of DVD on ‘Chartered Accountancy Course: An Excellent Career in Focus with Endless Opportunities’
- Constitution Task Force & Groups
- Empanelment of Resource Persons for Career Counselling Programmes

5.33 Management Committee

Some of the important decisions taken by the Committee including those recommended to the Council during the period under report related to matters on:

- Setting up of Branch of Western India Regional Council of the Institute at Bhuj (Gujarat), Branches of Southern India Regional Council of the Institute at Eluru and at Kancheepuram District.
- To follow Supreme Court’s directions regarding “Guidelines on Content Regulation of Government Advertising” in the ICAI as well, in view of the fact that ICAI is an autonomous statutory body.
- Approved the proposal of Young Members Empowerment Committee for starting the monthly E-newsletter.
- Approved the change in names of 12 cities and towns falling under Karnataka State w.e.f 1.11.2014 for inclusion in the Institute’s records

Recommendations received from respective Committee which were then brought before the Council along with the recommendations of the Management Committee:

- Approval of proposal for defining the age criteria for identifying Young Members
- Approval of draft guidelines for organizing programmes by various Committees of the Council through webcasts and for granting of credit of CPE hours.

6. International Affairs Committee

Initiatives for recognition of professional opportunities abroad

MoU signed during April, 2014 to July, 2015:

- MoU with the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) signed on 18th June, 2014 at ICAI Bhawan, New Delhi.
- Renewal of MoU with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales on 8th November, 2014 at Rome, coinciding with the World Congress of Accountants, 2014.
- Renewal of MRA with CPA Australia signed coinciding with the International Conference of the Australia (Sydney) Chapter of ICAI on 19th September, 2014
- Addendum in MoU signed with the Institute of Chartered Accountants in Australia coinciding with the International Conference of the Australia (Sydney) Chapter of ICAI on 19th September, 2014
- ICAI has entered into dialogue for exploring MoU with the South African Institute of Chartered Accountants.
- ICAI is in talks with Pakistan & Sri Lanka to establish mutual cooperation in accountancy profession between the two Institutes.
- ICAI & Canadian Institutes are now in process of renewing the existing arrangement so as to carry forward the bilateral relationship.
- ICAI in talks with the merged Australia & New Zealand Institute for mutual recognition arrangements.

Globalizing ICAI’s Brand Equity

- ICAI had organized a Study Tour to UK and Ireland from 26th October, 2014 to 2nd November, 2014
- The ICAI had its 24th Overseas Chapter inaugurated on 23rd November, 2014 at British Columbia.
- The Bangkok Chapter of ICAI was inaugurated on 12th January, 2015
- The Dar Es Salaam Chapter of ICAI was inaugurated on 13th January, 2015

Visit of delegation to ICAI

- Visit of Mr. Justin West, Head of Business operations, The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) on 22nd April, 2014
- Visit of IFAC delegation to India from 30th June, 2014 to 3rd July, 2014
- Visit of delegation from the International Integrated Reporting Council (IIRC) on 16th September, 2014
- Visit of Ms. Joanne Murphy, Managing Director, Asia Pacific, Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association on 15th November, 2014
- Visit of Mr. Srinivasan Janardanam, Senior Financial Management Specialist, Asian Development Bank on 2nd December, 2014
- Meeting with delegation from ISACA on 24th February, 2015

Conferences/ Programs

- International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) meet on 6th-7th March, 2014 and IFRS Regional Policy Forum on 8th-9th March, 2014
- Train The Trainer Programme on 2nd-3rd September, 2014
- SAFA-IFAC Regional SMP Forum and SAFA Women Conference on 10th October, 2014 at New Delhi
- ICAI International Conference in Bengaluru from 29th to 31st January, 2015
- SAFA Meetings in Bengaluru on 28th-29th January, 2015
- Training Programme on “Consulting Opportunities for Financial Due Diligence Engagements in Asian Development Bank” on 23rd February, 2015.

Technical Co-operation to under developed countries

ICAI has taken an initiative to extend its expertise to develop the accountancy profession in developing countries on no profit no loss basis. ICAI is keen to build capacity in transition economies to help them overcome the lack of professional knowledge in accounting domain.

Working for building blocks

“ICAI Global Career E-Kit” was launched at Dar es Salaam & Qatar besides Dubai, Kuwait & Muscat in order to make the potential ICAI members to capitalize on opportunities available in this era of technology. These kits are conceptualized to provide panoramic view of the primary information to our members intending to go abroad for professional forays.

7. OTHER ACTIVITIES**7.1 Human Resource Development**

Development of Human Resources is the main approach by which an organization can improve its quantitative goals and qualitative and cognitive aspects. The ICAI has always been committed to strive and to focus on the formidable talent issues, including reaching new talent pools, developing existing employees and skills; and addressing the emerging needs of leadership capability. In the light of this, the ICAI appointed its new Secretary, Shri V. Sagar in June, 2015. Further, various other recruitment drives were undertaken at all levels in order to map the manpower requirements in line with new and emerging responsibilities. Continuing with the assurance of providing a secure and better work atmosphere, the ICAI has, for the first time, introduced and facilitated a Medical Insurance Policy for its serving employees.

The ICAI identifies the role of its human resources becoming more critical and which needs to be adaptive, resilient and quick to change direction and stakeholder centered. In order to enable its manpower to sustain in the fast changing business environment, a series of training programmes have been and are being organized by the ICAI at Delhi and other regions. The learning outcome of these trainings is to ensure that the employees are able to think beyond mundane and work as a catalyst in path to personal and professional progress.

Further, HR initiatives have aimed at timely counseling, bringing into force improved policies for ensuring discipline, employee grievance redressal, mitigating bottlenecks and complementing the initiatives of the ICAI of creating a learning organization for employees' intellectual growth and to re-skill its workforce.

Human Resource Transformation Committee

With a view to strategically transform the Human resource management systems and introducing IT tools for better HR services, the Council had formed special purpose Committee namely Human Resource (HR) Transformation Committee in the year 2014-15 which is continuing in the year 2015-16 as well. While studying the internal practices and benchmarking the global HR management trends, the Committee aims to come up with innovative ideas for addressing and synchronizing the aspirations of internal stakeholders with that of management goals so as to achieve the ICAI Action Plan in future.

The Terms of reference of the Committee is as under:

1. To develop policies and systems for attracting and retaining the best talent within ICAI.
2. To develop job descriptions and job specifications for each level of personnel within ICAI so as to position right people at right jobs in a re-engineered organization structure and work towards authority responsibility matrix for overall development.
3. To explore and develop job evaluations and performance management parameters for effective implementation of compensation policy within ICAI.
4. To work towards career planning and management of the existing human resources.
5. To work for training and development of personnel at all levels so as to act as a change mentor by developing second line of command through job rotation and effective succession planning systems.
6. To develop internal stakeholders' capabilities, act as a growth driver, in tandem with the multi-faceted role of ICAI.
7. To design and implement various HR Policies in compliance with the regulatory requirements.
8. To integrate IT tools with existing HR services to ensure free flow of information.
9. To address and synchronize the expectations of management and internal stakeholders in terms of their aims and aspiration.

Activities of HR Transformation Committee

The Committee met four times during the period under report and has organized 5 training programmes since 18th September 2014 till October, 2014 which was attended by 365 employees and had received appreciation from all the participants. Committee also noted the feedback received from the employees in this regard as well. The details of the training programme conducted is as under:

Date	Topic	Faculty	Employees covered	Venue	Attendance
18 th September, 2014	Out of box thinking in Human Capital management in the knowledge economy	Dr. Debi S Saini, Professor & Chairperson-- Human Resource Management Area, MDI	Sr. Deputy Secretaries – Executive Officer located at ITO and Vishwas Nagar office	ITO Auditorium	84 out of 103 (81.5%)
19 th September, 2014	Creative thinking and effective problem solving	Dr. Monika Rastogi, Motivational Speaker, Cosmic Link Motivational Academy	Sr. Deputy Secretaries – Executive Officer located at Noida Sector -62 and Sector -1 office	Noida Sector - 62 auditorium	103 out of 144 (71.5%)
25 th September, 2014	Effective Presentation skills	Mr. Vivek Bindra, Founder, Global ACT	Section officer- Assistant located at ITO and Vishwas Nagar office	ITO Auditorium	46 out of 56 (82.1%)
1 st October, 2014	Making a winning team	Mr. Alokesh Banerjee, Sr. Faculty, NTPC	Section officer- Assistant located at Noida Sector - 62 and Sector -1 office	Sector-62 Auditorium	58 out of 73 (79.4%)
14 th October, 2014	Value of Action	Dr. Monika Rastogi, Motivational Speaker, Cosmic Link Motivational Academy	All employees of grade LDC/UDC and Class IV employees	ITO Auditorium	74 out of 97 (76.2%)

A 2-day orientation programme for the ICAI employees (Excluding Deputy Secretary and above) who had joined the Institute on or after 1st May 2013 had been organized on 2nd-3rd July, 2015 at ITO Auditorium wherein 52 employees including 12 employees from the regional offices participated. The programme was well appreciated by the participants.

The Committee, in order to institutionalize the training and developmental needs of its employees, would be imparting trainings on behavioural issues at the first instance as under:

S.No.	Employees covered	Institution
1	Upto Section Officer	All India Management Association (AIMA)
2	Executive Officer to Deputy Secretary	IMT Ghaziabad
3	Joint Secretary and above	IIM Lucknow (Noida Campus)

7.2 Committee on Management Accounting

Initiatives for Profession: Working for Building Blocks

Certificate Courses

The Committee on Management Accounting has been successfully conducting a very high valued certificate course of one year duration on Master in Business Finance (MBF) for last six years with an aim to provide cutting edge Finance skills to qualified and experienced Chartered Accountants at different cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad. It has successfully completed seven (7) Batches. The Committee is conducting classes for 8th Batch of MBF at Delhi and Mumbai. Inauguration of MBF - 8th Batch at Mumbai, Delhi was held on 10th and 11th January, 2015 respectively.

Post-Qualification Courses

The Committee also conducts two post qualification courses: 1. Management Accountancy Course, 2. Corporate Management Course. The Committee is taking initiatives to review the Course curriculum, delivery mechanism etc.

Industry/ Corporate Initiatives/ Programmes

The Committee has been conducting MBFCC for the CA executives of HPCL Executives since November, 2014. The first batch of the course is already completed on 27th June, 2015. The HPCL has proposed to launch 2nd batch of MBFCC for its CA Executives in August, 2015.

Seminars/ Workshops/ Conferences/ Other Programmes

The Committee conducted various Seminars/ Workshops jointly with Committee for Capacity Building of Members in Practice and with Vasai Branch, Jalgaon Branch and Nashik Branch of WIRC of ICAI.

Interaction with Ministries/ Regulators/ Govt. Offices on Professional Matters: Strengthening ties

1. Inauguration of MBF - 7th Batch at Delhi and Mumbai on 28th & 29th June, 2014. Chief Guest at Delhi was Shri Nand Kishore Garg, the Hon'ble Member, Legislative Assembly Delhi.
2. Convocation of MBF Batch at Delhi on 7th October, 2014. Chief Guest was Shri Pravin Rawal, Director, IR, Coordination, Establishment, Department of Financial Services, Government of India, Delhi
3. Convocation of MBF Batch at Mumbai on 14th October, 2014. Chief Guest was Ms. Kiran Maheshwari, Hon'ble Minister, Govt. of [Rajasthan](#).
4. Convocation of Master in Business Finance Certificate Course was organized at Delhi and Mumbai on 24th & 25th January, 2015 respectively. Chief Guest at Delhi was Shri Babu Lal Verma, Hon'ble State Minister, Department of Transport, Government of Rajasthan, and Guest of Honour was Advocate Amit Khemka.

Publications:

1. Committee released a book on "Frequently Asked Questions (FAQs) for Management Accounting" drafted by CA. Charantimath N.A., co-opted member of the Committee at the ICAI International Conference held at Bangalore Palace, Bengaluru from 29th-31st January, 2015.
2. Committee released MBF Study Module Level 1 Paper 1 at Annual Day function on 11th February, 2015

Important Decisions/ Initiatives

The Committee has decided to bring out publication of 6 MBF Study Material out of which 3 have been published.

For Members

The Committee published its quarterly Journal "Management Accounting and Business Finance-July, 2014, October, 2014, January, 2015 highlighting some recent developments on Management Accounting and Business Finance for dissemination of knowledge for the benefit of the members and others concerned.

7.3 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services

The curriculum of the Chartered Accountancy Course coupled with the practical training imbibes versatility in its members. As a result thereof, Chartered Accountants successfully play very significant role not only as practicing professional in the field of auditing & taxation and in the industry as professional executives in charge of financial management but also in various other sections of the Society. There are large numbers of Chartered Accountants who have become very successful entrepreneurs. Similarly, the contribution of Chartered Accountants in the field of Public Service as Members of Parliament or Legislative Assemblies, Judge of the Supreme Court or High Courts, Members of Tribunal etc is well recognized to be described.

The Professional Development Committee & the Committee for Members in Industry act as a useful link between the ICAI and the members in Profession and the members in Industry. With a view to provide such a link between ICAI and the members who are in Entrepreneurship or Public Services, Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services has been reconstituted for the Council Year 2015-16. The objective is to have mutually advantageous live connect between the ICAI and the members in Entrepreneurship or Public Services. Through the functioning of this Committee, the members in Entrepreneurship or Public Services would be brought into the mainstream of the ICAI enhancing their participation in the ICAI's activities. The Committee would also work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as the other members of the ICAI; so as to create and enlighten additional opportunity areas for young Chartered Accountants and furthering the profession, inter-alia.

The Committee has been working on updating the database of CA Members who are into Entrepreneurship or Public Services. An Announcement in this regard has been hosted on the ICAI website for the attention of not only members in Entrepreneurship or in Public Services but membership in general as well so that while members in Entrepreneurship & Public Services update their profile in the record of the ICAI, the other members can provide the details of such members whom they have come across through their dealing with such class of professionals.

Communication has also been sent to Department of Personnel & Training, Government of India, Company Law Board, Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Central Board of Excise & Customs (CBEC) and Director General of Income Tax with a request to kindly provide the details of Members/ Officers working in their respective organization who happen to be Chartered Accountants.

Till date, the Committee has compiled a database of around 353 CA Members who are into Public Services and 231 who are into Entrepreneurship.

The Committee is also planning to organize a Workshop of ICAI Member in Public Service to brainstorm on certain matters of national importance that ICAI can take up for research and further study and also to deliberate on various matters of current significance for response by the profession.

7.4 Committee for Co-operatives & NPO

The Committee for Co-operatives and NPO Sectors is a non-standing Committee of the ICAI formed in February, 2011 to identify issues and opportunities and NPO sectors and equip members and other stakeholders to find a new niche for themselves and as well as maintaining and developing the core competencies in the Co-operatives and NPO sectors.

Programmes with & regulators

- Training program on FCRA for the officers of the FCRA division - 25th July, 2014 - 40 officers Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building Jai Singh Road, Off. Parliament Street, Near Jantar Mantar, New Delhi
- Training Programme on Management of Accounts of Housing Cooperatives - 20th to 23rd August, 2014 in collaboration with National Cooperative Housing Federation of India Ltd, Dehradun
- Training Programme on DCCB and Urban Cooperative Banks - 20th & 21st December, 2014 hosted by Cooperative Department, Tamil Nadu was held at Chennai
- National Conference on Accounting, Income tax & Audit for Housing Co operatives schedule to be held on 7th February, 2015 at Goa in collaboration with National Cooperative Housing Federation of India Hosted by Goa Branch of ICAI
- 6 Days Training Program for Probationary Cooperative Assistants schedule to be starts from 7th February, 2015 to 14th March, 2015 at Hyderabad hosted by BHEL Employees Cooperative Credit Societies Limited

Representations made by the Committee

- The Committee has made representation on various issues and needs of these sectors to the departments of cooperation of several states and union territories to accelerate the role of Co-operatives
- The representations covered aspects that include:
 - E-governance in Co-operative Societies' Management
 - Audit Manual for audit of societies in respective states
 - Format of Financial Statements
 - Training Programme for officer of the department of Co-operative societies
 - Co-operative Governance for Large Co-operatives
 - Exit Scheme for defunct co-operative societies
 - Permanent Joint Committee of ICAI and Departments of Co-operation
 - Exit Scheme for defunct co-operative societies
 - Empanelment of Auditors
 - Representation by Chartered Accountants
- A representation covering the abovementioned aspects was also submitted to the Central Registrar for Co-operative Societies (CRCS)
- Representation to Joint Secretary Ministry of Home Affairs Foreigners Division seeks to draw attention to the operational issues in implementation of the Act and the rules related to foreign contributions, and solicit support to resolve them, through suitable amendment to the Act, Rules or administrative circular, as may be considered appropriate.
- Draft bill given for Central Government to be enacted on Charitable Trusts
- Representation to Deputy Governor of RBI
The representation covered areas such as:
 - RBI Circular for Accounting Standards
 - Separate LFAR for Urban Co-operative Banks
 - Act as applicable to Co-operative Banks

Tasks Force & Study Groups

Each state is encouraged to and are in the process to form study groups for knowledge sharing by the members

In every State, task forces are formed on both Co-operative and NPO sectors.

International Activities

Participated at 11th Regional Assembly of the ICA - 15th September to 20th September, 2014 in Bali, Indonesia. Co-operatives for Sustainable Development in Asia and Pacific.

Books & Publications

- Profile of the Committee for Co-operative and NPO Sectors
- Publications released by Committee for cooperative and NPOs Sectors in this council year
 - Guide on laws Governing Charitable organizations in India
 - Corporate Social Responsibility and Professional Opportunities for Chartered Accountants
 - Guide to Cooperative Sectors and Professional Opportunities for Chartered Accountants
 - Non Profit Organizations and Professional opportunities for Chartered Accountants
 - Cooperative Arbitration
 - Overview of Foreign Contribution regulation in India
 - Redevelopment of Housing Societies
 - Technical Guide on Accounting of Not for Profit Organizations
 - Reference Manual for Cooperative Housing Societies

Development faculties

- The Committee has been encouraging and facilitating the development of faculties for these sectors by providing suitable guidance and support to the interested and eligible experts.
- More and more members are encouraged to gain expert knowledge and act as faculties at various seminars, programmes and courses

1st ICAI CSR Awards

CSR is a continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic & social development, improving the quality of life of the work force, their families as well as of the local community and society at large. Business needs a stable social environment that provides a suitable environment for investment and trade and therefore it is in the self-interest to demonstrate the human face of business.

Through these Awards for Corporate Social Responsibility, we at ICAI, will provide recognition to Corporate, Enterprises, Not for Profit Organizations, Individuals and etc that have chosen this noble path of creating shared value and will help to build brand equity such organizations.

CSR Division of the Committee proudly announced First ICAI CSR Awards, 2014 on 5th February, 2015 at Hotel Lalit, Mumbai.

Jury Meeting for the same was held on 2nd February, 2015 at Hotel Sahara Star, Mumbai. Nominations were received in large numbers.

7.5 Legal – Advisory-cum-Litigation**Services rendered by the Legal Department**

- Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies, reports, as required from time to time by various Committees/ Departments of ICAI.
- Ensuring the providing of appropriate legal advice on a diverse range of substantive and procedural questions of law arising out of administrative functioning of ICAI, to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.
- Supervising and Overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various Committees/ Departments of ICAI.
- Serving on various standing and non-standing Committees, study groups and task force, as required, to take care of legal obligations in framing of policies.
- Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational Departments and Committees in preparing of reply to legal notices etc.
- Handling Court Cases.

7.6 Infrastructure Development Committee

A policy has been framed by ICAI for development of infrastructure of Branches and Regional Council/ Office specifying the guidelines of infrastructure development, cost factors involved and the procedures to be adopted. The Committee was constituted last year for implementation of the policy with regards to building proposals that will be received from various Branches/ Regional Councils of ICAI. The Committee reviews the surplus land/ building at various locations of ICAI. It also reviews entire existing infrastructure projects of ICAI and do due diligence of same.

Purchase of new Infrastructure after formulation of Infrastructure Policy

1. Kannur Branch, SIRC – Land purchased from private party
2. Jalandhar Branch, NIRC – Govt. land from Jalandhar improvement Trust
3. Jabalpur Branch, CIRC - Govt. land from Jabalpur Development Authority
4. Goa Branch, WIRC - Land purchased from private party
5. Gurgaon Branch, NIRC - Govt. land from HSIIDC
6. Moradabad Branch, CIRC - Govt. land from Moradabad Development Authority
7. Pali Branch, CIRC - Govt. land from Municipal Council, Pali
8. Agra Branch, CIRC - Govt. land from UP Awaas and Vikas Parishad

Construction proposal approved by the Committee

1. Ajmer Branch, CIRC
2. Surat Branch, WIRC
3. Hubli Branch, SIRC
4. Rajamahendravaram Branch, SIRC
5. COE, Jaipur

7.7 Right to Information Act, 2005

The Right to Information is implicitly guaranteed by the constitution. However, with a view to set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005. The basic object of the Right to Information Act is to empower the citizens, to promote transparency and accountability in the working of the Government. The ICAI, a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the ICAI have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (RTI) and Transparency Officer.

Disclosure under Section 4 (1) (b) of the RTI Act, 2005

In terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosure have been made by the ICAI by hosting them on the website of the ICAI www.icai.org and the same are updated from time to time. Link for the same is http://www.icai.org/new_post.html?post_id=1346&c_id=203.

Gist of the Quarterly Returns for the year 2014-15 submitted to Central Information Commission and thereafter published by the CIC

Quarter	Total number of applications replied in the quarter	Total Number of applications transferred to other PAs	Decisions where applications for information rejected	Percentage of rejection
1 st Quarter	127	0	29	26.9%
2 nd Quarter	221	1	38	17.8%
3 rd Quarter	128	0	27	27.0%
4 th Quarter	171	0	31	20.3%

7.8 XBRL

XBRL India, facilitated by the ICAI, spearheaded the XBRL initiative in the country with active participation of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI, IRDA and RBI from the year 2007. Since then the regulators have been working on the adoption of XBRL as a standard electronic business reporting language.

- **Status of Sector Specific Taxonomies developed**

The taxonomies for the Non Banking Financial Companies (NBFC) and Power Companies have been developed. The taxonomy for NBFCs has also been approved by the Reserve Bank of India. Both the taxonomies had been submitted to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for inclusion in its ambit of XBRL filings.

The taxonomy for the Insurance Companies, both Life and Non-life sector has been developed. The same has been sent to IRDA for approval. After the approval from the IRDA, the same shall be submitted to the Ministry of Corporate Affairs.

- **XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs**

The Commercial & Industrial (C&I) taxonomy is being used by the Ministry of Corporate Affairs for having annual filings of the financial statements of a select class of companies from the year 2010-11.

However, the taxonomy has been revised to meet the new requirements laid under the Companies Act 2013 and the rules and forms notified there under. The revised C&I taxonomy shall be used for the filing of the financial statements for the year 2014-15 from the companies.

Using the database of MCA21, which captures the data in both XBRL and non-XBRL formats, the Sub-Committee on Private Corporate Sector including PPPs under Central Statistics Office of Ministry of Statistics and Programme Implementation have come up with a report on the usage of XBRL data for generating National Accounts Statistics (NAS) for the Corporate Sector. As per the recommendations of the sub-committee, for the year 2012-13, the estimate of GVA for non-financial private corporate sector derived from MCA 21 database is 9.5% higher than the estimate obtained from NAS 2014. However, for non-financial service sector, estimate of GVA derived from MCA 21 database is 12.8% lower than the estimates obtained from NAS 2014. Estimated GVA for manufacturing industry obtained from MCA 21 data and annual report for public sector undertakings is 40% higher than the estimate of GVA for public and private limited companies from ASI 2011-12 data.

- **Taxonomies under development**

An announcement for inviting Expression of Interest (EOI) for the development of taxonomy based on Indian Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs, has been hosted on the website of the ICAI and

XBRL India. The last date for the submission of the EOI is 10th August, 2015. The said taxonomy shall be used for the filings of the financial statements prepared in accordance with the IFRS converged standards i.e. the Ind AS.

- **Involvement of Regulators**

- ✓ An XBRL India Advisory Council (XIAC) has been constituted under the aegis of XBRL India with representation from MCA, IRDA and RBI along with the Board members of XBRL India to provide strategic advice related to the XBRL activities in India. Recently, a meeting of the XIAC had been scheduled on 15th June, 2015. Shri Purnendu Kumar, Director, RBI has made a presentation on the experiences of RBI on the benefits derived with the use of XBRL. He informed that 95 returns (about one-third) of the total 299 returns are being received by RBI in XBRL form after the completion of the second phase of XBRL implementation. He also informed that in terms of the number of elements, more than 2/3rd of the total elements are being captured in XBRL format. He also informed that in addition to the regulatory returns the RBI has also asked the Banks to submit their financial statements also in XBRL format from the year 2013.
- ✓ A letter had been sent to the Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs requesting him to consider extending the due date in the light of various queries being raised by the members and companies with respect to levying of penalties for the non-submission of accounts within the stipulated time. Ministry of Corporate Affairs (MCA) has allowed the relaxation of additional fees and extension of last date of filing of forms for annual filing vide General Circular No. 10/2015 dated 13th July, 2015. MCA has relaxed the additional fees payable on Forms AOC-4, AOC-4 XBRL and MGT-7 upto 31st October, 2015. For the companies which are not required to file in XBRL and required to file its Consolidated Financial Statements (CFS), the last date to file the CFS in a separate form AOC-4 CFS would be 30th November, 2015 without any additional fees.
- ✓ The Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has conducted a workshop on the draft insurance taxonomies for life and non-life insurance companies. Representatives of various Insurance companies have participated in the said workshop.

- **XBRL Implementation**

Bombay Stock Exchange (BSE) has launched XBRL solution for online filing of Shareholding pattern w.e.f. 11th June, 2015. As per the media release of the BSE dated 21st July, 2015, 1062 companies have filed shareholding pattern for the quarter ending June, 2015 using BSE XBRL solution.

- **International Activities**

XBRL India regularly takes part at the various International events i.e. the conferences, the XBRL Asia Workshops, the Jurisdictional Leadership Exchange programmes, etc.

XBRL India has also offered itself to host the XBRL Asian Workshop and National Conference in India in January, 2016.

8. OTHER MATTERS

8.1 Committee for Review of Education & Training

The Chartered Accountancy Course is a dynamic course and hence it is reviewed periodically so as to maintain the edge of the profession vis-à-vis contemporary economic developments. Accordingly, a Committee for Review of Education and Training was constituted in 2013-14. This was reconstituted in 2014-15.

As a part of multiple pronged strategy, it held meetings with users of services, regulators and academicians in each region; issued a web-based questionnaire for Members, Students, Users of services including regulators and academicians of major accountancy bodies of the world; studied the scheme of education and training so as to have valuable inputs from cross section of the society and benchmarking the various International Education Standards issued by IFAC while formulating the new Scheme of Education and Training.

After detailed methodology explained above, the Council drafted a proposed Scheme of Education and Training. The scheme was exposed to public from 12th February, 2015 to 31st March, 2015. Side by Side, the President, ICAI appointed five Central Council Members as Regional Coordinators to hold Outreach meetings with members in practice, users of CA services i.e. and members in industry, person from HR Department and Regulators and academicians, students and parents in all regions to elicit maximum response from all the stakeholders.

In terms of the authority given by the Council at its 340th Meeting of the Council held in February, 2015, the President constituted a Group to finalise the recommendations on new scheme of education and training. The Group held a numbers of interactive meetings with various representatives of industry, members in practice and other stakeholders on pan India basis during April-June, 2015 to get their views/ inputs on the proposed scheme of education and training.

After considering views received from various sources mentioned above, the Group drafted a scheme of Education and Training.

The draft scheme was deliberated in the Council in its 343rd meeting held on 24th & 25th June, 2015. After consideration of the draft scheme, the Council approved the following Revised Scheme:

Revised Scheme of Education and Training for Chartered Accountancy Course

Revised Scheme: Route I - Foundation Course³

Under the Foundation Course Route, the following steps are required:

- Register with Board of Studies (BoS) after appearing in Class XII till June 30/ December 31.
- Be eligible to appear for Foundation examination after passing Class XII examination. The first Foundation examination can be taken in November/ May, as applicable, following passing of Class XII examination.
- Qualify Foundation Course.
- Register with the BoS for the Intermediate Course.
- Complete 8 months of study Course.
- Appear and Pass in either or both Groups of Intermediate Course.
- Successfully complete Four Weeks Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) before commencement of the practical training.
- Register for three years practical training on passing either or both the groups of Intermediate.
- Register for the Final Course after qualifying both the groups of Intermediate Course.
- Successfully complete four weeks Advanced ICITSS during the last two years of practical training.
- Complete practical training.
- Appear in Final examination after completion of practical training and Advanced ICITSS.
- Become Member.

Revised Scheme: Route II – Direct Entry Route⁴

The ICAI allows Commerce Graduates/ Post-Graduates (with minimum 55% marks) or other graduates/ post-graduates (with minimum 60% marks) and Intermediate level passed students of Institute of Company Secretaries of India and Institute of Cost Accountants of India to enter directly to its Intermediate Course. The following steps are required to be undertaken by the eligible graduates and post graduates under this route:

- Register with the BOS for the Intermediate course (provisional registration allowed to the students doing final year of graduation).
- Successfully complete four weeks Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) before commencement of the practical training.
- Register for three years practical training.
- Appear in Intermediate examination after nine months of practical training.
- Qualify Intermediate Course.
- Register for the final course after qualifying both groups of Intermediate Course.
- Successfully complete four weeks Advanced ICITSS during the last two years of practical training.
- Complete practical training.
- Appear in final examination after completion of practical training and Advanced ICITSS.
- Become Member

Foundation Course

Number and Name of Papers

Number of Papers – 4

Paper 1: Principles and Practices of Accounting (100 Marks)

Paper 2: Mercantile Law & General English (100 Marks)

Part I: Mercantile Law (60 Marks)

Part II: General English (40 Marks)

³ Note: ICAI has decided in principle the above mentioned Scheme. However, the scheme will be notified in the official Gazette in due course.

⁴ Note: Candidates who have passed Intermediate level examination of ICSI or ICWAI and enter the CA Intermediate course directly shall be treated at par with Foundation passed students and shall have to undergo the CA course in the manner akin to the Foundation passed students.

Paper 3 ⁵ :	Business Mathematics and Logical Reasoning & Statistics (100 Marks)
	Part I: Business Mathematics and Logical Reasoning (60 Marks)
	Part II: Statistics (40 Marks)
Paper 4 ⁶ :	Business Economics & Business and Commercial Knowledge (100 Marks)
	Part I: Business Economics (60 Marks)
	Part II: Business and Commercial Knowledge (40 Marks)

Note

- Passing percentage: Aggregate - 50% and Subject-wise - 40% at one sitting.
- Objective type question of 1 or more marks.
- Examination: In the month of November and May after passing Class XII.

Intermediate Course

Number and Name of Papers

Number of Papers – 8

Group I

Paper 1: Accounting (100 Marks)

Paper 2: Corporate Laws & Other Laws (100 Marks)

Part I: Corporate Laws (60 Marks)

Part II: Other Laws (40 Marks)

Paper 3: Cost Accounting (100 Marks)

Paper 4: Direct Tax Laws & Indirect Tax Laws (100 Marks)

Part I: Direct Tax Laws (60 Marks)

Part II: Indirect Tax Laws (40 Marks)

Group II

Paper 5: Advanced Accounting (100 Marks)

Paper 6: Auditing and Assurance (100 Marks)

Paper 7: Financial Management & Business Economic Environment (100 Marks)

Part I: Financial Management (60 Marks)

Part II: Business Economic Environment (40 Marks)

Paper 8: Information Technology & Strategic Management (100 Marks)

Part I: Information Technology (60 Marks)

Part II: Strategic Management (40 Marks)

Four Weeks Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS)

- Duration: 4 weeks (2 weeks for soft skills and 2 weeks for IT)
- When to complete: Students registering for the Intermediate course shall be required to successfully complete ICITSS before commencement of practical training.

Practical Training

- Duration of practical training: Three Years
- Commences after completing Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) and passing either or both groups of Intermediate.
- For direct entrants coming through graduation and post graduation route, the practical training commences immediately after they complete four weeks ICITSS.

Advance Four Weeks Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS)

- Duration: 4 weeks (2 weeks for soft skills and 2 weeks for Advance IT)
- When to complete: Students undergoing practical training shall be required to do AICITSS during the last 2 years of practical training but to complete the same before being eligible to appear in the final examination.

Final Course

Number and Name of Papers

Number of Papers – 8

Group I

Paper 1: Financial Reporting (100 Marks)

⁵ Paper 3 and Paper 4 will be Objective type papers.

⁶ Paper 3 and Paper 4 will be Objective type papers.

Paper 2: Strategic Financial Management (100 Marks)
 Paper 3: Advanced Auditing and Professional Ethics (100 Marks)
 Paper 4: Corporate Laws and other Economic Laws (100 Marks)

Group II

Paper 5: Advanced Management Accounting (100 Marks)
 Paper 6: Financial Services and Capital Markets & Information Systems Control and Audit (100 Marks)
 Part I: Financial Services and Capital Market (50 Marks)
 Part II: Information Systems Control and Audit (50 Marks)
 Paper 7: Advanced Direct Tax Laws & International Taxation
 Part I: Advanced Direct Tax Laws (70 Marks)
 Part II: International Taxation (30 Marks)
 Paper 8: Advanced Indirect Tax Laws (100 Marks)

8.2 Annual Function of the ICAI

The 65th Annual Function of the ICAI was held in Hotel Ashok, New Delhi on 11th February, 2015, which was inaugurated by the Chief Guest Union Minister of State (Independent Charge) for Power, Coal and New & Renewable Energy CA. Piyush Goyal. The Union Minister praised the Council for giving a dynamic shape to the profession, which has earned high regards for integrity and transparency. The Chief Guest also gave away the prizes to the ICAI Regional Councils and Branches that were adjudged best for their outstanding contributions under various categories in the year gone by. Student achievers were also awarded for their merit in various CA examinations.

8.3 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2015

ICAI celebrated its Foundation Day on 1st July, 2015 on completing 66 glorious years at its 150 branches 5 Regional Councils and overseas chapters. As per the tradition, the celebrations started with the ICAI flag hoisting event followed by the CA Day function in New Delhi, where one among our members and Union Minister of State (I/C) of Power, Coal and New & Renewable Energy, CA. Piyush Goyal, participated in the function as its Chief Guest. Secretary Shri V. Sagar welcomed the dignitary guests and the President had the opportunity to address them representing the Council. The function concluded with the addresses of illustrious past-Presidents of ICAI, CA. T.S. Vishwanath and CA. Mukund M. Chitale. CA. T.S. Vishwanath addressed the distinguished audience on the Paradigm Shift in Chartered Accountants' Profession, while taking note of changes and growth in profession vis-à-vis that in economy and world accountancy. CA. Mukund M. Chitale addressed the member participants on Strategy for Sustainability, where he pointed out the issues that institutions and organisations should take up as strategy in order to sustain and grow in their times.

During the function, the Revised Scheme of Education and Training for CA Course and a new Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (Anti-Money Laundering Specialist) were launched along with several other new publications including GST - A Boon for Indian Economy, as published by various Committees of the ICAI.

8.4 Central Council Library

The Central Council Library of the ICAI caters to the information requirements of its stakeholders. Its aims is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non print material to the present and anticipated members, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the committee(s) work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty - a library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under “know your Institute – Central Council Library” - online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library. The services under the website are self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/ Journals under “Suggest Books/Journal columns” for consideration by the ICAI.

Under the Column “Accountants Browser”, an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal “The Chartered Accountant”. One may note that The “Accountants Browser” is an index of important/ Professional Articles with archives for last 15 years. Reference service to library is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & CPT Course Students as a special case. Noida Office of the ICAI at Sector 62 & Vishwas Nagar Students' library have also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to various Directorates and Committees of the ICAI.

Besides above, a number of Online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line databases have been installed in the Central Council Library premises as well as at various Departments to facilitate the search for required material by the students, members, faculties and the research scholars. The Software – Liberty has been deployed for connecting the databases of the Central Council Library with all Regional libraries' databases.

Central Council Library is also procuring necessary publications/ Books for the current courses offered by ICAI including a provision of publications/ Books for all Committees. Several online journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council libraries at Head office and Noida respectively for the period April, 2014 to 7th July, 2015, are as follows:

Central Council Library (H.Q)

S.No.	Title	Approx. fig.
1.	Journals (Print) - National & International	65
2.	E-Access to Journals subscribed	13
3.	Online Resources	10
4.	Number of Books added during the period	654

Central Council Library (Sector 62, Noida)

S.No.	Title	Approx. fig.
1.	Journals (Print) - National & International	44
2.	E-Access to Journals subscribed	09
3.	Online Resources	08
4.	No. of Books added during the period	733

We are also in the process of modernizing the Central Council Library by subscribing E-Books, E-Journal and other online databases along with refurbishing the Central Council Library. Library rules for Students and Members etc. have been formulated for uniform functioning of all Libraries of ICAI.

8.5 Editorial Board

Disseminating Knowledge in 'Letter' and Spirit

The Editorial Board is a non-standing Committee of the ICAI with a Mission to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession, matters relating to the ICAI and its activities and such other matters as deemed to be of educational/ professional value in a structured manner, through the journal '*The Chartered Accountant*'. The journal is available online too as e-Journal, which is also compatible on iOS (IPad/ iPhone etc.) and Android devices. The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at more than 264,000 today, and its global readers include chartered accountants, allied professionals, CA Students and academic professionals from renowned national and international institutions. As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are mass-emailed to all the members.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the ICAI's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognised as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if its readers' feedback is any indication.

The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the ICAI's members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's age of fast-paced globalisation.

Following are some significant achievements between 1st April, 2014 and 7th July, 2015:

Contents and e-Journal:

- ♦ **Wide range of topics covered:** From April, 2014 to July, 2015 issues of the journal, as many as 194 articles/features and reports on various topics were published under various innovative theme issues.

- ♦ **Innovative Theme Issues:** Some new and Innovative theme issues were planned in line with the areas of strategic focus of ICAI Action Plan 2014-15/ 2015-16 besides other regular features. These theme issues were: 'Towards New Frontiers', 'Women Empowerment', 'Young Members empowerment', 'Leadership & Influence', 'Union Budget 2014-15', 'ICAI Achievements', 'Tax Audit', 'CA Education', and 'CAs and Technology', 'IFRS and India', 'ICAI partnering in Shaping a Resurgent India', and 'ICAI Significant Achievements in 2014-15', Union Budget 2015-16, ICAI Spearheading Excellence and ICAI for Inclusive Growth of the profession. Existing features like 'From the President', 'Legal Update', 'National Update' and 'International Update,' etc., were further upgraded.
- ♦ **Editorial Board Action Plan 2014-15 and 2015-16**
The Editorial Board finalized and put into effect its action plan for the years 2014-15 and 2015-16. The highlights of the action plans included 'starting several new features,' 'coming out with a special issue in July, 2014 and July, 2015 coinciding with the CA Day,' 'making the language of the journal more simple and reader friendly,' 'coming out with a fool-proof htmlised DVD of 61 years of journal with dynamic search facility,' 'expansion/ upgradation of journal in indexed mode,' 'highlighting major areas of strategic focus of ICAI Action Plan 2014,' 'Upgradation of design and presentation of the journal,' 'Using whiter gloss paper for printing of the journal' and introducing new user-friendly features in e-Journal.
- ♦ **Major Highlight:**
July 2014 special issue: The July 2014 special issue, carried the Development Agenda of the new Prime Minister Shri Narendra Modi alongwith profile of Shri Arun Jaitley, Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of State (Independent Charge), Commerce and Industry, Minister of State, Finance and Corporate Affairs and of CA. Piyush Goyal, Minister of State (independent Charge), Power, Coal and New and Renewable Energy. The issue also carried special messages from Shri Arun Jaitley, Shri Sashi Kant Sarma, Comptroller & Auditor General of India, among other dignitaries. The issue also highlighted the Significant Achievements of ICAI in the first four months of 2014-15. Note authors who contributed articles are Shri P.N. Vijay, Mr. Warren Allen, President, IAFC, Mr. Brian Blood, Chief Executive of CAPA, CA. Subodh Kumar Agrawal, President, SAARC and immediate past-president, ICAI, CA. T.N. Manoharan, past-president, ICAI etc. Other special features included 'Down the Memory Lane', 'What the leaders said about ICAI during 2013-14'.
- July 2015 Special Issue:** The July, 2015 issue was brought out as special and bigger issue coinciding with 1st July CA Day. The issue focused on past, present and future perspective of ICAI and accounting profession in India. The highlights of the issue included a special interview with Railway Minister CA. Suresh Prabhu, special article on Power Minister CA. Piyush Goyal and special articles authored by Members of Parliament CA. Kirit Somaiya, CA. K. Rahman Khan, IFAC President Olivia Kirtley, ICAI Past President and Padam Shri CA. Y.H. Malegam and XBRL India. Special features of the issue included a detailed report on ICAI's CSR Initiatives over the years, Coverage of some lesser known historic facts about Indian Accounting profession, Report on What the Leaders of Indian polity said about Indian accounting profession over last year, ICAI in Media in 2014-15, coverage of four CAs who have set an example defying all odds of physical disability and age bar, and tribute to late ICAI Past president CA. Rameshwar Thakur. Other regular features included articles on Economy and International Taxation. The Cover page artistically portrayed the concept titled 'ICAI Turn 66' with some rare photographs related to Indian accountancy profession.
- ♦ **DVD of Past Issues of *The Chartered Accountant* journal:** In an important initiative to provide a single point reference window to the readers of *The Chartered Accountant* journal and leverage the technology to serve them better, the Editorial Board brought out DVD of past issues of the journal in two phases. In phase one, a DVD of last 10 years of the journal (July 2002-June 2012) was brought out made available for sale at a nominal cost of Rs 25 per DVD +postal charges. In the second phase, a DVD containing 61 years of *The Chartered Accountant* journal was released. An upgraded master DVD of 63 years of journal (July 1952 to June 2015) is now also in advanced stage of development and will be released soon with a price tag of Rs 150/- including postal charges. This HTML version DVD has journal issues from July, 1952 to June, 2015 in a searchable mode. Readers can global search the contents through key words relating to accounting, auditing, taxation, etc., besides searching by month, year, volume, category (like Circulars & Notifications, ICAI News, Legal Decisions, etc.), author, etc.
- ♦ **Anti-Plagiarism Policy put in place and advanced anti-plagiarism software procured:** Taking cognizance of a steep rise in cases of submission of plagiarised content by authors including academicians, members and students of ICAI, etc. which had the potential to adversely affect the credibility and reliability of *The Chartered Accountant* journal, a comprehensive anti-plagiarism policy was finalized and implemented by the Editorial Board. A high trusted and popular plagiarism detection software has also been procured for the purpose.

- ◆ **Journal in Indexed Mode Launched:** The facility of 'journal in indexed mode' has been upgraded wherein all articles of past 10 years have been classified according to subjects and topics with a dynamic search application. The same has been hosted on the ICAI website.
- ◆ **New Facility of 'Getting The Chartered Accountant on Mobile/ ipad':** A free of cost mobile/ ipad version of *The Chartered Accountant* journal was made operational with effect from 1st March 2013. This facility has been further upgraded now. With this, ICAI e-Journal is now compatible on iOS (IPad/ iPhone etc.) and Android devices to enable our readers to browse through the journal just at the push of button anywhere, anytime. The new podcast and bookmark facilities have also been incorporated in the mobile compatible (on iOS, Android, tablet platform) version of e-Journal. Readers on mobile can now also listen to the textual material instead of reading and can make optimum use of their time while travelling. Readers may now access the e-journal on the above mentioned platforms without any specific download requirements. It can be accessed at <http://www.icai.org/> under 'e-journal' tab.
- ◆ **e-Journal Upgraded:** The electronic version of *The Chartered Accountant journal*, which is available online on ICAI website www.icai.org as a transformed new hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded. In the new version of e-journal, one can also 'listen to' the contents, besides making use of a range of other facilities. However, for the added and alternative convenience of readers, the journal continues to be hosted in the PDF format as well.
- ◆ **Two-tier Screening of Articles Introduced:** This year, the Editorial Board introduced a system of two-tier screening of articles, which are sent in large numbers for consideration of publication in the journal. The first round of screening of articles is done by the office while the Editorial Board members and designated reviewers screen and vet the articles in the second round to select the best articles for publication.
- ◆ **Journal Highlights through e-mail:** For added reach and convenience of members and readers, the highlights of journal with live links of the contents are being emailed to them in PDF format. This initiative is aimed at enabling the members get to know the highlights of the journal in real time just at the click of a mouse instead of waiting for the hard copy of the journal to arrive. This 'journal highlights' capsule has been upgraded to higher professional standard and made more reader-friendly.
- ◆ **Upgrading of President's Message format for mass mail:** As part of the drive to leverage technology to reach out to the ICAI membership in the best and most user-friendly manner, the format quality and look-and feel of the e-version of the President's Message has been significantly enhanced. This upgraded e-message of the President is now being mass-mailed to the members *w.e.f.* March, 2014 issue.
- ◆ **Policy on publishing names in signature line of Announcements in the Journal:** As part of the efforts to strengthen good governance mechanism, the Editorial Board revised the policy with respect to publication of names in the signature line of regular announcements published in the ICAI journal.

Layout and Design:

- ◆ The Cover page of the journal was re-oriented and made more creative, meaningful and thought-provoking based on themes and other related concepts relevant to the ICAI and the profession of accountancy. Further, additional alternative design and content development agencies are also engaged on need be basis for constant improvement. A four-tier mechanism to check the veracity of the cover photographs and content has also been introduced.
- ◆ The journal was given a design and presentation face-lift across the pages. The Mast Head of the journal has been upgraded while the design & Presentation of all the inside pages and features along with font type of the text has been changed in line with global standards.
- ◆ Layout-design and font type face of the entire journal were further upgraded to match international standards.
- ◆ The masthead and basic template of the cover and inside pages were further improved.
- ◆ With effect from May 2014 issue, the journal has switched over to a higher and whiter quality gloss finish 65 GSM paper as part of the concerted efforts to upgrade the overall content quality, look and feel, and appeal to the best standards.

- ◆ For practical ease of the programme organising units/ committees of the ICAI and to ensure uniformity, the Editorial Board has revised the format for publication of ICAI Events in The Chartered Accountant journal w.e.f August, 2015 issue of the journal.

Other Achievements/Initiatives:

- **Total Circulation of Journal crosses 264000 Mark:** Meanwhile, the total circulation figure of the ICAI journal crossed 2,64,000 mark for July, 2015 issue. Accordingly, a special approval has been obtained from Postal authorities to post increased number of copies at concessional rates.
- **Facility to Get Journal at Member's Residential Address:** As part of the efforts to enhance the reach and readership of the journal at the convenience of members, the Facility for members receiving the journal at their residential address (*earlier journals were sent only on their professional address recorded with the ICAI*) was further strengthened and popularised through Committee for Members in Industry, Journal and the ICAI website. The exclusive journal-related option of 'Getting the Journal at their residential address' has been reactivated and being popularized at a mass scale. Necessary back-end changes on the related 'address-change' link on ICAI website have already been done in this regard.
- **New Facility: 'Pay Online for Journal Subscription, Airmail Surcharge':** In line with concerted efforts to harness technology for added convenience, comfort and services to our members, the Editorial Board operationalised the online payment facility for *The Chartered Accountant* journal, which will benefit the readers across the globe. The online payment facility is now available on the ICAI website for 10 categories of readers, which include subscribers, members abroad, classified advertisers, student subscribers etc. This much desired online payment facility for the journal will prove to be immensely beneficial and convenient for its readers and other stakeholders.
- ◆ **Verification of the Printing and Dispatch of Journal:** As part of the continuous monitoring and checking, a new auditor based in Navi-Mumbai has been appointed for the purpose of verification of the number of copies printed at Navi-Mumbai based printing press of the journal printer and the copies dispatched through postal department in Mumbai.
- ◆ **Complimentary List Updated:** As part of the brand building exercise and to deepen ICAI reach among the prominent personalities relevant to the profession, the complimentary list of the journal has been further revised as a continuing process, by updating a number of addresses, deleting obsolete entries and adding several new names under various categories.
- ◆ **Furtherance of the System of Paper Testing:** As part of the continuous process to ensure that journal printer is using the same quality and specifications of the paper as specified in the agreement, samples of the paper used in journal in different months were at random sent to the Government Central Pulp and Paper Research Institute for testing.
- ◆ **Start of Journal dispatch to those becoming members via MRA Route:** The Editorial Board secretariat has started sending the journals to all those becoming ICAI members under MRA/ MOU with foreign accounting bodies. Since there is no provision in the system, they have been enrolled separately by maintaining manual records.
- ◆ **Compliance with legal requirements of Registrar of Newspapers in India:** Complying with legal requirements of Registrar of Newspapers in India (RNI), with which the ICAI is registered, the office has submitted online the mandatory annual report of the journal besides procuring the revised Form B with change in Publisher's name in the records of DCP Licensing Delhi for hindrance free publication of the journal and economical supply of the required paper.
- ◆ **Acquisition of Paper Import Licence for Journal:** Complying with legal requirements of Registrar of Newspapers in India (RNI) and to maintain hindrance free publication of the journal, the office has secured from RNI the license to import printing paper for the journal for this year. This will facilitate regular and economical supply of the required paper from abroad.
- ◆ **Daily Chronicle for International Conference:** A newspaper-type Daily Chronicle was brought out for three days of the ICAI mega international conference held in Bangalore Palace, covering all the discussions, programmes and personalities during the event.

8.6 Accountancy Museum of India

A treasure house of the rich intellectual heritage of accountancy profession, the *Accountancy Museum of India*, set up by the ICAI in 2009, presently holds a range of articles/ documents/ stories taken from the history of mankind. As such, this year, the Museum has acquired some more articles from the senior members and private collectors in India, which will soon be displayed in the Museum. Project *Prototype of AMI* was also taken further — prototype material was sent to 43 of the ICAI Branches this year, thus, making the total count where a prototype of the Museum has been set up, at 87 across the country. The Museum has contributed by making its rich stories and item collection available to the programmes of ICAI, i.e. *National Conference on Rising to the Challenges- Redefining our Role* organised by Committee for Public Finance & Government Accounting in Jaipur and *Global Exhibition on Services* organised by Committee for Economic, Commercial Laws & WTO in New Delhi. Indian media also covered the Museum -- a report on the Museum was carried out in *The Hindu* in August 2014. In addition to the increased number of member visitors, this year, the Museum had visitors in form of students and faculty members from the colleges of University of Delhi — *Shyama Prasad Mukherjee College* and *Satyawati College (Evening)*. The Museum also constantly contributes stories and articles to the journal of the ICAI, *The Chartered Accountant*.

8.7 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

The office pursued the following amendment proposals submitted by it to the Central Government on 5th December, 2013:

- (a) Amendment in Regulation 48 regarding increasing the rates of stipend payable to the articled assistants.
- (b) Amendment in Regulation 51 for recognising three years experience of IA&AS officers in the office of C&AG as equivalent to one year of industrial training.
- (c) Amendment to Regulation 28E reducing the study course from nine months to eight months
- (d) Amendment to Regulation 39 and insertion of new Regulation 39A for increasing the upper limit of fee for verification of marks and provision for inspection and/or supply of certified copy of evaluated answer book.
- (e) Amendment to Regulation 204 providing for post qualification course on international taxation.

As regards proposed amendment to Regulation 51 given at (b) above, the Council later on felt that it was necessary to take a macro view of the matter and decided to withdraw the amendment proposal as far as this matter was concerned.

Upon receipt of in-principle approval of the Central Government to the above amendment proposals, public comments were sought on the draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 notified vide Notification No. 1-CA(7)/167/2014 dated 10th September, 2014 in the Gazette of India. The Council, at its 337th meeting held on 29th-31st October, 2014 considered the comments received from members and students on proposed amendments. The Council on a consideration of these comments decided to make the draft amendments more clarificatory and further decided that an appropriate Explanatory Note be hosted on the website of the ICAI clarifying the intention behind the amendments proposed. Accordingly, the decision of the Council was communicated to the Central Government. The Central Government, vide its letter dated 22nd January, 2015 accorded its final approval to the amendments proposed excepting amendments in Regulation 39(4) and 39A.

The final notification containing amendments in Regulation 28, 48 and 204 were published in the Gazette of India on 23rd January, 2014 and have come into force from that date.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2015, 10,295 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,39,974 as on 1st April, 2015.

During the year ended 31st March 2014, 2,570 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3,262 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2015:

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	63702	43498	107200
In Part-time Practice	2906	5434	8340
Not in Practice	12658	111776	124434
Total	79266	160708	239974

9.2 Convocation

Since November 2008, the ICAI has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. The Convocation is organized at each of five Regional Headquarters twice a year covering the period from March to August and September to February of the financial year. Membership Certificates are conferred to members admitted to the membership during the said period.

This year Convocation - 1st Round 2015 was organized under the aegis of Regional Offices in the month of May-July, 2015 at the following places and schedule:

Place	Date	Place	Date
Ahmedabad	22 nd May, 2015	Hyderabad	10 th July, 2015
Mumbai	23 rd May, 2015	Kolkata	12 th July, 2015
Chennai	19 th June, 2015	New Delhi	16 th July, 2015
Pune	20 th June, 2015	Kanpur	19 th July, 2015
Jaipur	22 nd June, 2015		

In this Convocation, members enrolled during December, 2014 to March, 2015 were awarded membership Certificates. Total 3385 participants attended the convocation ceremony, including left out participants.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31 st March, 2014	119886
2.	Total Life Members as on 31 st March, 2015	123661
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31 st March, 2015)	3794
4.	Total Financial Assistance given during the year ended 31.03.2015	Rs. 1,37,50,107

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 st March, 2015 (Rs.)	During the year ended 31 st March, 2014 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,37,50,107	1,57,81,000
2. Administrative Expenses	22,966	24,991
3. Surplus (Deficit) of the Fund	55,65,697	(15,989)
4. Balance of the Fund	21,64,314	(34,01,383)
5. Balance of Corpus	16,00,92,797	14,44,41,795

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2015, 117 scholarships of the value of Rs.1000/- each per month are to be given to the students undergoing the articled training. The number of life membership of the Fund increased from 5920 as on 31st March, 2014 to 6932 as on 31st March, 2015. The balance in the credit of the Fund was Rs.44,27,885/- as on 31st March, 2014 as against Rs. 43,12,077/- as on 31st March, 2015.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2015, 394 students (who are undergoing the articled training) were granted financial assistance of the value of Rs.1000/- each per month for one year. The balance in the credit of the general fund was Rs. 9,70,88,753/- as on 31st March, 2015 as against Rs. 7,63,38,248/- as on 31st March, 2014.

10. STUDENTS

The Board of Studies is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to students undergoing Chartered Accountancy Course. The significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:-

1. Educational Inputs

Revision of Study Materials: As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of various study materials have been updated/ revised with incorporation of appropriate changes. The study material of CPT Course was revised in Nov. 2014. The study material for Intermediate (IPC) Course along with the Practice Manuals of all the subjects was revised in July, 2014 followed by Taxation in October, 2014. Based on the revised syllabus, the material for the subjects relating to Business Laws Ethics and Communication (BLEC) and Auditing and Assurance, were also revised in July, 2014 while the Practice Manual of BLEC was revised in Dec. 2014.

Similarly, the Study Material for Final Course along with the Practice Manuals of all the subjects were also revised in January, 2015. Based on the revised syllabus the material for subjects relating to Corporate and Allied Laws and Advanced Auditing and Professional Ethics, were also brought out in the month of October, 2014 and January, 2015 respectively.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

Course-wise e-Learning DVDs for CPT, Intermediate (IPC) and Final containing Chapter-wise Study Material including Practice Manual, e-Lectures, Podcast (MP3 Audio), PowerPoint Presentation (Short Notes) and Self Assessment Quiz were exhaustively revised to facilitate the students in their study. These DVDs are issued free of cost along with a set of Study Material at the time of their registration to the respective courses.

On the basis of English study material for subjects whose syllabus have been revised are translated in Hindi for IPCC and Final Course.

The same are also hosted on the web site with free downloading facility.

Digest of Select Cases: The digest of Select Cases in Direct and Indirect Tax Laws containing important case laws relating to Direct and Indirect Taxes have been published in October, 2014 and also hosted on the website with free downloading facility.

Supplementary Study Materials in Taxation subjects: Supplementary study material in Direct and Indirect Taxes for Final Level and Taxation for IPCC Level is an annual release containing amendments made in the Finance Act with latest circulars and notifications issued during the year. Accordingly, the Supplementary Study Material relating to Taxation for Intermediate (IPC) and Final Courses containing the amendments made in the Finance (No.2) Act, 2014 and important Budget notifications/ circulars in this respect issued between 1st May, 2013 and 30th April, 2014 were released for benefit of students.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

Revision Test Papers: The Revision Test Papers (RTPs) for IPCC/ATC and Final exams were published in time which enabled the students to prepare well for their examinations. These were also hosted on the website of the ICAI with free of cost downloadable facility.

Suggested Answers: In order to facilitate and guide the students for better preparation for examinations, Suggested Answers for Integrated Professional Competence Course (IPCC)/ Accounting Technician Course (ATC) and Final Course Examinations held in May, 2014 and November, 2014 were printed well in advance and made available for students.

These Suggested Answers were also hosted before declaration of the Results on the website of the ICAI with downloadable facility.

For benefit of students opting Hindi medium, the Suggested Answers and Revisionary Test Papers were also got translated in Hindi for the respective Examinations.

These were also hosted on the web site of the ICAI with free of cost downloadable facility.

How to Face CA Exams: “How to Face Common Proficiency Test” and “How to Face CA Examinations - Intermediate (IPC)/Final” are annual publications that offers guidance to the students in undertaking the Examinations to qualify them successfully and are also being distributed at the Special Career Counselling Programmes conducted by Regional Councils and their Branches.

These are hosted on the web site of the ICAI with downloadable facility.

Students' Journal: The Board of Studies, since June, 1997 has been publishing a monthly Journal for students named "The Chartered Accountant Student". The Students' Journal includes regular features such as articles on topics relevant to the CA Students, academic updates, theme issues, motivational write-ups and important announcements. The Journal continued to be popular and proved very useful to the student community, as well as members of the ICAI.

2. IT Initiatives

ICAI Cloud Campus: Evolving with the changing times, the physical brick and mortar campus is now available on the Cloud - The ICAI Cloud Campus (<http://cloudcampus.icai.org>). It galvanizes the power of cloud to reach out to students across the country and abroad to get education and training at their doorsteps; and at the same time provides One-Stop-Window to all their educational, administrative, examination, enrolment and other requirements. It starts with providing all pertinent information about the course, course registration, education, filling examination forms to getting results.

The Cloud Campus integrates navigation of six portals for easy access by students to provide One-Stop-Window; namely (a) e-Learning LMS, (b) BoS Knowledge Portal, (c) Webcasts, (d) Online Registration Portal for GMCS/ OP/ ITT, (e) Examination Portal and (f) Articleship Placement Portal.

Video Lectures on practical problem solving subjects: Video lectures for practical problem solving subjects like Accounts, Taxation, Financial Management, Advanced Management Accounting etc., are now available on the Cloud Campus providing greater conceptual clarity and problem solving skills. These lectures aim to teach step-by-step practical problem solving process – a key skill requirement today from examination perspective. Currently 476 video lectures covering 375 hours have been hosted, as on 7th July, 2015.

Online Mentoring: Online mentoring facility on the Cloud Campus aims to enable students across the country and abroad to get online mentoring subject and topic wise for the three levels of the CA Course including counseling. Students would be also able to ask queries on the session/ event topic, which would get answered subject to availability of time and relevance. ICAI has organized 61 session till 7th July, 2015.

Articled Training Resources: Audit Programs, Audit Checklists, guidelines etc., aim to facilitate students in their practical training.

Following portals pertaining to students have been integrated in cloud campus for easy access to provide one-stop-window are as follows:

E-Learning on Students LMS: The ICAI Cloud Campus provides a link to e-Learning facility for CA Course on Students Learning Management System (LMS) at <http://studentslms.icai.org> that provides a self-learning/ development facility for students. The Student LMS aims to provide quality education for learning, re-learning and revising anytime and anywhere across the country and abroad, in an easily accessible and affordable manner. It is a learning system to be pursued along with practical/ articulated training.

In addition to self-Learning/ e-Education, the e-Learning facility includes Self Assessment Quiz after each lecture to enable students make an assessment of their preparation for the forthcoming examinations - Chapter Wise and Subject Wise. Apart from being a tool for Self Assessment, the Self Assessment Quiz are designed as a Learning and Development facility through the "Review" facility, whereby students can learn the right answers vis-à-vis answers attempted by them.

The Student LMS keeps a track of the learning and development by the student in terms of lectures available, attempted/ completed, self assessment quiz attempted/ completed. The e-Learning is now Mobile Enabled – Students can view the e-Lectures on smart phones/ mobiles/ tablets. Currently 784 hours of e-Learning is available covering 185, 259 and 311 hours respectively for CPT, IIPC and Final courses, as on July 7, 2015.

BoS Knowledge Portal: The BoS Knowledge Portal provides Chapter Wise Study Material, Practice Manual, PowerPoint Presentations, Audio Lectures (Podcasts/ MP3) for the respective papers and chapters for CPT, Intermediate (IPC) and Final Courses. It also provides other resources/ publications issued by Board of Studies from time to time.

Articles Placement Portal: The Articles Placement Portal link on ICAI Cloud Campus enables students to register online and get selected for articles training in CA Firms having vacancies in their preferred city/ town.

e-Learning DVDs for CPT, Intermediate (IPC) and Final Courses: The Board of Studies has also released e-Learning DVDs for CPT, Intermediate (IPC) Course (Group-I and Group-II) and Final Course (Group-I and Group-II) offering Chapterwise Study Material, Practice Manual, e-Lecture, Podcast (MP3 Audio), PowerPoint Presentation (Short Notes) and Self-Assessment Quiz.

While these DVDs have been designed to work on Multimedia Desktop Computer and Laptop, they have been developed as a responsive site that may also work on recent Mobile Phones and Tablets (Android 4+, IOS), when copied on the Memory/ SD Card, and viewed using Mozilla Firefox Internet browser. Students can learn anytime/ anywhere without the need for Internet, waiting for content to download and costs thereto.

VoD of Webcasts: The Webcasts link on ICAI Cloud Campus provides video on demand lectures mentoring students on the success strategies to succeed in their examinations for respective subjects of Common Proficiency Course (CPC), Intermediate (IPC) Course and Final Course, as also for Accounting Standards, and specific topics of select subjects, where syllabus has changed or students are finding difficulties.

Online Registration Portal for GMCS/ OP/ ITT Courses: The Online Portal for Registration to GMCS/ OP/ ITT Courses on ICAI Cloud Campus enables students to register online for these courses, select convenient batches at preferred location/ Branch, batch transfer, faculty allocation, course scheduling, feedback submission and certificate generation. This portal has four modules namely Students, Faculty, PoU and HO Admin.

3. Other Initiatives

Reading Rooms: Board of Studies has been continuously following up with Regional Councils and Branches to explore the possibility of opening additional Reading Rooms for the benefit of students of the ICAI. So far, 89 Libraries-cum-Reading rooms and 35 Additional Reading rooms are being operated by Regional Councils and their Branches.

Board of Studies is in the process of opening one Additional Reading room each at Indore (Madhya Pradesh), Jalgaon (Maharashtra) and Tumkur (Karnataka).

4. Development Programmes

Four Weeks' Residential Programme on Professional Skills Development for students: Four weeks' Residential Programme on Professional Skill Development is organized by Board of Studies for the benefit of students who have passed Chartered Accountancy Final/ IPCC/ PCC/ PE-II/ Intermediate (IPC) Examination and pursuing last year of article training or completed Articleship training. The programme helps the Chartered Accountancy students and newly qualified Chartered Accountants in imbibing the professional skills required for effective functioning in business organisations and the profession. The programme environment focuses on development of communication skills, personal qualities, interpersonal and teamwork skills, problem solving skills and leadership skills. Twelve batches at Centre of Excellence, Hyderabad and one batch at National Institute of Financial Management, (NIFM), Faridabad have been organised successfully during the 1st April 2014 to July, 2015.

Courses on General Management and Communication Skills for Students: With a view to make the GMCS more effective, the Council at its 331st meeting decided to discontinue the existing GMCS course with effect from 1st April, 2014 and directed that students registered for Practical Training on or before 30th April, 2012 shall be required to undergo GMCS-II course only instead of existing GMCS course before applying for membership of the ICAI as per Regulation 51A/72A of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

As of now, 145 Programme Organizing Units (POUs) are organizing General Management and Communication Skills - I and 85 Programme Organizing Units (POUs) are organizing General Management and Communication Skills - II across the country.

During the period (April, 2014 - June, 2015), 1,275 batches of 15 days Course on GMCS-I were organized by 140 POUs across the country and 58,313 students participated in these programmes.

Further, during the period (April, 2014 - June, 2015), 512 batches of 15 days Course on GMCS-II were organized by 85 POUs across the country and 23,611 students participated in these programmes.

Orientation Programme for Students: CPT route students who are registering for Accounting Technician Course exclusively shall be required to undergo Orientation Programme before appearing in the ATE. Students coming through CPT route for Intermediate (Integrated Professional Competence) Course shall be required to complete Orientation Programme before registering for practical training (either before appearing or passing Group-I or both). Candidates entering through Direct Entry Route also are required to undergo Orientation Programme before joining for practical training.

As of now, 148 Programme Organizing Units (POUs) are organizing Orientation Programme across the country.

During the period (April, 2014 - June, 2015), 1,732 batches of Orientation Programme were organized by 141 POUs across the country and 74,995 students participated in these programmes.

Two days Faculty Development Programme for faculty of GMCS Course & Orientation Program: The Board of Studies has organized six “Two Day Faculty Development Programmes” on 20th-21st June, 2014 at Gandhi Research Foundation, Jain Hills, Jalgaon; on 19th-20th January, 2015 at Ras Resorts and Apart Hotels, Silvassa; on 22nd-23rd January, 2015 at Fort Chandragupt Heritage Hotel, Jaipur; on 28th-29th January, 2015 at Centre of Excellence, Hyderabad; on 2nd-3rd May, 2015 at ITC Grand Chola, Chennai and on 5th-6th July, 2015 at Ras Resorts and Apart Hotels, Silvassa for the faculty of Orientation Programme and GMCS Courses. The objective of the FDP is to standardize and ensure uniform delivery of the lecture sessions of the faculty of Orientation Programme and GMCS Courses.

ITT Centres: The ICAI has set up 159 ITT centres equipped with the latest computers, software and other infrastructural facilities to impart training at almost all its branches and regional offices.

ITT Course for Students: The ITT Course provides training on application software relevant for accounting/ auditing and allied areas including Office Automation, Accounting, Web Technology and e-Filing. Students registering for Accounting Technician Course exclusively after qualifying CPT be required to undergo ITT Course before appearing in the ATE. Intermediate (Integrated Professional Competence) Course students are required to complete ITT Course before registering for practical training (either before appearing or passing Group-I or both). Direct Entry students are also required to undergo ITT course before joining for practical training.

The ICAI has established 159 ITT Centres at Regional/ Branches Offices with requisite computer hardware/ software and infrastructural facilities to impart training for ITT and Advanced ITT Courses. During the year, five (5) new ITT Centres have been established.

Currently the ITT Course is available at 159 ITT Centres and 68,000+ students have completed the course in 1,623+ batches by July 7, 2015.

Advanced ITT Course for Students: The Advanced ITT course was launched in October, 2014 that is to be taken by Students of the Final Course. This course aims to provide training on computer applications relevant for the profession including Database Applications using MS-Access, Advanced features MS-Excel, CAAT, Core Banking Solution (CBS), Enterprise Resource Planning (ERP) and Office automation application and IT security in a CAs office.

Currently, the Advanced ITT Course is available at 111 ITT Centres and more than 15000 students have complete the course in 83+ batches by 7th July, 2015.

The Board of Studies has prepared and released the Study Material for Advanced ITT Course along with Lab Practice Manual, PowerPoint Presentations and Video Lectures in October, 2014.

Faculty Development Programme for Faculty Members at ITT Centres: The Board has organised three Faculty Development Programmes (FDPs) region-wise at Delhi, Hyderabad and Mumbai in August-September, 2014 for the Faculty Members at ITT Centres in which 126 faculty members have been trained from 82 ITT Centres.

Besides physical training to Faculty participants all across India, two live webcasts were also organised by the Board on ERP and CBS to provide orientation and training to Faculty Members at ITT Centres. A recording of these webcasts is also provided to students as a part of the Study Material.

The Board is also organizing Online FDPs for Faculty Members of ITT Centres to get required orientation and training to take classes and enhance practical coverage as a part of the Course. As a part of this initiative, (a) Overview and QA sessions are organised using Google HoA and (b) Video lectures on practical case studies are provided. Six (6) Overview & QA sessions and six (6) video lectures have been organised till date.

Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication: 5 branches organized 8 Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication

Mock Tests: With a view to encourage the students to evaluate their preparation for the examinations, Mock Tests for Intermediate (IPC)/Final and CPT Level were organised through Regional Councils and Branches for May/ November and June/ December main examinations.

100 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final level for May, 2014 examinations and 124 Branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for June, 2014 examination.

97 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final level for November, 2014 examinations and 110 branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for December, 2014 examination.

107 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final level for May, 2015 examinations and 126 Branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for June, 2015 examination.

Special Counselling Programmes (How to Face CA exam?): During the year 87 Special Counselling Programmes were organized by 45 branches, including Regional Councils.

5. MoUs/ MRAs/Recognitions/Other Arrangements

Recognition of CA Course for Ph.D Programme: With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 99 Universities, 6 IIMs and IIT Madras (Total 106) for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

Accreditation: The ICAI has been imparting education to students pursuing CA course through distance education mode, since inception across the country in a consistent manner. Comprehensive packages of educational inputs are provided to enable students to adequately prepare for the examinations. While the aforementioned efforts are being made at the central level, imparting oral coaching by the accredited institutions supplements the efforts of ICAI by providing quality classroom coaching at a reasonable cost. To make available quality Coaching Classes to the students, the Board of Studies has authorized and encouraged all the Regional Councils and Branches of the ICAI to organize oral coaching classes. Also, the Board of Studies grants accreditation to Universities/ Colleges, Schools, Trusts/ NGOs/ Societies and other academic institutions.

The Accreditation Scheme for granting accreditation to institutions for organizing coaching classes for CA students, has been revised recently to ensure that Institutions with better infrastructure and teaching faculty are granted accreditation for the benefit of students. As of now, the Board of Studies has 50 accredited institutions for CPT, Intermediate (IPC) and Final Course.

6. Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities

National Convention, All India Conference and International Conference for CA students: During the period, 36 National Conventions were organized at Jaipur, Indore, Nagpur, Kolkata, Guntur, Surat, Hisar, Guwahati, Vijayawada, Lucknow, Ahmedabad, Gurgaon, Ernakulam, Faridabad, Hubballi, Bhubaneswar, Ghaziabad, Bilaspur, Ranchi, New Delhi, Coimbatore, Aurangabad, Nashik, Mumbai, Ludhiana, Meerut, Karnal, Pune, Chennai, Tirupati, Thane and Cuttack in addition to an All India Conference at Hyderabad and an International Conference at Bangalore.

Regional/ Sub-Regional/ National Conclave for CA Students: During the period 14 National Conclaves were organized at Goa, Cuttack, Visakhapatnam, Rourkela, Patna, Bhopal, Jalgaon, Rajkot, Agra, Thrissur, Udupi, Jamshedpur and Sri Ganganagar. Also, 2 Regional Conferences at Vasai and Salem and 2 Sub-Regional Conferences at Thiruvananthapuram and Amravati were organised.

One-Day Seminars: During the year, 296 One-day Seminars were organized by 75 Branches including Regional Councils.

Two-day Mega Seminars: During the year, 9 Branches organized Two-day Mega Seminars.

Debate Competitions: The Debate Competitions at Branch Level were organised by 75 Branches including Regional Councils and at Regional Level the Debate Competitions were organized by WIRC, SIRC, EIRC and CIRC.

CA Students' Festivals: During the year, 51 Branches including Regional Councils, organized 55 CA Students' Festivals.

Sports Competitions: During the year, 55 Branches including Regional Councils, organized 69 Sports Competitions.

Elocution Contests: The Branch Level Elocution Contests were organized by 93 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. The All India Elocution Contest was held at CoE, Hyderabad on 28th January, 2015.

Quiz Contests: The Branch Level Quiz Contests were organized by 98 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. The All India Quiz Contest was held at CoE, Hyderabad on 28th January, 2015.

Joint Seminars with Universities: The Board of Studies is in continuous pursuit with different universities in India organise Joint Workshop/ Seminar on contemporary topics of Accountancy and Commerce.

The Board of Studies organized Joint Seminar with the following Universities:

Two day Joint Seminar with Mata Vaishno Devi University, Katra Jammu on 9th & 10th October, 2014 on “Accountancy and Commerce Education in India: Contemporary Issues and Challenges”; One day Joint with Mysore University, Mysore on 14th November, 2014 on “International Financial Reporting Standards (IFRS)”; Two day Joint Seminar with Osmania University, Hyderabad dated 1st & 2nd December, 2015 on “Forensic Accounting and Fraud Examination”; Two day Joint Seminar with Tejpur University, Assam dated 30th-31st January, 2015 on “Companies Act, 2013 and Corporate Governance”; One day Joint Seminar with Tumkur University, Tumkur on 6th February, 2015 on “New Policy Implementation and Issues in Direct Tax and Foreign Trade”; One day Joint Seminar with Bangalore University, Bengaluru on 23rd April, 2015 on “Changing Dimension of Corporate Reporting in India under IFRS”.

7. Measures for creating awareness about the CA Course

Career Counselling Programmes: Career Counselling Programmes are being organized at Regional Councils and Branches to popularize the CA Course and also to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum resolved. During the period from 1st April, 2014 to 7th July, 2015, 177 Career Counselling Programmes were organized by 35 Branches, including Regional Councils, at different locations throughout the country.

Mega Career Counselling Programmes: During the year, 10 Mega Career Counselling Programmes were organized by branches throughout the country.

8. Scholarships granted to students

The Board of Studies awards scholarships under following categories:-

Scholarships to Meritorious students: Scholarships are awarded to the meritorious students whose names appear at Sl.No. 1 to 10 (in case the rank of Sl.No.10 continues to Sl.No.11 or to Sl.No. 12 or so on, all such rank holders) of the merit lists of Intermediate (IPC) Examinations, held in May & November and of Common Proficiency Test, held in June & December every year respectively as a token of appreciation for their achievement and sincere efforts put in by them while pursuing the Chartered Accountancy course.

Scholarships to Meritorious and needy students: To appreciate and promote the meritorious students with financially weak background to take up further studies, 60 Merit-cum-Need scholarships are being awarded to the Rank Holders of Intermediate (IPC) Examinations, held in May & November and of Common Proficiency Test, held in June & December every year on fulfilling the specified conditions.

Scholarships to Need-based & Weaker Sections: In order to facilitate and support the deserving students belonging to economically weaker sections, the number of scholarships has been increased from 100 to 200 for Intermediate (IPC) Students and from 100 to 300 for the students of Final Course per year w.e.f. October, 2014. Also, the children of the deceased members of the ICAI pursuing CA Course and whose spouses are getting financial assistance under Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF), shall be provided the scholarship under “Need Based and Weaker Sections” category, on receipt of their applications.

Scholarships under Endowment Schemes: Contributing towards the common cause of profession building, the endowment funds have been created by the Individual donors and as Joint Corpus by the donors. Out of interest earned on these funds, the scholarships are being awarded for the benefit of the upcoming students belonging to weaker sections on the basis of the criteria applicable for awarding the scholarships for Need-based & weaker Sections category.

During the year, the Board of studies awarded 1225 Scholarships to selected students under above categories.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

The total number of branches of Regional Councils is 150 as on July, 2015.

Currently, there are 26 Chapters of the Institute outside India.

Currently, there are 20 Reference libraries all over India.

11.1 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 119 branches of Students' Association have been set up.

11.2 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 86 branches have their own premises.

11.3 Award for best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association

These awards are given by the Institute every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2014 these Shields were awarded at the Annual Function held on 11th February, 2015 to the following winners:-

1. Best Regional Council
 - WIRC and EIRC jointly: Best Regional Council Trophy & Certificate
 - SIRC: Highly commended Regional Council Trophy & Certificate
 - NIRC and CIRC: Certificate of Appreciation and Trophy.
2. Best Students' Association
 - WICASA: Best Student' Association Trophy & Certificate
 - EICASA and SICASA jointly: Highly commended Students' Association Trophy & Certificate
3. Best Branch of Regional Council
 - Mega Branch Category (2501 & above members)
 - Ahmedabad and Bangalore jointly: Best Branch Trophy & Certificate
 - Hyderabad and Jaipur jointly: Highly commended Branch Trophy & Certificate
 - Gurgaon: Certificate of Appreciation and Trophy
 - Large Branch Category (1001 to 2500 members)
 - Indore: Best Branch Trophy & Certificate
 - Ernakulam: Highly commended Branch Trophy & Certificate
 - Nagpur: Certificate of Appreciation and Trophy
 - Medium Branch Category (501 to 1000 members)
 - Siliguri: Best Branch Trophy & Certificate
 - Aurangabad: Highly commended Branch Trophy & Certificate
 - Bhopal, Pimpri Chinchwad & Raipur jointly: Certificate of Appreciation and Trophy
 - Small Branch Category (201 to 500 members)
 - Hubli & Salem jointly: Best Branch Trophy & Certificate
 - Ahmednagar: Highly commended Branch Trophy & Certificate
 - Bikaner and Bhilai jointly: Certificate of Appreciation and Trophy
 - Micro Branch Category (upto 200 members)
 - Ratlam and Udupi jointly: Best Branch Trophy & Certificate
 - Tuticorin: Highly commended Branch Trophy & Certificate
 - Quilon and Nanded jointly: Certificate of Appreciation and Trophy
4. Best Branch of Students' Association
 - Large Branch Category (more than 1000 students)
 - Aurangabad and Nagpur jointly: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate
 - Bangalore and Nasik jointly: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate
 - Indore: Certificate of Appreciation and Trophy

- Medium Branch Category (301 to 1000 students)
 - Raipur and Salem jointly: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate
 - Bhillai and Bhopal jointly: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate
 - Hubli: Certificate of Appreciation and Trophy
- Small Branch Category (upto 300 students)
 - Siliguri: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate
 - Tuticorin: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2015 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 2006, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2014-15 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2014-15.

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to CA. Suresh P. Prabhu, Hon'ble Union Minister for Railways, CA. Piyush Goyal, Hon'ble Minister of State (I/C), Ministry of Power, Coal, New & Renewable Energy, CA. K. Rahman Khan, M.P., Rajya Sabha, Former Union Minister of Minority Affairs & Former Deputy Chairman Rajya Sabha, Shri Shivraj Chauhan, Hon'ble Chief Minister, Madhya Pradesh, Ms. Kiran Maheshwari, Hon'ble Minister, Govt. of [Rajasthan](#), Shri Babu Lal Verma, Hon'ble Minister, Department of Transport, Government of Rajasthan, Dr. Nasim Zaidi, Chief Election Commissioner, Shri P.K. Dash, Director General, Election Commission of India, Shri Prasenjit Mukherjee, Deputy Comptroller and Auditor General (CAG) & Chairman, Audit Board, Dr. B.S. Bhandari, Member, Pension Fund Regulatory & Development Authority, Dr. Subhash Chandra, Chairman, Zee Entertainment Enterprises Ltd., Shri Rana Kapoor, President Assocham & Founder, MD & CEO, Yes Bank Limited, Shri Pawan Kant Munjal, Vice Chairman, CEO & MD, Hero MotoCorp Limited, CA. T.S. Vishwanath, Past President, ICAI, CA. Mukund M. Chitale, Past President, ICAI and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2014-15 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2005)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481

1 st April, 2009	Associate Fellow Total	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 st April, 2010	Associate Fellow Total	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 st April, 2011	Associate Fellow Total	38608 19831 58439	22998 15612 38610	9154 7406 16560	12329 11182 23511	18547 14943 33490	101636 68974 170610
1 st April, 2012	Associate Fellow Total	45273 20510 65783	25505 16132 41637	11069 7578 18647	15963 11720 27683	23332 15431 38763	121142 71371 192513
1 st April, 2013	Associate Fellow Total	52846 21522 74368	28020 16918 44938	13258 7815 21073	20606 12327 32933	27743 16051 43794	142473 74633 217106
1 st April, 2014	Associate Fellow Total	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 st April, 2015	Associate Fellow Total	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974

MEMBERS*(From 1st April, 1950)***TABLE II**

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1 st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1 st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1 st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1 st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1 st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1 st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974

STUDENTS REGISTERED*(From 31st March, 2010)*

During the year	Final	CPT	PCC	IPCC & IPCC	ATC	Total
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712	-	85,053	2,099	2,96,379
2012-13	45,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642

COUNCIL (2015-2016)

Members of the Council (2015-16)	
President	Elected Members
CA. Manoj Fadnis	CA. Adukia Rajkumar S. Mumbai
	CA. Agarwal Sanjay New Delhi
	CA. Agarwal Shyam Lal Jaipur
Vice-President	CA. Agrawal Subodh Kumar Kolkata
CA. M. Devaraja Reddy	CA. Babu Abraham Kallivayalil Kochi
	CA. Bandyopadhyay Abhijit Kolkata
	CA. Chaudhary Sanjiv Kumar New Delhi
	CA. Chhaira Jay Surat
	CA. Chhajed Prafulla Premsukh Mumbai
Period	CA. Devaraja Reddy M. Hyderabad
12 th February, 2015 onwards	CA. Fadnis Manoj Indore
	CA. Garg Vijay Jaipur
	CA. Ghia Tarun Jamnadas Mumbai
	CA. Goyal Anuj Ghaziabad
Secretary to the Council	CA. Guha Sumantra Kolkata
Mr. V. Sagar	CA. Gupta Atul Kumar Delhi
	CA. Gupta Naveen N.D. New Delhi
	CA. Gupta Vijay Kumar Faridabad
	CA. Jain Pankaj Inderchand Mumbai
	CA. Jambusaria Nihar Niranjan Mumbai
	CA. Joshi Shriniwas Yeshwant Mumbai
	CA. Kushwah Mukesh Singh Ghaziabad
	CA. Maheshwari Sanjeev Krishnagopal Mumbai
	CA. Murali V. Chennai
	CA. Nanda Charanjot Singh New Delhi
	CA. Raghu K. Bangalore
	CA. Santhanakrishnan S. Chennai

CA. Sekar G.	Chennai
CA. Shah Dhinal Ashvinbhai	Ahmedabad
CA. Venkateswarlu J.	Hyderabad
CA. Vikamsey Nilesh Shivji	Mumbai
CA. Zaware Shiwaji Bhikaji	Pune
Nominated Members	
Dr. Bhaskar Chatterjee	New Delhi
Mr. J.S. Deepak	New Delhi
Mr. Manoj Kumar	New Delhi
Mr. P.K. Mishra [w.e.f. 10.9.2015]	New Delhi
Mr. P. Sesh Kumar [till 9.9.2015]	New Delhi
Mr. R.K. Jain	New Delhi
Mr. Salil Singhal	Gurgaon
Mr. Sidharth Kumar Birla	New Delhi
Mr. Sunil Kanoria	New Delhi

ASA & Associates LLP
chartered accountants
www.asa.in

B.M. Chatrath & Co.
chartered accountants
www.bmchatrath.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**To the Members of
The Institute of Chartered Accountants of India**

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2015, and its surplus and its cash flow for the year ended on that date.

Other Matter

We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centre, Students Associations, Regional Councils and their Branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs. 38,226 lac, total revenues of Rs. 20,773 lac and net cash flows/ (outflow) amounting to Rs. (2,450) lac are considered in the consolidated financial statements, have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches are based solely on the reports of the other auditors.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

- a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) in our opinion proper books of account as required by Chartered Accountants Act, 1949 have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books;
- c) the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- d) in our opinion, the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards issued by the Institute.

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 009571N/N500006

Sd/-
Parveen Kumar
Partner
Membership No. 088810

For B.M. Chatrath & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 301011E

Sd/-
Umesh C. Pandey
Partner
Membership No. 055252

Place: New Delhi
Date: September 1, 2015

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

		As at March 31, 2015	(Rs. In lacs) As at March 31, 2014
SOURCES OF FUNDS			
(1) Surplus and Earmarked Funds			
(a) Reserves and surplus	3	108,661	102,740
(b) Earmarked funds	4	25,799	20,852
(2) Other long-term liabilities		134,460	123,592
(a) Other long-term liabilities	5	961	1,013
(b) Long-term provisions	6	5,530	3,762
(3) Current liabilities		6,491	4,775
(a) Other long-term liabilities	7	23,868	22,171
(b) Short-term provisions	6	250	325
		24,118	22,496
TOTAL		165,069	150,863
APPLICATION OF FUNDS			
(1) Non-current assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible assets	8	48,885	46,246
(ii) Intangible assets	9	30	4
(iii) Capital Work-in-progress		11,387	9,523
		60,302	55,773
(b) Non-current investments	10	13,737	-
(c) Long-term loans and advances	11	3,724	2,968
(d) Other non-current assets	12	747	110
(2) Current assets		78,510	58,851
(a) Current investments	10	72,757	77,572
(b) Inventories	13	1,700	1,024
(c) Cash and cash equivalents	14	6,027	6,886
(d) Short-term loans and advances	11	3,841	3,611
(e) Other current assets	15	2,334	2,919
		86,559	92,012
TOTAL		165,069	150,863

See accompanying notes forming part of the financial statements

Sd/-
H.K. Jain
Joint Secretary

Sd/-
V. Sagar
Secretary

Sd/-
CA. M. Devaraja Reddy
Vice-President

Sd/-
CA. Manoj Fadnis
President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

For B.M. Chatrath & Co.
Chartered Accountants
FRN: 301011E

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No.-088810

Sd/-
CA. Umesh C. Pandey
Partner
M.No.-055252

Place : New Delhi
Dated : 1st September, 2015

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(Rs. In lacs)
For the Year
Ended
March 31, 2015

I Income			
(a) Fees received	16	47,802	49,558
(b) Seminars participation fees		6,807	6,311
(c) Other income	17	11,321	7,295
Total Income		65,930	63,164
II Expenses			
(a) Seminars		6,797	5,939
(b) Employee benefit expense	18	12,568	7,693
(c) Printing and stationery		7,103	6,921
(d) Depreciation and amortization expense	8,9	2,348	2,026
(e) Other expenses	19	26,449	22,988
Total Expenses		55,265	45,567
III Net surplus before prior period adjustments (I-II)		10,665	17,597
IV Less: Prior period adjustments		256	16
V Net surplus after prior period adjustments		10,409	17,581
VI Appropriation to funds/reserves			
(a) Education fund [See Note 2.4 (iii)]		5,027	5,916
(b) Employees benevolent fund [See Note 2.4 (iv)]		39	37
(c) Earmarked Fund (Net of expenses) [See Note 20.9]		1,691	-
(d) General reserve		3,652	11,628
Total		10,409	17,581

See accompanying notes forming part of the financial statements

Sd/-
H.K. Jain
Joint Secretary

Sd/-
V. Sagar
Secretary

Sd/-
CA. M. Devaraja Reddy
Vice-President

Sd/-
CA. Manoj Fadnis
President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

For B.M. Chatrath & Co.
Chartered Accountants
FRN: 301011E

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No.-088810

Sd/-
CA. Umesh C. Pandey
Partner
M.No.-055252

Place : New Delhi
Dated : 1st September, 2015

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(Rs. In lacs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2015	For the Year Ended March 31, 2014
Cash Flow from Operating Activities		
Net surplus after prior period adjustment	10,409	17,581
Opening Bal of Reserve/Earmarked Fund of Students Associations	101	-
Adjustments for :		
Depreciation and amortization	2,348	2,026
Assets discarded	58	24
Interest Income	(7,971)	(5,008)
Operating surplus before Working Capital changes	4,945	14,623
Adjustment for :		
(Increase)/Decrease in inventories	(676)	(187)
(Increase)/Decrease in loans & advances	(1,336)	(709)
(Increase)/(Decrease) in liabilities	1,691	908
(Increase)/(Decrease) in provisions	1,693	145
	6,317	14,780
Income Tax Deducted at Source (recoverable)	350	(513)
Cash generated from Operating activities (A)	6,667	14,267
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(6,981)	(5,492)
Acquisition of Investments	(8,822)	(15,842)
Interest income received ³	7,919	5,572
Capital	125	923
Cash (used in) Investing activities (B)	(7,759)	(14,839)
Cash Flow from Financing Activities		
Admission fees from new members	68	178
Contribution from members	233	361
Cash from Financing activities (C)		

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	(859)	(211)
Cash and Cash Equivalents at beginning of the years	6,886	7,097
Cash and Cash Equivalents at closing of the years	6,027	6,886

Notes :

- (1) Cash and Cash Equivalent represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 14).
- (2) Figures in brackets represent outflows.
- (3) Includes income (net of expenses) from earmarked funds.
- (4) Opening balance of reserves is added since, Student Associations have been incorporated for the first time in the financials.

Sd/-
H.K. Jain
Joint Secretary

Sd/-
V. Sagar
Secretary

Sd/-
CA. M. Devaraja Reddy
Vice-President

Sd/-
CA. Manoj Fadnis
President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

For B.M. Chatrath & Co.
Chartered Accountants
FRN: 301011E

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No.-088810

Sd/-
CA. Umesh C. Pandey
Partner
M.No.-055252

Place : New Delhi
Dated : 1st September, 2015

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July, 1949 under an Act of Parliament viz. The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For the purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai & New Delhi, 18 Regional Offices and Decentralised Offices, 147 branches and one overseas office.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Accounting

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with applicable Accounting Standards issued by the Institute. The financial statements are prepared under the historical cost convention on going concern and on accrual basis unless otherwise stated. The accounting

policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2.2 Use of Estimates

The presentation of financial Statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosures of contingent liabilities as at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the year. Examples of such estimates include useful life of fixed assets, employee benefits, contingent liabilities etc. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

2.3 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information

2.4 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

- (i) Fee received from member for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.
- (ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.
- (iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.
- (iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- (v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:
 - (a) From Accounting Research Building Fund 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building relating to Accounting Research Building.
 - (b) From Educationa Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to other Fixed Assets.

2.5 Fixed Assets

(i) Tangible Assets

Tangible assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). The cost of an asset includes the purchase cost of materials, including import duties and non-refundable taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to the location and condition of its intended use. The cost of leasehold land includes the amounts paid for acquiring leasehold rights. Subsequent expenditure relating to tangible assets are capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

Cost of Leasehold land is amortised over the primary lease period. Depreciation on all other tangible fixed assets are provided on a written down value method based on the estimated useful life at the following rates as approved by the Council of the Institute.

Class of Assets	Rate of Depreciation
(i) Buildings	5%
(ii) Air conditons	15%
(iii) Electrical Installations and Fittings	10%
(iv) Furniture and Fixtures	10%
(v) Office Equipments	15%

(vi) Computers	60%
(vii) Lifts	10%
(viii) Vehicles	20%
(ix) Library Books	100%

(ii) Intangible Assets

Intangible assets are stated at acquisition cost, less accumulated amortisation and accumulated impairment (if any). The cost of an intangible asset includes purchase cost (net of rebates and discounts), including any import duties and non-refundable taxes, and any directly attributable costs on making the asset ready for its intended use. Subsequent expenditure on an intangible asset after its purchase / completion is recognised as an expense when incurred unless it is probable that such expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably, in which case such expenditure is added to the cost of the asset.

The Cost of Intangible assets are amortised on a straight line basis over their estimated useful life of three years.

(iii) Capital Work in progress

Expenditure incurred on construction of assets which are not ready for their intended use are carried at cost less impairment (if any), under Capital work-in-progress. The cost includes the purchase cost of materials, including import duties and non-refundable taxes, any directly attributable costs.

2.6 Investments

Investments in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. The investments are available for use freely at the discretion of the council of the Institute except to the extent of total of the Earmarked and Employee benefit funds.

2.7 Inventories

- Inventory of publications, study materials, stationery and other stores are valued at lower of cost and net realisable value. Cost of inventory is determined on First In First Out (FIFO) method.
- A provision of 100% is made on the cost of stock of old study material and Institute's publications older than one year. Further, a provision of 25% is made on the cost of remaining stock of BOS publications.

2.8 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprises of cash on hand and balances in current and savings deposits accounts with banks.

2.9 Revenue recognition

- Membership Fee
 - One third of Entrance Fee collected at the time of admission of person as member recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.
 - Annual Membership and Certificate of Practice Fee are recognised as income in the year in which they become due.
- Distance education and post qualification course fee are recognised over the duration of the respective courses.
- Examination fee is recognised on the basis of conduct of the respective examinations.
- Subscription for the journal is recognised as income in the year in which they become due.

- (v) Income from sale of publication are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincides with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other sales related taxes (if any).
- (vi) Interest income from bank deposits and loans to employees are recognised on a timely basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

2.10 Foreign Currency Transaction

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency ie., Indian Rupees using the exchange rates prevailing on the date of transactions. Monetary assets and liabilities in currencies other than the reporting currency remaining unsettled are remeasured at the rates of exchange prevailing at the balance sheet date. Exchange difference arising on the settlement of monetary items, and on the remeasurement of monetary items are included in the statement of income and expenditure.

2.11 Impairment of assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.12 Employee benefits

(i) Short term employee benefits

Short term employee benefits like salary, allowances, exgratia are recognised as expenses in the year in which the related services are rendered.

(ii) Defined Contribution Plans

Defined contribution plans are those plans where the Institute pays fixed contributions to Provident Fund managed by independent trust. Contributions are paid in return for services rendered by the employees during the year and recognised as expenses in line with salary and allowances. The Institute has no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay/extend benefits to the Employees.

(iii) Defined Benefits Plans

The Institute provides gratuity, post retirement pension and compensated absence to its employees. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India. The liabilities towards compensated absence and post retirement pension are not funded. The present value of these defined benefit obligations are ascertained by an independent actuarial valuation as per the requirements of Accounting Standard (AS)-15 Employee Benefits. The liability recognised in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations on the balance sheet date less the fair value of plan assets (for funded plans) together with adjustments for unrecognised past service costs. Past service costs is recognised immediately to the extent that the benefits are vested. All actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in full in the year in which they occur.

2.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

(i) Provision

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

(ii) Contingent Liabilities and assets

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

3. Reserves and surplus**As at March 31, 2015**

					(Rs. in lacs)
	Education	Infrastructure	General	Others*	Total
Balance at the beginning of the year	29,739	4,571	67,826	604	102,740
Add: Opening balance of reserves of Student Associations		3	96		99
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	—	—	3,652		3,652
	29,739	4,574	71,574	604	106,491
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	—	8	(96)	88	—
Transfer from / (to) Earmarked	2,411	(60)	(174)	(1)	2,176
Fund	-	165	-	-	165
Admission fees and allocated Entrance fees					
Donation received for buildings	-	68	-	-	68
(Utilization)/Addition	-	(29)	(171)	(39)	(239)
Balance at the end of the year	32,150	4,726	71,133	652	108,661

As at March 31, 2014

(Rs in lacs)

	Education	Infrastructure	General	Others*	Total
Balance at the beginning of the year	23,092	4,161	55,897	582	83,732
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	11,628	-	11,628
	23,092	4,161	67,525	582	95,360
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	16	(26)	10	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	6,647	-	(178)	(1)	6,468
Admission fees and allocated Entrance fees	-	183	-	-	183
Donation received for buildings	-	178	-	-	178
(Utilization)/Addition	-	33	505	13	551
Balance at the end of the year	29,739	4,571	67,826	604	102,740

* Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves.

Earmarked Funds							
As at March 31, 2015							
	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Other Funds (Regional Council and Branches)
Balance at the beginning of year	1,760	610	14,731	176	91	410	3,074
Add: opening balance of Earmarked Funds of Student Associations							2
Appropriation from Statement of Income and Expenditure			5,027			39	
Transfer from/(to) Reserves and Surplus			(2,411)				235
Contribution received/ Addition during the year				4	17		343
income during the year	165	57	1,379	16	9	38	187
payments the year	(5)			(12)	(5)		(138)
balance at the end of the year	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703

As at March, 20 14

(Rs in lacs)

	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Other Funds (Regional Council and Branches)
Balance at the beginning of the year	1,603	556	14,088	171	89	341	2,508

		(Rs. in lacs)	
		As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
5. Other Long-term Liabilities			
(a)	Fees received in advance		
(i)	Fees from students	952	1,002
(ii)	Journal subscription	9	11
	Total	961	1,013
		As at March 31, 2015 Long-term	As at March 31, 2014 Long-term
		As at March 31, 2015 Short-term	As at March 31, 2014 Short-term
6. Provisions			
Provisions for employee benefits			
a)	Post employment defined benefits		
(i)	Gratuity	-	-
(ii)	Pension	2,673	1,402
b)	Other Long-term employee benefits	2,857	2,360
	Total	5,530	3,762
		239	321
	Total	250	325
7 Other Current Liabilities			
a)	Fees received in advance		
(i)	Examination fees	4,872	4,471
(ii)	Journal subscription	19	23
(iii)	Membership fees	1,296	1,150
(iv)	Education fees	8,656	9,335
(v)	Post Qualification Courses fees	108	145
(vi)	Certificate Courses fees	18	9
(vii)	Seminar fees and Other collections	1,171	1,719
		16,140	16,852
(b)	Expenses and other payables	5,653	3,176
(c)	Other liabilities		
(i)	Creditors for purchase of fixed assets	120	166
(ii)	Employees recoveries and employer's contributions	111	85
(iii)	Statutory dues	269	186
(iv)	Deposits	548	489
(v)	Others	1,027	1,217
		2,075	2,143
	Total	23,868	22,171

(Rs. in lacs)
As at March 31, 2015

	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	Lifts & Electrical Installation and Fittings	Computers	Furniture and Fixtures	Air Conditioner & Office Equipment	Vehicles	Library Books	Total
8. Tangible Assets										
Cost at the beginning of the year	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504
Additions	149	914	2,415	135	528	356	424	30	78	5,029
Deletions	-	-	-	(23)	(110)	(50)	(66)	(1)	-	(250)
Cost at the end of the year	15,690	5,399	26,932	1,757	4,463	3,765	4,236	134	907	63,283
Depreciation at the beginning of the year	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
Charge for the year	-	80	1,131	96	376	236	324	11	78	2,332
Deletions	-	-	-	(11)	(105)	(28)	(47)	(1)	-	(192)
Depreciation at the end of the year	-	499	4,325	873	3,958	1,535	2,219	82	907	14,398
Net book value at beginning of the year	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33	-	46,246
Net book value at end of the year	15,690	4,900	22,607	884	505	2,230	2,017	52	-	48,885

(Rs in lacs)
As at March 31, 2014

	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	Lifts & Electrical Installation and Fittings	Computers	Furniture and Fixtures	Air Conditioner & Office Equipment	Vehicles	Library Books	Total
Cost at the beginning of the year	15,376	3,701	13,421	1,552	3,760	3,055	3,484	103	759	45,211
Additions	165	784	11,096	96	328	431	405	2	71	13,378
Deletions	-	-	-	(3)	(43)	(27)	(11)	-	(1)	(85)
Cost at the end of the year	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504
Depreciation at the beginning of the year	-	355	2,182	699	3,478	1,118	1,641	64	759	10,296
Charge for the year	-	64	1,012	91	250	220	307	8	71	2,023
Deletions	-	-	-	(2)	(41)	(11)	(6)	-	(1)	(61)
Depreciation at the end of the year	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
Net book value at the beginning of the year	15,376	3,346	11,239	853	282	1,937	1,843	39	-	34,915
Net book value at the end of the year	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33	-	46,246

9. Intangible Assets(Rs. in lacs)
As at March 31, 2015

	Software	Total
Cost at the beginning of the year	595	595
Additions	42	42
Deletions	-	-
Cost at the end of the year	637	637
Amortisation at the beginning of the year	591	591
Charge for the year	16	16
Deletions	-	-
Amortisation at the end of the year	607	607
Net book value at the beginning of the year	4	4

(Rs in Lacs)
As at March 31, 2014

	Software	Total
Cost at beginning of the year	593	593
Additions	2	2
Deletions	-	-
Cost at end of the year	595	595
Amortisation at beginning of the year	588	588
Charge for the year	3	3
Amortisation at end of the year	591	591
Net book value at beginning of the year	5	5
Net book value at end of the year	4	4

	As at March 31, 2015 Non- current	As at March 31, 2014 Non-current	As at March 31, 2015 Current	As at March 31, 2014 Current
10. Investments				
Fixed deposits with banks	13,737	-	72,657	77,572
	13,737	-	72,657	77,572
Investments include	13,737	-		
-Earmarked funds		-	12,062	20,852
-Employee benefits	-	-	5,780	4,087
	As at	As at	As at	As at

		March 31, 2015 Non- current	March 31, 2014 Non-current	March 31, 2015 Current	March 31, 2014 Current
11.	Loans and Advances				
(a)	Security Deposits	307	270	234	-
(b)	TDS Recoverable	1,965	1,640	-	675
(c)	Other loans and advances				
(i)	Retirement benefit assets	-	-	19	46
(ii)	Loans and advances to Employees	854	814	454	477
(iii)	Other receivables	598	244	3,134	2,413
	Total	3,724	2,968	3,841	3,611
				As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
12.	Non-current assets				
(a)	Interest accrued on bank deposits			646	-
(b)	Interest accrued on loans to employees			101	110
	Total			747	110
13.	Inventories				
(a)	Publication and Study Materials			1,571	932
(b)	Stationery and Stores			129	92
	Total			1,700	1,024
14.	Cash and Cash equivalents				
(a)	Cash on hand			50	33
(b)	Balances with banks			5,977	6,853
	Total			6,027	6,886
15.	Other Current Assets				
(a)	Interest accrued on bank deposits			2,314	2,916
(b)	Interest accrued on loans to employees			20	3
	Total			2,334	2,919

		For the Year Ended March 31, 2015	For the Year Ended March 31, 2014
16.	Fees received		
	(a) Education	28,222	31,453
	(b) Examination	11,211	10,061
	(c) Membership	5,366	5,120
	(d) Students' registration	589	714
	(e) Entrance	52	62
	(f) Students' Association	401	535
	Post Qualification Courses	472	625
	(g)		
	(h) Certificate Courses	1,489	988
	Total	47,802	49,558
			(Rs in Lacs)
		For the Year Ended March 31, 2015	For the Year Ended March 31, 2014
17.	Other Income		
	(a) Publications	1,495	936
	(b) Interest received on investments	6,044	4,941
	(c) Interest received on earmarked funds investments	1,851	-
	(d) Interest received from loans to employees	76	67
	(e) Students' Newsletter	3	6
	(f) Journal Subscription	202	155
	(g) News Letters - Regional Councils and Branches	55	56
	(h) Campus Interview	486	398
	(i) Expert Advisory Fee	30	16
	(j) Provision no longer required written back	310	10
	(k) Others	769	710
	Total	11,321	7,295
18.	Employee Benefit Expense		
	(a) Salary, Pension and other allowances	11,597	7,185
	(b) Contribution to Provident and other funds	748	398
	(c) Staff Welfare Expenses	223	110
	Total	12,568	7,693

19. Other Expenses

(a)	Postage and Telephone	2,660	2,513
(b)	Rent, rates and taxes	3,611	2,768
(c)	Travelling and Conveyance - Domestic	1,714	1,487
(d)	Overseas Relations		
(i)	Overseas Travelling	251	217
(ii)	Membership fees for Foreign Professional Bodies	332	338
(iii)	Others	28	31
(e)	Repairs and Maintenance	1,642	1,548
(f)	Publications	1,131	962
(g)	Professional fee paid to Consultants and Examiners	7,204	6,644
(h)	Class room training expenses	4,557	4,444
(i)	Advertisement and Publicity	405	255
(j)	Meeting Expenses	292	178
(k)	Merit Scholarship	94	87
(l)	Audit Fees		
(i)	Head Office	11	6
(ii)	Other Offices	28	21
(m)	Payments from Earmarked Funds	160	-
(n)	Other Expenses	2,329	1,489
	Total	26,449	22,988

20. Additional information to the Financial Statements**20.1 Contingent liabilities and commitments****(Rs in Lacs)**

	As at March 31, 2015	As at March 31, 2014
(i) Claims against the Institute not acknowledged as debts	1,378	1,440
(ii) Capital commitments (net of advances)	8,084	9,402

20.2 Other Receivables in Note 11 Long term Loans & Advances include Rs 243.75 Lakh for Stamp duty refund receivable on cancellation of Principal and supplementary Agreements of acquiring property at nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The Institute has filed two Appeals before chief Controlling Revenue Authority, Pune under Section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the Orders passed by JDR, Nagpur which are still pending. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

20.3 Directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

20.4 Out of the fee received from the students towards Students Association fee, a sum of Rs.250 per student, in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

- 20.5** Leasehold land value includes Rs. 6.17 Lacs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.
- 20.6** The Institute had initiated a process for digitisation of entire activities including members, students and other professional activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. Pursuant to this initiative and following a due process, Institute had appointed a global integrated service provider supervised by a globally reputed project management consultant. This contract included requirement study, recommendation of selection of software and hardware, development of software where necessary, providing appropriate application softwares, implementation and also selection and maintenance of IT infrastructure at a total estimated cost of Rs.3,981 lacs. A sum of Rs.867 lacs has been incurred upto 31st March 2015. The integrated service provider did not carry out the development as per the requirement, even after extended periods leading to institute raising a dispute and cancelling the contract. Pending final settlement, Institute invoked the bank guarantee of Rs.295 lacs in the month of June 2015. The same has been shown as receivable as at 31st March 2015 in the financials under the head other receivable (Current) in Note No. 11. After deducting amount of bank guarantee subsequently realised, amount of Rs.572 lacs (867 lacs - 295 lacs) has been fully expensed off in the financials.
- 20.7** Capital Work in Progress includes capital advances.
- 20.8** A piece of land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by HUDA (Harayana).
- 20.9** The Institute has changed the presentation of income & expenditure on earmarked funds from directly crediting/debiting to the earmarked funds to the respective item of income & expenditure and transferred the net increase to respective earmarked funds.
- Had this presentation been followed in previous year, the other income would have been higher by Rs 1,817 Lacs, other expenses by Rs 179 Lacs and net surplus by Rs 1,638 Lacs.
- 20.10** Previous year's figures have been re-grouped and re-classified where considered necessary to make them comparable with those of the current year.

21. Disclosure under Accounting Standards

21.1 Employee Benefits

Defined Contribution Plans

The Institute has recognised an amount of **Rs.327.65 Lacs** for the year ended 31st March 2015 (Previous year Rs.326.37 Lacs) towards contribution to Provident Fund.

Defined Benefit plans

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity : Funded
Post retirement Pension : Non Funded
Compensated Absence: Non Funded

Details of the Gratuity Plan are as follows

Description	2014-15	(Rs. in lacs) 2013-14
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation		
a. Obligation as at beginning of the year	2,057	1,957
b. Current service cost	167	147
c. Interest cost	154	171
d. Actuarial (gain)/loss	32	(63)
e. Benefits paid	(197)	(155)
f. Obligation as at end of the year	2,213	2,057
2. Change in fair value of plan assets		
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	2,103	1,950
b. Expected return on plan assets	184	174

Details of the Post Retirement Pension Plans

Details of the Post Retirement Pension Plans		(Rs. in lacs)
Description	2014-15	2013-14
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation		
a. Obligation as at beginning of the year	1,406	1,489
b. Interest cost	110	134
c. Actuarial (gain)/loss	1,169	(215)

			(2)
	d. Benefits paid	(1)	
		2,684	1,406
	e. Obligation as at end of the year		
2.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations		
		2,684	1,406
	a. Present value of obligation		
	b. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(2,684)	(1,406)
3.	Expenses recognised during the year		
			134
	a. Interest cost	110	
			(215)
	b. Actuarial (gain)/loss	1,169	
			(81)
	c. Expenses recognised during the year	1,279	
4.	Assumptions		
	a. Discount rate (per annum)	7.80%	9%
	c. Rate of escalation in salary	Basic 3%	Basic 3%
	d. Attrition Rate	5%	5%
	e. Mortality table	LIC 1996-98	LIC 1996-98
		Ultimate	Ultimate
21.1	Employee Benefits (Contd..)		
	Details of the Compensated absences		(Rs. in lacs)
	Description	2014-15	2013-14
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation		
	a. Obligation as at beginning of the year	2,359	2,239
		338	104
	b. Current service cost		199
	c. Interest cost	175	
		259	(83)
	c. Actuarial (gain)/loss		(100)
	d. Benefits paid	(274)	
		2,857	2,359
	e. Obligation as at end of the year		
2.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations		
		2,857	2,359
	a. Present value of obligation		
#	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(2,857)	(2,359)
3.	Expenses recognised during the year		
		338	104
	a. Current Service Cost		199
	b. Interest cost	175	
		259	(83)
	c. Actuarial (gain)/loss		
	d. Expenses recognised during the year	772	220
4.	Assumptions		
	a. Discount rate (per annum)	7.85%	9.10%
	b. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	c. Attrition	5%	5%

	Rate		
	d. Mortality	IAL 2006-08	IAL 2006-08
	table		
		Ultimate	Ultimate
#	This pertains to Long Term Liability worked in respect of deferred leave only. Expected Short Term liability of Rs 239 Lacs will be added to this figure.		
21.2	Segment Reporting		
	The Institute's operations are confined to "furtherance of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.		
21.3	Prior-period items		
		For the Year Ended March 31, 2015	For the Year Ended March 31, 2014
		(Rs. in lacs)	(Rs. in lacs)
	Break up of Prior-period items		
i)	Income	38	93
ii)	Expenses		(97)
	a) Project Parivartan	-	
	b) Service Tax	-	26
	c) Others	294	180
		294	109
		256	16
	Total		
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
H.K. Jain	V. Sagar	CA. M. Devaraja Reddy	CA. Manoj Fadnis
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President
As per our Report attached			
For ASA & Associates LLP		For B.M. Chatrath & Co	
Chartered Accountants		Chartered Accountants	
FRN: 009571N/N500006		FRN: 301011E	
Sd/-		Sd/-	
CA. Parveen Kumar		CA. Umesh C. Pandey	
Partner		Partner	
M.No - 088810		M.No - 055252	
Place: New Delhi			
Date: 1st september, 2015			

V. SAGAR, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./104/15(219)]